देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

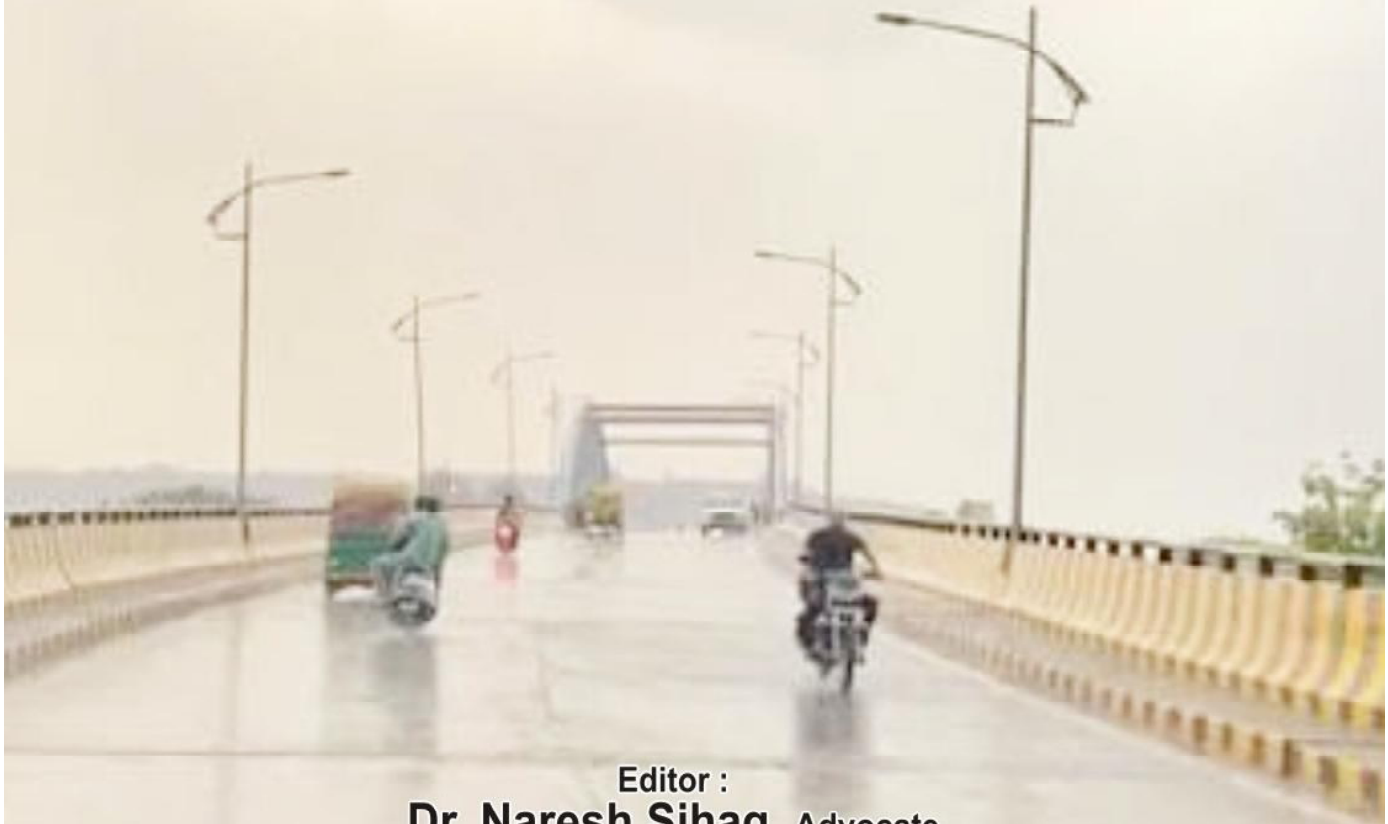
9 772395 711007

Impact Factor
8.642

ISSN : 2395-7115
July 2026
Vol.-24, Issue-1

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL



Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate

Publisher :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
#202, Old Housing Board, Bhiwani, Haryana-127021

स्व. चौ. गुगनराम सिहाग व उनकी छोटी बहन स्व. श्रीमती गीना देवी के शुभाशीर्वाद से प्रकाशित

JOURNAL OF HUMANITIES, COMMERECE, SCIENCE, MANAGEMENT & LAW

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Vol. 24 ISSUE-1, Part-3 (जुलाई 2026) ISSN : 2395-7115

प्रेरणा :

चौ. एम. सिहाग

सम्पादक :

डॉ. नरेश सिहाग 'बोहल', एडवोकेट

एम.ए. (समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिन्दी शिक्षा शास्त्र, पत्रकारिता),
एम.फिल (समाजशास्त्र, हिन्दी) एम. लिब., एल-एल.बी. (ऑनर्स),
डिप्लोमा पंचायती राज (रजत पदक विजेता), पी.एच.डी. (हिन्दी)
डी.लिट् (मानद उपाधि), काठमांडू, नेपाल

कार्यकारी सम्पादक :

प्रो. शकुन्तला चौहान

शामली, उत्तर प्रदेश।

प्रकाशक :

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)

202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड, भिवानी-127021 (हरियाणा)

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL REFEREED/REVIEWED AND INDEXED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL
ISSN 2395-7115

सम्पादकीय सम्पर्क :
डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट
202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड,
भिवानी-127021 (हरियाणा)
Email : nksihag202@gmail.com
मो. 09466532152

Published by :
Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)
202, Old Housing Board,
Bhiwani-127021 (Haryana) INDIA
Email : grsbohal@gmail.com
Facebook.com/bohalshodhmanjusha
Website : www.bohalsm.blogspot.com
WhatsApp : 9466532152

All Right Reserved by Publisher & Editor

Price

Individual/Institutional : 1100/-

Disclaimer :

1. Printing, Editing, Selling and distribution of this Journal is absolutely honorary and non-commercial.
2. All the Cheque/Bank Draft/IPO should be sent in the name of Gugan Ram Educational & Social Welfare Society payable at Bhiwani.
3. Articles in this journal do not reflect the Views or Policies of the Editor's or the Publisher's. Respective authors are responsible for the originally of their views/opinions expressed in their articles.
4. All dispute will be Subject to Bhiwani, Hry. Jurisdication only.

Printed by : Manbhawan Printers, Old Bus Stand Road, Naya Bazar, Bhiwani (Hry.)

बोहल शोध मंजूषा परिवार*

मानद संरक्षक

डॉ. कैलाश चन्द्र शर्मा 'शंकी'
पूर्व शिक्षा अधिकारी,
साहित्यकार,
चरखी दादरी (हरियाणा)

डॉ. विश्वबंधु शर्मा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
बाबा मस्तनाथ वि.वि.
रोहतक (हरियाणा)

डॉ. विनोद तनेजा
पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
गुरूनानक वि.वि. अमृतसर
पंजाब।

सम्पादक मण्डल

सह सम्पादिका :
डॉ. रेखा सोनी
उप प्राचार्या, शिक्षा विभाग
टाटिया वि.वि. श्रीगंगानगर।

सह सम्पादिका :
डॉ. सुशीला आर्या
हिन्दी विभाग, चौ. बंसीलाल
विश्वविद्यालय, भिवानी।

प्रबंध सम्पादक :
समुन्द्र सिंह
भिवानी, हरियाणा।

विधि विशेषज्ञ

डॉ. रामफल दलाल, एडवोकेट
जिला न्यायालय
भिवानी, हरियाणा।

अजीत सिहाग, एडवोकेट
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट,
चंडीगढ़।

चरणवीर सिंह, एडवोकेट
जिला न्यायालय
पटियाला, पंजाब।

विषय विशेषज्ञ/परामर्शदात्री/शोधपत्र निरीक्षण समिति

डॉ. कुमारी लक्ष्मी जोशी
हिन्दी विभाग, त्रिभुवन वि.वि.
काठमाण्डू, नेपाल।

डिल्लीराम शर्मा संग्रौला
विभागीय प्रमुख, संस्कृत, पत्रकारिता, हिंदी
पद्मकन्या बहुमुखी कैंपस, काठमांडू, नेपाल।

डॉ. संजय एल. मादार
विभागाध्यक्ष, पी.जी. केन्द्र
द.भा.हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद।

डॉ. गीता दहिया, प्राचार्या,
नैशनल टीटी कॉलेज फॉर गर्ल्स
अलवर, राजस्थान

डॉ. इस्पाक अली
पूर्व प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री
शिक्षा महाविद्यालय, बेंगलूरू

डॉ. मो. रियाज़ खान
बीएमएस वूमैन कॉलेज आटोनोमेस
बेगलूरू

डॉ. वनिता कुमारी
च. दादरी (हरियाणा)

श्री सहदेव समर्पित
सम्पादक, शान्तिधर्मी, जीन्द

डॉ. अंजली उपाध्याय
उत्तर प्रदेश

डॉ. लता एस. पाटिल
राजीव गांधी बीएड कालेज
धारवाड़, कर्नाटक

प्रो. अमनप्रीत कौर
गुरू तेग बहादुर खालसा कॉलेज
फॉर वूमैन, दसूहा, पंजाब

डॉ. वर्षा रानी
संस्कृत विभाग, डॉ. भीमराम
अम्बेडकर, वि.वि., आगरा

प्रो. कमलेश चौधरी
राजकीय रणबीर महाविद्यालय
संगरूर, पंजाब

डॉ. किरण गिल
दीनदयाल टी.टी. महाविद्यालय
बारी, जिला सीकर, राज.

डॉ. सविता घुड़केवार
पीजी विभाग, दक्षिण भारत
हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

डॉ. परमजीत कौर
बरेली कॉलेज बरेली,
उत्तर प्रदेश।

डॉ. राजकुमारी शर्मा
श्रीराम कॉलेज,
नई दिल्ली।

डॉ. श्रीविद्या एन.टी.
श्री शंकराचार्य संस्कृत वि.वि.
केरल।

डॉ. बी. संतोषी कुमारी
पी.जी.विभाग, दक्षिण भारत हिन्दी
प्रचार सभा, मद्रास।

श्री राकेश ग्रेवाल
सन जॉस,
कैलिफोर्निया, यू.एस.ए.

डॉ. पंडित बन्ने
भारत महाविद्यालय,
सोलापुर (महाराष्ट्र)

डॉ. करमजीत कौर
प्राचार्या, दशमेश गर्ल्स कॉलेज
चक आला, मुकेरिया, पंजाब।

श्री राकेश शंकर भारती
साहित्यकार व अनुवादक,
यूक्रेन।

डॉ. उमा सैनी
आई.ए.एस.ई. विश्वविद्यालय
सरदारशहर, राजस्थान

डॉ. मनमीत कौर
राधा गोविन्द वि.वि.,
रामगढ़, झारखण्ड।

डॉ. रीना उन्नीयाल तिवारी
शिक्षा संकाय, डी.ए.वी. पीजी
कालेज, देहरादून

डॉ. सुरजीत सिंह कस्वां
डीन फिजिकल एजुकेशन
टांटिया वि.वि., श्रीगंगानगर,

डॉ. शबाना हबीब
गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वूमैन
त्रिवन्तपुरम, केरल।

डॉ. शिवकरण निमल
सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान
एसपीसी राजकीय महा. भीम, राजस्थान।

डॉ. राधाकृष्णन गणेशन
भारत कला भवन
वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

डॉ. मानसिंह दहिया
संस्कृत विभाग
हरियाणा सरकार।

डॉ. नीलम आर्या
संस्कृत विभाग
उत्तर प्रदेश।

डॉ. रवि सुण्डयाल
हॉयर एजुकेशन डिपार्टमेंट
जम्मू कश्मीर।

प्रो. नरेन्द्र सोनी
सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी,
हरियाणा सरकार।

डॉ. रोहतास
एस.जी.पी.जी.आई.एम.एस.
लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

प्रो. सत्यबीर कालोहिया
पूर्व प्राचार्य,
कैलिफोर्निया।

पठान चिन्ना जानी
सहायक प्राध्यापक
सी.एच.एस.डी. सेंट थेरेसा
महिला महाविद्यालय (ए)
एलुरु, आंध्र प्रदेश

डॉ. वैशाली सिंह
सहायक प्राध्यापक
शिक्षा विभाग, एस.एम.टी. अनार देवी
टी.टी. कॉलेज, बखराना
(कोटपुतली) राजस्थान।

डॉ. रेखा रानी
गवर्नमेंट रणबीर कॉलेज
संगरूर, पंजाब

डॉ. के.के. मल्हौत्रा
पूर्व विभागाध्यक्ष
गवर्नमेंट कॉलेज, गुरदासपुर

डॉ. अंकिता चतुर्वेदी, प्रवक्ता
भीमसेन डिग्री कॉलेज
(आगरा यूनिवर्सिटी)

शिओंग छन श्यू
चीन

*सम्पूर्ण बोहल शोध मञ्जूषा परिवार/सम्पादक मण्डल अवैतनिक है।

देवानां भद्रा सुमतिर्ऋजूयताम्।। ऋ० १/८९/२

ISSN : 2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED & REFEREED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Publisher : Gugan Ram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Table 2

Methodology for University and College Teachers for calculating Academic/Research Score

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc,.)

S.N.	Academic/Research Activity	Faculty of Sciences /Engineering / Agriculture / Medical /Veterinary Sciences	Faculty of Languages / Humanities / Arts / Social Sciences / Library /Education / Physical Education / Commerce / Management & other related disciplines
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper	10 per paper
2.	**Publications (other than Research papers)**		
	(a) Books authored which are published by ;		
	International publishers	12	12
	National Publishers	10	10
	Chapter in Edited Book	05	05
	Editor of Book by International Publisher	10	10
	Editor of Book by National Publisher	08	08
	(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties		
	Chapter or Research paper	03	03
	Book	08	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**		
	(a) Development of Innovative pedagogy	05	05
	(b) Design of new curricula and courses	02 per curricula/course	02 per curricula/course

अनुक्रमाणिका – जुलाई 2026

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1.	सम्पादकीय	डॉ. नरेश सिहाग	09–09
2.	दक्षिण एशिया में चीन की सॉफ्ट पावर कूटनीति और नेपाल में उसका प्रभाव	स्वेता कुमारी, डॉ. लक्ष्मी कुमारी	11–16
3.	Customer Perceptions and Expectations of Digitalization in the Banking Industry : An Empirical Study with Chi-Square Analysis	Shashi Kant Upadhyay	17-29
4.	'छाया मत छूना मन' में स्त्री जीवन की विडंबनाएँ	निकिता पंत	30–33
5.	महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य में नारी चेतना और मानवीय संवेदना	डॉ० शीला छीपा	34–40
6.	डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' के समीक्षा-साहित्य का चिंतन	सुशीला देवी, डॉ० धनेश कुमार मीणा	41–46
7.	तुलसीकाव्य का वैशिष्ट्य	डॉ. संजय कुमार सिंह	47–51
8.	IoT Components and Machine Learning Algorithms for Smart Vehicles	Tejas Rajaram Jadhav, Dr. Hiren Jayantilal Dand	52-63
9.	संस्कृत में नवाचार : परम्परा से प्रौद्योगिकी तक	डॉ. वर्षा रानी	64–68
10.	A POLITICAL AND CONSTITUTIONAL STUDY OF MULTICULTURALISM IN INDIA WITH REFERENCE TO THE SIXTH SCHEDULE	Tina Kimngaiting Vaiphei, Amy Nemchanpha Vaiphei	69-78
11.	The China - Pakistan Strategic Axis : Implications for India's National Security	Prof. Bina Rai, Nikhil Kumar Rai	79-86
12.	मध्यप्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का सतत् प्रबंधन और भविष्य की चुनौतियों का भौगोलिक विश्लेषण (विकसित भारत @2047 के सन्दर्भ में)	डॉ. अजय तिवारी	87–94
13.	अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में पर्यावरणीय चेतना एवं समकालीन वैश्विक पर्यावरण संकट	अंकित चौरसिया	95–99
14.	पर्यावरण चेतना में यज का महत्त्व	अमल बर्मण	100–105
15.	Changing Nature of Modern State in Digital era and Construction of New Political Identity through Biometric and Various Technological Advancement	Mukesh Kumar	106-114

16.	**Social Engineering, Caste Coalitions and Electoral Politics : BJP's Strategy in Haryana (2014–2024)**	**Kamal**	**115-126**
17.	**Beyond the Binary : Male Victimization and the Unfinished Project of Gender Justice in India**	**Ms. Sangeeta**	**127-148**
18.	मतदान व्यवहार और इसके बहुआयामी निर्धारक तत्व : भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक विस्तृत समाजशास्त्रीय और राजनीतिक विश्लेषण	डॉ. एस.पी. शुक्ला, अंजुलि शुक्ला	149–162
19.	विकासशील देशों में शहरीकरण के रूझानों का विश्लेषण	Vajeer Singh	163-166
20.	कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में यथार्थ का स्वरूप : एक विश्लेषण	सतीश भास्कर, अरविंदर कौर चुंबर	167–172
21.	प्रेत और छाया उपन्यासो में वर्णित पुरूष मनोवृत्ति का यथार्थ चित्रण	चंचल जाट, डॉ. मलय पानेरी	173–178
22.	**Colonialism : Space, Violence and a new Geographic Conception of India**	**Asha Yadav, Durgesh Kumar**	**179-186**
23.	**Motherhood, Sacrifice and Female Identity in Tony Morrison's Beloved**	**Shamama Bano**	**187-194**
24.	**Strengthening Climate Action through the India–Japan Joint Crediting Mechanism : An Analysis of the June 2026 Rules of Implementation**	**Jai Shri Prajapat, Dr. Arvind Verma**	**196-200**
25.	आदिवासी ज्ञान और सतत् विकास : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की थारू जनजाति के विशेष सन्दर्भ में)	अजय कुमार विश्वकर्मा, डॉ. नेहा मालवीय	201-213
26.	శ్రీశ్రీ కవిత్వం - మార్క్సిస్టు ప్రభావం	డా.పసుపులేటి నాగమల్లిక	214–216

संपादकीय...

ज्ञान, अनुसंधान और नवाचार : विकसित भारत की आधारशिला

मानव सभ्यता का विकास ज्ञान, जिज्ञासा और अनुसंधान की सतत प्रक्रिया का परिणाम है। प्रत्येक युग में समाज की प्रगति उन व्यक्तियों और संस्थानों के कारण संभव हुई है जिन्होंने स्थापित धारणाओं से आगे बढ़कर नए विचारों को जन्म दिया। आज इक्कीसवीं सदी के इस ज्ञान–आधारित युग में शोध केवल शैक्षणिक उपाधि प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, वैज्ञानिक उन्नति, सांस्कृतिक संरक्षण और राष्ट्रीय विकास का सशक्त साधन बन चुका है। ऐसे समय में बोहल शोध मंजूषा का जुलाई 2026 अंक अपने पाठकों और शोधकर्ताओं के समक्ष विविध विषयों पर आधारित शोध आलेखों का समृद्ध संकलन प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है।

वर्तमान समय अनेक नई चुनौतियों और संभावनाओं का समय है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, शिक्षा में नवाचार, भारतीय ज्ञान परंपरा, सामाजिक समरसता तथा वैश्विक सहयोग जैसे विषय आज शोध के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं। इन क्षेत्रों में गंभीर एवं तथ्यपरक अनुसंधान न केवल नई जानकारियाँ प्रदान करता है, बल्कि नीति–निर्माण, सामाजिक जागरूकता और व्यवहारिक समाधान विकसित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शोध तभी सार्थक होता है जब वह समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से जुड़कर जनहित में उपयोगी सिद्ध हो।

भारतीय ज्ञान परंपरा सदैव अनुसंधान और विमर्श की संस्कृति को प्रोत्साहित करती रही है। वेद, उपनिषद, बौद्ध एवं जैन साहित्य, आयुर्वेद, गणित, खगोलशास्त्र और दर्शन के क्षेत्र में भारत ने विश्व को अमूल्य ज्ञान प्रदान किया है। आज आवश्यकता है कि हम अपनी इस समृद्ध बौद्धिक विरासत का आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ पुनर्पाठ करें और उसे वैश्विक संदर्भों में प्रस्तुत करें। नई शिक्षा नीति 2020 ने भी अनुसंधान, नवाचार और बहुविषयक अध्ययन को विशेष महत्व देकर इसी दिशा में एक सशक्त पहल की है।

उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शोध की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। केवल शोध–पत्रों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, उनकी गुणवत्ता, मौलिकता, वैज्ञानिक पद्धति, नैतिकता तथा सामाजिक उपयोगिता भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। साहित्यिक चोरी, तथ्यहीन निष्कर्ष और औपचारिक शोध संस्कृति जैसी प्रवृत्तियाँ शोध की विश्वसनीयता को प्रभावित करती हैं। इसलिए प्रत्येक शोधकर्ता का दायित्व है कि वह सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और बौद्धिक ईमानदारी के साथ अपने अनुसंधान कार्य को संपन्न करे। एक उत्कृष्ट शोध वही है जो नए प्रश्न उत्पन्न करे, नए दृष्टिकोण विकसित करे और भविष्य के अनुसंधानों के लिए मार्ग प्रशस्त करे।

आज अंतःविषयक अनुसंधान का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, वाणिज्य, शिक्षा, चिकित्सा और प्रौद्योगिकी के बीच समन्वित अध्ययन जटिल समस्याओं के व्यापक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण तथा डिजिटल समावेशन जैसे विषय बहुआयामी दृष्टिकोण की अपेक्षा करते हैं। इसलिए शोधकर्ताओं को पारंपरिक

सीमाओं से बाहर निकलकर सहयोगात्मक अनुसंधान को अपनाना चाहिए।

यह भी आवश्यक है कि शोध के निष्कर्ष केवल पुस्तकालयों या शोध पत्रिकाओं तक सीमित न रहें, बल्कि समाज तक पहुँचें। जब अनुसंधान के परिणाम शिक्षा, प्रशासन, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक जीवन में व्यावहारिक रूप से उपयोग किए जाते हैं, तभी शोध की वास्तविक सार्थकता सिद्ध होती है। ज्ञान का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं, बल्कि समाज के जीवन स्तर में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। इस दृष्टि से शोध पत्रिकाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वे शोधकर्ताओं और समाज के बीच एक प्रभावी सेतु का कार्य करती हैं।

बोहल शोध मंजूषा का उद्देश्य भी यही है कि विभिन्न विषयों के विद्वानों, शिक्षकों, शोधार्थियों और स्वतंत्र चिंतकों को एक ऐसा अकादमिक मंच उपलब्ध कराया जाए जहाँ मौलिक, प्रमाणिक और गुणवत्तापूर्ण शोध कार्यों का प्रकाशन हो सके। इस अंक में प्रकाशित शोध आलेख विविध विषयों पर नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं तथा समकालीन समस्याओं के समाधान की दिशा में सार्थक विमर्श को आगे बढ़ाते हैं। हमें विश्वास है कि यह अंक पाठकों के ज्ञानवर्धन के साथ–साथ नए शोध के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगा।

हम सभी लेखकों, समीक्षकों, संपादकीय मंडल, सलाहकारों तथा सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिनके समर्पण और विद्वत्ता से इस अंक का प्रकाशन संभव हो सका। साथ ही हम युवा शोधकर्ताओं से आग्रह करते हैं कि वे अनुसंधान को केवल शैक्षणिक आवश्यकता न मानें, बल्कि राष्ट्र निर्माण और मानव कल्याण के व्यापक उद्देश्य से जोड़कर देखें। सत्य की खोज, नवीन ज्ञान का सृजन और समाज के प्रति उत्तरदायित्व यही एक सफल शोधकर्ता की वास्तविक पहचान है।

आइए, हम सब मिलकर ऐसी शोध संस्कृति का निर्माण करें जो मौलिकता, नैतिकता, वैज्ञानिक दृष्टि और सामाजिक उत्तरदायित्व पर आधारित हो। यही संस्कृति भारत को ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में सशक्त आधार प्रदान करेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बौद्धिक विरासत का निर्माण करेगी।

संपादक :

डॉ. नरेश सिहाग

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 11-16

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

दक्षिण एशिया में चीन की सॉफ्ट पावर कूटनीति और नेपाल में उसका प्रभाव

स्वेता कुमारी, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग
डॉ. लक्ष्मी कुमारी, सहायक प्राध्यापक
वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार।

सारांश (Abstract)

सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी आज अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसके जरिए देश अपनी संस्कृति, शिक्षा और आर्थिक सहयोग से दूसरों को प्रभावित करते हैं। चीन ने अपनी आर्थिक ताकत के साथ इस नीति का उपयोग कर दक्षिण एशिया, विशेषकर नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाया है। नेपाल में चीन ने BRI, आधारभूत संरचना, व्यापार, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उपस्थिति मजबूत की है। इससे नेपाल को विकास, निवेश और संपर्क के नए अवसर मिले हैं। लेकिन इसके साथ आर्थिक निर्भरता, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक प्रभाव जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं।

मुख्य शब्द : सॉफ्ट पावर, चीन, दक्षिण एशिया, नेपाल, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, कूटनीति।

प्रस्तावना (Introduction)

21वीं सदी में अंतरराष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप तेजी से बदल रहा है, जहाँ केवल सैन्य शक्ति और आर्थिक दबाव ही किसी देश की वैश्विक स्थिति तय नहीं करते, बल्कि संस्कृति, शिक्षा, तकनीक और कूटनीतिक आकर्षण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी बदलाव के साथ सॉफ्ट पावर की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, जिसका अर्थ है किसी देश द्वारा बिना बल प्रयोग किए अपनी संस्कृति, मूल्यों और नीतियों के माध्यम से अन्य देशों को प्रभावित करना। Joseph Nye के अनुसार, सॉफ्ट पावर वह क्षमता है जिसके जरिए कोई राष्ट्र आकर्षण और सहयोग के आधार पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव स्थापित करता है। आज कई देश अपनी विदेश नीति में सॉफ्ट पावर को एक प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं।

चीन ने भी अपनी तेज आर्थिक वृद्धि और वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के साथ सॉफ्ट पावर को अपनी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। दक्षिण एशिया, जो भौगोलिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, चीन की इस रणनीति का प्रमुख केंद्र बन गया है। इस क्षेत्र में चीन ने आर्थिक सहयोग, निवेश, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान–प्रदान और आधारभूत संरचना विकास के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ाया है। नेपाल, जो भारत और चीन के बीच स्थित एक स्थलरुद्ध देश है, चीन की इस सॉफ्ट पावर रणनीति का विशेष रूप से महत्वपूर्ण भाग बन चुका है।

हाल के वर्षों में चीन ने नेपाल में सड़क, रेलवे, ऊर्जा परियोजनाओं के साथ–साथ शिक्षा और सांस्कृतिक सहयोग के माध्यम से अपने संबंधों को मजबूत किया है, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

सॉफ्ट पावर की अवधारणा :

सॉफ्ट पावर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वह क्षमता है जिसके माध्यम से कोई देश बिना सैन्य बल या दबाव का उपयोग किए अपनी संस्कृति, मूल्यों, शिक्षा, भाषा और नीतियों के जरिए अन्य देशों को आकर्षित और प्रभावित करता है। यह शक्ति मुख्य रूप से आकर्षण, सहयोग और विश्वास पर आधारित होती है, न कि भय या दबाव पर। हार्ड पावर की तुलना में सॉफ्ट पावर अधिक स्थायी और प्रभावशाली मानी जाती है, क्योंकि यह लोगों की सोच और दृष्टिकोण को धीरे–धीरे बदलती है। आधुनिक वैश्विक राजनीति में देश सॉफ्ट पावर का उपयोग अपनी सकारात्मक छवि बनाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए करते हैं। Joseph Nye के अनुसार, सॉफ्ट पावर वह साधन है जिसके जरिए कोई राष्ट्र अपनी आकर्षक छवि और वैचारिक प्रभाव के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करता है। आज शिक्षा, संस्कृति, मीडिया, तकनीक और कूटनीति सॉफ्ट पावर के प्रमुख माध्यम बन चुके हैं, जिनके जरिए देश वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करते हैं।

दक्षिण एशिया में चीन की सॉफ्ट पावर कूटनीति :

दक्षिण एशिया विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ वैश्विक जनसंख्या का लगभग एक–चौथाई हिस्सा निवास करता है। यह क्षेत्र हिंद महासागर, मध्य एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया के बीच स्थित होने के कारण सामरिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीन ने अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस क्षेत्र में सॉफ्ट पावर कूटनीति को एक प्रमुख रणनीति के रूप में अपनाया है। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक प्रभाव बढ़ाना नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, शैक्षणिक और तकनीकी संबंधों के माध्यम से दीर्घकालिक प्रभाव स्थापित करना है।

1. बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)

चीन की सॉफ्ट पावर और विदेश नीति का सबसे प्रमुख आधार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) है, जिसे 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य एशिया, यूरोप और अफ्रीका को सड़क, रेल और समुद्री मार्गों के माध्यम से जोड़कर व्यापार, संपर्क और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। दक्षिण एशिया के नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देश इस पहल का हिस्सा हैं। नेपाल ने 2017 में BRI समझौता किया, जिसके बाद वहाँ सड़क निर्माण, रेलवे, जलविद्युत और संचार परियोजनाओं में चीनी निवेश में वृद्धि हुई। इन परियोजनाओं ने नेपाल में विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन इसके साथ ही बढ़ते ऋण और आर्थिक निर्भरता को लेकर चिंताएँ भी सामने आई हैं।

2. सांस्कृतिक प्रभाव :

चीन अपनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक कूटनीति पर विशेष ध्यान देता है, जिसमें "कन्फ्यूशियस संस्थानों" के माध्यम से चीनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं का प्रचार शामिल है। नेपाल सहित कई दक्षिण एशियाई देशों में चीनी भाषा शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विस्तार हुआ है, जिससे युवाओं में चीन के प्रति रुचि और सकारात्मक धारणा विकसित हुई है। इसके साथ ही चीन बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक संबंधों

को भी प्रोत्साहित करता है, विशेषकर नेपाल जैसे देशों में जहाँ बौद्ध विरासत का विशेष महत्व है।

3. शिक्षा और छात्रवृत्ति :

शिक्षा चीन की सॉफ्ट पावर रणनीति का एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसके तहत वह दक्षिण एशियाई देशों, विशेषकर नेपाल के छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करता है। हर वर्ष बड़ी संख्या में छात्र चीन में चिकित्सा, इंजीनियरिंग और तकनीकी विषयों की पढ़ाई करते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच शैक्षणिक सहयोग मजबूत हुआ है। शिक्षा और छात्र आदान–प्रदान कार्यक्रमों ने चीन की छवि को एक आधुनिक और विकासशील राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करने में मदद की है तथा युवाओं के बीच उसका प्रभाव बढ़ाया है।

4. मीडिया और तकनीकी प्रभाव :

चीन ने मीडिया और तकनीकी क्षेत्र में भी दक्षिण एशिया में अपनी उपस्थिति मजबूत की है, जहाँ सरकारी मीडिया और समाचार एजेंसियाँ चीन की सकारात्मक छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने में भूमिका निभाती हैं। तकनीकी क्षेत्र में चीनी कंपनियाँ नेपाल सहित कई देशों में दूरसंचार, इंटरनेट, डिजिटल नेटवर्क और ई–कॉमर्स के विकास में निवेश कर रही हैं, जिससे डिजिटल अवसंरचना मजबूत हुई है। हालांकि, इसके साथ ही डेटा सुरक्षा और तकनीकी निर्भरता से जुड़ी चिंताएँ भी सामने आई हैं।

नेपाल पर चीन की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का प्रभाव

1. आर्थिक प्रभाव :

चीन नेपाल का एक प्रमुख निवेशक और विकास साझेदार बन चुका है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने नेपाल में सड़क, पुल, हवाई अड्डे, जलविद्युत परियोजनाएँ और ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश किया है, जिससे देश की आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विशेष रूप से दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने से स्थानीय विकास को गति मिली है और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न हुए हैं। इसके साथ ही चीन नेपाल का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार बनता जा रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों के विस्तार से नेपाल को नए बाजार उपलब्ध हुए हैं, जिससे आयात–निर्यात की संभावनाएँ बढ़ी हैं। चीन के साथ बढ़ते आर्थिक संबंधों ने नेपाल की अर्थव्यवस्था को विविधता प्रदान की है, हालांकि दीर्घकाल में ऋण और निवेश पर निर्भरता एक महत्वपूर्ण चुनौती भी बन सकती है।

2. राजनीतिक प्रभाव :

चीन नेपाल की राजनीति में भी धीरे–धीरे अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। चीन ने नेपाल की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के साथ अपने संबंध मजबूत किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद और सहयोग बढ़ा है। चीन का मुख्य उद्देश्य नेपाल में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना और ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जो उसके क्षेत्रीय हितों के अनुकूल हो। इसके अलावा, चीन नेपाल को अपने "वन चाइना नीति" के समर्थन में बनाए रखने पर भी ध्यान देता है और चाहता है कि नेपाल किसी भी चीन–विरोधी गतिविधि के लिए अपनी भूमि का उपयोग न होने दे। इस प्रकार नेपाल की विदेश नीति पर चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे उसे संतुलित कूटनीति अपनाने की आवश्यकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

3. सांस्कृतिक प्रभाव :

नेपाल में चीन की सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण पहलू सांस्कृतिक प्रभाव है। चीनी भाषा, संस्कृति और

परंपराओं के प्रति नेपाल में विशेषकर युवाओं के बीच रुचि बढ़ रही है। विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में चीनी भाषा पढ़ाई जा रही है और सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से लोगों को चीन की संस्कृति से जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन गतिविधियों और शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क मजबूत हुआ है। चीन बौद्ध धर्म और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों को भी बढ़ावा देता है, जिससे नेपाल के साथ उसके सांस्कृतिक संबंध और अधिक गहरे होते जा रहे हैं।

4. सामरिक प्रभाव :

नेपाल की भौगोलिक स्थिति चीन के लिए अत्यंत रणनीतिक महत्व रखती है, क्योंकि यह देश भारत और चीन के बीच स्थित है और दक्षिण एशिया तक पहुँच का एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है। चीन नेपाल के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी सामरिक और रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। सड़क, रेल और संचार परियोजनाओं के विकास के माध्यम से चीन नेपाल के साथ अपने भौगोलिक संपर्क को बढ़ा रहा है, जिससे उसकी क्षेत्रीय पहुँच और प्रभाव दोनों मजबूत हो रहे हैं। इससे चीन न केवल व्यापारिक लाभ प्राप्त करता है, बल्कि दक्षिण एशिया में अपनी दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिति को भी सुदृढ़ करता है।

चुनौतियाँ और समस्याएँ :

चीन की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ने नेपाल को विकास, आधारभूत संरचना, व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में कई लाभ दिए हैं। इससे दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं और नेपाल में विकास परियोजनाओं को गति मिली है। लेकिन इसके साथ ही कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी सामने आई हैं, जो नेपाल की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति को प्रभावित करती हैं।

1. आर्थिक निर्भरता :

नेपाल में चीन के बड़े निवेश और ऋण ने सड़क, रेलवे, जलविद्युत और संचार जैसे क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया है। इससे रोजगार और आधारभूत संरचना में सुधार हुआ है। लेकिन बढ़ता विदेशी ऋण नेपाल के लिए दीर्घकालिक जोखिम भी पैदा करता है। यदि ऋण का बोझ बढ़ता रहा, तो नेपाल की आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। साथ ही, चीन के साथ व्यापार में असंतुलन (आयात अधिक, निर्यात कम) नेपाल की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालता है। इसलिए आर्थिक आत्मनिर्भरता नेपाल के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

2. भारत-चीन प्रतिस्पर्धा :

नेपाल की भौगोलिक स्थिति उसे भारत और चीन के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है। भारत के साथ नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध गहरे हैं, जबकि हाल के वर्षों में चीन का प्रभाव भी तेजी से बढ़ा है। दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा नेपाल की विदेश नीति को संतुलन में रखने की चुनौती पैदा करती है। यदि नेपाल किसी एक पक्ष की ओर अधिक झुकता है, तो दूसरे के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए नेपाल के लिए संतुलित और सावधानीपूर्ण विदेश नीति आवश्यक है।

3. सांस्कृतिक पहचान का प्रश्न :

चीन की सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों के कारण नेपाल में चीनी भाषा और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ी है। यह सांस्कृतिक संपर्क को मजबूत करता है, लेकिन इसके साथ ही स्थानीय पहचान को लेकर चिंताएँ भी उत्पन्न होती हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि विदेशी सांस्कृतिक प्रभाव की अधिकता नेपाल की पारंपरिक भाषा,

संस्कृति और सामाजिक मूल्यों को प्रभावित कर सकती है। नेपाल की अपनी ऐतिहासिक हिंदू–बौद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसे संरक्षित रखना आवश्यक है।

निष्कर्ष :

चीन की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी ने 21वीं सदी में दक्षिण एशिया की राजनीति और कूटनीति को एक नई दिशा प्रदान की है, और नेपाल इस नीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। चीन ने आर्थिक सहायता, व्यापार, आधारभूत संरचना निर्माण, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान–प्रदान तथा तकनीकी सहयोग के माध्यम से नेपाल में अपनी मजबूत उपस्थिति स्थापित की है। सड़क, रेलवे, ऊर्जा और संचार परियोजनाओं में निवेश ने नेपाल के विकास कार्यों को गति दी है तथा रोजगार और व्यापार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं। इसके साथ ही, छात्रवृत्तियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शैक्षणिक सहयोग के माध्यम से चीन ने नेपाली समाज, विशेषकर युवाओं के बीच अपनी सकारात्मक छवि बनाने का प्रयास किया है। नेपाल जैसे विकासशील और स्थलरुद्ध राष्ट्र के लिए चीन का सहयोग आर्थिक विकास, आधुनिक आधारभूत संरचना और अंतरराष्ट्रीय संपर्क के विस्तार की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है।

हालाँकि, चीन की बढ़ती उपस्थिति नेपाल के लिए कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी प्रस्तुत करती है। अत्यधिक आर्थिक निर्भरता भविष्य में नेपाल की आर्थिक और नीतिगत स्वायत्तता को प्रभावित कर सकती है। इसके अतिरिक्त, नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत और चीन के बीच होने के कारण दोनों देशों की प्रतिस्पर्धा का प्रभाव उसकी विदेश नीति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेपाल के लिए यह आवश्यक है कि वह चीन और भारत दोनों के साथ संतुलित और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखे, ताकि क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन के बीच अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सके। साथ ही, वैश्विक सांस्कृतिक प्रभावों के बीच अपनी सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को सुरक्षित रखना भी नेपाल के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, चीन की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी नेपाल के लिए अवसर और चुनौती दोनों प्रस्तुत करती है, और नेपाल का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वह विकास, कूटनीतिक संतुलन और राष्ट्रीय स्वायत्तता के बीच किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करता है।

References :

1. Joseph Nye, J. S. (2004). Soft power : The means to success in world politics. PublicAffairs.
2. Nye, J. S. (2011). The future of power. PublicAffairs.
3. Shambaugh, D. (2013). China goes global: The partial power. Oxford University Press.
4. Fallon, T. (2015). The new Silk Road: Xi Jinping's grand strategy for Eurasia. American Foreign Policy Interests, 37(3), 140–147.
5. Rolland, N. (2017). China's Belt and Road Initiative: Understanding the dynamics of a global project. National Bureau of Asian Research.
6. Ministry of Foreign Affairs, Nepal. (n.d.). Bilateral relations between Nepal and China. https://mofa.gov.np
7. State Council of the People's Republic of China. (2015). Vision and actions on jointly building

Belt and Road. http://english.www.gov.cn
8. Asian Development Bank. (2021). South Asia economic focus: Global value chains and development. https://www.adb.org
9. Bertelsmann Stiftung. (2020). China's influence in South Asia. https://www.bertelsmann-stiftung.de
10. World Bank. (2022). Nepal development update. https://www.worldbank.org
11. International Crisis Group. (2019). China's growing influence in Nepal. https://www.crisisgroup.org

Mail Id : Kumariswetask1975@gmail.com
मोबाइल : 9162133822

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 17-29

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Customer Perceptions and Expectations of Digitalization in the Banking Industry : An Empirical Study with Chi-Square Analysis

Shashi Kant Upadhyay

Abstract : This paper investigates customer perceptions and expectations of digitalization in the Indian banking industry. Primary survey data were collected from 385 respondents in Vadodara, Gujarat. A quantitative descriptive research design was adopted, and chi-square goodness-of-fit tests were applied to ten key survey dimensions. All ten tests yielded statistically significant results ($p < 0.05$), confirming non-random patterns in customer adoption behaviour. Key findings: 91.4% awareness of digital banking; 73.2% daily or weekly mobile banking usage; 74.3% overall satisfaction; 67.0% security features satisfaction — revealing a distinct security communication gap; and 67.8% preference for digital over traditional banking. Theoretical grounding is provided through Davis's (1989) TAM, Venkatesh et al.'s (2003) UTAUT, Parasuraman et al.'s (1988) SERVQUAL, and Oliver's (1980) Expectation-Confirmation Model. Evidence-based recommendations are offered for banking institutions.

Keywords : Digital Banking; Customer Perceptions; Digitalization; Mobile Banking; TAM; SERVQUAL; Chi-Square Analysis; India.

1. INTRODUCTION :

The banking industry occupies a strategically critical position in the Indian financial sector. Over the last two decades, rapid internet penetration, affordable smartphones, and the Unified Payments Interface (UPI) ecosystem have collectively transformed banking service delivery. The traditional branch-based banking network is progressively being replaced by digital channels offering automated, lower-cost, and geographically unconstrained interactions (Daniel, 1999; Mobarek, 2007). Rao and Budde (2015) found that 67% of Indian bank customers prefer multi-channel banking interaction, reinforcing the imperative for robust digital infrastructure.

The theoretical foundations for digital banking adoption are well-established. Davis (1989), through the Technology Acceptance Model (TAM), identified perceived usefulness and ease of use

as the primary determinants of technology acceptance. Venkatesh et al. (2003) extended this through UTAUT, identifying performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions as adoption drivers. Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) provided SERVQUAL — evaluating service quality through reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles — while Oliver (1980) established through the Expectation-Confirmation Model (ECM) that satisfaction results from the congruence between pre-adoption expectations and post-adoption performance.

Demonetization in November 2016 served as a pivotal inflection point: digital wallets and UPI platforms saw a dramatic surge (Nielsen Report, 2016), with sustained behavioural impact documented by Sobti (2019). Srivastava (2007) established that demographic characteristics influence adoption willingness; Laforet and Li (2005) identified convenience and time-saving as primary motivators; and Jun and Palacios (2016) demonstrated a direct positive relationship between electronic service quality and loyalty. Ahmed and Sur (2023) documented further acceleration during COVID-19.

Despite growing empirical literature, three significant gaps persist. First, studies typically examine individual adoption dimensions in isolation — TAM-based adoption intention, SERVQUAL-based service quality, or single-variable satisfaction surveys — rarely integrating customer awareness, satisfaction, security perceptions, convenience expectations, desired features, and 24/7 availability preferences within a single empirical framework. Second, the geographical focus of existing Indian digital banking research is heavily skewed toward large metropolitan centres such as Mumbai, Delhi, and Bengaluru, leaving significant Tier-2 urban markets such as Vadodara empirically under-represented. Third, the majority of existing studies report descriptive percentages without formally testing whether the observed response distributions are statistically significant or could plausibly arise from random variation. This paper addresses all three gaps: it provides integrated multi-dimensional analysis, focuses on Vadodara as a representative Tier-2 commercial city in Gujarat, and applies chi-square goodness-of-fit tests to ten key dimensions to formally establish statistical significance.

1.1 Research Objectives :

1. To examine customer perceptions, awareness, usage patterns, and satisfaction levels regarding digital banking services.
2. To investigate security, reliability, and convenience perceptions and identify adoption barriers.
3. To identify features and improvements most desired by customers in digital banking platforms.
4. To apply chi-square goodness-of-fit tests to formally assess statistical significance of observed response patterns.

H□: Customer responses across the surveyed digital banking perception and adoption dimensions are equally (randomly) distributed across categories, with no significant pattern.

H□: Customer responses across the surveyed digital banking perception and adoption dimensions are not equally distributed across categories, reflecting a significant non-random pattern.

2. LITERATURE REVIEW

2.1 Theoretical Frameworks

The Technology Acceptance Model (Davis, 1989) postulates that two primary beliefs — perceived usefulness, the degree to which a user believes a system enhances performance, and perceived ease of use, the degree to which the system is free of effort — determine adoption

attitude, behavioural intention, and actual usage. In digital banking, perceived usefulness manifests as the ability to transact quickly and conveniently; perceived ease of use reflects the intuitiveness and navigability of banking interfaces. Alalwan, Dwivedi and Rana (2017), extending UTAUT2 with trust, confirmed performance expectancy as the strongest predictor of mobile banking adoption intention among Jordanian bank customers — a finding directly applicable to the Indian digital banking context.

The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (Venkatesh et al., 2003) synthesises eight prior models and identifies performance expectancy, effort expectancy, social influence, and facilitating conditions as the four core determinants of adoption intention and sustained usage behaviour. In India's digital banking context, the government's JAM trinity — Jan Dhan Yojana, Aadhaar, and Mobile — created the foundational facilitating conditions for mass digital banking adoption. Yang et al. (2012) confirmed that behavioural beliefs and social influences are significant predictors of mobile payment adoption across time, with social influence increasing in importance as digital payment platforms become socially normalised — consistent with this study's 96.4% recommendation intent finding.

SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988) operationalises service quality through reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. Zeithaml, Parasuraman and Malhotra (2002) extended this to electronic service quality (e-SQ), identifying efficiency, fulfilment, reliability, and privacy as the critical digital dimensions. Jun and Palacios (2016) confirmed reliability and security as the most critical e-SQ determinants in mobile banking contexts. The present study's finding that security features satisfaction (67.0%) lags behind overall satisfaction (74.3%) directly identifies a gap in the assurance and privacy dimensions of digital banking e-SQ.

The Expectation-Confirmation Model (Oliver, 1980) establishes that customer satisfaction results from the comparison between pre-adoption expectations and post-adoption evaluations: positive disconfirmation — where perceived performance meets or exceeds expectations — generates satisfaction and drives continued usage. Applied to this study, the 74.3% overall satisfaction rate implies that digital banking services have broadly met respondents' pre-adoption expectations, while the 23.6% neutral security response suggests that security-specific expectations remain partially unconfirmed.

2.2 Empirical Literature and Research Gap

Sardana and Singhania (2018) reviewed digital technology in banking, identifying mobile banking, AI-driven services, and blockchain as primary technological dimensions reshaping the industry, while noting that customer readiness and cybersecurity constitute the principal implementation challenges. Their review confirms that remaining adoption barriers in the Indian context are primarily demand-side rather than supply-side infrastructure. Bhatia and Jain (2020) found that digital banking has produced measurable shifts in customer behaviour, with growing preference for self-service digital channels for routine transactions, and that customer expectations have grown more sophisticated — seeking personalised services, proactive notifications, and integrated financial management tools — directly confirmed in this study's desired features analysis, where 48.1% sought personalised offers and 44.3% desired integration with financial tools.

Mia, Rahman and Uddin (2007), applying Porter's Five Forces to digital banking, found that competitive pressure from fintech and telecom companies is intensifying, with boundaries between banking and non-banking financial services progressively dissolving. The present study's payment

platform data — Google Pay (82.1%), Paytm (63.1%), PhonePe (55.6%) dominating over bank-specific apps — empirically confirms this competitive displacement in the Vadodara context, consistent with the multi-app usage rate of 65.2%. Bastari et al. (2020) demonstrated that intrinsic motivation mediates the relationship between digitalization initiatives and organisational performance in banking. Ahmed and Sur (2023) documented the structural permanence of India's digital banking transition through accelerated MSME adoption during both demonetization and the COVID-19 pandemic.

Three significant gaps in the existing literature justify the present study. First, integrated multi-dimensional studies examining awareness, satisfaction, security, convenience, desired features, and 24/7 availability expectations within a single empirical framework are rare. Second, research concentrates heavily on metropolitan centres, leaving Tier-2 urban markets such as Vadodara empirically under-represented. Third, most perception studies report descriptive percentages without formally testing whether observed distributions reflect statistically significant patterns or random variation. This study addresses all three gaps through its integrated survey design, Vadodara focus, and application of chi-square goodness-of-fit testing across ten key dimensions.

3. RESEARCH METHODOLOGY

This study adopts a quantitative descriptive research design. Primary data were collected through a structured questionnaire administered via Google Forms to respondents in Vadodara, Gujarat. The sample size of 385 was determined using the Cochran (1977) formula: $n = Z^2pq/e^2 = (1.96)^2 \times 0.5 \times 0.5 / (0.05)^2 = 384.16 \approx 385$ at 95% confidence with a 5% margin of error. Purposive convenience sampling targeted bank customers who had actively used digital banking at least once in the preceding twelve months.

The questionnaire covered: digital banking awareness, usage frequency, payment platforms, device preferences, activities performed, UI satisfaction, overall satisfaction, security satisfaction, perceived reliability, perceived security, convenience, time-saving perception, desired features and improvements, willingness to pay for additional features, importance of 24/7 availability, overall banking experience, importance of digital banking, banking preference, and recommendation intent. Secondary data were sourced from peer-reviewed journals and industry reports. Limitations include geographic confinement to Vadodara, convenience sampling restricted to existing digital banking users, and cross-sectional data precluding causal inference.

Descriptive statistics (frequency distributions and percentages) and chi-square goodness-of-fit tests were applied. For each chi-square test, H_0 states that responses are equally distributed across all categories ($\alpha = 0.05$). The chi-square statistic $\chi^2 = \Sigma[(O_i - E_i)^2 / E_i]$, where $df = k - 1$. Critical values: df=1: 3.841; df=2: 5.991; df=3: 7.815; df=4: 9.488.

4. DATA ANALYSIS AND INTERPRETATION

4.1 Demographic Profile

Of 385 respondents, 61.0% (n=235) were male and 39.0% (n=150) female. The 18–24 cohort comprised 53.8% (n=207) and the 25–34 cohort 30.9% (n=119), together accounting for 84.7% of the sample — reflecting the dominance of digitally active younger age groups in mobile banking adoption (Srivastava, 2007).

4.2 Awareness and Usage

91.4% of respondents (n=352) reported awareness of digital banking services, with 8.6% (n=33) unaware. This near-universal awareness reflects the sustained impact of post-demonetization digital literacy campaigns, proliferation of UPI-based payment platforms (Nielsen Report, 2016), and widespread banking advertising (Sobti, 2019). The 8.6% unaware segment represents a market development opportunity addressable through targeted digital literacy programmes and simplified onboarding.

Awareness Level	Count (n=385)	%
Aware of Digital Banking Services	352	91.4%
Not Aware	33	8.6%

Table 1: Awareness of Digital Banking Services

73.2% (n=282) used mobile banking apps daily or weekly, with a further 16.1% (n=62) using them occasionally, and only 10.6% (n=41) rarely. The high daily and weekly usage rate confirms habitual integration of mobile banking into daily financial management, consistent with Laforet and Li's (2005) finding that convenience and time-saving are self-reinforcing adoption drivers — once experienced, these benefits make mobile banking use habitual.

Usage Frequency	Count (n=385)	%
Daily or Weekly	282	73.2%
Occasionally (a few times a month)	62	16.1%
Rarely	41	10.6%

Table 2: Frequency of Mobile Banking App Usage

4.3 Digital Payment Platforms and Devices

Google Pay (82.1%, n=316) was the most widely used platform, followed by Paytm (63.1%, n=243), PhonePe (55.6%, n=214), PayPal (34.9%), and HDFC Mobile Banking App (33.0%). The dominance of UPI-based non-bank platforms over bank-specific apps confirms the competitive displacement theorised by Mia, Rahman and Uddin (2007) through Porter's competitive forces analysis. Furthermore, 65.2% of respondents used multiple banking apps simultaneously — indicating distributed rather than exclusive platform loyalty, intensifying competitive pressure on individual banking institutions. Smartphones were the dominant access device (77.4%, n=298), followed by laptops (43.4%), tablets (31.1%), and desktops (29.2%), confirming India's mobile-first digital banking paradigm driven by the ubiquity of affordable Android devices.

The most frequent digital banking activities were paying bills (67.8%, n=261), checking account balances (67.0%, n=258), and transferring funds (66.0%, n=254). Investment and wealth management activities were conducted by only 42.6% (n=164) of respondents, indicating that the majority are at an intermediate adoption stage — comfortable with routine transactional digital banking but yet to fully utilise higher-order financial management capabilities.

4.4 Satisfaction with User Interface and Overall Digital Banking

72.7% of respondents were satisfied with the user interface of their mobile banking applications (40.5% very satisfied; 32.2% somewhat satisfied), with 20.8% neutral and only 6.5% dissatisfied. The high UI satisfaction rate reflects the significant investment Indian banks have made in

improving app design, navigation, and accessibility. The 20.8% neutral response represents a concrete improvement opportunity.

Overall digital banking satisfaction stood at 74.3% — 34.8% very satisfied and 39.5% satisfied — with 20.8% neutral and only 4.9% dissatisfied. This strong aggregate satisfaction rate affirms Davis's (1989) TAM framework: high perceived usefulness (85.9% time-saving agreement) and ease of use (72.7% UI satisfaction) produce positive adoption attitudes. The ECM (Oliver, 1980) further explains these results: the majority of respondents have experienced services that met or exceeded their pre-adoption expectations, generating positive disconfirmation and satisfaction.

Satisfaction Level	UI (%)	Overall (%)
Very Satisfied	40.5%	34.8%
Satisfied	32.2%	39.5%
Neutral	20.8%	20.8%
Dissatisfied	4.7%	3.9%
Very Dissatisfied	1.8%	1.0%

Table 3: UI and Overall Digital Banking Satisfaction

4.5 Perceived Security and Reliability

Security features satisfaction stood at 67.0% (31.2% very satisfied; 35.8% somewhat satisfied), with a notable 23.6% neutral and 9.3% dissatisfied. The 7.3 percentage-point gap between overall satisfaction (74.3%) and security satisfaction (67.0%) is the study's most analytically significant finding. This gap is concentrated in the neutral response category, signalling not actual security failure but rather inadequate customer awareness of existing security mechanisms — biometric authentication, two-factor verification, end-to-end encryption, and real-time fraud monitoring. This finding is consistent with Zeithaml et al.'s (2002) identification of privacy and security as the most critical and most difficult-to-satisfy dimensions of electronic service quality, and with Jun and Palacios's (2016) confirmation that security is the pivotal loyalty driver in mobile banking.

Perceived security was positive for 72.7% of respondents (30.1% extremely secure; 42.6% somewhat secure), with 23.6% neutral and only 3.7% perceiving insecurity. Perceived reliability was the strongest positive dimension at 76.4% (39.5% extremely reliable; 36.9% somewhat reliable), with only 1.8% perceiving any unreliability — reflecting progressive improvements in Indian banking technology infrastructure, including the RBI's settlement systems and NPCI's UPI infrastructure.

Dimension	Positive (%)	Neutral (%)	Negative (%)
Security Features Satisfaction	67.0%	23.6%	9.3%
Perceived Security Level	72.7%	23.6%	3.7%
Perceived Reliability	76.4%	21.8%	1.8%

Table 4: Security and Reliability Perceptions

4.6 Convcnicncc, Timc-Saving, and 24/7 Availability

73.5% of respondents found mobile banking apps convenient (45.2% very convenient; 28.3% somewhat convenient), with only 7.5% finding them inconvenient. The time-saving endorsement was even stronger: 58.4% strongly agreed and 27.5% somewhat agreed that digital banking saves

time — an aggregate 85.9% endorsement that directly validates Davis's (1989) perceived usefulness construct and explains the high habitual usage rate documented in Section 4.2.

On 24/7 availability, 54.5% (n=210) rated it extremely important and 34.0% (n=131) very important — a combined 88.5%, with no respondent rating it unimportant. This near-universal endorsement confirms that round-the-clock service availability has been irreversibly normalised as a baseline expectation rather than a premium differentiator in the digital banking relationship. Banks that experience extended downtime — even during overnight hours — risk significant reputational and loyalty penalties among a population for whom continuous availability is taken for granted.

Dimension	Strongly Positive (%)	Positive (%)	Neutral (%)	Negative (%)
Convenience of Mobile Banking Apps	45.2%	28.3%	19.0%	7.5%
Time-Saving Perception	58.4%	27.5%	10.4%	3.7%

Table 5: Convenience and Time-Saving Perceptions

Importance of 24/7 Availability	Count (n=385)	%
Extremely Important	210	54.5%
Very Important	131	34.0%
Moderately Important	33	8.6%
Slightly Important	11	2.9%

Table 6: Importance of 24/7 Service Availability

4.7 Desired Features and Improvements

Top desired features: more payment options (57.5%), enhanced security (56.6%), user-friendly interface (50.0%), personalised offers (48.1%), and integration with financial tools (44.3%). Top desired improvements: better mobile app performance (66.0%), improved customer service (64.2%), faster transactions (56.6%), fee transparency (50.0%), and improved website navigation (46.2%). These map directly onto SERVQUAL dimensions — reliability (performance, speed), responsiveness (customer service), assurance (fee transparency), and empathy (personalisation) as documented by Parasuraman et al. (1988) and Bhatia and Jain (2020).

Rank	Desired Feature	%	Desired Improvement	%
1	More Payment Options	57.5%	Better Mobile App Performance	66.0%
2	Enhanced Security Features	56.6%	Improved Customer Service	64.2%
3	User-Friendly Interface	50.0%	Faster Transaction Processing	56.6%
4	Personalised Offers	48.1%	Transparency in Fees	50.0%
5	Integration with Financial Tools	44.3%	Improved Website Navigation	46.2%

Table 7: Desired Features and Improvements

4.8 Overall Banking Experience, Preference and Recommendation

75.3% of respondents were satisfied with their overall banking experience (37.9% very satisfied; 37.4% satisfied), with only 3.9% expressing any dissatisfaction. Regarding the role of digital banking in the overall experience, 87.8% rated it as very important or important (52.7% very important; 35.1% important) — confirming that digital banking has transitioned from a supplementary channel to a core determinant of overall banking satisfaction and perceived banking relationship quality.

67.8% (n=261) expressed preference for digital over traditional banking (21.8% traditional; 10.4% no preference). Recommendation intent was exceptionally high: 59.5% (n=229) would definitely and 36.9% (n=142) would probably recommend digital banking services to others — a combined positive intent of 96.4%. Only 3.6% expressed reluctance to recommend. This near-universal advocacy reflects strong net promoter sentiment and confirms that digital banking adoption in this sample is not merely passive acceptance but active endorsement and social promotion, consistent with Yang et al.'s (2012) finding that social influence intensifies as platforms become socially embedded.

Metric	Category	Count	%
Banking Preference	Digital Banking	261	67.8%
	Traditional Banking	84	21.8%
	No Preference	40	10.4%
Recommendation	Definitely Recommend	229	59.5%
	Probably Recommend	142	36.9%
	Probably Not / Not	14	3.6%

Table 8: Banking Preference and Recommendation Intent

5. CHI-SQUARE ANALYSIS

Chi-square goodness-of-fit tests were applied to ten survey dimensions. H□ for each test: responses are equally distributed across all categories. $\alpha = 0.05$.

No.	Variable	Categories	χ^2	df	Critical (α=0.05)	Result
T1	Usage Frequency	Daily / Occasionally / Rarely	277.719	2	5.991	Significant ($p < 0.05$)
T2	Overall Satisfaction	5-point Likert	234.494	4	9.488	Significant ($p < 0.05$)
T3	Digital vs Traditional Preference	3 categories	213.262	2	5.991	Significant ($p < 0.05$)
T4	Security Perception	5-point scale	248.286	4	9.488	Significant ($p < 0.05$)

T5	Time-Saving Perception	5-point scale	440.857	4	9.488	Significant ($p < 0.05$)
T6	Importance of 24/7 Availability	4-point scale	264.049	3	7.815	Significant ($p < 0.05$)
T7	Awareness of Digital Banking	Aware / Not Aware	264.314	1	3.841	Significant ($p < 0.05$)
T8	Willingness to Recommend	4-point scale	370.688	3	7.815	Significant ($p < 0.05$)
T9	Security Features Satisfaction	5-point Likert	168.442	4	9.488	Significant ($p < 0.05$)
T10	Importance in Overall Expcricncc	5-point scale	404.545	4	9.488	Significant ($p < 0.05$)

Table 9: Chi-Square Goodness-of-Fit Results (N=385, α=0.05)

All ten chi-square values substantially exceed their critical values, leading to rejection of H□ in every case. The strongest endorsements appear in time-saving (T5: χ^2=440.857), importance of digital banking in experience (T10: χ^2=404.545), and recommendation intent (T8: χ^2=370.688). Security features satisfaction produced the lowest value (T9: χ^2=168.442) — still highly significant, but reflecting the most distributed response pattern with 23.6% neutral, quantitatively confirming security as the most contested perception dimension. H□ is therefore rejected: customer responses across all ten dimensions reflect statistically significant, non-random patterns rather than equal distribution across categories. H□ is accepted.

6. DISCUSSION

The 91.4% awareness and 73.2% habitual usage rates confirm that digital banking has achieved mainstream adoption status in urban Vadodara, moving decisively beyond early-adopter stages. In TAM terms (Davis, 1989), perceived usefulness is strongly internalised — validated by 85.9% time-saving agreement and 73.5% convenience endorsement. UTAUT's facilitating conditions (Venkatesh et al., 2003) are evidenced by widespread smartphone access (77.4%), government-built UPI infrastructure, and affordable mobile data — collectively lowering effort expectancy barriers to adoption. The 96.4% recommendation intent signals strong social influence normalisation, consistent with Yang et al.'s (2012) finding that social influences intensify as digital payment platforms become socially embedded. The data reveal a population for whom digital banking is not an optional convenience but an embedded financial habit.

The 7.3 percentage-point gap between overall satisfaction (74.3%) and security features satisfaction (67.0%) is the study's most strategically significant finding — concentrated in the 23.6% neutral security response rather than in the dissatisfied category. This directly corroborates

Zeithaml et al.'s (2002) identification of privacy and security as the most critical and most difficult-to-satisfy dimensions of electronic service quality, and Jun and Palacios's (2016) confirmation of security as the pivotal mobile banking loyalty driver. Critically, the gap signals inadequate communication of existing security mechanisms — not actual security failure — as the primary actionable priority. Banks must treat security communication as a front-end customer engagement priority rather than a back-end technical concern. The perceived reliability rate of 76.4% — the strongest positive dimension across all security and reliability measures — indicates that customers have confidence in the operational continuity of digital platforms, reflecting improvements in India's RBI settlement systems and NPCI UPI infrastructure.

The dominance of non-bank UPI platforms — Google Pay (82.1%), Paytm (63.1%), PhonePe (55.6%) — over bank-specific applications confirms the competitive displacement theorised by Mia, Rahman and Uddin (2007) through Porter's Five Forces. The 65.2% multi-app usage rate establishes that customer loyalty is distributed rather than exclusive, intensifying competitive pressure on individual banking institutions. Sardana and Singhania (2018) identified this boundary erosion between banking and fintech as a defining structural feature of modern digital banking. Banks' competitive response must centre on the three dimensions most prominently demanded in this study: performance (app speed and reliability), personalisation (tailored offers and recommendations), and security assurance (transparent, proactively communicated protection).

The desired improvements data map precisely onto SERVQUAL dimensions (Parasuraman et al., 1988): mobile app performance and transaction speed onto the reliability dimension; customer service support onto responsiveness; fee transparency onto assurance; personalised recommendations onto empathy. This mapping confirms that SERVQUAL retains strong explanatory validity in the digital banking context, consistent with Zeithaml et al.'s (2002) e-SQ extensions. Bhatia and Jain (2020) similarly found that customer expectations have become increasingly sophisticated — seeking personalisation and transparency beyond mere transactional functionality — a finding directly corroborated by the desired features profile in the present study. The 88.5% endorsement of 24/7 availability as extremely or very important confirms that continuous service availability has been irreversibly normalised as a non-negotiable baseline standard of digital banking, consistent with the 'always-on' expectations of the contemporary digital economy.

7. RECOMMENDATIONS

1. Proactively communicate security measures: The 23.6% neutral security response indicates that a significant proportion of customers are not adequately informed about existing security protections. Banks should deploy visible in-app security dashboards, biometric authentication promotion, post-transaction security confirmations, and proactive fraud alert systems to convert uncertain users into confident digital banking advocates.
2. Prioritise mobile app performance as a tier-one business investment: Cited by 66.0% as the single most desired improvement, mobile app performance requires sustained investment in app architecture optimisation, load testing, and user experience research to ensure fast, stable,

and reliable performance across all device types and network conditions.

3. Redesign customer service for digital delivery: 64.2% of respondents demand improved customer service support. AI-powered chatbots, voice assistants, and hybrid human-AI support models providing first-contact resolution within seconds — including outside business hours — are essential competitive requirements, not optional enhancements.
4. Guarantee 24/7 service availability: With 88.5% of respondents rating round-the-clock availability as extremely or very important, and no respondent rating it unimportant, high-availability distributed architectures, redundant failover systems, and zero-downtime deployment practices are non-negotiable operational standards for all critical digital banking systems.
5. Implement proactive fee transparency: 50.0% of respondents desired greater transparency in fees and charges. Itemised, clearly presented fee disclosures at the point of transaction within digital interfaces — before completion — should be standard practice across all platforms, eliminating post-transaction surprises that erode trust.
6. Accelerate personalisation and expand payment options: 48.1% of respondents desired personalised offers and recommendations, while 57.5% desired more payment options. Machine learning-driven personalisation engines based on transaction data analytics, combined with deeper integration with emerging payment rails, cross-border systems, and financial management tools, are the priority investment areas.
7. Close the digital awareness gap: The 8.6% unaware of digital banking services represents a market development opportunity. Targeted digital literacy programmes, simplified onboarding journeys, and community-based outreach — particularly in underserved urban segments — can systematically close this gap and expand the addressable digital banking market.

8. CONCLUSION

This study provides empirically grounded and statistically rigorous evidence confirming that digitalization has fundamentally reshaped the customer-bank relationship in urban India. Ten chi-square goodness-of-fit tests — all significant at $p < 0.05$, with chi-square values ranging from χ^2=168.442 (security features satisfaction) to χ^2=440.857 (time-saving perception) — establish that customer perceptions, satisfaction levels, and adoption preferences reflect strong, non-random directional patterns. The null hypothesis is rejected: customer responses across the surveyed dimensions are not equally distributed across categories but instead reflect statistically significant, non-random patterns. The alternate hypothesis is accepted.

The data reveal an urban Indian banking population for whom digital banking has achieved unambiguous mainstream status: 91.4% awareness, 73.2% habitual daily or weekly usage, 74.3% overall satisfaction, 87.8% rating digital banking as very important or important in their overall banking experience, and 96.4% positive recommendation intent. The four theoretical frameworks applied — TAM (Davis, 1989), UTAUT (Venkatesh et al., 2003), SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988), and ECM (Oliver, 1980) — all find strong empirical support in the data, confirming their continued validity and applicability in the contemporary Indian digital banking context.

The study also identifies specific, actionable service quality gaps: a 7.3 percentage-point security communication deficit (67.0% security satisfaction vs 74.3% overall satisfaction), concentrated demand for better mobile app performance (66.0%), improved customer service responsiveness (64.2%), and greater pricing transparency (50.0%). These gaps reflect rising customer expectations — the natural and inevitable consequence of successful digital banking adoption — that banking institutions must continuously address to sustain customer satisfaction, deepen loyalty, and remain competitive against fintech and UPI platform providers. The study's methodological contribution — the application of formal chi-square goodness-of-fit testing to digital banking perception data — provides a replicable and statistically rigorous model for future customer perception research in the digital financial services domain.

Future research could productively extend this work through longitudinal studies tracking how perceptions and satisfaction levels evolve as digital banking platforms improve, cross-city comparisons to assess whether Vadodara's patterns generalise across Indian Tier-2 urban markets, and the application of structural equation modelling to explore the causal relationships among the perception, satisfaction, security, and adoption dimensions examined in this study. Such extensions would further advance the evidence base for digitalization strategy in the Indian banking industry.

References :

[1] Ahmed, S. and Sur, S. (2023). Change in the uses pattern of digital banking services by Indian rural MSMEs during demonetization and Covid-19 pandemic-related restrictions. Vilakshan – XIMB Journal of Management, 20(1), pp. 166–192.

[2] Alalwan, A. A., Dwivedi, Y. K. and Rana, N. P. (2017). Factors influencing adoption of mobile banking by Jordanian bank customers: Extending UTAUT2 with trust. International Journal of Information Management, 37(3), pp. 99–110.

[3] Bastari, A., Eliyana, A., Syabarrudin, A., Arief, Z. and Emur, A. P. (2020). Digitalization in banking sector: The role of intrinsic motivation. Heliyon, 6(12), e05801.

[4] Bhatia, D. and Jain, N. (2020). Digitalization in banking industry and its impact on customers' behaviour. Journal of Emerging Technologies and Innovative Research, 7(8), pp. 163–168.

[5] Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. 3rd edn. New York: John Wiley and Sons.

[6] Daniel, E. (1999). Provision of electronic banking in the UK and Republic of Ireland. International Journal of Bank Marketing, 17(2), pp. 72–82.

[7] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), pp. 319–340.

[8] Jun, M. and Palacios, S. (2016). Examining the key dimensions of mobile banking service quality. International Journal of Bank Marketing, 34(3), pp. 307–326.

[9] Laforet, S. and Li, X. (2005). Consumers' attitudes towards online and mobile banking in China. International Journal of Bank Marketing, 23(5), pp. 362–380.

[10] Mia, M. A. H., Rahman, M. A. and Uddin, M. M. (2007). E-banking: Evolution, status and prospect. Cost and Management, 35(1), pp. 36–48.

[11] Mobarek, A. (2007). E-banking practices and customer satisfaction. 20th Australasian Finance and Banking Conference. Available at: https://ssrn.com/abstract=1012117

[12] Nielsen Report Part II (2016). Post-demonetization digital wallets surge in India. Nielsen Holdings.

[13] Oliver, R. L. (1980). A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions. Journal of Marketing Research, 17(4), pp. 460–469.

[14] Parasuraman, A., Zeithaml, V. A. and Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1), pp. 12–40.

[15] Rao, V. and Budde, S. (2015). Banking technology: Innovations in Indian banking sector. International Journal of Information Research and Review, 2(7), pp. 826–831.

[16] Sardana, V. and Singhania, S. (2018). Digital technology in the realm of banking: A review of literature. International Journal of Research in Finance and Management, 1(2), pp. 28–32.

[17] Sobti, N. (2019). Impact of demonetization on the digital payments industry and consumer adoption of mobile wallets in India. Journal of Advances in Management Research, 16(4), pp. 472–497.

[18] Srivastava, R. K. (2007). Customer's perception on usage of internet banking. Innovative Marketing, 3(4), pp. 67–73.

[19] Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B. and Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), pp. 425–478.

[20] Yang, S., Lu, Y., Gupta, S., Cao, Y. and Zhang, R. (2012). Mobile payment services adoption across time. Computers in Human Behavior, 28(1), pp. 129–142.

[21] Zeithaml, V. A., Parasuraman, A. and Malhotra, A. (2002). Service quality delivery through websites. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(4), pp. 362–375.

Author Note : *Shashi Kant Upadhyay is an independent researcher with a postgraduate qualification in Commerce. Research interests include digital banking, consumer behaviour, and financial services marketing. Correspondence: sku9838@gmail.com.*

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 30-33

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

'छाया मत छूना मन' में स्त्री जीवन की विडंबनाएँ

निकिता पंत

शोधार्थी, हिन्दी विभाग,

लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़ (हल्द्वानी)

कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल।

शोध सार :

'छाया मत छूना मन' उपन्यास में उपन्यासकार हिमांशु जोशी द्वारा भारतीय समाज के मध्यवर्गीय परिवार की कठिनाइयों, आर्थिक विपन्नता तथा स्त्रियों के संघर्षों का अत्यन्त संवेदनशील चित्रण किया गया है। उपन्यास की कथावस्तु नायिका वसुधा के ईद–गिर्द ही घूमती है। वसुधा के द्वारा हिमांशु जोशी ने मध्यवर्गीय स्त्रियों के त्याग, संघर्ष तथा निराशा भरे जीवन को उजागर किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में मेरे द्वारा स्त्री जीवन की विडंबनाओं का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है, कि किस प्रकार आर्थिक विपन्नता, समाज में फैली रुढ़ियाँ तथा पितृ सत्तात्मक सोच स्त्री को जंजीर की तरह जकड़े रहती है। 'छाया मत छूना मन' एक नायिका प्रधान भावनात्मक उपन्यास है। यह उपन्यास उन सभी स्त्रियों की गाथा है जो परिवार की खुशियों के खातिर अपनी सारी खुशियों को झोंक देती है।

मुख्य शब्द : छाया मत छूना मन, मध्यवर्ग, स्त्री संघर्ष, आर्थिक विडंबना, नारी जीवन।

'छाया मत छूना मन' उपन्यास में मध्यवर्गीय स्त्रियों के जीवन को के संघर्षमय जीवन का चित्रण हुआ है। उपन्यास में वसुधा, कंचन तथा परवीन (वसुधा की माँ) के माध्यम से स्त्रियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेखक ने पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसीलिए यह उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास बन गया है। उपन्यास की केन्द्रिय पात्र वसुधा है जो परिवार की जिम्मेदारियों के कारण देवेन्द्र के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा देती है :–

'मैं विवाह कर लूं तो कंची की पढ़ाई का क्या होगा? पिता बीमार हैं। पैसे के अभाव में उनका इलाज नहीं हो पा रहा मीचे छोटा है। उसके भविष्य का क्या बनेगा? मां अपनी आदतों से बाज नहीं आतीं। इस उम्र में भी उन्हें घूमने–फिरने का शौक है! ऐसी स्थिति में तुम्हीं बताओ.... इन सबका क्या होगा?'[1]

उपन्यासकार ने इस उपन्यास के माध्यम से समाज की संकीर्ण मानसिकता को भी दर्शाया है। वसुधा के माध्यम से उन सभी स्त्रियों को केन्द्र में रखा गया है जो यह सोचती है कि हमारे आस–पास के लोग क्या कहेंगे और दूसरों की नजर में उनकी क्या छवि रह जाएगी। कंचन का गैंग रेप होने पर वसुधा उसे समझाती हुए कहती है :–

'और अब सब नए सिरे से सोच। यह बात बाहर किसी से मत कहना। कोई पूछे तो बोल देना कि देहरादून अपनी सहेली के घर चली गई थी, चाईजी से रूठकर। वहीं बीमार हो गई थी। अब कुछ ठीक होने पर सहेली ने समझा–बुझाकर वापस भेजा है।'[2]

वसुधा बाहर से जितनी शांत है, भीतर से वह उतनी ही अशांत दिखाई देती है। वह अपनी मनःस्थिति को किसी के सामने व्यक्त नहीं करती क्योंकि उसे लगता है कि उसकी पीड़ा उसकी जिम्मेदारियों के आगे बहुत छोटी है। ट्रांसफर होकर जब वसुधा बंबई गयी तो और उदास रहने लगी :–

'बंबई की जिंदगी रास न आयी उसे, जब से गई, बीमार रहने लगी। न खाने को मन करता, न सोने को। एक विचित्र–सी बैचेनी हर क्षण छाए रहती।

हर समय घर की याद आती। कंचन के लापता होने का आघात वह अब तक सह न पाई थी। जब भी बाहर हवा से दरवाजा खटकता उसे लगता–कंचो तो नहीं आई .... !'[3]

वसुधा कठिन से कठिन परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक सामना करती है। फिर भले वह कंचन के विवाह के समय आर्थिक संकट हो या पिता के दवाओं का खर्च हो। किसी भी परिस्थिति में वह अपने आत्मसम्मान, गरीमा से समझौता नहीं करती है। शर्मा की कुदृष्टि से बचने के लिए वसुधा ने नौकरी छोड़ दी :–

'मन महीं लगा, उस नरक में। मैंने बतलाया न कि वह अच्छा आदमी नहीं था। अभी सर्विस में लगे तीन ही दिन बीते थे कि हजरत एक दिन मेरे पीछे घर आए और डेढ़–दो सौ रुपए राशन–पानी में खर्च कर गए। मां खुश थीं। सबसे उसकी तारीफों के पुल बांधे जा रही थीं। तनख्वाह घर आकर 'एडवांस' में दे गया। अब तो कहता है सारी 'एकेडमी' बस्सो पर छोड़घ्कर कोई साइड–बिजनेस करूंगा....।

पांचवें दिन मैंने वहां जाने से इनकार कर दिया तो मां आगबबूला हो उठीं। मुझे लात–घूसों से मारने लगीं। कंचन ने भी उसी का साथ दिया।'[4]

उपन्यासकार ने उपन्यास में मध्यवर्गीय परिवार की सीमित आय, समय के साथ बढ़ती जिम्मेदारियों तथा परिवार के भविष्य को लेकर स्त्री की चिन्ता को व्यक्त किया है। मध्यवर्गीय परिवार में स्त्रियाँ परिवार के अन्य सदस्यों की इच्छाओं को पूरा करने में अपना सम्पूर्ण जीवन व्यतीत कर देती है तथा अपनी इच्छाओं को दबाती जाती है। यही स्थिति वसुधा के जीवन में भी दिखायी देती है :–

'दुनिया से ही एक तरह वितृष्णा हो रही थी। क्या–क्या नहीं करना पड़ता जीने के लिए! सारी व्यवस्था से ही उसे घृणा हो रही थी, लेकिन क्या करती! कंचन का भविष्य हमेशा आड़े आ जाता।'[5]

उपन्यासकार ने उपन्यास के माध्यम से मनोवैज्ञानिक संघर्ष भी प्रस्तुत किया है। वसुधा कभी भी अपनी परेशानी किसी अन्य पर नहीं डालती बल्कि मौन रहकर स्वयं उनसे लड़ने को तत्पर रहती है। वसुधा के माध्यम से उपन्यासकार ने स्पष्ट किया है कि स्त्री का संघर्ष केवल अपने आस–पास मौजूद वस्तुओं से ही नहीं होता अन्यथा अपने भीतर चलने वाली भावनाओं, आशंकाओं से भी होता है :–

"जब भी उसे बहुत परेशानी अनुभव होती है, जब भी वह एक गहरी निराशा में डूबने लगती है, तभी उसकी आंखों के आगे एक आकार उभर आता है...। और तब ही कभी–कभी उस बहाव में वह पत्र लिखने लगती है। जो कुछ जी में होता है, सब उड़ेल देती है...। लेकिन पत्र भेजती नहीं, दिनों तक अपने पास संजोए रखती है, फिर चुपके – से फाड़ देती है।'[6]

भारतीय समाज में स्त्रियों को त्याग की मूर्ति कहा जाता है। 'छाया मत छूना मन' उपन्यास भी वसुधा के त्याग की कथा है, जिसके अन्तर्गत वसुधा ने अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने सुख–चैन की आहुति दे दी है। यह उपन्यास पाठक वर्ग को सोचने पर विवश करता है कि क्या त्याग करना केवल स्त्री का ही दायित्व है? क्या उसकी खुद की खुशियों का कोई मोल नहीं? वसुधा कंचन की खुशियों में अपनी खुशियाँ खोजने लगी है। कंचन के विवाह के समय वसुधा की मानसिक स्थिति इस प्रकार थी :–

'वसुधा सारी चीजें आप ही खरीद खरीदकर ला रही थी। जो साड़ी उसे पसंद आती, खरीद लेती। यदि उसका अपना विवाह होता तो वह ठीक ऐसी ही, नहीं–नहीं, यही साड़ी खरीदती। जेवर उसे कुछ विशेष ढंग से पसंद थे। कंचन से पूछे बिना वह उन्हें ले आई। शायद अपने विवाह पर भी वह ऐसे ही खरीदती!'[7]

हिमांशु जोशी हिन्दी साहित्य में उन उपन्यासकारों के अन्तर्गत आते है जिन्होंने अपने उपन्यास में स्त्रियों को केवल बेबस और बेसहारा घोषित नहीं किया, बल्कि आत्मगौरवी, संघर्षशील, संवेदनशील रूप में भी व्यक्त किया है। 'छाया मत छूना मन' उपन्यास में वसुधा की पीड़ा कभी–भी उसे कमजोर नहीं बनाती है, जबकि कठिन परिस्थितियों में वे धैर्य, विवेक तथा नैतिक शक्ति के साथ उनका सामना करती है। प्राचीन हिन्दू ग्रंथों में स्त्रियों को देवताओं के स्थान पर रखा गया है, उनमें नारी के संदर्भ में स्पष्ट लिखा है– 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता' अर्थात् जहाँ स्त्रियों का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। उपन्यास में वसुधा कभी मानसिक रूप से पीड़ित है तो कभी शारीरिक रूप से पीड़ा की शिकार होती है। अंत में वसुधा कैंसर से ग्रसित हो जाती है फिर भी वह अपनी शारीरिक जीवन को छोड़घ्कर परिवार के लिए कई कष्टों का सामना करती है। इस सन्दर्भ में देवेन्द्र वसुधा से कहता है :–

'कंचन की जिंदगी तुम नहीं सुधार सकी। तुम्हारी मां को पैसे के अलावा किसी से कोई सरोकार नहीं। पिता कभी भी कूच कर सकते हैं। अंत में तुम्हारे हाथ क्या आएगा, बोलो।'[8]

उपन्यास में उपन्यासकार ने वसुधा के कठिनाइयों से भरे जीवन के बीच उसके मानवीय मूल्यों का सुन्दर प्रस्तुतीकरण किया है। वसुधा अपनी पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने व्यक्तिगत जीवन के सभी सपनों को समाप्त कर देती है। वसुधा अपने जीवन के सभी कष्टों को समेटकर जीवन यापन करती हैं :–

"यह उपन्यास एक ऐसी हृदय–द्रावक कहानी है, कहानी होते हुए भी जो कहानी नहीं, सच लगती है ऐसी त्याग, ऐसी तपश्चर्ण भी कहीं देखने को मिलती है आज इस उपन्यास में वसुधा के रूप में, जिस वसुधा की सृष्टि हुई है, वह अनुपम है, विस्थापित परिवार के पुनः विस्थापित होने की यह करुणगाथा बहुत कुछ सोचने के लिए विवश करती है। संघर्ष, शोषण, स्नेह, वासना, त्याग, तिरस्कार के विविध रंगों से रॅगी यह कुहासे की तस्वीर आज का यथार्थ भी है कहीं।'[9]

हिमांशु जोशी ने उपन्यास में वसुधा के माध्यम से नारी का सबला रूप प्रस्तुत किया है। वसुधा के मन में दैनिक जीवन के संघर्षों के कारण एक बार भी अपने परिवार के लिए प्रतिशोध की भावना नहीं आयी। इसके विपरीत वसुधा ने हर परिस्थिति का धैर्यपूर्वक सामना किया। उसके सम्पूर्ण जीवनकाल में धैर्य कभी भी उसकी कमजोरी नहीं बना, बल्कि इस विशेषता ने उसके व्यक्तित्व को और अधिक निखारा है। वसुधा ने अपने मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को कभी समाप्त नहीं होने दिया। मानवीय मूल्यों तथा संवेदनाओं की झलक उपन्यास के नायक पात्र देवेन में भी देखने को मिलती है। जो वसुधा के कैन्सर होने पर भी उसका साथ नहीं छोड़ता है,

उसकी सेवा करता रहता है। इस संदर्भ में वसुधा देवेन्द्र से कहती हैं :–

'तुम यहां क्यों लाए मुझे...! जहां इतने लंबे समय तक न मिले, वहां कुछ दिन और रुक जाते। मेरे मरने के बाद आते तो तुम्हें इतना कष्ट न होता। अपना सारा कारोबार, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे कब तक चलते रहोगे? मुझे तो अधिक जीना नहीं, फिर मुझ पर इतना खर्च क्यों कर रहे हो देवेन, अब मुझे घर ले चलो, घर ...!'[10]

'छाया मत छूना मन' उपन्यास की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। वर्तमान समय में स्त्रियाँ पढ़–लिखकर हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है लेकिन कहीं–न–कहीं उन्हें आज भी सामाजिक उपेक्षाएँ, मानसिक दबाव, कार्य–जीवन सन्तुलन जैसी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। यह उपन्यास केवल भारतीय समाज का दर्पण नहीं बल्कि समाज में स्त्रियों की यात्रा का एक दस्तावेज है। उपन्यास के माध्यम से उपन्यासकार स्पष्ट करते हैं कि आर्थिक विपन्नता, मानसिक दबाव, सामाजिक उपेक्षाएँ और आत्मसम्मान स्त्री जीवन की विडम्बनाओं को प्रस्तुत करते हैं। हिमांशु जोशी इन समस्याओं का चित्रण पाठकों में करुणा उत्पन्न करने के लिए नहीं करते, बल्कि यह सोचने पर प्रेरित करते हैं कि स्त्रियों को समान अवसर, अधिकार, सम्मान तथा स्वतंत्रता देना एक सभ्य समाज का उत्तर–दायित्व हैं।

संदर्भ :

1. महेश दर्पण, संपूर्ण उपन्यास हिमांशु जोशी (भाग–1), किताबघर, दरियागंज, नई दिल्ली, 2019, पृ. 285
2 वही, पृ. 313–314
3. वही, पृ. 308
4. वही, पृ. 286
5. वही, पृ. 316
6. वही, पृ. 310
7. वही, पृ. 316
8. वही, पृ. 300
9. https://prayog.pustak.org
10. वही, पृ. 351

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 34-40

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य में नारी चेतना और मानवीय संवेदना

डॉ० शीला छीपा
सह–आचार्या, हिन्दी
विद्या प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज, पालड़ी, भीलवाड़ा।

सारांश :

महादेवी वर्मा का गद्य विचार, अनुभव और करुणा की विशिष्ट भूमि तैयार करता है। उनके निबंधों, संस्मरणों और रेखाचित्रों में स्त्री की पराधीनता, आर्थिक निर्भरता, श्रम की अवमानना, बाल–विवाह, विधवा जीवन और पारिवारिक रूढ़ियों का सूक्ष्म विवेचन है। श्रृंखला की कड़ियाँ स्वतंत्र व्यक्तित्व, नागरिक अधिकार और अर्थ–स्वातंर्त्य की वैचारिक स्थापना करती है; स्मृति की रेखाएँ तथा अतीत के चलचित्र उपेक्षित स्त्रियों, बच्चों, श्रमिकों और निर्धन जनों को आत्मीयता से सामने लाते हैं। भक्तिन, बिन्दा, सबिया, घीसा और अलोपी श्रम, स्वाभिमान, प्रतिरोध और नैतिक शक्ति के प्रतिनिधि बनते हैं। महादेवी की नारी चेतना मानवीय संवेदना से जुड़कर व्यापक सामाजिक चेतना ग्रहण करती है। उनके गद्य में करुणा अन्याय को पहचानने और मनुष्य की अस्मिता की रक्षा करने वाली सक्रिय शक्ति है।

मुख्य शब्द : महादेवी वर्मा, नारी चेतना, मानवीय संवेदना, स्त्री अस्मिता, गद्य साहित्य, रेखाचित्र, संस्मरण।

प्रस्तावना :

महादेवी वर्मा को प्रायः छायावाद की प्रमुख कवयित्री के रूप में स्मरण किया जाता है, पर उनका गद्य उतना ही व्यापक, तेजस्वी और सामाजिक अर्थों से भरा हुआ है। कविता में व्यक्त वेदना उनके गद्य में जीवन के ठोस यथार्थ से मिलती है। यहाँ घर के भीतर दबा स्त्री जीवन है, गाँव की श्रमशील स्त्री है, उपेक्षित बालिका है, निर्धन विद्यार्थी है, दृष्टिहीन विक्रेता है और सामाजिक व्यवस्था के किनारे धकेला गया साधारण मनुष्य है। इन पात्रों के माध्यम से लेखिका उस समाज की संरचना को पढ़ती हैं जो मनुष्य का मूल्य उसके लिंग, धन, जातिगत स्थान, उपयोगिता और शक्ति से निर्धारित करता है।

उनके निबंध पूछते हैं– स्त्री को नागरिक का पूरा स्थान क्यों नहीं मिला, उसका श्रम अदृश्य क्यों रहा और उसके जीवन का निर्णय परिवार क्यों करता है। रेखाचित्रों में यही प्रश्न जीवित कथाएँ बन जाते हैं। महादेवी पात्र की बोली, दुःख, हठ, हास्य और आत्मसम्मान को साथ लेकर चलती हैं। इसी कारण उनका गद्य विचारशील होकर भी शुष्क नहीं बनता।

श्रृंखला की कड़ियाँ के आरंभ में भारतीय स्त्री की विरोधाभासी दशा का तीखा चित्र मिलता है– वह कभी देव–मंदिर की अधिष्ठात्री देवी बना दी जाती है और कभी अपने ही घर के मलिन कोने की बंदिनी रहती है।[1], इस एक कथन में महादेवी उस सांस्कृतिक विडंबना को पकड़ लेती हैं जिसमें स्त्री की पूजा उसके अधिकार की गारंटी नहीं बनती। आदर्शीकरण कई बार वास्तविक स्वतंत्रता का विकल्प बन जाता है। सम्मान के शब्द ऊँचे होते हैं, जीवन की स्थिति संकुचित बनी रहती है।

नारी चेतना का वैचारिक आधार :

महादेवी की नारी चेतना का पहला आधार स्त्री को स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में स्वीकार करना है। उनके लिए समानता का अर्थ स्त्री को पुरुष की प्रतिकृति बना देना नहीं है। वे स्त्री और पुरुष की मानवीय समानता को स्वीकार करते हुए उनकी अनुभवगत भिन्नताओं का मूल्य भी समझती हैं। इसीलिए वे लिखती है :

"पुरुष समाज का न्याय है, स्त्री दयाय पुरुष प्रतिशोधमय क्रोध है, स्त्री क्षमाय पुरुष शुष्क कर्तव्य है, स्त्री सरस सहानुभूति।"[2]

इस कथन को जैविक नियति के कठोर सूत्र की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। इसका आशय उन मानवीय गुणों की प्रतिष्ठा से है जिन्हें शक्ति–प्रधान समाज अक्सर कमतर मानता है। दया, क्षमा और सहानुभूति महादेवी के यहाँ कमजोरी नहीं, सभ्यता को मानवीय बनाए रखने वाली शक्तियाँ हैं।

स्त्री की मुक्ति उनके लिए घर से पलायन या पुरुष से प्रतिस्पर्धा भर नहीं है। उसका वास्तविक अर्थ है– विकास के अवसर, निर्णय की स्वतंत्रता, शिक्षा, सामाजिक भागीदारी और अपने जीवन के प्रति उत्तरदायित्व। वे स्त्री को कुटुंब, समाज, नगर और राष्ट्र की विशिष्ट सदस्य मानती हैं। उसके कार्यों का प्रभाव निजी सीमा से बाहर जाता है; अतः उसे अपने उत्तरदायित्व के अनुरूप मानसिक और शारीरिक विकास के लिए "विस्तृत स्वाधीनता" चाहिए।[3], यहाँ अधिकार और दायित्व एक साथ रखे गए हैं। स्त्री को स्वतंत्रता इसलिए भी चाहिए कि वह समाज की सक्रिय निर्माता है, सजावटी उपस्थिति नहीं।

महादेवी उस सुधारवादी दृष्टि से भी संतुष्ट नहीं होतीं जो स्त्री के लिए कुछ सुविधाएँ तो स्वीकार करती है, पर व्यवस्था की बुनियादी असमानता को छूना नहीं चाहती। शिक्षा का उद्देश्य केवल बेहतर गृहिणी बनाना नहीं हो सकता। शिक्षित स्त्री अपने अधिकार, योग्यता और सामाजिक भूमिका को पहचानती है; तब पुरानी संरचना से उसका संघर्ष स्वाभाविक है। महादेवी इस संघर्ष को अवज्ञा या परिवार–विरोध नहीं मानतीं। वह जड़ व्यवस्था और विकसित हो रहे व्यक्तित्व के बीच का टकराव है।

आर्थिक स्वतंत्रता और स्त्री की गरिमा :

स्त्री की पराधीनता का सबसे ठोस आधार आर्थिक निर्भरता है। 'स्त्री के अर्थ–स्वातंत्र्य का प्रश्न' में महादेवी लिखती हैं–

"अर्थ सदा से शक्ति का अन्ध–अनुगामी रहा है।"[4]

जिसके पास शक्ति रही, उसने साधनों के वितरण पर अधिकार रखा। परिवार में स्त्री का श्रम निरंतर चलता है, फिर भी आय, संपत्ति और निर्णय पर उसका अधिकार सीमित रहता है। पत्नी, पुत्री और माता के रूप में उसकी पहचान तो है, आर्थिक व्यक्ति के रूप में उसका नाम धुँधला पड़ जाता है।

महादेवी समझती हैं कि आर्थिक निर्भरता केवल धन की कमी नहीं पैदा करती। यह आत्मविश्वास,

निर्णय–क्षमता और सामाजिक सम्मान को भी प्रभावित करती है। जब जीवन–निर्वाह के साधन किसी अन्य की इच्छा पर निर्भर हों, तब प्रेम, त्याग और सेवा भी स्वाधीन चुनाव के बजाय विवश कर्तव्य जैसे दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए अर्थ–स्वातंर्त्य स्त्री को परिवार से काटने का प्रस्ताव नहीं, संबंधों को अधिक सम्मानपूर्ण बनाने की शर्त है। आर्थिक अधिकार मिलने पर स्त्री का त्याग भी स्वतंत्र होगा और उसका सहयोग बराबरी पर आधारित होगा।

यह दृष्टि आज भी प्रासंगिक है। घरेलू श्रम का मूल्यांकन, संपत्ति में समान अधिकार, शिक्षा और रोजगार तक पहुँच, विधवा तथा परित्यक्ता स्त्रियों की सुरक्षा– ये प्रश्न उसी वैचारिक भूमि से जुड़े हैं। महादेवी ने आर्थिक प्रश्न को भावनात्मक अपील में विलीन नहीं होने दिया। उन्होंने स्पष्ट देखा कि सामाजिक सम्मान की भाषा तब तक अधूरी है जब तक साधनों पर न्यायपूर्ण अधिकार न हो।

भक्तिन : श्रम, प्रतिरोध और स्त्री अस्मिता :

स्मृति की रेखाएँ की भक्तिन महादेवी के गद्य की सर्वाधिक जीवंत स्त्रियों में है। उसका वास्तविक नाम लछमिन अर्थात लक्ष्मी है, पर जीवन में समृद्धि का कोई सहज मार्ग उसे नहीं मिला। बचपन में मातृस्नेह का अभाव, कम आयु में विवाह और पारिवारिक कठोरता उसके हिस्से आती है।[5], तीन बेटियों की माँ बनने पर सास और जिठानियाँ उसका तिरस्कार करती हैं। घर का कठिन श्रम भक्तिन और उसकी छोटी बेटियाँ करती हैं, जबकि भोजन और सुविधा में पुत्रों को प्राथमिकता मिलती है।[6], यहाँ पुत्र–मोह किसी अमूर्त सामाजिक दोष के रूप में नहीं, रसोई, दूध, मलाई, श्रम और भूख के असमान बँटवारे में दिखाई देता है।

फिर भी भक्तिन दीन या निष्क्रिय नहीं है। वह परिश्रमी है, खेती और पशुपालन का व्यावहारिक ज्ञान रखती है, अपने श्रम से गृहस्थी सँभालती है और पति की मृत्यु के बाद संपत्ति बचाने के लिए दृढ़ रहती है। पुनर्विवाह के लिए दबाव पड़ने पर उसका उत्तर तीखा है– वह अपने मन के विरुद्ध किसी दूसरे घर जाने को तैयार नहीं।[7], इस प्रसंग में उसकी बोली ही उसका प्रतिरोध बनती है। शिक्षित भाषा से दूर रहने वाली ग्रामीण स्त्री अपने जीवन पर निर्णय का अधिकार सहज आत्मविश्वास से घोषित करती है।

भक्तिन की बड़ी बेटी के साथ पंचायत का व्यवहार पितृसत्तात्मक न्याय की विडंबना उजागर करता है। एक युवक जबरन उसकी कोठरी में घुसता है; युवती प्रतिरोध करती है, फिर भी पंचायत उसी घटना को विवाह का आधार बना देती है। अपराधी की इच्छा सामाजिक मान्यता पा लेती है, स्त्री की असहमति निरर्थक कर दी जाती है।[7], महादेवी यहाँ पंचायत की हास्यास्पद तर्क–पद्धति को व्यंग्य से सामने लाती हैं। हँसी के भीतर गहरा क्रोध है।

भक्तिन और लेखिका का संबंध मालिक–नौकर की सीमा तोड़ देता है। महादेवी उसके "स्वतंत्र व्यक्तित्व" को स्वीकार करती हैं और उसके भीतर से फूटती स्नेह तथा सहानुभूति की आभा को पहचानती हैं।[8], भक्तिन में दोष भी हैं, रूढ़ियाँ भी, हठ भी; फिर भी वह पूर्ण मनुष्य है। लेखिका उसे आदर्श मूर्ति बनाकर निर्जीव नहीं करतीं। यही मानवीय संवेदना की प्रामाणिकता है– किसी व्यक्ति को उसकी जटिलताओं सहित स्वीकार करना।

बिन्दा और बालिका जीवन की करूण सच्चाई :

अतीत के चलचित्र की बिन्दा एक ऐसी बालिका है जिसकी माँ नहीं रही और नई माँ का कठोर व्यवहार उसके जीवन को यातना में बदल देता है। उसे तपती धरती पर खड़ा रखा जाता है, खंभे से बाँधा जाता है, भूखा

रखा जाता है और छोटे भाई की सेवा में लगाया जाता है। अपराध हो या न हो, दंड उसी को मिलता है।[9], महादेवी बालिका की पीड़ा को नाटकीय भाषा में नहीं बढ़ातीं। कुछ घरेलू दृश्य ही व्यवस्था की क्रूरता खोल देते हैं।

खौलता दूध गिरने से बिन्दा के पैर जल जाते हैं, पर वह उपचार माँगने से डरती है। भय इतना गहरा है कि पीड़ा छिपाना उसे अधिक सुरक्षित लगता है। बाद में बीमारी के समय वह अकेली पड़ी रहती है।[9], यहाँ मानवीय संवेदना बाल–मन की दृष्टि से विकसित होती है। बालिका–वर्णन करने वाली स्मृति स्वयं बालसुलभ प्रश्नों, उलझनों और असहाय क्रोध से भरी है। इस कारण बिन्दा केवल पीड़ित पात्र नहीं रहती; वह उस बचपन का प्रतीक बनती है जिसे परिवार की प्रतिष्ठा और अनुशासन के नाम पर आवाजहीन कर दिया जाता है।

बिन्दा का प्रसंग नारी चेतना की जड़ तक पहुँचता है। स्त्री की पराधीनता वयस्क जीवन से आरंभ नहीं होती। बेटी के रूप में उपेक्षा, भोजन और स्नेह में भेद, घरेलू सेवा का बोझ और प्रश्न करने पर दंड– ये अनुभव उसकी चेतना को बचपन से आकार देते हैं। महादेवी इस आरंभिक असमानता को पहचानती हैं। उनके लिए स्त्री–मुक्ति का प्रश्न बालिका की सुरक्षा, षिक्षा और आत्मसम्मान से अलग नहीं है।

सबिया : सहनशीलता के भीतर छिपी नैतिक शक्ति :

सबिया श्रमशील, कर्तव्यनिष्ठ और भावनात्मक रूप से उदार स्त्री है। उसका पति मैकू दूसरी स्त्री गेन्दा को घर ले आता है। सबिया के जीवन पर अतिरिक्त श्रम और मानसिक आघात का बोझ पड़ता है, फिर भी वह अंधी सास, बच्चों और घर की जिम्मेदारी उठाती रहती है। अपनी नीली साड़ी तक गेन्दा को दे देती है।[10], इस उदारता को महादेवी निष्क्रिय समर्पण के रूप में प्रस्तुत नहीं करतीं। सबिया का दुःख स्पष्ट है; वह कभी नीम से सिर टिकाकर रोती है, कभी काम करते हुए आँसू पोंछती है। उसके भीतर भावनाएँ जीवित हैं, पर परिस्थितियाँ उन्हें खुलकर व्यक्त होने का अवसर नहीं देतीं।

जब एक संपन्न महिला सबिया को "चोर की औरत" कहकर तिरस्कार करती है, महादेवी का शीतल क्रोध उभरता है। वे संपत्ति–संचय की सामाजिक नैतिकता पर प्रश्न उठाती हैं और सबिया की कर्तव्यनिष्ठा को कथित सभ्य समाज से ऊँचा रखती हैं।[10], संवेदना यहाँ दया नहीं, मूल्यांकन की नई कसौटी है। सामाजिक प्रतिष्ठा से अधिक महत्त्व श्रम, निष्ठा और मनुष्यता को दिया जाता है।

सबिया के माध्यम से स्त्री जीवन की एक कठिन गाँठ खुलती है। समाज स्त्री की सहनशीलता की प्रशंसा करता है, पर उसी प्रशंसा के सहारे उसके शोषण को लंबा भी करता है। महादेवी उसकी सहनशक्ति का सम्मान करती हैं, साथ ही उस व्यवस्था को कठघरे में खड़ा करती हैं जिसने उसके विकल्प सीमित किए। इस दोहरी दृष्टि में नारी चेतना की गहराई है।

घीसा और अलोपी : मनुष्य की गरिमा का विस्तार :

महादेवी की संवेदना स्त्री पात्रों तक सीमित नहीं रहती। घीसा निर्धन बालक है, पर उसकी नैतिक संपन्नता असाधारण है। मिले हुए थोड़े से मिष्ठान में वह माँ और बिना माँ के पिल्ले का हिस्सा पहले निकालता है। ज्वर से पीड़ित होने पर भी वह अपनी शिक्षिका को संभावित खतरे से सावधान करने चल पड़ता है।[11], उसके पास संपत्ति नहीं, पर सत्य, निष्ठा और प्रेम का "खरा सोना" है। महादेवी की दृष्टि सामाजिक मूल्यांकन को उलट देती है। मलिन शरीर में छिपी नैतिक उज्ज्वलता को पहचानना ही उनके मानवतावाद का मूल है।

अलोपी दृष्टिहीन सब्जी–विक्रेता है। वह दया का याचक बनकर नहीं आता; श्रम से अपना और अपनी माँ का जीवन चलाता है। लेखिका के बीमार होने पर वह देवी की विभूति लेकर पहुँचता है। वह उन्हें देख नहीं सकता, फिर भी उसकी चिंता और आत्मीयता दृष्टि से अधिक प्रखर है।[12], महादेवी उसके विश्वास पर उपहास नहीं करतीं। वे उस भावना की गरिमा को समझती हैं जिसके भीतर कर्तव्य की कठोरता और ममता की कोमलता साथ रहती है।

घीसा और अलोपी के चरित्र बताते हैं कि मानवीय संवेदना किसी एक सामाजिक आंदोलन का परिशिष्ट नहीं। यह मनुष्य को बाहरी श्रेणियों से परे देखने की क्षमता है। निर्धनता, अशिक्षा या शारीरिक अक्षमता व्यक्ति की गरिमा कम नहीं करती। उलटे, महादेवी कई बार उन्हीं उपेक्षित जीवनों में वह नैतिक ऊँचाई देखती हैं जो संपन्न और शिक्षित समाज में दुर्लभ है।

नारी चेतना और मानवीय संवेदना का अंतर्संबंध :

महादेवी के गद्य में नारी चेतना और मानवीय संवेदना दो अलग धाराएँ नहीं हैं। स्त्री की मुक्ति का प्रश्न उनके लिए व्यापक मानवीय न्याय का प्रश्न है। जो समाज स्त्री की इच्छा, श्रम और अधिकार को नहीं पहचानता, वह बच्चे, गरीब, सेवक, ग्रामीण और दिव्यांग मनुष्य की गरिमा भी सहजता से नहीं पहचान पाएगा। सत्ता की संरचना अलग–अलग रूपों में वही रहती है– कहीं पुरुष का अधिकार, कहीं संपत्ति का अहंकार, कहीं वयस्क का दमन, कहीं शिक्षित वर्ग का उपहास।

उनकी करुणा व्यवस्था की आलोचना को कमजोर नहीं करती; उसे नैतिक आधार देती है। भक्तिन की कथा में हास्य है, पर उसके श्रम और संघर्ष का अपमान नहीं। बिन्दा के प्रसंग में वेदना है, पर अनावश्यक विलाप नहीं। सबिया के जीवन में सहनशीलता है, पर शोषण का महिमामंडन नहीं। घीसा और अलोपी के चित्रों में आत्मीयता है, पर उन्हें दया के प्रदर्शन का साधन नहीं बनाया गया। महादेवी पात्रों को बोलने देती हैं। उनकी बोलियों, मौन, आँखों, हाव–भाव और छोटे निर्णयों से व्यक्तित्व उभरता है।

यह दृष्टि स्त्री–विमर्श को भी अधिक व्यापक बनाती है। महादेवी केवल अधिकारों की सूची प्रस्तुत नहीं करतीं; वे पूछती हैं कि स्वतंत्रता किस प्रकार का मनुष्य और कैसा समाज बनाएगी। उनके लिए मुक्ति का उद्देश्य कठोर प्रतिस्पर्धी बनना नहीं, न्यायपूर्ण और संवेदनशील जीवन–व्यवस्था रचना है। स्त्री के अनुभव से प्राप्त दया, सहानुभूति, धैर्य और संबंध–बोध को वे सार्वजनिक जीवन के लिए आवश्यक मानती हैं। इसीलिए उनकी नारी चेतना प्रतिशोध से अधिक पुनर्निर्माण की चेतना है।

भाषा और शिल्प :

महादेवी के गद्य की शक्ति उसकी भाषिक विविधता है। वैचारिक निबंधों में संयत, तर्कपूर्ण भाषा है; रेखाचित्रों में ग्रामीण बोलियाँ, संवाद, व्यंग्य और चित्रात्मक विवरण आते हैं। भक्तिन का प्रतिरोध उसकी बोली में विश्वसनीय बनता है, जबकि बिन्दा का मौन उसके भय को तीव्र करता है।

व्यंग्य महादेवी का महत्त्वपूर्ण औजार है। पंचायत, पुत्र–मोह, रूढ़ शास्त्रीयता और संपन्न समाज की नैतिकता पर वे तीखा प्रहार करती हैं, पर भाषा चीखती नहीं। कई बार एक हल्का वाक्य पूरे सामाजिक ढोंग को खोल देता है। उनके चित्रण में रेखाएँ कम हैं, प्रभाव गहरा। चरित्र का बाहरी रूप, एक विचित्र आदत, कोई संवाद और जीवन की निर्णायक घटना– इनसे पूरा व्यक्तित्व सामने आ जाता है।

आत्मीय 'मैं' अपनी भूल, उलझन और असहायता भी स्वीकार करता है। लेखक और पात्र के बीच दूरी घटती है, फिर भी आलोचनात्मक दृष्टि बनी रहती है। यही संतुलन निजी स्मृति को सामाजिक दस्तावेज बना देता है।

समकालीन प्रासंगिकता :

महादेवी के प्रश्न ऐतिहासिक होकर भी समाप्त नहीं हुए। स्त्री शिक्षा बढ़ी है, रोजगार के अवसर विस्तृत हुए हैं और कानूनी अधिकार मजबूत हुए हैं, फिर भी घरेलू श्रम का असमान बँटवारा, आर्थिक निर्भरता, पुत्र–प्राथमिकता, बालिकाओं पर नियंत्रण, विवाह में स्त्री की इच्छा की उपेक्षा और कार्यस्थल पर असमानता आज भी दिखाई देती है। उनका गद्य याद दिलाता है कि कानून आवश्यक है, पर मानसिकता और दैनिक व्यवहार में परिवर्तन के बिना समानता अधूरी रहती है।

घीसा, अलोपी और भक्तिन जैसे पात्र उपयोगिता–केंद्रित दृष्टि को चुनौती देते हैं। वे बताते हैं कि आत्मसम्मान, श्रम और संबंधों की ऊश्मा धन या औपचारिक शिक्षा की बपौती नहीं है।

निष्कर्ष :

महादेवी वर्मा का गद्य भारतीय स्त्री जीवन की पराधीनता का निर्भीक विश्लेषण करते हुए मनुष्य की व्यापक गरिमा की स्थापना करता है। श्रृंखला की कड़ियाँ में स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व, नागरिकता, शिक्षा और आर्थिक अधिकार का सुसंगत विचार मिलता है। स्मृति की रेखाएँ तथा अतीत के चलचित्र इन विचारों को जीवन के ठोस चेहरों में बदलते हैं। भक्तिन का श्रम और प्रतिरोध, बिन्दा की मौन पीड़ा, सबिया की कर्तव्यनिष्ठा, घीसा की निर्मल निष्ठा और अलोपी की आत्मीयता पाठक को सामाजिक श्रेणियों से परे मनुष्य को देखने की दृष्टि देते हैं। महादेवी की नारी चेतना पुरुष–विरोध पर नहीं टिकती। उसका केंद्र अन्याय–विरोध, आत्मसम्मान और स्वतंत्र विकास है। मानवीय संवेदना भी उनके यहाँ आँसू या दया का क्षणिक आवेग नहीं, वह विवेक, प्रतिरोध और नैतिक उत्तरदायित्व की शक्ति है। इसी संगम से उनका गद्य स्थायी महत्त्व प्राप्त करता है। वह स्त्री को देवी, दासी या त्याग–मूर्ति की जड़ छवियों से बाहर लाकर जीवित, निर्णय क्षम और जटिल मनुष्य के रूप में स्थापित करता है। साथ ही वह समाज के उन मौन जीवनों को भाषा देता है जिन्हें इतिहास और प्रतिष्ठित साहित्य प्रायः अनदेखा करते रहे। महादेवी के गद्य का मूल संदेश सीधा है– किसी भी सभ्यता की वास्तविक पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कम शक्तिशाली मनुष्य की स्वतंत्रता, पीड़ा और गरिमा को कितना समझती है।

संदर्भ-सूची :

- वर्मा, महादेवी. (1944). श्रृंखला की कड़ियाँ (तृतीय संस्करण, पष्० 1). प्रयाग : साधना–सदन।
- वर्मा, महादेवी. (1944). श्रृंखला की कड़ियाँ (तृतीय संस्करण, पष्० 7). प्रयाग : साधना–सदन।
- वर्मा, महादेवी. (1944). श्रृंखला की कड़ियाँ (तृतीय संस्करण, पष्० 9–12). प्रयाग : साधना–सदन।
- वर्मा, महादेवी. (1944). श्रृंखला की कड़ियाँ (तृतीय संस्करण, पष्० 124–126). प्रयाग : साधना–सदन।
- वर्मा, महादेवी. (1948). स्मृति की रेखाएँ (प्रथम संस्करण, पृ० 2–3). इलाहाबाद : भारती–भण्डार, लीडर प्रेस।
- वर्मा, महादेवी. (1948). स्मृति की रेखाएँ (प्रथम संस्करण, पृ० 3–4). इलाहाबाद : भारती–भण्डार, लीडर

प्रेस।

- वर्मा, महादेवी. (1948). स्मृति की रेखाएँ (प्रथम संस्करण, पृ० 6–9). इलाहाबाद : भारती–भण्डार, लीडर प्रेस।
- वर्मा, महादेवी. (1948). स्मृति की रेखाएँ (प्रथम संस्करण, पृ० 15–16). इलाहाबाद : भारती–भण्डार, लीडर प्रेस।
- वर्मा, महादेवी. (1949). अतीत के चलचित्र (पृ० 35–38). इलाहाबाद : भारती भण्डार।
- वर्मा, महादेवी. (1949). अतीत के चलचित्र (पृ० 46–49). इलाहाबाद : भारती भण्डार।
- वर्मा, महादेवी. (1949). अतीत के चलचित्र (पृ० 78–82). इलाहाबाद : भारती भण्डार।
- वर्मा, महादेवी. (1949). अतीत के चलचित्र (पृ० 101–104). इलाहाबाद : भारती भण्डार।

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 41-46

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' के समीक्षा–साहित्य का चिंतन

सुशीला देवी, शोधार्थी

डॉ० धनेश कुमार मीणा, शोध निर्देशक

श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, चुरू रोड़, झंझनू– 333001 (राजस्थान)

साहित्य–समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। शोध–प्रक्रिया के पहले चरण में शोधार्थी को किसी विषय की खोज और चयन करना शामिल होता है। वह एक विषय पर ज्ञान का आधार प्रदान करने वाली पुस्तकों, विद्वानों के लेखों और किसी विशिष्ट विषय से संबंधित अन्य स्रोतों, लेखक विशेष की मौलिक पुस्तकों का एक व्यवस्थित और व्यापक विश्लेषण करता है। शोध में अंतराल को उजागर करके अपने शोध को सही ठहराने के लिए किसी विषय पर मौजूदा साहित्य की पहचान करने और उसकी आलोचना करने के लिए साहित्य समीक्षा अथवा चिंतन तैयार किया जाता है। एक साहित्य समीक्षा के अंतर्गत किसी विषय पर वर्तमान शोध के महत्त्वपूर्ण विन्दुओं पर विश्लेषण किया जाता है और साथ ही उस विश्लेषण के आधार पर अपने शोध उद्देश्य को निर्धारित कर सम्पन्न करना होता है। एक अच्छी साहित्य समीक्षा की कुंजी शोध प्रक्रिया का प्रलेखन होता है। शोध अध्ययन को रेखांकित करने वाले विश्लेषण को साहित्य समीक्षा कहा जाता है।

अपनी सोचने–समझने की क्षमता से ही मनुष्य नई सभ्यता और संस्कृति और साहित्य का निर्माण कर सका है, जबकि जानवर नहीं कर सके। चिंतन की सहायता से मनुष्य कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है, चिंतन का उपयोग न केवल समस्या समाधान में बल्कि अन्य प्रकार की अधिगम में भी किया जाता है। वस्तुतः साहित्य में चिंतन शब्द का प्रयोग शिक्षित लोगों, विद्वानों व शोधार्थियों की बातचीत में कई प्रकार की अव्यक्त मानसिक क्रियाओं के लिए किया जाता है।

सामान्यतः सभी वर्ग के लोग चिंतन शब्द के स्थान पर 'सोच' शब्द का प्रयोग बहुतायत में करते हैं, जबकि कोई कवि कविता लिखता है या कोई कलाकार कलाकृतियाँ बनाता है या कोई समीक्षक किसी रचना की समीक्षा करता है तो वह अपनी कल्पना के माध्यम से कई प्रकार की छवियों या गुण–दोषों का अन्वेषण कर, उजागर करने का प्रयास करता है।

डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' के साहित्य संसार पर जब दृष्टि डालते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने गद्य–पद्य दोनों विधाओं में ही साहित्य सर्जना की है। डॉ० 'मंगलेश' हिंदी साहित्य की गद्य विधा आलोचना के अधिकारी विद्वान है। उन्होंने साहित्यिक गद्य विधा आलोचना अथवा समीक्ष्य सृजन में ही साहित्य सर्जना अधिक की है। उनकी अन्य साहित्यिक गद्य विधाओं में निबंध, आलेख, लोक साहित्य, जीवनी और प्रेरक लेख, शोध लेख आदि प्रमुख हैं। एक सजग साहित्यकार समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकृतियों को अपनी सृजनात्मकता के द्वारा

प्रतिबिंबित करता है। वह समाज के हर अच्छे–बुरे यथार्थ को अपनी रचनाओं अथवा लेखन कौशल से परिचित कराता है और बेहतर भविष्य के लिए समाज का मार्ग प्रशस्त कराता है।

इसलिए साहित्य और समाज के परस्पर संबंध से इन्कार नहीं किया जा सकता। जीव सृष्टि में सबसे विकसित जीवन मानव को माना जाता है। मानव समाज का सृष्टिकर्ता है और साहित्यकार न केवल मानव जीवन और समाज का अंग है, अपितु पथ प्रदर्शक भी है। हिंदी साहित्य में गद्य लेखन की परंपरा नई नहीं है। समय–समय पर साहित्य लिखने वाले गद्यकारों और उनकी नई–नई विधाओं में सृजन निरन्तर होता रहा है। हिंदी आलोचना साहित्य में एक स्थापित नाम है, डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' जी का जिन्होंने समीक्षा साहित्य में अपनी अलग पहचान बनाई है और इसका मूल कारण यह है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में विचारात्मक, व्यावहारिक, सैद्धांतिक तथा वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से विविध पक्षों को अत्यन्त सजगता के साथ उद्घाटित किया है। हिंदी के वरिष्ठ समीक्षकों और श्रेष्ठ सृजनशील लेखकों ने भी उनकी रचनाओं को खूब सराहा है। ऐसे लेखक के साहित्य के स्वरूप की गहरी पहचान और उसका यथोचित मूल्यांकन शोधक का एक महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है।

आधुनिक आलोचना साहित्य में प्रगतिशील एवं विकसित विचारधारा को लेकर चलने वाले समीक्षकों में डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' बहुत चर्चित एवं सशक्त हस्ताक्षर हैं। डॉ० 'मंगलेश' के जीवन पर भारतीय समाज अथवा संस्कृति का व्यापक प्रभाव है। 'संस्कृतिः संस्कृताश्रिताः' यह कथन लेखक पर नितान्त लागू होता है। किसी भी साहित्यकार के पास महत्ता की सीढियाँ चढ़ने के लिए जो आवश्यक प्राकृतिक अवदान जरूरी होता है, वह सब डॉ० 'मंगलेश' के पास है अर्थात् समीक्षक के पास नीर–क्षीर–विवेक की प्रतिभा बहुत ही समृद्ध रूप में है।

अतः साहित्यकार निःसंदेह व्यक्ति ही होता है लेकिन उसका सृजन व्यक्तिगत होते हुए भी सामान्य भावभूमि पर ही कल्पना की तुलना से रंजित होता है और तभी वह अपने युग का प्रतिनिधित्व कर पाता है। डॉ० 'मंगलेश' की भी अपनी एक जीवन–दृष्टि है, अपना स्पंदन है और अपना अलग रचना–शिल्प है। उनकी इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें भीड़ से अलग किया है। जब मनुष्य को किसी समस्या का समाधान खोजना होता है तो वह चिंतन प्रक्रिया का सहारा लेता है। वह चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से पर्यावरण, उसकी वस्तुओं और वस्तुओं के बीच संबंध को जानने का प्रयास करता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि सोच एक महत्त्वपूर्ण मानसिक प्रक्रिया है, जो समस्या समाधान की ओर उन्मुख होती है। साहित्यकार या समीक्षक की इस सोच के अनेक पक्ष हो सकते हैं, विचारात्मक, सर्जनात्मक, व्यावहारिक, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक आदि। यहाँ हम डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' के हिंदी साहित्य समीक्षा चिंतन का विश्लेषण कर, शोध विषय के विशेष क्षेत्र से अवगत होंगे।

गजानन माधव मुक्तिबोध ने कविता की रचना–प्रक्रिया के सन्दर्भ में लेखक की वैचारिक दृष्टि की भूमिका पर विचार किया। उनके अनुसार विचारधारा या विश्वदृघष्टि कला–रचना के बाहर का तत्त्व नहीं है। वह रचना–प्रक्रिया का हिस्सा है, यह दृष्टि अर्जित करने हेतु कवि को प्रयास करना पड़ता है। मुक्तिबोध इसी को विश्वदृष्टि कहते हैं। यह दृष्टि अर्जित करने हेतु कुछ लेखक प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा नहीं करते।

डॉ० 'मंगलेश' भी कुछ ऐसा ही सोचते हैं। 'काव्य पर्यालोचन' आलोचनात्मक पुस्तक में अपनी विश्वदृष्टि

देते लिखते हैं, "पुस्तकें साहित्य, समाज, संस्कृति और जीवन में गहरे तक घुसने का मार्ग प्रशस्त करती हैं। हर पुस्तक के पढ़ने पर कुछ–न–कुछ नया सीखता हूँ–विचारधारा के स्तर पर, भाषा, कला और शिल्प के स्तर पर, अनुभूतियों के स्तर पर तथा विशेषतः आलोचना के स्तर पर। अंतोगत्वा बस ! इतना समझ पाता हूँ कि कोई एक विचार, भाषा, शिल्प, अनुभूति या आलोचना कभी पूरे समाज का नेतृत्व नहीं कर सकती है। चूंकि सब पाठक भी एक समान नहीं होते। प्रत्येक के पुस्तक पढ़ने के उद्देश्य और कारण अलग–अलग होते हैं। पाठकों का एक बड़ा वर्ग है। एक जो समय काटने के लिए पढ़ता है, ऐसा पाठक पुस्तक को पढ़कर डाल देता है, उसमें से कुछ खोजता नहीं। दूसरे, मनोरंजन के लिए पड़ते हैं जिनकी संख्या सर्वाधिक है। इस वर्ग की पसंद के विषय, प्रेम, रोमांच, रोमांस तथा रहस्य होते हैं। तीसरा पाठक वर्ग वह है जो वर्तमान की हल्की–फुल्की गतिविधियों की जानकारी पढ़ना पसंद करता है। चौथा पाठक वर्ग मात्र दिखावे का पाठक होता है घर पर अथवा यात्रा में प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक हाथ में रखता है, पढ़ता नहीं सिर्फ पेज पलटता है।

पाठकों का पाँचवाँ वर्ग, साहित्य के प्रति रुचि रखता है और अच्छा साहित्य पढ़ता है, उससे ग्रहण करता है, प्रभावित होता है और अपने में और समाज में परिवर्तन करने का प्रयास करता है। पाठकों का छठा वर्ग, गंभीर पाठकों का होता है, जो अध्ययन के आधार पर अपना मानस बनाता है, चिंतन करता है, नव–सृजन भी करता है। इस साहित्य रूपी दर्पण में यह पाठक स्वयं को देखता है, जिनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे साहित्यरूपी दर्पण के एक पाठक हुए फणीश्वर नाथ रेणु, जो अपने को 'पाठकराम' कहते थे। वर्तमान में 'पाठकराम' बनने की कोशिश में एक नाम है, भारत यायावर का, जो 'खोजीराम' के रूप में विख्यात हैं। इसी 'खोजीराम' की ललक में मैं भी प्रयासरत हूँ। अभी मैं अपने को सिर्फ खोजी मानता हूँ, न मैं कवि, न लेखक, और न अच्छा आलाचेक किंतु मेरे पास शब्द हैं, विचार हैं, भाव है, संवेदना है और विशेषतः भाषा, कला–शिल्प है। चूंकि कतिपय वरिष्ठ साहित्यकार ऐसा कहते हैं, मैं समीक्षा एवं आलोचना में सिद्धहस्त हूँ, मेरी आलोच्य–दृष्टि को खूब प्रशंसा करते हैं, मेरा आलोच्य–क्रम किस स्तर का है, किस परंपरा का है, किस वाद अथवा आलोचक से प्रभावित है, मैं इस बात से अनभिज्ञ हूँ। हाँ, मैं इसे अपना सौभाग्य जरूर मानता हूँ कि जिन वरिष्ठ साहित्यकारों का सान्निध्य मुझे प्राप्त हुआ है, जब मैं उन्हें अपनी पीठ को थपथपाते पाता हूँ, तो मेरे अंदर आत्मबल और ऊर्जा का भरपूर संचरण होता है। इसी के फलीभूत मैं और अधिक ऊर्जा और तीव्रता के साथ अपने आलोच्य–क्रम पर लग जाता हूँ।"[1]

समीक्षकों को लेकर आलोचक डॉ० 'मंगलेश' लिखते हैं, "आजकल आलोचकों अथवा समीक्षकों का एक वर्ग ऐसा भी सामने आता है, जिनकी आए दिन ढेर सारी समीक्षाएँ पड़ने को मिलती, खूब धड़ल्ले से छापी जा रही हैं जिनमें एक पैराग्राफ रचनाकार का, दूसरा संक्षिप्त–सा रटा रटाया भाव पक्ष और अंत में वही गिने–चुने शिल्प पक्ष के चंद शब्द। ऐसी समीक्षाओं के पीछे समीक्षक का अपना उद्देश्य होता है, जिसका मूल होता है–छपास। आजकल पत्रिकाएँ विज्ञापन के सहारे चलती हैं और संपादक महोदय इन समीक्षकों को भी विज्ञापन के तौर पर ही छापता है। जिस तरह पूर्वकालिक 'तार' में और वर्तमान में 'विज्ञापन' को लेकर लागत (खर्चा) वर्णों के हिसाब से जोड़ी जाती है, वैसे ही समीक्षाएँ शब्दबद्ध आमंत्रित की जाती है। यदि समीक्षा की शब्द–सीमा निर्धारण से बाहर है, तो अतिरिक्त खर्चा तक वसूला जाता है। बाकी जो स्तरीय या विभागीय पत्रिकाएँ हैं, वहाँ स्थापित साहित्यकारों और आलोचकों से ट्सत नहीं है। परिणामस्वरूप, आज का लेखक अथवा नवोदित वहाँ भी पिछड़ जाता है। यही कारण है, नवोदित को सही समय पर, विधागत सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता और फिर

ऊपर से यह भी सुनना पड़ता है, कुकुरमुत्तों के भाँति लेखकों, कवियों और पिका क्षकों की बाढ़ आई हुई है, साहित्यिगत सिद्धांतों, परंपरराओं एवं मानदंडों आरि को ताक पर रख, लेखन हो रहा है।"[2]

कविता और अकविता निबंध में डॉ० जगदीश चन्द्र गुप्त लिखते हैं, "किसी काव्यकृति का 'कविता' होने के साथ ही 'नयी' होना अभीष्ट है। वह 'नयी' हो और 'कविता' न हो, यह स्थिति साहित्य में कभी स्वीकार नहीं हो सकती... अतएव नया क्या है? इस प्रश्न के साथ यह प्रश्न भी जीवित प्रश्न है कि कविता क्या है? और यदि सत्य कहा जाए तो पहले की अपेक्षा अब यह दूसरा प्रश्न अधिक महत्त्वपूर्ण हो उठा है? आगे लिखते हैं. मैं शब्द को ही काव्य, विशेषतः कविता की इकाई मानने के पक्ष में हूँ।"[3]

संक्षेप में, विचारशील डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' की चिंतनशील सोच में समष्टिगत सोच से व्यष्टिगत प्रतिबिंब के माध्यम से गहन अंतर्दृष्टि या समझ प्राप्त करने व लक्ष्य के साथ किसी विशेष विषय या विचार पर ध्यान केंद्रित होने की अपार क्षमता है और साथ ही, सुविचारित निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए व्यवस्थित, तटस्थ और तार्किक तरीके से जानकारी और तर्कों का मूल्यांकन करना शामिल है। सृजनात्मक चिंतन के चार प्रमुख तत्त्व माने हैं जिनमें प्रवाहित, लचीलापन, मौलिकता, और विस्तारण। इसके अतिरिक्त प्रवाहिता में वैचारिकता, अभिव्यक्ति और साहचर्य तथा शब्द प्रवाह शामिल हैं।

सृजनात्मक चिंतन की उपयोगिता तथा उपादेयता पर डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' ने लिखा है, "सृजनात्मकता सर्वव्यापक है अर्थात् यह योग्यता अथवा प्रतिभा प्रकृति प्रदत्त प्रत्येक व्यक्ति में आंशिक तौर पर अवश्य होती है, निखार के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा व अभ्यास द्वारा इसे और अधिक प्रबल व मजबूत बनाया जा सकता है। साथ ही उसका क्षेत्र, स्थान भी कुछ अलग हो सकते हैं।"[4]

'युग से युग तक' कविता संग्रह की समीक्षा करते डॉ० 'मंगलेश' कहते हैं, "साहित्य में नयापन आया है, इसे नई–नई दिशाएँ मिली हैं, नए–नए रूप प्राप्त हुए हैं तथा नए आयाम मिले हैं। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा भोगौलिक परिस्थितियाँ परिवर्तित हुई हैं। ऐसी नितांत नई बदलती हुई परिस्थितियों ने युग को तो प्रभावित किया ही है, युग भी बदले हैं। इसलिए परिवर्तित युग में साहित्य का स्वर परिवर्तित होना भी स्वाभाविक है। भारतीय चिंतकों एवं रचनाकारों ने परिवर्तित जीवन–मूल्यों, विषमताओं तथा विद्रूपताओं को देखा व समझा है। अपने अनुभवों तथा दूरदर्शिता को साहित्यिक अभिव्यक्ति प्रदान की है। इसी बीच अकूत मात्रा में उत्कृष्ट साहित्य का सृजन तथा उस साहित्य पर प्रभूत मात्रा में विश्लेषण हुआ है, आगे भी होता रहेगा। युग–युगांतर के संदर्भ में सृजित साहित्य की खूब आलोचना हो रही है तथा आगे भी होती रहेगी। परंतु यहाँ ध्यातव्य यह है कि भारतीय साहित्य में जितने बदलाव आए हैं वे अभूतपूर्व हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में वह वैविध्य अप्राप्त है जो आधुनिककाल के साहित्य में विद्यमान है।"[5]

सृजनात्मकता के संदर्भ में डॉ० 'मंगलेश' की दृष्टि व्यापक और विशाल है। एक तरह से मुक्तिबोध की विश्वदृष्टि के समान खड़ी दिखाई है।

सैद्धांतिक चिंतन या समीक्षा का उद्देश्य किसी मुद्दे, अवधारणा, सिद्धांत, घटना के संबंध में सैद्धांतिक जांच–परख करना होता है। सैद्धांतिक साहित्य चिंतन यह स्थापित करने में मदद करता है कि कौन से सिद्धांत पहले से मौजूद हैं, उनके बीच संबंध क्या है, और नई परिकल्पना विकसित करने के लिए कौन से सैद्धांतिक साहित्य का चिंतन किया जाना चाहिए। सैद्धांतिक साहित्य चिंतन का उपयोग उपयुक्त सिद्धांतों की कमी को

स्थापित करने में मदद करने में करता है या यह प्रकट करता है कि नई या उभरती हुई शोध समस्याओं को समझाने के लिए वर्तमान सिद्धांत अपर्याप्त हैं।

डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' के मतानुसार, "आलोचना की अपनी एक विलग भाषा है। आलोचना परंपरा समय, समाज, संस्कृति, नए प्रयोग के साथ सामयिक युग–बोध का चिंतन और शोधात्मक अध्ययन का विषय है, जो पाठक के अंतस में उद्वेलन पैदा कर, चिंतन–मनन करने को बाध्य करे, शोधार्थी के लिए उपादेय हो, न कि रचनाकार की प्रशंसा मात्र। एक आलोचक का बौद्धिक स्तर समग्र विधाओं में परिपक्वता का परिचायक है। जिस तरह से कवि या लेखक का मूल, समाज जीवन का एक खंड होता है, वहाँ एक आलोचक का मूल परंपरा, संस्कृति और समाज होता है। जब किसी रचना का सर्जन होता है तो उसकी एक पृष्ठभूमि, देशकाल, वातावरण तथा भाषा शैली का असर उसमें समाहित होता है। परंपरा और संस्कृति का मिश्रण होता है। जब रचना सर्जन, भारतीय संस्कृति के बीच अथवा धरा पर रहकर करते हैं, तो सिद्धांत पाश्चात्य शास्त्रों के क्यों? जबकि उसका पाठक भारतीय है।"[6]

डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' ने 'प्रयोजनपरक हिंदीः अनुप्रयोग और अनुवाद' शोध ग्रंथ में विषय–वस्तु की आलोचनात्मक समीक्षा के साथ–साथ अपनी शोध वृत्ति का, गहन गंभीर अध्ययन एवं विश्लेषण–दृष्टि का भी परिचय दिया है। हालाँकि इस विषय पर अनेक पुस्तकें पहले भी उपलब्ध हैं, किंतु नई दृष्टि से, नई शैली में तथा मौलिक एवं बोधगम्य प्रविधि से तैयार की गई इस पुस्तक को लेखक ने सहज, सुबोध, सुगम तथा संप्रेषणीय भी बना दिया है। सोदाहरण विवेचना, विषयानुकूल गरिमा मंडित भाषा शैली इस पुस्तक के आभूषण हैं।"[7]

डॉ० 'मंगलेश' व्यावहारिक, आदर्शवाद के विपरीत प्रकृतिवाद के साथ सहयोग करके व्यक्तित्व का संकीर्ण अर्थ बताता है। साहित्य में गुणात्मक और मात्रात्मक चिंतन की गुणवत्ता के मानदंड मानक भिन्न–भिन्न होते हैं। डॉ० 'मंगलेश' लिखते हैं, "काव्यशास्त्र काव्य और साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। यह काव्य कृतियों संश्लेषण–विश्लेषण के आधार पर युगानुरूप उद्‌भावित सिद्धांतों की ज्ञान–राशि के है। काव्य का सक्से महत्त्वपूर्ण पक्ष कृति है और कृति को लेकर प्रश्न उठता है–कवि, कलाकार या काव्यकर्ता को लेकर तथा काव्यानुशीलन अथवा काव्यालोचना को लेकर। इस प्रकार काव्यशास्त्रीय चिंतकों के अनुसार काव्यकृति मुख्यतः कवि, काव्य और काव्यालोचन से जुड़ी है इस संदर्भ में मेरा मानना है कि प्रत्येक मनुष्य क्रांतदर्शी न सही, ईश्वर न सही, किंतु परमेश्वर का अंश अवश्य है और उसका अंशमात्र ज्ञान भी यदि इसमें निहित है तो वह कवि है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य कवि है और उसके साथ निर्झर–सी बहती कविता है। अर्थात् यह कहना अतिशयोक्ति न होगा कि जिस प्रकार इस सृष्टि के कण–कण मैं ईश्वर है, शब्द है, नाद है, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य में कवित्व शक्ति निहित है, सिर्फ आवश्यकता है तो उस शक्ति को जागृत करने की, जानने की और हृदय की अतल गहराइयों में सुप्त अथवा उत्पन्न प्रबल संवेगों और भावों का सहज प्रकटीकरण करने की। कहा जाता है कविता गहरी संवेदना की अनायास उपज है, जिसका जन्म करुणा, अवसाद, पीड़ा तथा दुःख के क्रोड से होता है।"[8]

वरिष्ठ अनुवादक प्रो० सुरेश सिंहल लिखते हैं, "आज गद्य–पद्य की विभिन्न विधाओं का खूब सृजन हो रहा है। नित नई–नई विधाओं, छंदों और शैलियों का नवोन्मेष हो रहा है किंतु इनकी सार्थकता को प्रमाणिकता प्रदान करने वाली कलम की पैनी धार के सिपाही आलोचकों का नितांत अभाव ही है। ऐसे में डॉ० 'मंगलेश' की कलम में सटीकता, यथार्थता और सामर्थ्यवान दृष्टव्य है।"[9]

प्रो० (डॉ०) दिग्विजय कुमार शर्मा लिखते हैं, "डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' का आलोचनात्मक–कर्म बड़ा शोधपरक, विस्तारपूर्वक, व्यापक और शोधार्थियों के लिए बहुत उपादेय है। जो बाबू गुलाबराय द्वारा लिखी गई आलोचना की परिभाषा में सटीक बैठता है।"[10]

निष्कर्ष :

निष्कर्षतः डॉ० 'मंगलेश' के आलोच्य साहित्य को आधुनिक हिंदी समीक्षा के जगत में प्रथम श्रेणी का कहने में मुझे गर्व एवं हर्ष की अनुभूति हो रही है। 'काव्य पर्यालोचन', 'सृजन और समीक्षा', 'साहित्य सृजन और साहित्यालोचन' और 'हिंदी आलोचना के विविध प्रतिमान' कृतियों में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रचना भी आलोचक/समीक्षक द्वारा आलोचित/समीक्षित होकर लोकग्राह्य व लोकप्रिय बनी है। आलोचक डॉ० 'मंगलेश' की समीक्षाओं में रचनाकारों के प्रति यथासम्भव निरपेक्ष–निर्लिप्त रहने के प्रयास को देखा जा सकता है।

संदर्भ सूची :

1. डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश', काव्य पर्यालोचन, पृ० 08
2. डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश', काव्य पर्यालोचन, पृ० 10
3. गजानन मुक्तिबोध, समकालीन हिंदी आलोचक और आलोचना, पृ० 124
4. डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश', काव्य पर्यालोचन, पृ० 10
5. डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश', काव्य पर्यालोचन, पृ० 45
6. डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश', साहित्य सृजन और साहित्यालोचन, पृ० 08
7. डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश', प्रयोजनपरक हिंदीः अनुप्रयोग और अनुवाद, पृ० 08–09
8. डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश', काव्य पर्यालोचन, पृ० 11
9. डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश', विदेशी कहानी हिंदी अनुवाद, शुभकामना से।
10. डॉ० दिग्विजय कुमार शर्मा, डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' : साहित्य समालोचन, प्राक्कथन से।

संपर्क सूत्र : सुशीला देवी, चरखी दादरी (हरियाणा) मो. 8168109769

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 47-51

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

तुलसीकाव्य का वैशिष्ट्य

डॉ. संजय कुमार सिंह
सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार।

यह कहना सही है कि तुलसी सामाजिक दुरावस्था के काल में पैदा हुए थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तुलसी के महत्त्व को रेखांकित करते हुए भारतीय संदर्भ में यह ठीक ही कहा है कि– भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। दूसरी तरफ, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल की दृष्टि में भी तुलसी अतिविशिष्ट हैं। शुक्लजी लिखते हैं कि भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो तुलसीदास को। तुलसी की ख्याति का मूलाधार उनका महाकाव्य रामचरितमानस है। भारत में रामकाव्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। वाल्मीकि रामायण रामकथा का मूल स्रोत है। रामकथा महाभारत में भी वर्णित है, यथा– द्रोणपर्व, शांतिपर्व, भीष्मपर्व में। ऋषि मार्कण्डेय ने युधिष्ठिर को रामोपाख्यान सुनाया था। अगस्त्य संहिता और राघवीय संहिता में भी रामकथा का वर्णन है। रहस्योपनिषद् के साथ–साथ पुराणों में भी रामकथा अनेक रूप में वर्णित है। जैसे– वायुपुराण, विष्णुपुराण, भागवतपुराण इत्यादि में। साथ ही अध्यात्मरामायण, आनंदरामायण तथा अद्भुतरामायण की कथा भी रामकथा ही है। बौद्ध जातकों में भी रामकथा कई रूपों में वर्णित है। जैनग्रंथ पउमचरिउ, उत्तरपुराण तथा महापुराण इत्यादि में भी रामकथा का जिक्र है। दक्षिण के भक्तों के काव्यों में भी रामकथा निबद्ध है। पर, तुलसी की रामकथा अपने आप में विशिष्ट है। यद्यपि तुलसी ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह रामचरितमानस–

"नानापुराणनिगमागम सम्मत् यद्"[1] है।

रामचरितमानस तुलसी की कृति का अक्षय भंडार है। महाकवि तुलसी की अनेक विशेषताएं हैं जिनमें से एक विशेषता यह है कि तुलसी राम परंपरा के सभी कवियों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि–

"तेहि बल मैं रघुपति गुनगाथा।
कहिहउ नाई राम पद माथा।।''

विनय भक्ति कवि की परंपरा का भाग है–

"समुझत अमित राम प्रभुताई।
करत कथा मन अति कदराई।।

□–––––□–––––□

सब जानत प्रभु प्रभुता सोई।

तदपि कहें बिनु रहा न कोई।''[2]

आगे तुलसी कहते हैं कि यदि राम की श्रेष्ठता भव्य है तो मेरी यह साधारण कविता भी उनके संपर्क में आकर श्रेष्ठ हो जाएगी। तुलसी की कवि प्रतिभा उस लौह की भाँति है जो श्रीराम कथा रूपी पारसमणि के स्पर्श से स्वर्णमयी हो उठती है। इसीलिए वे कहते हैं कि–

"कबि न होऊं नहीं चतुर कहावउं।
मति अनुरूप रामगुण गावउं।।''[3]

तुलसी अति कृतज्ञता प्रकट करते हुए आगे कहते हैं–

"संभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी।
रामचरितमानस कवि तुलसी।।"

कवि की कृतज्ञता सभी के प्रति है –देव, दनुज, खग–मृग आदि के प्रति। भालू राजा जामवंत, राक्षसराज विभीषण, वनराज सुग्रीव, सुर–असुर सभी का कृतज्ञतापूर्वक गान करते हैं। परंपरा तथा रचना सामर्थ्य, सभी का कवि ने बहुत चतुराई से प्रयोग किया है। यथा –

"रचि महेश निज मानस राखा।
पाइ सुसमय सिवा सन भाषा।।"[4]

तुलसी की काव्यदृष्टि स्पष्ट है। मानस के मंगलाचरण में तुलसी कहते हैं–

"वर्णानामर्थसंघानां रसानां छंदसामपि। मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ।।"[5]

इसके द्वारा उन्होंने सभी काव्य संप्रदायों का समन्वय कर दिया है– वर्णानाम से अलंकारवाद, अर्थसंघानाम से ध्वनिवाद, रसानां से रसवाद, छन्दसामपि से रीतिवाद का मौलिक ढंग से उल्लेख किया है। तुलसी काव्यतत्वों के अंतर्गत शब्द, अर्थ, अलंकार, छंद, प्रबंध, भाव, रस, गुण और दोष का उल्लेख करते हैं। तुलसी कहते हैं–

"आखर अरथ अलंकृत नाना।
छंद प्रबंध अनेक विधाना।।
भाव भेद रस भेद अपारा।
कबित दोष गुण बिबिध प्रकारा।।"[6]

काव्य प्रयोजन के तहत तुलसी ने दो बातें कही एक, कविता स्वांतःसुखाय होनी चाहिए और दूसरी वह लोकमंगलकारी भी होनी चाहिए– अर्थात वही कीर्ति, कविता एवं ऐश्वर्य अच्छा है जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो। स्वांतःसुखाय और बहुजन हिताय में कोई तात्विक भेद नहीं है। क्योंकि बहुजन हिताय में ही तुलसी का स्वांतःसुखाय समाहित है। कला पक्ष के बारे में तुलसी की अभिव्यक्ति अद्‌भुत है। तुलसी लिखते हैं–

"सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे।
अरथ अमित अति आखर थोड़े।।"

वस्तु पक्ष की दृष्टि से तुलसी में व्यापक विविधता है। तुलसी की कविता का मूल स्रोत मानव प्रेम है। कविता प्रेम और आनंद की सरिता के समान उमड़ चलने वाली है। तुलसी कहते हैं–

"चली सुभग कविता सरिता सी"।

तुलसी कविता को वर्ड्सवर्थ की तरह स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो यानी, स्वतःस्फूर्त भी नहीं मानते। वे उसमें विचार और चिंतन के योग को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि–

"हृदय सिंधुमती सीप समाना।
स्वाति शारदा कहहि सुजाना।।"

तुलसी के संपूर्ण काव्य में युग बोलता है। तुलसी अपनी रचनाओं में जहाँ–जहाँ तत्कालीन परिस्थितियों का यथातथ्य वर्णन करते हैं, वस्तुतः वहाँ–वहाँ तत्कालीन युगबोध ही है। राजनीतिक स्थिति भी धर्मपरायण नहीं थी। तुलसी लिखते हैं –

"नृप पाप परायण धर्म नहीं।
करि दंड विंडंब प्रजा नित ही।।"

तत्कालीन समय में सामाजिक विषमता और ऊंच–नीच का भेद विद्यमान था। मिथ्याडंबर सामाजिक पहचान बन गए थे–

"मारग सोई जा कहुं जोई भावा।
पंडित सोई जो गाल बजावा।।"

स्त्री की दशा बहुत दयनीय थी। नारी को भोग्या मान लिया गया था। तुलसी लिखते हैं–

"नारि विवस नर सकल गोसाईं।
नाचहिं नर मरकट की नाईं।।
सौभागिनी विभूषण हीना।
विधवन के श्रृंगार नवीना।।"

आर्थिक दशा का चित्र तुलसी ने बड़ी संजीदगी से खींचा है। सामाजिक विषमता के कारण आर्थिक कठिनाई से जनजीवन दूभर हो रहा था। तुलसी कहते हैं–

"कलि बार ही बार अकाल परे।
बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे।।"

किसान की स्थिति का वर्णन करते हुए तुलसी लिखते हैं–

"खेती न किसान को भिखारी को न भीख बलि।
बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी।।"

धार्मिक स्थिति भी विडंबनापूर्ण थी। वस्तुतः धार्मिक व्यवस्था पंगु हो गई थी। धर्म के नाम पर वितंडावाद फैलाया जा रहा था। तुलसी आगे लिखते हैं–

"कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भए सदग्रंथ।
दम्भिन निज मत कल्प करि प्रकट किए बहुपंथ।।"

तुलसी लोकमंगल के कवि हैं। लोकमंगल का अर्थ है, 'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय।' उनकी काव्य रचना का मूल उद्देश्य है, लोकमंगल का विधान करना–

"कीरति भनिति भूति भलि सोई।
सुरसरि सम सब कहं हित होई।।"[7]

लोकमंगल का विधान करने वाले दो भाव है– करुणा और प्रेम। वाल्मीकि रामायण का बीज भाव करुणा है। राम दुष्टों का वध करते हैं, उनको निजधाम भेजते हैं और उन्हें वैध उत्तराधिकारी को गद्दी सौंप देते हैं। वे विजित किये गए किसी भी राज्य को अयोध्या का अंग नहीं बनाते। लंका भी विभीषण को सौंप देते हैं। तुलसी के राम लोकरक्षक और धर्म संस्थापक हैं। राम मंगल भवन अमंगल हारी हैं।

सामाजिक पारिवारिक आदर्श पर तुलसी का विशेष जोर है। मुनि वशिष्ठ एवं ऋषि विश्वामित्र के लिए राजा दशरथ अपना आसन छोड़कर खड़े होते हैं और आगवानी करने द्वार तक जाते हैं। गुह निषाद वशिष्ठ जी का पांव छूकर दूर हटने का प्रयास करते हैं, पर वशिष्ठ उसे खींचकर गले लगा लेते हैं। केवट राम से उतराई नहीं लेता क्योंकि राम निर्वासित थे। वापसी के समय हँसी–खुशी का समय होगा तब, जो मिलेगा वह स्वीकार होगा। केवट का कहना है–

"फिरती बार मोहि जो देवा।
सोई प्रसाद मैं सिरु धरू लेवा।।"[8]

पारिवारिक मर्यादा के तहत राम पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हैं और वन गमन करते हैं। राम का कथन है–

"सुनु जननी सोई सुत बड भागी।
जो पितु मातु वचन अनुरागी।।"

भरत और लक्ष्मण के चरित्रों के माध्यम से तुलसी ने भारतीय भ्रातृत्व का श्रेष्ठतम आदर्श प्रस्तुत किया है। यहाँ तक कि सीताहरण के बाद भी रावण सीता के शीलहरण की बात नहीं सोचता।

रामराज्य की परिकल्पना तुलसी की विशेष निधि है। सर्वोत्तम राज व्यवस्था के संदर्भ में दो कल्पनाएँ सर्वमान्य हैं– एक, कल्याणकारी राज्य (वेलफेयर स्टेट) तथा अराजकतावादी (एनार्किस्ट) व्यवस्था। वह शासन सर्वोत्तम है जहाँ शासन की आवश्यकता ही न पड़े, या जो सबसे कम शासन करे। प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करें। रामराज्य की तुलसी की परिकल्पना इन पंक्तियों में व्यक्त हुई है–

"दैहिक दैविक भौतिक तापा।
राम राज काहुहि नहीं व्यापा।।"[9]

अत्याचारी राजाओं के बारे में तुलसी कहते हैं–

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अवसी नरक अधिकारी।।"

रामराज्य पूर्ण व्यवस्थित है। तुलसी टिप्पणी करते हैं –

"फूलहि फरहिं सदा तरू कानन।
रहहि एक संग गज पंचानन।।"[10]

रामचरितमानस में चित्रकूट सभा का विश्लेषण महत्वपूर्ण है। इस सभा में एकतंत्र और प्रजातंत्र का समन्वित रूप दिखाई पड़ता है। यह कितनी महान परिकल्पना है, जिसमें प्रजाजन से यह कहा गया कि वर्तमान परिस्थिति पर लोकमत, साधुमत, वेदमत एवं राजनीति के संदर्भ में अपना निर्णय सुना दें। और इससे भी बड़ी बात कि वह निर्णय सबके लिए मान्य होगा।

तुलसी मर्यादावादी कवि हैं और उनके राम मर्यादा पुरुषोत्तम। श्रृंगार के अवसर पर भी तुलसी का वर्णन संयमित एवं संयत है। पुष्प वाटिका में राम–सीता के प्रथम मिलन में तुलसी पूर्ण मर्यादित रहे। सीता के आभूषणों की ध्वनि सुनकर राम अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं–

"कंकन किंकिंनि नूपुर ध्वनि सुनि।
कहत लखन सन राम हृदय गुनि।।
मानहुं मदन दुंदुभी दीन्हीं।
मनसा विश्वविजय कहं कीन्हीं।।"

यहाँ तुलसी ने रूप सौंदर्य का वर्णन किया है, मनरूस्थिति का चित्रण किया है, जो राम–सीता के प्रणय का मौन निमंत्रण है। राम की एक झलक देखने के बाद सीता की दशा का मार्मिक, सरस, किंतु मर्यादित चित्र देखिये–

"चितवति चकित चहुँ दिसि सीता।
कहं गए नृप किशोर मन चीता।।
लता ओट तब सखिन लखाए।
हरसे जनु निज निधि पहिचाने।।"

वैसे ही वन गमन के क्रम में राम लक्ष्मण और सीता को देखकर ग्राम बालाएं सीता से उनका संबंध जानना चाहती हैं। तुलसी लिखते हैं कि–

"सहज सुभाय सुभग तन गोरे।
नामु लखन लघु देवर मोरे।।
बहुरि बदन विधु अंचल ढांकी।
पियतन चितई भौंह करि बांकी।।"

तुलसी की महत्ता का समग्रता में विश्लेषण करते हुए बाबा बेणीमाधव दास के शब्दों में कह सकते हैं कि–

"भारी भवसागर उतारतो कवन पार।
जो पै यह रामायण तुलसी न गावतो।।"

संदर्भ सूची :

1. टीका. पोद्दार हनुमान प्रसाद, श्रीरामचरितमानस, गीताप्रेस, गोरखपुर, पृष्ठ सं. 2
2. वही, पृ. 16
3. वही, पृ. 16
4. वही, पृ. 39
5. वही, पृ. 1
6. वही, पृ. 13
7. वही, पृ. 18
8. वही, पृ. 387
9. वही, पृ. 854
10. वही, पृ. 855

ई–मेल : sanjaysagarbdo@gmail.com
मो. नं. 9931420894

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 52-63

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

IoT Components and Machine Learning Algorithms for Smart Vehicles

Tejas Rajaram Jadhav, Research Scholar,
Dr. Hiren Jayantilal Dand, Research Guide,
Departmant of Computer Science,
Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Jhunjhunu, Rajasthan.

Abstract :

The convergence of machine learning and the Internet of Things is transforming modern transportation, transforming conventional automobiles into intelligent, networked, and autonomous systems. Modern smart automobiles rely on a variety of IoT components to perceive their surroundings, including LiDAR, radar, cameras, ultrasonic sensors, GPS modules, and V2X communication interfaces. In order to provide critical operations like object identification, lane maintaining, collision avoidance, traffic prediction, and autonomous decision-making, the ensuing high-volume data streams are processed using machine learning and deep learning algorithms.According to recent research, hybrid deep-learning architectures (like CNN + LSTM ensembles) achieve traffic-congestion prediction accuracies up to 98%, vehicular fog-computing models reduce end-to-end latency by up to 35% when compared to pure cloud solutions, and reinforcement-learning agents successfully learn complex lane-change and overtaking behaviours. The essay maps four common machine learning paradigms—supervised, unsupervised, reinforcement, and federated learning—to a five-layer IoT architecture in order to further show the design space. The findings indicate that IoT-driven sensing and ML-driven inference must cooperate to enable safer, greener, and more efficient mobility.

Keywords : Internet of Things, Smart Vehicles, Machine Learning, V2X Communication, Sensor Fusion, Autonomous Driving, Edge Computing, Intelligent Transportation Systems,

1. Introduction :

The transportation sector is undergoing a paradigm shift because to new machine learning algorithms and the growth of the Internet of Things. Conventional automobiles are rapidly being replaced with smart cars, which can perceive their surroundings, communicate with other drivers and infrastructure, and make decisions with little to no human input. Smart transportation is a single intelligent system that combines route optimization, parking, street illumination, accident prevention/detection, road anomaly monitoring, and infrastructure management. Road safety remains a key motivator: studies reveal that over 90% of road accidents are caused by human mistake, with only 2% being due to vehicle issues.This figure highlights the possible consequences of automated driving features that make up for human error.Beyond safety, smart vehicles are expected to deliver value-added services such as infotainment, predictive maintenance, route optimization, and energy management.The Internet of Things (IoT) is the enabling layer that connects physical objects' sensors, actuators, GPS receivers, smartphones, and on-board diagnostics units so that data can be continuously collected, transmitted, and processed. On top of this layer, machine learning algorithms transform the resulting big-data streams into actionable predictions and decisions, supporting applications ranging from cooperative collision avoidance to traffic-signal control. Multi-sensor fusion has become a cornerstone of autonomous-driving research because using a single sensor for perception is unreliable due to noise, occlusion, and bad weather.The goal of this paper is to present an integrated review of the following topics: (i) the IoT components used in smart cars; (ii) the machine learning algorithms used on the data they produce; (iii) the architectural decisions (cloud, edge, and fog) that act as a mediator between data and decisions; and (iv) the open issues related to security, latency, and scalability.

2. Litreature Review

2.1 IoT in Smart Transportation :

The Internet of Things (IoT) paradigm uses embedded electronics, sensors, and software to link physical things and facilitate data flow with little assistance from humans. Drivers in smart cities may access parking, safety, logistics, and traffic control services thanks to the Internet of Things. Machine learning techniques are needed to convert the massive amounts of quantitative data produced by IoT devices into qualitative insights and intelligent applications.ML and IoT applications in Intelligent Transportation Systems and observed that

while ML coverage for smart lighting and smart parking is still rather limited, the most popular research subdomains are route optimization, parking, and accident detection/detection. Because it supports vehicle-to-everything (V2X) connectivity, where ultra-low latency and great dependability are essential, the development of 5G and the next 6G vision is crucial.

2.2 IoT Architectures for Vehicles :

The vehicular-domain implementation of IoT, known as IoV, is characterized by extremely dynamic interactions between humans, vehicles, and their surroundings. IoV is divided into four levels by a commonly used architecture: application, network access and transport, coordinative computing control, and vehicle-network environment sensing and control. Artificial intelligence is made up of artificial intelligence. The connected-vehicle stack is broken down into three levels by a complementary design: (i) the device level (sensors, actuators, GPS, smartphones) (ii) the communication level (V2V, V2I via satellite and cellular; in-car bus-area sensor networks) and (iii) the service level (context, application, and management services).

2.3 Machine Learning Algorithms Applied to Smart Vehicles :

Convolutional neural networks for visual perception, recurrent neural networks and LSTM units for traffic-flow forecasting, deep belief nets for intrusion detection in vehicular networks, support vector machines for traffic-sign recognition, and reinforcement-learning agents for motion planning are just a few of the many machine learning algorithms that have been applied to transportation issues in recent reviews. LSTM networks applied to a large-scale Los Angeles traffic dataset offer 30–50% improvement over traditional baselines in peak-hour and post-accident forecasting.

2.4 Autonomous Driving and Decision-Making :

Autonomous cars must function in contexts marked by complicated spatial-temporal dynamics and changeable circumstances caused by social events, weather, and seasonal behaviour. For this goal, Markov-decision-process-based reinforcement learning, deep neural networks, and probabilistic SVMs have all been studied. Because (a) labelled data are costly, (b) various drivers can adopt different safe behaviours in identical conditions, and (c) the agent must learn to interact dynamically with other agents, comparative evaluations show that reinforcement learning is especially well suited to autonomous driving. Lane-change choices have been developed as partial-observable MDPs, deep RL systems have been trained using the TORCS

simulator to manage lane-keeping, overtaking, and collision avoidance, and deep Q-Networks have been employed for lateral control policies with safety checkers.

2.5 Edge, Fog, and Cloud Computing for Connected Vehicles :

Computational resources are being moved from cloud data centers to the network edge due to the latency requirements of safety-critical vehicle applications. Many people believe that Multi-access Edge Computing is a practical and affordable addition to V2X. Vehicle-mounted fog computing minimizes reaction times for citywide events by treating parked and moving automobiles as fog nodes; these three-layer distributed systems have been proven by real-world taxi trajectories. It has been demonstrated that an Adaptive Fog framework that automatically transitions between LTE networks may increase fog and cloud latency service assurance by 30–50%.

3. Statement of Problem :

Despite quick progress, a number of unresolved issues prevent the widespread use of IoT and ML-enabled smart cars:

1. **Multi-sensor data heterogeneity and noise.** Individual IoT sensors suffer from limitations: cameras are computationally expensive and susceptible to poor lighting; LiDAR is poor for very-near (<2 m) measurement; radar and sonar have poor angular resolution. Relying on any one sensor is unsafe; therefore, robust fusion algorithms are required.
2. **Latency-constrained decision-making.** Pre-crash warning and other critical safety services need an end-to-end latency of 20–50 ms. This constraint is often broken by current cloud-centric designs. The best task-offloading strategies are still up for debate, notwithstanding the respite provided by edge and fog computing.
3. **Data scarcity and labelling cost.** Large, expert-labelled datasets (such as KITTI, Waymo Open, V2V4Real, V2X-Sim, and OPV2V) are necessary for supervised-learning techniques, but actual corner-case labelling is costly.
4. **Trust, privacy, and security.** Although many secure-connection systems completely ignore privacy or, on the other hand, merely reveal coarsened data to requesting services, vehicular data is intrinsically sensitive. One of the biggest obstacles to service-oriented vehicular networks is still authentication delay in V2I.

5. **Algorithm interpretability and safety verification.** Failure diagnosis is challenging and regulatory certification is still a hurdle since machine learning inference is based on probabilistic rather than causal reasoning.

4. Experimental Techniques / Research Methodology :

4.1 Research Design :

This work uses a comparative experimental technique derived from published standards in addition to a thorough literature-review methodology. The research procedure is summarized in Figure 1.

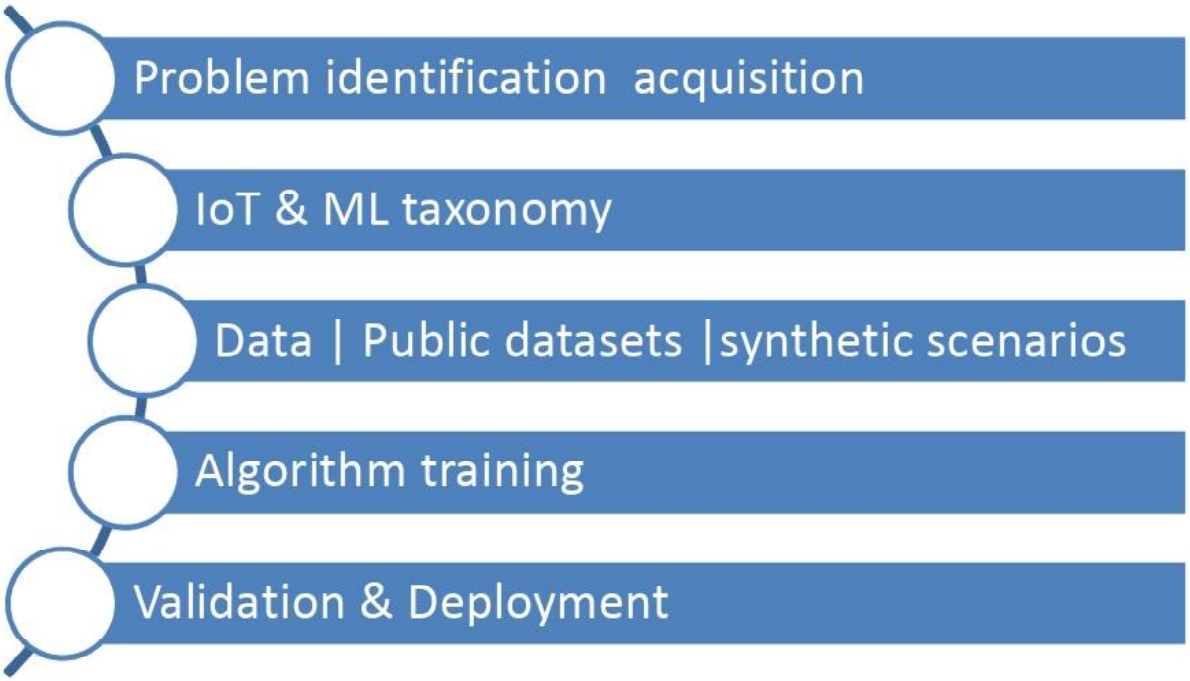


Figure 1. Five-stage research methodology for IoT-and-ML smart-vehicle studies.

4.2 IoT-Component Layer :

The following components are deployed to instrument a smart vehicle :

Component Type	Function	Typical Range / Notes
LiDAR	3-D mapping & localization; high-resolution point clouds	High resolution, all-weather, ~100–200 m
Millimeter-Wave Radar / RADAR	Obstacle detection and speed estimation	100–200 m, robust in adverse weather
Camera / Optical Sensor	Object detection/classification via CNN; lane & sign recognition	Computationally heavy; affected by lighting

Ultrasonic / Sonar	Short-range object detection, parking assistance	Effective <2 m; poor angular resolution
GNSS / GPS	Vehicle positioning	Used with map and inertial sensors
Inertial Measurement Unit	Acceleration & orientation	Fuses with GPS for localization
Body-Area Sensor Networks	Driver health monitoring	Heart rate, fatigue, biometrics

Table 1. Comparative summary of IoT-sensor components used in smart vehicles.

4.3 Communication Layer :

The Internet of the Internet of the Internet of the Internet. There are four canonical canonical modalities. Vehicular fog computing and multi-access edge computing are assessed as latency-optimizing overlays.

4.4 Learning Algorithm Layer :

Algorithm Family	Representative Models	Application
Supervised Learning	SVM, Random Forest, CNN, MLP/DNN	Object detection, signclassification, takeover decision
Unsupervised / Generative	Autoencoders, RBM, GAN	Anomaly detection, feature compression
Sequence / Recurrent	LSTM, GRU, RNN, Mixture-Deep-LSTM	Traffic-flow prediction, post-accident forecasting
Reinforcement Learning	DQN, DDPG, A3C, PPO, Deep RL	Lane change, overtaking, merging, offloading

Table 2. ML-algorithm families mapping to smart-vehicle tasks.

4.5 Dataset Sources :

Every experiment under examination is supported by public benchmarks. KITTI, Waymo Open, V2V4Real, V2X-Sim, and OPV2V are often used datasets (the latter two are usually produced using the CARLA simulator). Fog/edge offloading models are fed real-world trajectory information, such as taxi GPS traces.

4.6 Computing Frameworks :

For hybrid CNN + LSTM models, TensorFlow is frequently utilized. While CARLA enables 3-D perception situations, SUMO and OMNeT++ are frequently combined for traffic simulation. A lightweight framework for RL training and verification is offered by TORCS.

4.7 Performance Metrics :

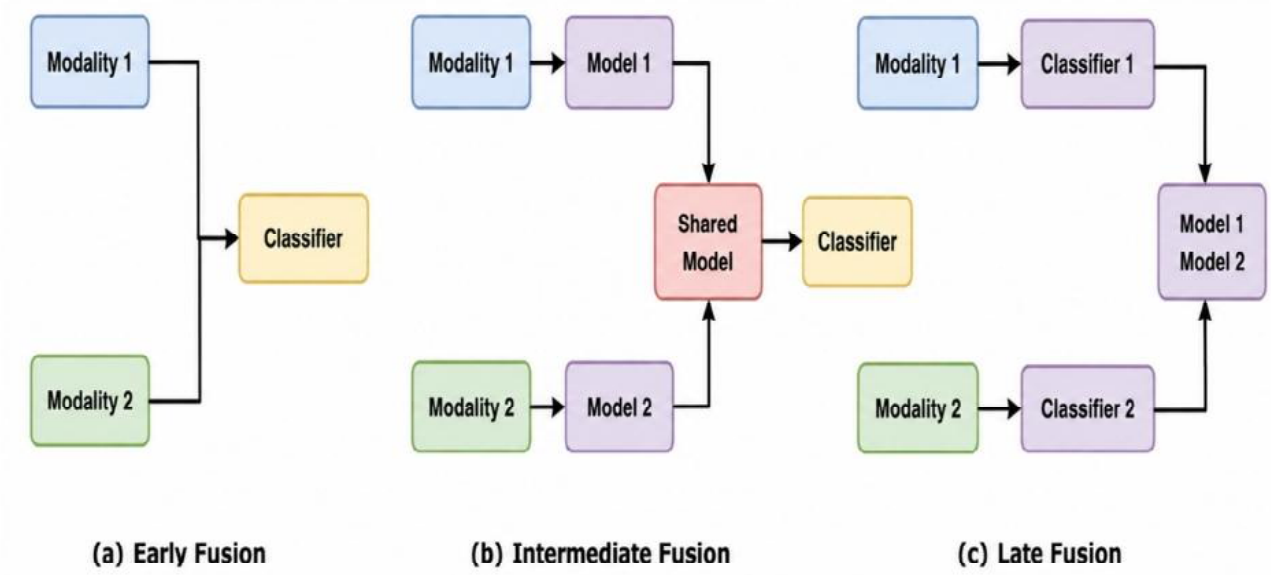
The examined research present the following essential indicators: prediction accuracy, precision, recall, mean absolute percentage error, end-to-end latency, processing delay, service-confidence level, and reinforcement-reward maximisation.

5. Figures and Tables (Data analysis Or Interpretation of Data)

5.1 Figure 2 : Five-Layer IoT Architecture for Smart Vehicles :



5.2 Figure 3 : Multimodal Learning Framework for Sensor Fusion



5.3 Table 3 : Empirical Results of Selected Hybrid Deep-Learning Models

Model	Task	Accuracy	Precision	Recall	Specs
BLSTME + CNN	Traffic-congestion prediction	98%	96%	94%	SUMO + OMNeT++
BLSTME + CNN	Smart-city congestion	98%	96%	94%	TensorFlow
Mixture-Deep-LSTM	Peak hour & post-accident traffic forecasting	—	—	—	Los Angeles data; 30–50% improvement over baselines
RNN + RBM (parallel)	Traffic-congestion evolution, 1-hour forecast	88%	—	—	Computed within <6 minutes using taxi GPS
Distributed CNN + LSTM	Vehicle classification + flow prediction	—	—	—	Edge-cloud splitting

5.4 Table 4 : Latency Performance of Edge / Fog Architectures

Architecture	Reported Improvement	Notes
Priority-based fog + 5G-MEC smart-city VANET	Data latency ↓ 20 %, processing delay ↓ 35 %	Versus cloud-only baseline
AdaptiveFog	Service-confidence ↑ 30 – 50 %	Based on real 5-month LTE measurements
MEC-enabled V2X service placement	Meets 20–50 ms pre-crash warning bound	ETSI / US-DOT requirement
Fog-IoV offloading, M/M/1 queue	Lower average response time	Real-world taxi trajectory validation
Three-layer VFC	Outperforms Min-Min, Max-Min heuristics	Greedy heuristic scheduling

5.5 Table 5 : Reinforcement-Learning Algorithms Used in Autonomous Driving

Algorithm Use-Case	Key Contribution
DQN-based lateral control with safety checker	Lane-keeping under uncertainty
POMDP-DQN lane-change	Partial-observation modelling
Hybrid DQN + rule-based lane change	Combines safety rules with learning
OpenAI Baselines, Unity ML-Agents, RL Coach	RL frameworks for autonomous-driving research
Deep RL	Lane-keeping + overtaking, collision avoidance
Deep RL + MDP	ML-enabled MEC offloading decisions

5.6 Interpretation of Data :

With reported accuracies exceeding 95% under simulation, hybrid CNN-LSTM ensembles routinely beat single-modality baselines on urban traffic forecasting, as seen by the data in Table 3. Joint modelling of normal and accident circumstances is significantly better than single-condition models, as evidenced by the Mixture-Deep-LSTM's 30–50% improvement over traditional baselines. Even more instructive are the latency numbers in Table 4. Offloading strategies need to be priority-aware rather than homogeneous, as evidenced by a 35% decrease in processing latency when fog computing and 5G MEC are coupled. The penalty of neglecting wireless-access variability while constructing latency-sensitive vehicular stacks is shown by the AdaptiveFog result, which shows a 30–50% increase in service confidence. The agreed conclusion is that computational placement (cloud, edge, fog, in-vehicle) is at least as crucial as algorithmic precision for safety-critical judgments.

6. Results and Discussions

6.1 Convergence of IoT and ML is the Core Enabler :

The aforementioned synthesis demonstrates how IoT and ML compliment one another: Large amounts of raw, multi-modal sensor streams are provided by IoT, and machine learning transforms these streams into safe, effective, and predictive judgments. ML and IoT co-evolve most aggressively in the most common ITS subdomains, such as route optimization, parking, and accident detection.

6.2 ML Algorithm Choice is Task-Dependent :

For visual perception, CNNs dominate. They require fine-grained GPU-level inference but excel when supplied with rich datasets such as KITTI, Waymo Open, or V2V4Real. Hybrid CNN + LSTM approaches extend this to temporal scenes.

For traffic forecasting, recurrent architectures achieve the lowest MAPE, particularly for long horizons (30–60 min); for very short horizons (15 min), SVM is sometimes competitive because small data samples limit the discrimination boundary of LSTMs.

For decision-making and control, RL leads to safe and adaptable behaviour without the requirement for vast labelled datasets, addressing the brittleness of supervised techniques when distribution shifts occur.

6.3 Latency is Solved by Geographic Compute Placement :

The 20–50 ms pre-crash warning constraint cannot be met by pure cloud systems. Rather, it may be exploited by using the following the following the following the following methods. AdaptiveFog's 30–50% improvement in service confidence reveals that interaction with the cellular radio is vital.

6.4 Trust, Privacy, and Security are Persistent Bottlenecks :

The initial blockchain-ML method is still a key architectural solution to the centralization issue. In order to balance security and performance, lightweight authentication algorithms have since been adapted to the diversity of in-car embedded platforms. Location privacy, especially for V2P and V2G, and authentication delay in V2I are still open research concerns despite advancements.

6.5 Limitations of Current Evidence :

The majority of quoted performance metrics, such as 98% accuracy, are acquired in simulation settings (SUMO, OMNeT++, CARLA, TORCS). Transferability is constrained by the established simulation-to-reality gap. Furthermore, public road may appear to appear to be biased road.

7. Recommendation :

Based on the synthesis above, the following recommendations are offered to automotive manufacturers, and policy-makers:

1. **Adopt multi-modal sensor-fusion architectures.** For safety-grade autonomy, a single

sensor—such as a camera, LiDAR, radar, or sonar is inadequate. Standardized datasets should be used to benchmark hybrid early, intermediate, and late-fusion designs.

2. **Deploy federated, edge-resident ML.** Given that 90% of vehicular data are likely to remain local due to privacy and bandwidth constraints, federated learning and edge inference should be preferred over centralised cloud training wherever feasible.
3. **Prioritise reinforcement learning with safety constraints.** End-to-end supervised learning requires a lot of data and is challenging to certify. Traceable and verifiably safe behaviour is provided by constrained-RL frameworks (e.g., DQN + safety-checker, DRL with rule-based merging).
4. **Standardise latency-aware compute placement.** Use Adaptive Fog-style cross-layer optimisation and priority-based VFC scheduling to bind the end-to-end latency to the strict 20–50 ms bound required for crash avoidance.
5. **Integrate lightweight blockchain authentication.** A reliable route to integrity without taxing embedded processors is provided via lightweight consensus on top of ML-based anomaly detection.
6. **Promote shared datasets and benchmarking.** Corner situations (weather extremes, atypical pedestrian behaviour, road works) should be covered by initiatives like KITTI, Waymo Open, V2V4Real, V2X-Sim, and OPV2V.
7. **Investigate explainable AI for AV certification.** Hybrid causal-probabilistic models should be investigated since probabilistic outputs impede certification.

8. Conclusion :

This research has presented a comprehensive review of the IoT components and machine-learning algorithms that power modern smart vehicles. The perception layer, comprising LiDAR, radar, cameras, ultrasonic sensors, GPS, and IMUs, provides the raw data substrate required for situational awareness. The network layer, through V2X communication standards and 5G/6G mobile systems, enables low-latency multi-agent information exchange. The intelligence layer imposes machine-learning algorithms CNNs for perception, LSTMs and Mixture-Deep-LSTM for forecasting, RL for control onto this data substrate, delivering accuracies as high as 98% in congestion prediction and 30–50% forecasting gains over classical baselines. The application layer exposes these capabilities as infotainment, ADAS,

traffic-management, and emergency-response services.Empirical results consolidate a clear case for geographic compute placement: edge/fog architectures deliver measurable latency reductions (20–35%) and service-confidence improvements (30–50%), making safety-critical V2X services feasible at cloud levels alone. Reinforcement-learning frameworks particularly DQN with safety constraints provide interpretable and verifiable models for autonomous control. Security and privacy remain the most pressing open issues: lightweight authentication, blockchain-supported integrity, and federated ML are promising directions.Future research must address (a) the simulation-to-reality gap in RL training; (b) causal-XAI integration for safety certification; (c) ubiquitous connectivity via 6G for V2X; and (d) lifecycle management of privacy-preserving vehicular big data. As IoT instrumentation and ML inference co-evolve, the realisation of fully-autonomous, safe, and sustainable smart transportation is increasingly a matter of integrated engineering rather than isolated algorithmic breakthroughs.

References :

1. (Dogra & Kaur, 2022) Moving towards smart transportation with machine learning and Internet of Things: a review. Int. J. Syst. Assur. Eng. Manag.
2. (Fayyad et al., 2020) Deep Learning Sensor Fusion for Autonomous Vehicle Perception and Localization: A Review. IEEE Access.
3. (Alkashto&Elewi, 2024) Integration of blockchain and machine learning for safe and efficient autonomous car systems: A survey. Journal of King Saud University — Computer and Information Sciences.
4. (Ušinskis et al., 2024) Towards Autonomous Driving: Technologies and Data for Vehicles-to-Everything Communication. Sensors.
5. (Liu et al., 2024) CrowdTransfer: Enabling Crowd Knowledge Transfer in AIoT Community. ACM Computing Surveys.
6. (Zantalis et al., 2019) A Review of Machine Learning and IoT in Smart Transportation. Future Internet.
7. (Oladimeji et al., 2023) Smart Transportation: An Overview of Technologies and Applications. Sensors.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 64-68

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

संस्कृत में नवाचार : परम्परा से प्रौद्योगिकी तक

डॉ. वर्षा रानी
असि. प्रो. संस्कृत विभाग,
डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा।



संस्कृत विश्व की प्राचीनतम एवं वैज्ञानिक भाषाओं में से एक है। यह केवल धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रन्थों की भाषा नहीं, बल्कि भारतीय ज्ञान–परम्परा की आधारशिला भी है। आधुनिक युग में सूचना प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), संगणकीय भाषाविज्ञान (Computational Linguistics), डिजिटल मानविकी तथा नवशिक्षण पद्धतियों के विकास ने संस्कृत के अध्ययन–अध्यापन एवं अनुसंधान को नई दिशा प्रदान की है। संस्कृत में नवाचार का तात्पर्य केवल नवीन विषयों की अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि परम्परागत ज्ञान को आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाजोपयोगी बनाना भी है। प्रस्तुत शोध आलेख में संस्कृत में नवाचार की अवधारणा, उसके विविध आयाम, डिजिटल तकनीक के साथ उसका समन्वय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में संस्कृत की भूमिका, शिक्षण–पद्धतियों में नवाचार तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है। वर्तमान समय में संस्कृत केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य की प्रौद्योगिकी और ज्ञान–विज्ञान की भाषा के रूप में भी उभर रही है।

1. प्रस्तावना :

संस्कृत भाषा भारतीय सभ्यता और संस्कृति की आत्मा मानी जाती है। वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, पुराण, आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, व्याकरण तथा दर्शन जैसे विशाल ज्ञान–साहित्य का सृजन संस्कृत में हुआ है। संस्कृत का व्याकरणिक ढाँचा अत्यन्त व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक है, जिसका निर्माण महर्षि पाणिनि ने किया। आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों और संगणक वैज्ञानिकों ने संस्कृत की संरचना को कम्प्यूटर प्रसंस्करण के लिए अत्यन्त उपयुक्त माना है।

21वीं शताब्दी में जब शिक्षा, अनुसंधान और संचार के क्षेत्र में डिजिटल क्रान्ति आई, तब संस्कृत के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार हेतु अनेक नवाचार प्रारम्भ हुए। आज संस्कृत पाण्डुलिपियों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन शिक्षण, मशीन अनुवाद, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुप्रयोग, ई–कोश निर्माण तथा डिजिटल शोध मंच संस्कृत अध्ययन को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा रहे हैं।

2. नवाचार की अवधारणा :

नवाचार (Innovation) का अर्थ है– नवीन विचारों, तकनीकों अथवा पद्धतियों का सृजनात्मक प्रयोग। संस्कृत के संदर्भ में नवाचार का आशय उन प्रयासों से है जिनके माध्यम से संस्कृत भाषा, साहित्य और

ज्ञान–परम्परा को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जाए।

संस्कृत में नवाचार के प्रमुख उद्देश्य हैं –

1. संस्कृत को जनसामान्य तक पहुँचाना।
2. आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जोड़ना।
3. प्राचीन ज्ञान को डिजिटल रूप में संरक्षित करना।
4. शिक्षण–पद्धतियों को प्रभावी बनाना।
5. शोध एवं नव–अनुसंधान को प्रोत्साहित करना।

3. संस्कृत और डिजिटल प्रौद्योगिकी :

डिजिटल युग ने संस्कृत के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किए हैं। आज हजारों संस्कृत ग्रन्थों को डिजिटल स्वरूप में संरक्षित किया जा रहा है। डिजिटल पुस्तकालयों एवं ऑनलाइन डेटाबेसों ने शोधकर्ताओं को वैश्विक स्तर पर सामग्री उपलब्ध कराई है।

3.1 पाण्डुलिपियों का डिजिटलीकरण :

भारत में लाखों संस्कृत पाण्डुलिपियाँ विभिन्न पुस्तकालयों और संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। इन पाण्डुलिपियों को डिजिटल माध्यम से संरक्षित करने के लिए अनेक परियोजनाएँ संचालित की जा रही हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित इमेज प्रोसेसिंग तथा मल्टीस्पेक्ट्रल तकनीकों के माध्यम से क्षतिग्रस्त पाण्डुलिपियों को पुनः पठनीय बनाया जा रहा है।

3.2 डिजिटल शब्दकोश एवं ई–कोश :

संस्कृत के अनेक कोश अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। डिजिटल शब्दकोशों के माध्यम से शब्दार्थ, व्युत्पत्ति तथा प्रयोग सम्बन्धी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकती है। इससे शोध एवं शिक्षण दोनों में सुविधा हुई है।

3.3 ई–लर्निंग प्लेटफॉर्म :

ऑनलाइन कक्षाओं, मोबाइल अनुप्रयोगों तथा डिजिटल पाठ्यक्रमों के माध्यम से संस्कृत शिक्षा वैश्विक स्तर पर सुलभ हो रही है। वीडियो व्याख्यान, इंटरैक्टिव अभ्यास तथा आभासी कक्षाएँ संस्कृत शिक्षण में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला रही हैं।

4. संगणकीय भाषाविज्ञान और संस्कृत :

संगणकीय भाषाविज्ञान (Computational Linguistics) भाषा और कम्प्यूटर विज्ञान का समन्वित क्षेत्र है। संस्कृत की व्याकरणिक संरचना इसे इस क्षेत्र के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में संस्कृत और संगणकीय भाषाविज्ञान के संयुक्त अनुसंधान चल रहे हैं। इन संस्थानों में व्याकरण परीक्षक, रूपविश्लेषक, मशीन अनुवाद प्रणाली तथा भाषा संसाधन उपकरण विकसित किए जा रहे हैं।

4.1 रूपविश्लेषण (Morphological Analysis)

संस्कृत शब्दों की जटिल संरचना का विश्लेषण करने हेतु कम्प्यूटर आधारित उपकरण विकसित किए गए हैं। ये उपकरण शब्द के धातु, प्रत्यय, विभक्ति एवं लिंग की पहचान कर सकते हैं।

4.2 सन्धि-विच्छेद एवं समास विश्लेषण :

सन्धि एवं समास संस्कृत की प्रमुख विशेषताएँ हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित मॉडल अब सन्धि–विच्छेद तथा समास विश्लेषण में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त कर रहे हैं।

4.3 मशीन अनुवाद :

संस्कृत से हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद हेतु अनेक परियोजनाएँ संचालित हैं। इससे संस्कृत साहित्य का वैश्विक प्रसार सम्भव हो रहा है।

5. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और संस्कृत :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) वर्तमान युग की सबसे प्रभावशाली तकनीक है। संस्कृत की नियमबद्ध संरचना AI अनुसंधान के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है।

पाणिनीय व्याकरण का सूत्रात्मक ढाँचा कम्प्यूटर एल्गोरिद्म के समान कार्य करता है। यही कारण है कि संस्कृत को प्राकृतिक भाषा संसाधन (NLP) के क्षेत्र में विशेष महत्त्व दिया जा रहा है।

5.1 संस्कृत आधारित AI मॉडल :

हाल के वर्षों में संस्कृत के लिए विशेष भाषा मॉडल विकसित किए गए हैं, जिनमें SansGPT उल्लेखनीय है। यह संस्कृत पाठों के विशाल संग्रह पर प्रशिक्षित मॉडल है जो भाषा संसाधन कार्यों में उपयोगी सिद्ध हो रहा है।

5.2 संस्कृत और NLP :

NLP तकनीक के माध्यम से संस्कृत पाठों का विश्लेषण, वर्गीकरण, सार–संक्षेपण तथा प्रश्नोत्तर प्रणाली विकसित की जा रही है।

5.3 ज्ञान-आधारित AI :

संस्कृत साहित्य में निहित नैतिक, दार्शनिक एवं वैज्ञानिक ज्ञान को AI प्रणालियों में समाहित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

6. संस्कृत शिक्षण में नवाचार :

पारम्परिक शिक्षण पद्धति के साथ आधुनिक तकनीकों के समन्वय ने संस्कृत शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया है।

6.1 गेम आधारित शिक्षण :

AI और गेमिंग तकनीक का उपयोग करके संस्कृत शिक्षण को रोचक बनाया जा रहा है। विद्यार्थियों को खेल–खेल में संस्कृत व्याकरण एवं शब्दावली सिखाने वाले प्लेटफॉर्म विकसित हुए हैं।

6.2 स्मार्ट कक्षाएँ :

डिजिटल बोर्ड, मल्टीमीडिया प्रस्तुतीकरण, ऑडियो–वीडियो सामग्री एवं आभासी प्रयोगशालाएँ संस्कृत शिक्षण को आकर्षक बना रही हैं।

6.3 MOOCs एवं ऑनलाइन पाठ्यक्रम :

विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संस्कृत के ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे वैश्विक स्तर पर विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

7. भारतीय ज्ञान परम्परा और संस्कृत नवाचार :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय ज्ञान परम्परा को शिक्षा प्रणाली का महत्त्वपूर्ण अंग बनाया है। संस्कृत के माध्यम से आयुर्वेद, योग, गणित, वास्तुशास्त्र, खगोलशास्त्र तथा दर्शन के अध्ययन को प्रोत्साहन मिल रहा है।

7.1 आयुर्वेद एवं चिकित्सा :

चरकसंहिता और सुश्रुतसंहिता जैसे ग्रन्थों का डिजिटल अध्ययन आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान में सहायक सिद्ध हो रहा है।

7.2 योग और मानसिक स्वास्थ्य :

संस्कृत ग्रन्थों में वर्णित योग–दर्शन को आधुनिक जीवनशैली और मानसिक स्वास्थ्य से जोड़कर नए शोध किए जा रहे हैं।

7.3 गणित एवं खगोल विज्ञान :

भास्कराचार्य एवं आर्यभट्ट जैसे विद्वानों के ग्रन्थों का पुनर्पाठ आधुनिक विज्ञान के इतिहास और विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

8. संस्कृत में नवाचार की चुनौतियाँ :

यद्यपि संस्कृत के क्षेत्र में अनेक नवाचार हुए हैं, तथापि कुछ चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं –

1. संस्कृत विशेषज्ञों एवं तकनीकी विशेषज्ञों के बीच समन्वय का अभाव।
2. पर्याप्त डिजिटल संसाधनों की कमी।
3. वित्तीय एवं संस्थागत सहयोग की सीमाएँ।
4. युवा पीढ़ी में संस्कृत के प्रति सीमित रुचि।
5. मानकीकरण एवं तकनीकी शब्दावली की समस्या।

9. भविष्य की संभावनाएँ :

संस्कृत में नवाचार की संभावनाएँ अत्यन्त व्यापक हैं।

- संस्कृत आधारित चौटबॉट और वर्चुअल सहायक।
- AI आधारित संस्कृत अनुवाद प्रणाली।
- डिजिटल पाण्डुलिपि पुनर्निर्माण।
- वाणी से पाठ (Speech-to-Text) तकनीक।
- संस्कृत ज्ञान–आधारित विशेषज्ञ प्रणालियाँ।
- वैश्विक स्तर पर संस्कृत शोध नेटवर्क का निर्माण।

यदि संस्कृत को आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से निरन्तर जोड़ा जाता रहा, तो यह भाषा भविष्य में ज्ञान–विज्ञान के वैश्विक विमर्श में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

उपसंहार :

संस्कृत में नवाचार वर्तमान समय की आवश्यकता है। संस्कृत केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का आधार भी है। डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संगणकीय भाषाविज्ञान तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों ने संस्कृत को नई ऊर्जा प्रदान की है। पाणिनीय व्याकरण की वैज्ञानिकता, संस्कृत

साहित्य की ज्ञानसम्पदा तथा आधुनिक तकनीकों का समन्वय इस भाषा को पुनः वैश्विक महत्त्व प्रदान कर सकता है। अतः आवश्यक है कि सरकार, शिक्षण संस्थान, शोधकर्ता एवं समाज मिलकर संस्कृत नवाचार को प्रोत्साहित करें, जिससे भारतीय ज्ञान परम्परा का संरक्षण एवं संवर्धन हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची :

1. पाणिनि – अष्टाध्यायी, चौखम्बा संस्कृत संस्थान, वाराणसी।
2. कपिलदेव द्विवेदी – संस्कृत साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, विश्वविद्यालय प्रकाशन।
3. वाचस्पति गैरोला – संस्कृत साहित्य का इतिहास, चौखम्बा विद्याभवन।
4. बलदेव उपाध्याय – संस्कृत साहित्य का इतिहास, शारदा निकेतन।
5. सत्यव्रत शास्त्री – संस्कृत और आधुनिकता, नई दिल्ली।
6. Pollock, Sheldon. The Language of the Gods in the World of Men.
7. Rajib Sinha, Sanskrit in the Digital Era: Challenges and Opportunities Ahead.
8. Tanmayi Maharana, The Pâninian Code: Sanskrit's Renaissance in Digital Technology.
9. Vivek Pathak, Artificial Intelligence and Sanskrit: The Role of Computational Linguistics.
10. Chaudhari et al., SansGPT: Advancing Generative Pre-Training in Sanskrit.
11. Pawan Goyal et al., SanskritShala: A Neural Sanskrit NLP Toolkit.
12. दिल्ली विश्वविद्यालय, Computational Linguistics Research and Development Lab रिपोर्ट।
13. IIT खड़गपुर, Sanganaka Sanskrit Computational Research Lab.

Mail : vasu14rani@gmail.com

Mob – 9671904323

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 69-78

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

A POLITICAL AND CONSTITUTIONAL STUDY OF MULTICULTURALISM IN INDIA WITH REFERENCE TO THE SIXTH SCHEDULE

Tina Kimngaiting Vaiphei
PhD Scholar, Department of Political Science,
University of Delhi, Delhi
Amy Nemchanpha Vaiphei
PhD Scholar, Department of Sociology,
North-Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya

ABSTRACT :

India has long been recognised as a unique civilisational mosaic, embodying a diversity of languages, religion, ethnicities, and cultural traditions. The Indian Constitution was adopted as a moral and political document ensuring the coexistence of this diversity under the guiding principles of secularism, equality, and fraternity. Articles 14 to 30 safeguards cultural, religious, and linguistic freedoms, while the Preamble envisions India as a "sovereign, socialist, secular, democratic, republic." The Sixth Schedule, to protect the distinct social, cultural, and political practices of tribal communities in the North-Eastern region, serves as a significant constitutional instrument for accommodating diversity within the framework of the Indian Union. This paper examines how these protections contribute to India's broader multiculturalism with reference to the Sixth Schedule in managing ethnic diversity, political autonomy, and regional aspirations.

KEYWORDS : multiculturalism, federalism, secularism, asymmetrical federalism, ethnic conflict, nation-building, identity politics.

INTRODUCTION :

India's federal framework has long functioned as an instrument of accommodation for its vast cultural, religious, and linguistic diversity. Through constitutional mechanisms such as the Fifth and Sixth Schedules, special provisions under Article 371, and the principle of asymmetrical federalism,

India has sought to manage and celebrate its multicultural composition. The intersection between multiculturalism and federalism is sometimes in between promise and peril. While inclusive federal arrangements can contribute to nation-building by granting recognition and autonomy to marginalised communities, divisive identity politics and ethnic clashes, from the Gujarat riots (2002) to the debates around the Citizenship Amendment Act (2019) may challenge the secular and integrative feature of the Indian Union. This paper explores how India's multiculturalism within its federal structure, identifies the challenges posed by communal polarisation, and proposes ways to strengthen secular and inclusive governance in the post-2014 political climate.

India's federal framework and its deeply multicultural society present one of the most diverse experiments in democratic coexistence. Federalism in India has been not only a system of governance but a mechanism for accommodating the country's immense ethnic, linguistic, and religious diversity. The relationship between multiculturalism and Indian federalism represents both the potential for nation-building through diversity and the risk of nation fragmentation. India is a melting pot of cultures, an embodiment of pluralism that harmonizes differences within a single national identity. The Constituent Assembly debates of 1946–49 reflected it vividly. Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, and Sardar Patel envisioned a nation that would celebrate diversity. The Constitution drafted institutionalized this vision by embedding multicultural principles across its Fundamental Rights and Directive Principles.

India's sociopolitical landscape is marked by unparalleled cultural, linguistic, and religious pluralism. From the Himalayas to Kanyakumari, the Indian subcontinent embodies multiple faiths, and languages that coexist within one nation-state. In theoretical terms, multiculturalism is defined as the recognition and institutional accommodation of cultural differences within liberal democracies. Kymlicka's notion of "multicultural citizenship" emphasizes how minority rights are essential for achieving substantive equality in diverse societies. Parekh's framework of "multiculturalist ethics" argues that diversity must be embraced as a positive resource for moral and civic learning rather than as a threat to cohesion. In India, these theories find practical expression in constitutional provisions such as linguistic autonomy, religious freedom, and asymmetric federal arrangements. However, Indian multiculturalism is also under constant strain. The challenge, therefore, lies in maintaining a balance between diversity and unity between call nation-building and nation fragmentation tendencies (Saxena, 2011; Kothari, 1989).

The Indian model of secularism differs from its Western counterpart. Rather than having a strict wall of separation between religion and state, it adopts what Rajeev Bhargava (1998) calls "principled distance." This model acknowledges the pervasive role of religion in Indian society while

ensuring that no particular faith dominates public life. The Sixth Schedule allows for the establishment of Autonomous District Councils (ADCs) in tribal areas of the Northeast to protect their customary laws and traditional governance systems.

However, the reality of India's multiculturalism is more complex. While the Constitution promotes inclusivity, several instances reveal patterns of exclusion and conflict. The celebration of cultural festivals and ethnic diversity coexists with rising intolerance and religious polarization. The recent surge in majoritarian politics which privileges cultural identity over others poses a fundamental challenge to the pluralist foundations of the Indian state. This paradox forms the central concern: how a country founded on secular and multicultural ideals is witnessing the ascendancy of majoritarianism in its political and social life.

1. THEORITICAL FOUNDATION OF MULTICULTURALISM :

Will Kymlicka (1995) defines multiculturalism as a framework for recognizing and protecting the cultural rights of minority groups within liberal democracies. In Multicultural Citizenship, he distinguishes between polyethnic rights, special representation rights, and self-government rights. According to Kymlicka, multiculturalism is essential for achieving substantive equality in societies marked by historical inequalities between dominant and minority cultures.

According to Charles Taylor (1994) multicultural theory, the concept of "politics of recognition", he argues that acknowledging diverse cultural identities within a political framework strengthens, rather than weakens, the sense of belonging in a democratic nation-state. Bhikhu Parekh (2000) asserts that multiculturalism is not a threat to unity but a means to create a richer, more inclusive conception of national identity.

1.1 FEDERALISM AS A FRAMEWORK FOR MULTICULTURAL ACCOMODATION :

Federalism is often described as a system that divides powers between a central authority and constituent units to accommodate diversity while maintaining unity **(Elazar, 1987)**. In multicultural societies, federal structures become mechanisms for managing identity-based conflicts and ensuring political representation. **Alfred Stephan (1999)** introduced the concept of "holding-together federalism"where the federal design aims to prevent disintegration in highly diverse societies. India exemplifies this type of federalism, using decentralization to contain ethnic and linguistic tensions.

Rekha Saxena (2011) emphasizes that Indian federalism is both multilayered and asymmetrical. The Indian Constitution grants special provisions to states with distinct cultural or historical identities for example, Articles 370, 371, and the Sixth Schedule. These asymmetries illustrate India's attempt to balance national integration with regional autonomy, a feature that Kymlicka's advocates for group-differentiated rights within a liberal democracy.

1.2 MULTICULTURALISM AND FEDERALISM IN INDIAN CONTEXT :

Rajeev Bhargava (1998), Gurpreet Mahajan (2002), and **Rekha Saxena (2011)** have conceptualized India as a "multicultural federation." The federal design allows for plural identities to coexist under a single constitutional framework. **Bhargava (2008)** highlights India's concept of "principled distance", a secular model that respects religious and cultural diversity without strict separation or dominance of one group.

But in practice we see that India's federal system provides the institutional architecture for managing diversity through shared sovereignty. States like Nagaland, Mizoram, and Jammu & Kashmir before 2019 were granted special constitutional protections for their distinct cultural and religious practices. These examples demonstrate that India's federalism is designed to preserve multiculturalism, though political centralization and uneven development sometimes challenge this balance.

1.3 ACCOMMODATING CULTURAL DIVERSITY IN INDIAN FEDERALISM :

India's federal system was designed as a mechanism of inclusion rather than exclusion. The Constitution of 1950 embeds multicultural accommodation through multiple layers of recognition. The Fifth Schedule provides for the administration and protection of Scheduled Areas, empowering Governors to regulate land transfers and protect tribal autonomy (Government of India, 2020). The Sixth Schedule, applicable to Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram goes by granting legislative, executive, and judicial powers to Autonomous District Councils. These councils in Meghalaya, Mizoram, and Assam exemplify institutionalized multiculturalism, allowing local tribes to govern their affairs in accordance with traditional customs **(Saxena, 2019)**.

Beyond these schedules, India's linguistic reorganization of states in 1956 marked a historic shift of multicultural accommodation. By reorganizing state boundaries along linguistic lines, India transformed potential secessionist movements into cooperative federal units. The recognition of 22 official languages in the Eighth Schedule of the Constitution further exemplifies the pluralist vision underlying Indian federalism **(Bhattacharyya, 2018)**. Such arrangements is in effect with Kymlicka's notion that recognizing minority cultures within federal structures can strengthen, rather than weaken, the state by embedding diverse identities within a shared constitutional framework **(Kymlicka, 1995)**.

Affirmative action policies also serve as multicultural instruments. Reservations for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes in education, employment, and politics institutionalize cultural justice with Article 29 and 30 guaranteeing cultural and educational rights to minorities. Together, these constitutional provisions embody what **Bhargava (1998)** calls "principled distance", maintains neutrality while acknowledging religious and cultural pluralism.

ETHNIC AND COMMUNAL CONFLICTS : FROM GUJARAT 2002 to CAA 2019 :

Despite the institutional safeguards, India's multicultural compact has been repeatedly tested by ethnic and religious conflicts. The Gujarat riots of 2002 remain a watershed moment in India's post-independence history. Triggered by the burning of a train in Godhra, which killed 58 Hindu pilgrims, the ensuing violence led to the deaths of over 1,000 people (mostly Muslims) and displacement of tens of thousands (Government of India, 2002; Human Rights Watch, 2003). The National Human Rights Commission (2003) noted "serious failure of state machinery" in controlling the violence. Beyond its immediate human cost, the Gujarat riots symbolized a profound breakdown of India's secular federal dynamic, wherein a state government appeared to align with majoritarian sentiments rather than constitutional neutrality (Jaffrelot, 2021).

The Citizenship Amendment Act (CAA) introduced religion as a criterion for citizenship for the first time in India's constitutional history. By providing citizenship to non-Muslim minorities from Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan, the Act was perceived as discriminatory against Muslims (Jayal, 2020). The CAA triggered nationwide protests, particularly in Assam and the Northeast, where ethnic groups feared that large scale migration would alter local demographics and threaten indigenous rights protected under the Sixth Schedule (Baruah, 2020). Several state governments of Kerala, Punjab, and West Bengal, publicly declared their refusal to implement the Act, marking significant moment of federal dissent in contemporary India (Saxena, 2020).

Data from the National Crime Records Bureau (NCRB, 2022) indicate that communal incidents in India have fluctuated but remain a persistent issue, with states like Uttar Pradesh, Bihar, and Maharashtra recording the highest numbers. According to NCRB's Crime in India reports, incidents of communal violence rose from 703 in 2014 to 822 in 2017 before stabilizing around 700 annually. These figures, while relative to India's population, underscore a troubling persistence of religious polarization. Such conflicts not only cause human suffering but also destabilize centre–state relations by drawing federal institutions into politically charged law and order crises.

ETHNIC CLEAVAGES AND THEIR IMPACT ON FEDERALISM POST-2014 :

The post-2014 political landscape has reshaped the contours of Indian federalism. The rise of a central government under the BJP has led to what has been described as a "centripetal shift," wherein the Centre's dominance over state governments has intensified. This trend is particularly visible in policies with cultural or religious undertones such as the CAA, the abrogation of Article 370 in Jammu and Kashmir (2019), and uniform national education policies that centralize authority over matters traditionally under state jurisdiction.

These developments have produced two contrasting tendencies. On one hand, the Centre asserts

that such policies strengthen nation-building by promoting uniform citizenship and a singular national identity. On the other hand, critics argue that they undermine the federal compact by ignoring regional, ethnic, and religious specificities (Bhattacharya, 2018). The removal of Jammu and Kashmir's special status, for example, was viewed by many as a violation of asymmetrical federalism, diluting trust among other states with special constitutional protections (Jaffrelot, 2021).

In the Northeast, ethnic tensions linked to identity and migration have re-emerged, illustrating how local autonomy mechanisms under the Sixth Schedule remain vital and fragile. While autonomous councils offer political voice to tribal groups, inadequate fiscal devolution and administrative overlap often limit their efficacy (Saxena, 2019). The Fifth Schedule areas, home to India's largest tribal populations, continue to face resource exploitation and cultural marginalization despite constitutional safeguards (Government of India, 2020).

AN OVERVIEW :

While the appointment of a tribal woman, Droupadi Murmu, as the President of India is symbolically significant, it contrasts sharply with the persistent neglect of tribal autonomy in states like Manipur and Mizoram. In Manipur, tensions between the Kuki and Meitei communities in 2023 highlights the fragility of India's multicultural equilibrium. While some critics once feared that granting autonomy would encourage separatism, the denial of such autonomy has produced the very instability it sought to prevent.

Religion has always been a driving force in India. A cohesive nation-building out of manifold, complex diversity is hand in hand with extremes of social and economic inequalities. When compared with most of other post-colonial countries, India's prioritizes on multiculturalism, India can still be taken as a "classic example that unity and diversity can be reconciled". Against the background of globalization and ever growing social and economic disparities, an adequate and effective developmental and social policy is of importance for keeping unity and diversity together.

Thus, the core issue is not India's constitutional design but the dilution of its multicultural principles through selective governance and politicisation of identity. The challenge is to reconcile constitutional secularism with the growing assertiveness of majoritarian nationalism. The Indian Constitution's multiculturalism is not a mere theoretical aspiration but a lived principle embedded in law, language, and federalism. Linguistic reorganization of states in 1956 was a landmark recognition of cultural diversity, affirming that linguistic identity could coexist with national unity (Austin, 1999).

THE SIXTH SCHEDULE : A UNIQUE FEATURE OF INDIAN CONSTITUTION :

The Sixth Schedule has empowered tribal communities by granting them autonomous district council and regional councils, which allows them to preserve their traditional institutions, cultural

practices and customary self- governance.It has enabled these councils to control land, forests and natural resources preventing indiscriminate transfer of tribal land to outsiders and thereby safeguarding the economic rights and territorial integrity of indigenous communities. It has been instrumental in improving local administration and served as a framework for inclusive development allowing tribal groups to make governance responsive and promote grassroots participation and protecting tribal identity while also integrating with the broader democratic structure of government.

The Sixth Schedule offers a constitutional guideline of autonomy, which is sometime limited because financial and political reliance on the state government limits its execution. As much as the Sixth Schedule helps in preserving the federal integrity of India, it has given space for ethnic conflicts and political fragmentation. The success of the Sixth Schedule lies in the capacity of the administration, democratic governance, and the fair inclusion of the minorities into the autonomous regions. Increased fiscal autonomy of ADCs is positively associated with better development outcomes and security to people. Balancing between customary laws and constitutional values promotes inclusivity and gender representation in society. Proper implementation of asymmetric federalism enhances national unity due to tolerance of regional diversity.The ADCs having a distinct fiscal autonomy and clear mechanisms of local revenue collection will show significantly better development indicators compared to fiscally dependent ADCs. Where ADCs institutionalize the processes to balance customary law and the constitutional norms, e.g. gender inclusion provisions, social outcomes like the health of women and their education is enhanced.

The Sixth Schedule of the Indian Constitution remains a constitutional framework in accommodating diversity through federalism. Its constitutional design reflects an enduring faith through inclusion. The Sixth Schedule endures and it embodies the spirit of the Constitution, a spirit that values pluralism within unity. It provides a framework that can evolve with India's democracy, provided it is renewed through reforms and constitutional processes. India's federal democracy fulfill a larger extent of its constitutional feature of federal structure as it Sixth Schedule preserves social and legal autonomy. The recognition of customary laws particularly in matters of marriage, inheritance, village administration, and dispute resolution reflects a multicultural legal philosophy. Instead of imposing a uniform legal code, the Indian Constitution allows tribal communities to follow their traditional systems of justice.

The Sixth Schedule contributes to what scholars call "deep diversity," a form of multiculturalism that goes beyond symbolic recognition and instead creates meaningful power-sharing arrangements. The Autonomous District Councils have the power to levy taxes, regulate markets, establish educational institutions, and manage local resources. These economic and administrative powers are essential

for self-governance and demonstrate an institutional recognition of tribal agency. The tribal populations covered under the Schedule constitute minorities within their respective states but possess distinct cultural identities that require preservation. As a result, the Sixth Schedule provides group-specific protections, embodying the normative belief that equality sometimes requires differential treatment. The Sixth Schedule can be understood as a constitutional device for safeguarding minority rights by giving indigenous communities the authority to control cultural reproduction, land relations, and social organization.

The Sixth Schedule also fosters multiculturalism by reducing conflict and promoting peaceful coexistence. Conflicts in the North-East often arise from fears of cultural and demographic dilution. By creating institutional guarantees for cultural preservation, the Sixth Schedule reduces conflicts related to assimilation, loss of control over land, and political marginalization. It provides a framework within which tribal communities can coexist with other groups while retaining their distinctiveness. This asserts with Bhikhu Parekh's argument that a multicultural society must build trust among communities by ensuring that minority groups feel secure about their cultural future. The autonomous councils ensure such security by constitutionally embedding tribal authority.

The significance of the Sixth Schedule becomes even clearer when contrasted with regions where similar protections do not exist. Tribal communities outside the Sixth Schedule areas too faced discrimination, cultural erosion, and political marginalization despite the existence of the Fifth Schedule. This difference highlights the strength of the Sixth Schedule as a multicultural instrument: it creates foundational institutions of self-governance that enable indigenous communities to resist exploitative forces. By providing legislative, executive, and fiscal powers, the Sixth Schedule gives tribal groups substantive control over their social and economic development. This institutional empowerment reflects the multicultural belief that marginalized communities must have not only cultural recognition but also political power and economic autonomy.

The Sixth Schedule strengthens India's multicultural constitutional identity by demonstrating the importance of recognition of autonomy. The Indian state, through this Schedule, acknowledges that cultural differences may require differentiated governance models. The recognition of autonomous councils, customary laws, and community control over resources illustrates the constitutional commitment to "unity in diversity," not as a mere slogan but as a governing principle. It reflects a vision of nationhood that accepts diverse cultural pathways and recognizes that indigenous communities are not peripheral populations but integral participants in India's democratic life.

The linkage between multiculturalism and the Sixth Schedule of the Indian Constitution is both strong and deliberate. The Sixth Schedule is not merely an administrative provision, it is a

constitutional embodiment of multicultural principles that seek to protect, preserve, and empower indigenous tribal communities. By granting self-governance, recognizing customary law, protecting land rights, and enabling political representation, the Sixth Schedule operationalizes the normative ideals of multiculturalism in the Indian context. It ensures that tribal minorities are not subjected to assimilationist pressures or political marginalization. Instead, it offers them structural autonomy to sustain their cultural identities while participating in the broader constitutional framework of India. In doing so, the Sixth Schedule contributes meaningfully to the Indian experiment of building a pluralistic and inclusive multicultural society. Its institutional arrangements represent a deep commitment to pluralism, minority rights, and the recognition of autonomy, thus forming one of the strongest constitutional linkages between multicultural theory and governance.

CONCLUSION :

Multiculturalism in India is both a civilizational inheritance and a constitutional principle. The framers of the Indian Constitution envisioned a Republic that would reconcile unity with diversity, law with culture, and secularism with spirituality. This vision remains embedded in the Preamble and the Fundamental Rights. India must reaffirm the principles of constitutional secularism and asymmetrical federalism. The implementation of the Sixth Schedule, protection of minority rights, and depoliticization of citizenship are essential steps toward a truly multicultural polity.

India has always been in its ability to weave differences into unity. The challenge today is to ensure that the foundation of diversity are held in principle and practice. By holding to the principle in multiculturalism can India remain faithful to the constitutional promise of equality, fraternity, and liberty for all. India's experience demonstrates both the resilience and fragility of multicultural federalism. Through its asymmetrical structures, constitutional protections, and secular features, India has successfully accommodated immense diversity for over seven decades. Multiculturalism and federalism in India are deeply intertwined in a symbiotic relationship. In fact, India's federal structure has largely succeeded in transforming diversity into an asset for nation-building. The future of Indian democracy depends on revitalizing federal pluralism, decentralizing power, and reaffirming the constitutional framework of democracy.

REFERENCES :

- Austin, G. (1999). *Working a democratic constitution: The Indian experience.* Oxford University Press.
- Barry, B. (2001). *Culture and Equality: An Egalitarian Critique of Multiculturalism.* Harvard University Press.

- Baruah, S. (2020). *In the Name of the Nation: India and Its Northeast.* Stanford University Press.
- Bhargava, R. (1998). *Secularism and Its Critics*. Oxford University Press.
- Bhattacharyya, H. (2018). *Federalism and Regionalism in India: Institutional Strategies and Political Accommodation*. Routledge.
- Brass, P. (1991). *Ethnicity and nationalism: Theory and comparison.* Sage Publications.
- Government of India. (2020). *The Constitution of India (as amended up to 104th Amendment)*. Ministry of Law and Justice.
- Human Rights Watch. (2003). *We Have No Orders to Save You: State Participation and Complicity in Communal Violence in Gujarat.* HRW Report.
- Jaffrelot, C. (2021). *Modi's India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy.* Princeton University Press.
- Jayal, N. G. (2020). Citizenship and its Discontents: An Indian History. *The Indian Journal of Political Science*, 81(2), 89–105.
- Kothari, R. (1989). *Politics in India.* Orient Blackswan.
- Kymlicka, W. (1995). Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford University Press.
- Kymlicka, W. (2001). *Universal Minority Rights? Ethnicities, 1(1),* 21–23. http://www.jstor.org/stable/23890374
- Kymlicka, W. (2007). *Multicultural Odysseys: Navigating the New International Politics of Diversity.* Oxford University Press.
- Lijphart, A. (1999). *Patterns of democracy: Government forms and performance in thirty-six countries.* Yale University Press.
- National Crime Records Bureau. (2022). *Crime in India 2021–2022:* Annual Report. Ministry of Home Affairs, Government of India.
- NITI Aayog. (2022). *India SDG Index 2022.* Government of India.
- Parekh, B. (2000). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory.* Palgrave Macmillan.
- Saxena, R. (2011). Asymmetrical Federalism in India: Exploring a Theoretical Framework. *Indian Journal of Federal Studies, 21*(1), 1–20.
- Saxena, R. (2019). *Federalism, Diversity and Accommodation in India.* Primus Books.
- Saxena, R. (2020). Federal Dissent and Cultural Centralization: The CAA Protests in India. *Economic and Political Weekly*, 55(10), 23–28.
- Taylor, C. (1994). The politics of recognition. In A. Gutmann (Ed.), Multiculturalism: Examining the politics of recognition (pp. 25–73). Princeton University Press. https://doi.org/10.1515/9781400821402-004

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 79-86

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

The China - Pakistan Strategic Axis : Implications for India's National Security

Prof. Bina Rai

Principal, Avadh Girls' Degree College, University of Lucknow.

Nikhil Kumar Rai

Ph.D. Research Scholar, Department of Political Science, University of Lucknow.

Abstract :

The research analysis of this paper has to do with the China Pakistan alliance and in what all ways it can impact on security, economy, and geopolitical strategy of India. It is going to explore in terms of the strategic consequences of China Pakistan Economic Corridor (CPEC), military cooperation, particularly regarding the territorial disputes of Pakistan-occupied Kashmir. India, in response to the prevailing, circumstances emphasize to for strengthening its regional alliances, military modernization, economic diplomacy, and infrastructure development. And this paper concludes with some recommendations to enhance defence preparedness and foster regional cooperation for India to safeguard its interests.

Introduction :

China-Pakistan Axis is a geostrategic partnership with broader implications for South Asian peace and security, leading to the long-standing strategic alliance that has developed into a comprehensive collaboration in terms of military, diplomatic, and broad economic aspects. The cornerstone of this partnership is China's ongoing military and economic assistance to Pakistan, which improves Pakistan's position with India as China has strengthened the partnership by improving Pakistan's strategic capabilities by giving in terms of investments in vital infrastructure and cutting-edge military hardware. And a key component of China's Belt and Road Initiative (BRI), the China Pakistan Economic Corridor (CPEC) that facilitates economic integration through various means of communication like an extensive network of ports, railroads, and highways. In addition, CPEC puts China in a position to threaten India's naval dominance by expanding its strategic reach into the Arabian Sea while strengthening Pakistan's strategic and economic development.

China and Pakistan's military cooperation provides stimulus to India's security concerns when we see strategically, which is another essential aspect of their alliance. The increased military synergy of these two countries, brought about by the supply of advanced Chinese weapons, its defence technologies, and joint military drills with Pakistan, poses a direct threat to India's defensive readiness. Because along its Indian border, China's participation in strategic consultations and particularly defence production partnership has strengthened Pakistan's military posture. Along with the military ties and strategic alignment which are bolstering their shared goal of opposing India's supremacy in security, both of these countries are highly interested in rebalancing India's expanding regional influence. Moreover, China is expanding military presence in Pakistan-occupied Kashmir (PoK) and the possibility of combined actions further increased the security danger to India, which worsened the already tensed situation by the territorial conflicts surrounding the CPEC route going through the contested areas that India has been claiming.

India's dominance, from an economic standpoint, in the region is being threatened by the China Pakistan axis, because China now has the chance to directly invest in Pakistan's infrastructure through CPEC, enhancing its geopolitical influence and economic resilience, consequently shifting the balance of regional economic power by lessening Pakistan's confidence in India. What is especially noteworthy is building of Gwadar Port through China's CPEC, since it's providing China direct access to the Arabian Sea, avoiding the conventional Indian controlled shipping lanes. In addition, China gains another marine outpost which is crucial sea access that further encircles India's geopolitical interests. We can see the Influence of China is growing along both the land and marine borders, which means that India's regional economic and security goals are being more and more shrinked.

The increased collaboration between Pakistan and China has further intensified the tensions along India's borders is now more military and geopolitical. As a result of it, there are now regular skirmishes and military standoffs along the Line of Control (LoC) with Pakistan and the Line of Actual Control (LAC) with China. The two nations strategic partnership is trying to pose a threat to India's regional ambitions militarily at two front, compelling India's concentration and its resources. These concerns have been well handled by India in a number of ways, by advancing economic diplomacy, modernising its military, and fortifying its regional ties.

India further strengthened its strategic alliances with nations, as part of the larger Indo-Pacific strategy, including the US, Japan, and Australia. These multi alliances help keeping in check on the China-Pakistan axis since they are holding similar democratic ideals and economic objectives. And it is important, in order to preserve strategic deterrence, India's military modernisation program has prioritised developing domestic technologies, purchasing cutting edge weaponry, and improving

defence capabilities. India, furthermore, by concentrating on regional economic projects like the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC), is able to challenge China's Belt and Road Initiative by establishing alternative commercial routes in the area. In addition, diplomatic ties of India with China and Pakistan are still vital for controlling tensions and looking into potential areas of collaboration on particular problems.

What India needs to include as a reaction is the development of infrastructure in its border areas and must aim to fortify its military posture and advance regional economic integration by improving logistics and better means of communications. The Projects such as Iran's Chabahar Port is an option to Gwadar, provide to India as major entry point to the Persian Gulf and Central Asia. By working on its infrastructure, India seems better equipped to protect its interests and hold sway over the area.

The future of the China Pakistan axis and how it is going to affect India is still the issue to contemplate about. The area may become even more unstable as a result of increasing tensions, increased military buildups, and potential border clashes. However, there is a chance for diplomatic achievements on certain fronts, like economic cooperation or counter-terrorism collaboration. India's main task is to strengthen its military, economic, and diplomatic initiatives as it continues to navigate this complicated geopolitical landscape. In order to safeguard its national interests and mitigate the challenges presented by the China-Pakistan axis, India can establish regional partnerships, support sustainable economic development, and maintain strengthen defence capabilities.

Understanding and Analysing China-Pakistan Axis :

The strong and diverse partnership that China and Pakistan have developed, covers a wide range of areas, including infrastructure, energy, economics, military affairs, and regional geopolitics and China is currently Pakistan's largest trading partner, and this relationship has been further solidified by China's substantial military and financial support over the past few decades. One of the most prominent examples of this collaboration is the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), a $62 billion infrastructure project that aims to establish a direct trade route from China's Xinjiang region to Pakistan's Gwadar port. CPEC, the centrepiece of China's Belt and Road Initiative (BRI), aims to enhance connectivity, stimulate economic growth, and promote regional integration. It is not only crucial for Pakistan's economic growth but also strategically significant for China, as it provides a secure route for crude imports from the Middle East and direct access to the Arabian Sea, thereby avoiding the perilous Strait of Malacca.

CPEC has the potential to address a number of significant issues that Pakistan's economy is currently facing, including its acute energy shortages. Projects under CPEC, which include the

construction of power plants and the modernization of the national infrastructure, are expected to significantly contribute to the resolution of Pakistan's electrical crisis. And as a result of these energy advances, Pakistan's GDP is expected to increase by 2-2.5%, giving the country much-needed economic stimulation. Pakistan's transportation network will be modernised by CPEC's infrastructure improvements, including as ports, railroads, and roadways, along with energy which will increase regional connectivity and trade efficiency. Although these initiatives are not without difficulties. Due to Pakistan's mounting debt to China, the long-term economic viability of CPEC has come under scrutiny. Large-scale infrastructure projects raise extra environmental issues because they have the ability to significantly harm the environment. Despite these worries, preliminary results of ventures such as the Karot Hydropower Project, which tries to cut carbon emissions, indicate that, with competent governance, the gains of CPEC may exceed the risks.

Military cooperation is another essential component of the China-Pakistan relationship. China has been a key supplier of Pakistan's cutting-edge military hardware, such as missiles, fighter jets, and submarines. This support has significantly enhanced Pakistan's defence capabilities, allowing it to modernize its armed forces and strengthen deterrence against potential challenges, particularly those originating from India. Joint military drills like, "Shaheen" air force drills and the "Sea Guardians" navy exercises that strengthen military ties and improve operational readiness. In addition to providing conventional weapons, China has played an important role in strengthening Pakistan's nuclear program and increasing its strategic deterrence against regional adversaries. This military cooperation secures China's strategic interests in South Asia, particularly its investments in CPEC, and serves as a check on India's growing military might.

China's military deployment in Pakistan has broader regional implications, in addition to strengthening bilateral defence. Its military presence in Pakistan is becoming quite visible, which is alarming neighbouring nations, particularly India regards it as part of China's bigger regional influence expansion. Furthermore, the China-Pakistan alliance serves as a venue for cooperation geopolitical efforts, such as diplomatic aid to global organizations such as the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and the United Nations. China and Pakistan work together to counter India's growing regional influence, particularly through its participation in the Quad alliance and diplomatic isolation of Pakistan. The strategic relationship also greatly benefits China. It defends China's western boundaries while also ensuring the control of India's growing influence in Central and South Asia. Furthermore, the alliance ensures the security of China's oil routes from the Middle East and enables China to protect its critical infrastructure projects, particularly those related to the China-Pakistan Economic Corridor. Pakistan requires the alliance to bolster its military deterrent, grow its economy, and counter India's

regional aspirations. And Pakistan also hopes to leverage this relationship to raise global awareness of its long-running dispute with India over Kashmir. Although the partnership Is not without difficulties. Pakistan's expanding debt, challenges to regional security, and concerns about China's growing geopolitical influence all hinder collaboration. Concerns have been voiced about the risk of regional instability as China's influence in South Asia grows, particularly in light of the unsolved tensions between India and Pakistan. Despite these challenges, the strategic alliance between China and Pakistan is expected to strengthen due to their shared strategic objectives and advantages in the areas of economics, defence, and regional power relations. However, for this alliance to be successful, both nations must be able to manage geopolitical and economic risks so that their cooperation benefits both parties while without exacerbating regional tensions.

Implications for India :

India looks at China and Pakistan's increasing strategic alliance as a severe security issue that has exacerbated South Asian tensions. And it sees the military alliance as an attempt to balance its strength in the region. New Delhi is concerned about the significant enhancement in Pakistan's defence capabilities caused by the injection of sophisticated Chinese military aid, such as fighter jets, submarines, and missile systems. India is particularly concerned about the military implications of the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), which could result in a permanent Chinese military presence in Pakistan, particularly at strategic places such as the Gwadar port. This increased presence, combined with joint military exercises near India's borders and China's support for Pakistan's nuclear program, exacerbates India's security concerns and increases the likelihood of an undetected nuclear arms race in the region.

India's fears are magnified by the fact that the CPEC runs through territory it claims, such as Gilgit Baltistan and Pakistan Occupied Kashmir (PoK). Given that the infrastructure created along the CPEC is considered to bolster Pakistan's authority over these disputed areas, India considers these developments as an infringement of its territorial sovereignty. The CPEC's proximity to Aksai Chin and the Siachen Glacier has heightened tensions between India and Pakistan. Pakistan regards CPEC as a vital economic initiative that will enhance its control over disputed territory while also fostering development in underprivileged areas and enhancing regional connectivity. While emphasizing the corridor's strategic and economic benefits and strengthening its connections with Pakistan, China maintains a neutral stance on the Kashmir question.

China and Pakistan's growing military and economic cooperation poses a direct danger to India's regional dominance, which has historically been defined by its military and economic superiority in South Asia. Pakistan's strengthened military capabilities, as well as China's Belt and

Road Initiative (BRI) and China-Pakistan Economic Corridor (CPEC), have weakened India's influence in the region. India has responded by advancing its own military modernization, strengthening its alliances with countries such as the United States, Japan, and Australia through the Quad, and focusing on improving regional diplomacy and infrastructure. Nonetheless, China and Pakistan's increasing competition and strategic encirclement will continue to impact India's security strategy and its larger international aspirations.

India's Response to counter China-Pakistan Axis :

India, in a variety of ways, has responded to China and Pakistan's growing strategic cooperation, addressing the alliance's complex security, economic, and geopolitical challenges. In acknowledgment of the significance of this axis, India has significantly improved its military capabilities by focusing on modernization programs along the Line of Actual Control (LAC) with China and the Line of Control (LoC) with Pakistan. Troops deployments have been expanded by Indian military, in order to get ready for possible two-front wars, and India has modernised its defence facilities, as well as held extensive drills. In the event that tensions with China and Pakistan worsen, these measures guarantee that India is prepared for anything.

India has worked to bolster its position both regionally and internationally by forming strategic relationships. And forging close ties with nations that share similar principles, such as the United States, Japan, Australia, and others, has been an essential component of India's foreign policy. The purpose of programs like the Quadrilateral Security Dialogue (Quad) is to promote regional security while countering China's growing influence in the Indo-Pacific. These relationships, which provide political, military, and financial backing, boost India's power on the global stage.

India has adopted economic measures to counter China's Belt and Road Initiative (BRI), particularly in South Asia. And it hopes to reduce its dependency on Chinese investments by providing alternative avenues for regional growth through projects such as the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC). In addition to boosting regional economic integration, strengthening economic links with neighbours helps balance out China's growing economic power.

India has taken steps to handle tensions with both China and Pakistan diplomatically, focusing on dispute resolution through bilateral conversations and international forums. It frequently participates in regional and international forums to attract attention to issues such as cross-border terrorism and border conflicts, emphasizing the need of regional stability. Backchannel diplomacy is still an important method when dealing with sensitive matters, such as the current conflict with Pakistan over Kashmir. Another major aspect of India's policy is infrastructural development, particularly in border regions.

To provide strategic alternatives to China's Gwadar Port, projects such as Iran's Chabahar Port, as well as enhancements to roads and communication networks in important locations, are being implemented. These programs enhance military logistics, mobility, and connectivity, ensuring fast deployment in the event that tensions rise.

India's response is broad, encompassing economic efforts, diplomatic engagement, strategic relationships, and military preparation. Addressing the economic and security concerns posed by the China-Pakistan axis, India aims to defend its interests as a nation and maintain its regional dominance.

Recommendations and Conclusion :

To combat the China-Pakistan axis and prepare for any challenges, India must prioritize modernizing its military and reinforcing its border defences. This approach relies heavily on strengthening strategic alliances, particularly with the United States, Japan, and Australia, through groups such as the Quad, which may give economic, military, and diplomatic support. and it needs to make an effort to build strong relationships with extended neighbours, including Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, and others. At the same time, expanding regional economic cooperation through programs like BIMSTEC will reduce reliance on China and deepen ties with neighbouring countries.

Development of infrastructure, particularly in critical border regions and initiatives such as the Chabahar Port, will improve military logistics, strengthen connectivity, and obstruct China's Belt and Road Initiative. And stability in the region depends on diplomatically communicating with China and Pakistan to lessen tensions and avert wars, as well as creating strong cybersecurity and counterterrorism systems to protect national security.

Investing in sustainable development and diversifying energy sources can also help to ensure long-term resilience, reducing reliance on external influences. India's worldwide position will increase by promoting soft power measures, engaging in cultural exchanges, and increasing its global effect. With this multipronged approach of military preparation, diplomacy, and economic expansion, India will be able to successfully counter the China-Pakistan axis while protecting its national interest.

References :

1. Krishnan, A. (2022). India's China Challenge. HarperCollins India, Publishers.
2. Gokhale, V. (2021). The Long Game: How the Chinese negotiate with India. Penguin Random House India.
3. Mohan, C. R. (2020, February 20). India's response to the Pakistan-China axis. The Indian Express.
4. Ali, M. (2018). Pakistan's foreign policy: An historical analysis. Routledge.

5. Small, A. (2015). The China-Pakistan axis: Asia's new geopolitics. Penguin Random House India.
6. Alam, M. M. (2019). China-Pakistan Economic Corridor: Challenges and opportunities. Economic and Political Weekly, 54(22), 25-27.
7. Bakshi, G. D. (2020). Pakistan-China military cooperation: A threat to India's national security. IDSA Comment, 1-4.
8. Chatterji, S. K. (2020). Pakistan-China strategic partnership: Implications for India. Journal of Defence Studies, 14(1), 35-48.
9. Ministry of External Affairs, Government of India. (2020). India's national security strategy.
10. Noorani, A. G. (2020, January 15). The Pakistan-China axis and regional instability. The Hindu.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 87-94

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

मध्यप्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का सतत् प्रबंधन और भविष्य की चुनौतियों का भौगोलिक विश्लेषण (विकसित भारत @2047 के सन्दर्भ में)

डॉ. अजय तिवारी
डी. लिट्., भूगोल विभाग
शास. मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

सारांश :

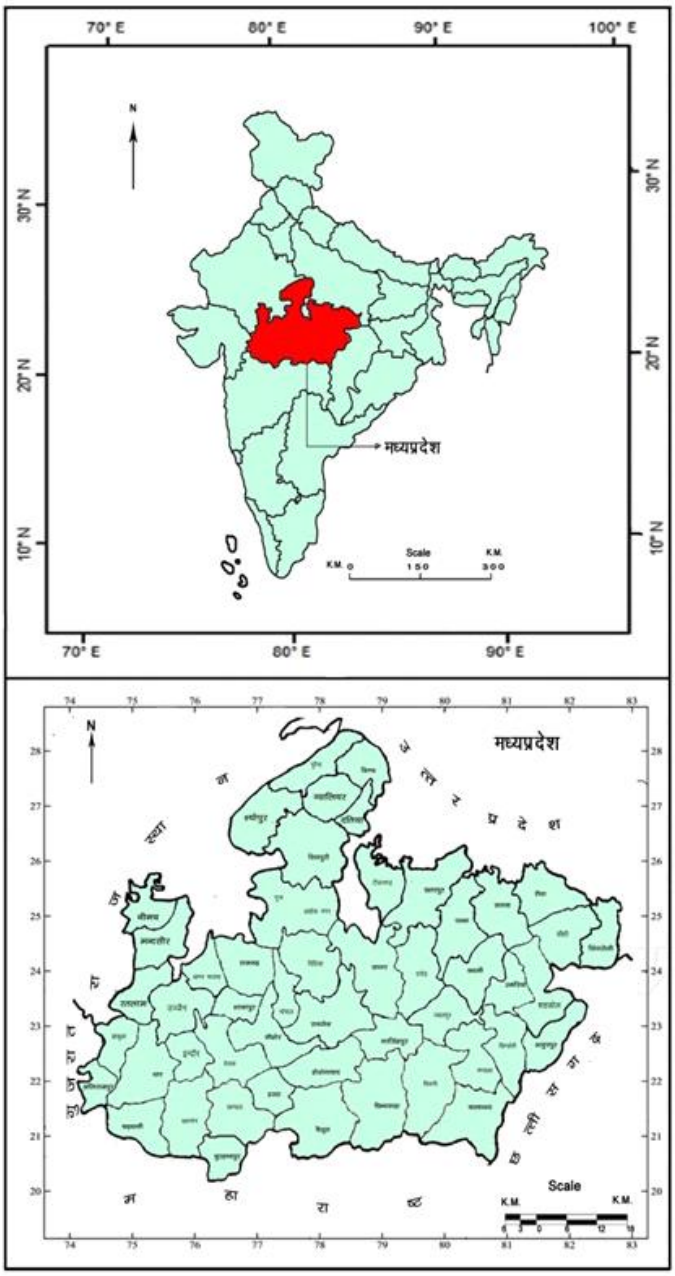
भारत ने वर्ष 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसकी सफलता प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण और सतत् प्रबंधन पर टिकी है। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारत के हृदय कहे जाने वाले मध्यप्रदेश राज्य के सन्दर्भ में प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर वन, जल, भूमि और खनिज की वर्तमान स्थिति और भविष्य की चुनौतियों का विश्लेषण करना है। भौगोलिक दृष्टि से मध्यप्रदेश अत्यंत सम्पन्न है, यहाँ देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र लगभग 77,493 वर्ग किमी, नर्मदा और चम्बल जैसी प्रमुख नदी प्रणालियाँ और प्रचुर खनिज भण्डार मौजूद हैं।

प्रस्तुत अध्ययन में यह रेखांकित किया गया है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में मध्यप्रदेश के समक्ष कई जटिल चुनौतियाँ हैं। तीव्र शहरीकरण, औद्योगिक विस्तार के कारण भूमि उपयोग प्रतिरूप में बदलाव, गिरता भू–जल स्तर और जलवायु परिवर्तन के कारण पैदा होने वाली चरम मौसमी घटनाएँ प्रमुख चिन्ताएँ हैं। शोध पत्र में अध्ययन किया गया है कि कैसे अनियंत्रित संसाधन दोहन न केवल पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ रहा है, बल्कि जनजातीय समुदायों की आजीविका को भी प्रभावित कर रहा है।

यह शोध स्पष्ट करता है कि 2047 तक विकसित मध्यप्रदेश की संकल्पना को साकार करने के लिए पारम्परिक प्रबंधन के स्थान पर आधुनिक तकनीकी हस्तक्षेप, जैसे– सुदूर संवेदन और भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग अनिवार्य है। साथ ही चक्रीय अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित ग्रीन विकास मॉडल को अपनाकर ही राज्य आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच वांछित संतुलन स्थापित कर सकता है। यह अध्ययन नीति निर्धारकों के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है ताकि संसाधनों का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना किया जा सके।

कुंजी शब्द – सुदूर संवेदन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, संसाधन दक्षता, पर्यावर्णीय नैतिकता, जैव विविधता, शहरीकरण, औद्योगीकरण, डिजिटल मानचित्रण।

प्रस्तावना :



इक्कीसवीं सदी का तृतीय दशक वैश्विक स्तर पर संसाधन संकट और पारिस्थितिक असंतुलन के संक्रमण काल के रूप में जाना जा रहा है। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् जिस तीव्र गति से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ, उसने न केवल पर्यावरण को क्षति पहुँचाई है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की उत्तरजीविता पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है। सतत् विकास का सिद्धांत आज केवल एक दार्शनिक विचार न रहकर एक अनिवार्य भौगोलिक और आर्थिक आवश्यकता बन चुका है। इसी पृष्ठभूमि में भारत ने अपनी स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक स्वयं को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया है। विकसित भारत @2047 का यह विजन एक ऐसी समावेशी प्रगति की मांग करता है, जहाँ आर्थिक समृद्धि और पर्यावरणीय नैतिकता के मध्य एक सुदृढ़ संतुलन हो।

भारत के हृदय स्थल में स्थित मध्यप्रदेश अपनी विशिष्ट भू–आकृतिक संरचना और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण संसाधन भूगोल के अध्ययन का एक उत्कृष्ट केन्द्र है। देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य के रूप में मध्यप्रदेश लगभग 3,08,252 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है। यह राज्य भारत के कुल वन क्षेत्र का लगभग 25% हिस्सा धारित करता है, जो न केवल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है बल्कि जैव विविधता का वैश्विक केन्द्र भी है। नदियों के मायके के रूप में विख्यात यह प्रदेश नर्मदा, चम्बल, सोन, और बेतवा जैसी बारहमासी जल धाराओं का उद्गम स्थल है, जो मध्य भारत की कृषि और औद्योगिक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा हैं। साथ ही हीरा, तांबा और कोयला जैसे खनिजों के मामले में राज्य की रणनीतिक स्थिति इसे राष्ट्रीय विकास का ऊर्जा केन्द्र बनाती है।

विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बुनियादी ढांचे का विस्तार, शहरीकरण और औद्योगीकरण अपरिहार्य हैं, किन्तु इन प्रक्रियाओं का सीधा प्रभाव प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ता है। मध्य प्रदेश के सन्दर्भ में, पिछले कुछ वर्षों में भूमि उपयोग और भूमि आवरण में व्यापक परिवर्तन देखे गए हैं। तीव्र शहरीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि का संकुचन और मालवा व बुन्देलखण्ड जैसे अंचलों में गिरता भू–जल स्तर एक गम्भीर चेतावनी है। कोयला और अन्य खनिजों के निष्कर्षण ने पारिस्थितिक तंत्र के विखंडन की समस्या उत्पन्न की है। इसके

अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून की अनिश्चितता ने जल प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा के समक्ष नई चुनौतियाँ पेश की हैं। एक ओर विकास की भूख है, तो दूसरी ओर संसाधनों की सीमितताय यही वह भौगोलिक द्वन्द है जिसका समाधान सतत् प्रबंधन में निहित है।

यह प्रस्तावना इस तर्क को पुख्ता करती है कि विकसित भारत का स्वप्न तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक मध्यप्रदेश जैसे संसाधन–समृद्ध राज्य अपने प्राकृतिक वैभव का संरक्षण सुनिश्चित न करें। हमें दोहन की संस्कृति से निकलकर संरक्षण और पुर्नजनन की संस्कृति की ओर बढ़ना होगा। यह शोध उन बाधाओं की पहचान करेगा जो 2047 की विकास यात्रा में रोड़ा बन सकती हैं और एक ऐसा हरित रोडमैप प्रस्तुत करेगा जो मध्यप्रदेश को स्थिरता के साथ समृद्धि की ओर ले जाए।

अध्ययन क्षेत्र :

मध्यप्रदेश भारत के केन्द्र में स्थित एक राज्य है, जिसका अक्षांशीय विस्तार 21°6' उत्तरी अक्षांश से 26°30′ उत्तरी अक्षांश तक और देशान्तरीय विस्तार 74°9′ पूर्वी देशान्तार से 82°48′ पूर्वी देशान्तार तक है। जिसका कुल क्षेत्रफल 308252 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का लगभग 9.38 प्रतिशत है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य को 10 सम्भागों, 55 जिलों एवं 313 विकास खण्डों में विभाजित किया गया हैं, जिसमें 22921 ग्राम पंचायते है। मध्यप्रदेश के उत्तर में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात तथा उत्तर पश्चिम में राजस्थान राज्य की सीमा लगती हैं। मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या 8.95 करोड़ हैं जिसमें महिलाओं की संख्या 4.26 करोड़ तथा 4.69 करोड़ पुरूष हैं। यहाँ का औसत जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है जो देश के औसत घनत्व 382 से कम है। यहाँ कि 73 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जबकि 75 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है जिनका जीविका का मुख्य साधन कृषि है इस तरह यह ग्राम प्रधान राज्य हैं।

शोध के उद्देश्य :

इस शोध कार्य के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. मध्यप्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों वन, जल, खनिज और भूमि की वर्तमान स्थिति और उनके स्थानिक वितरण का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना।
2. विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं जैसे–जलवायु परिवर्तन, तीव्र शहरीकरण और संसाधन क्षरण का विश्लेषण करना।
3. राज्य सरकार द्वारा संचालित वर्तमान संसाधन संरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता की समीक्षा करना और उनमें आवश्यक सुधार सुझाना।

शोध प्रश्न :

इस अध्ययन के दौरान हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे –

1. क्या मध्यप्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान उपलब्धता और उनके दोहन की दर 2047 के विकसित राष्ट्र के विजन के साथ सामंजस्य रखती है?
2. बढ़ते तापमान और अनिश्चित वर्षा प्रतिरूप का मध्यप्रदेश के कृषि–पारिस्थितिकी और जल सुरक्षा पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा?
3. औद्योगिक विस्तार और शहरीकरण के कारण मध्यप्रदेश के वन आवरण और जैव विविधता में होने वाले

ह्रास को कम करने के लिए कौन से प्रभावी भौगोलिक उपाय किए जा सकते हैं?

शोध पद्धति :

इस शोध को पूर्ण करने के लिए गुणात्मक शोध पद्धति का सहारा लिया गया हैं, शोध की प्रकृति वर्णात्मक और विश्लेषणात्मक है।

आँकड़े संग्रह के स्रोत :

चूंकि यह एक बृहद वर्णात्मक अध्ययन है इसलिए इसमें द्वितीयक आँकड़ों का गहन उपयोग कर तुलनात्मक तकनीक द्वारा शोध पत्र को तैयार किया गया है।

शोध विवेचना और विश्लेषण :

1. मध्यप्रदेश की प्राकृतिक पूँजी– एक स्थानिक विश्लेषण :

मध्यप्रदेश की भौगोलिक विशिष्टता इसकी विविधतापूर्ण संसाधन संरचना में निहित है। विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य की प्राकृतिक पूँजी का मूल्यांकन अनिवार्य है। वर्तमान में मध्यप्रदेश का वन आवरण देश में सर्वाधिक है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.14% है। विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रेणियां न केवल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखती हैं, बल्कि कार्बन सिंक के रूप में राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों में योगदान देती हैं। वनोन्मूलन और वनों के विखंडन की समस्या, विशेषकर विकास परियोजनाओं और खनन क्षेत्रों के आसपास, एक गम्भीर भौगोलिक चुनौती है।

2. जल सुरक्षा और नदी बेसिन प्रबंधन :

मध्यप्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, जहाँ नर्मदा, चम्बल, सोन और बेतवा जैसी नदियाँ न केवल सिंचाई बल्कि पेयजल और जल विद्युत का आधार हैं। विकसित भारत @2047 के विजन में जल सुरक्षा सर्वोपरि है। शोध का विषय यह है कि नर्मदा बेसिन में जल का आवंटन और उसका कुशल उपयोग कैसे सुनिश्चित हो। मालवा के पठार और बुन्देलखण्ड के उच्च प्रदेशों में भू–जल का अनियंत्रित दोहन एक गम्भीर स्थिति पैदा कर रहा है। भविष्य की चुनौती यह है कि 2047 तक बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिक मांग के बीच प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को कैसे बनाए रखा जाए। यहाँ सूक्ष्म सिंचाई और नदी जोड़ो परियोजनाओं जैसे केन–बेतवा लिंक की भूमिका पर गहन विश्लेषण की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्रीय जल असंतुलन को दूर किया जा सके।

3. खनिज सम्पदा और सतत् खनन :

खनिज संसाधन मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हीरा, तांबा, मैंगनीज और कोयले के भण्डार राज्य को खनिज मानचित्र पर अग्रणी रखते हैं। विकसित भारत के लिए ऊर्जा और कच्चे माल की मांग बढ़ेगी, जिससे खनन गतिविधियों में तीव्रता आना स्वाभाविक है। शोध का एक महत्वपूर्ण पहलू खनन बनाम पर्यावरण का द्वंद्व है। सिंगरौली जैसे ऊर्जा केन्द्रों में कोयला खनन से होने वाला पर्यावरणीय क्षरण और विस्थापन एक बड़ी सामाजिक–भौगोलिक समस्या है। 2047 के विजन में ग्रीन माइनिंग की अवधारणा को अपनाना होगा, जहाँ खनन के साथ–साथ भूमि का पुनरूद्धार और वनीकरण अनिवार्य हो। तकनीक के माध्यम से संसाधन दक्षता (Resource Efficiency) बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है।

4. कृषि–पारिस्थितिकी और खाद्य सुरक्षा :

मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि आधारित है। सोयाबीन और गेहूं के उत्पादन में अग्रणी होने के बावजूद, राज्य की कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील है। अध्ययन से यह तथ्य उभर कर आता है कि तापमान में वृद्धि और वर्षा के बदलते स्वरूप से रबी और खरीफ दोनों फसलें प्रभावित हो रही हैं। विकसित भारत @2047 के लिए हमें स्मार्ट एग्रीकल्चर की ओर बढ़ना होगा। मृदा स्वास्थ्य का गिरता स्तर और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग भविष्य में भूमि की उत्पादकता को कम कर सकता है। अतः जैविक खेती और जलवायु–लचीली फसलों को भौगोलिक आधार पर प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

5. शहरीकरण और भूमि उपयोग परिवर्तन :

इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर जैसे महानगरों का अनियंत्रित भूमि विस्तार उपयोग और भूमि आवरण में तीव्र परिवर्तन ला रहा है, विश्लेषण से पता चलता है कि कृषि भूमि का उपयोग गैर–कृषि कार्यों आवास और उद्योग के लिए बढ़ रहा है। यह प्रवृत्ति 2047 तक खाद्य सुरक्षा और स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए संकट पैदा कर सकती है। अध्ययन विश्लेषण का निष्कर्ष यह है कि स्मार्ट सिटी के साथ–साथ स्थायी गाँव Sustainable Village की अवधारणा पर काम करना होगा ताकि ग्रामीण–शहरी प्रवास को नियंत्रित किया जा सके और संसाधनों पर दबाव कम हो।

6. भविष्य की चुनौतियाँ और तकनीकी हस्तक्षेप :

अध्ययन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि 2047 तक की यात्रा बाधाओं रहित नहीं है। संसाधन प्रबंधन के पारम्परिक तरीके अब अपर्याप्त हैं। यहाँ भौगोलिक सूचना प्रणाली और सुदूर संवेदन जैसे उपकरणों का महत्व बढ़ जाता है। वास्तविक समय की निगरानी के माध्यम से वनों की कटाई, अवैध खनन और जल स्रोतों के अतिक्रमण को रोका जा सकता है। डिजिटल मानचित्रण संसाधनों के कुशल आवंटन में सहायक होगा।

मध्यप्रदेश के पास विकसित भारत @2047 का इंजन बनने की पूरी क्षमता है, बशर्ते वह अपने प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग करने के बजाय उनका सम्बर्धन करे। अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विकास की गति को पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर रखना ही सतत् प्रबंधन की असली सफलता होगी।

परिणाम :

1. वन संसाधन – सघनता का ह्रास और पारिस्थितिक विखंडन :

मध्यप्रदेश के वन संसाधनों के विश्लेषण से प्राप्त आँकड़े दर्शाते हैं कि राज्य का कुल वन क्षेत्र 77,493 वर्ग किमी राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक बना हुआ है। हालाँकि, पिछले एक दशक के उपग्रह आँकड़ों 2021–23 की तुलना करने पर यह पाया गया कि अति सघन वनों के क्षेत्रफल में लगभग 1.5% की गिरावट आई है, जबकि खुले वनों में वृद्धि हुई है। यह वनों के गुणवत्तापूर्ण ह्रास का स्पष्ट प्रमाण है।

भौगोलिक दृष्टिकोण से वनों का यह रूपान्तरण विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों के लिए चिन्ताजनक है। जिसका मुख्य कारण यह है कि विकास की अंधी दौड़ में हम कार्बन सिंक खो रहे हैं। मध्यप्रदेश के विंध्य और सतपुड़ा अंचल में बढ़ती रैखिक बुनियादी ढांचा परियोजनाएं सड़कें, रेल लाइनें वनों को छोटे–छोटे टुकड़ों में विभाजित कर रही हैं, जिसे वन विखंडन कहा जाता है। 2047 तक यदि यह प्रवृत्ति जारी रही, तो जैव–विविधता का क्षरण अपूरणीय होगा। सतत् प्रबंधन के लिए हमें नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु केवल वृक्षारोपण नहीं,

बल्कि पारिस्थितिक बहाली पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

तालिका – 1

विकसित मध्यप्रदेश @2047 रणनीतिक रोडमैप

रणनीति	वर्तमान स्थिति	लक्ष्य
नवीकरणीय ऊर्जा	5,500 मेगावाट	20,000 मेगावाट (नेट जीरो लक्ष्य)
सिंचाई पद्धति	मुख्यतः पारम्परिक	100% सूक्ष्म सिंचाई
डिजिटल गवर्नेंस	आंशिक GIS मैपिंग	100% रियल–टाइम रिसोर्स ऑडिटिंग
अपशिष्ट प्रबंधन	कुछ शहरों तक सीमित	जीरो वेस्ट स्टेट (चक्रीय अर्थव्यवस्था)
वन सघनता	मध्यम और खुले वन अधिक	33% सघन वनाच्छादन (VDF वृद्धि)

स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021–2023

2. जल सुरक्षा – क्षेत्रीय असंतुलन और भू–जल का संकट :

अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि मध्यप्रदेश के पश्चिमी भाग मालवा का पठार और उत्तरी भाग बुन्देलखण्ड में भू–जल का स्तर अति–दोहित श्रेणी में पहुँच चुका है। आँकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों में भू–जल पुनर्भरण की तुलना में निष्कर्षण की दर 130% अधिक है। इसके विपरीत, नर्मदा बेसिन में जल की उपलब्धता अधिशेष है।

यह क्षेत्रीय जल असंतुलन मध्यप्रदेश की भावी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। विकसित भारत @2047 के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु केन–बेतवा लिंक जैसी अंतर–बेसिन स्थानांतरण योजनाएं तकनीकी रूप से प्रभावी दिखती हैं, लेकिन उनकी पर्यावरणीय लागत जैसे– पन्ना टाइगर रिजर्व का जलमग्न होना एक बड़ा भौगोलिक विवाद पैदा करती है। अध्ययन का मुख्य केन्द्र मांग पक्ष प्रबंधन होना चाहिए। भविष्य में कृषि क्षेत्र को ''बाढ़ सिचांई'' Flood Irrigation से हटकर 100% बूंद और फब्बारा सिंचाई Drip and Sprinkler Irrigation की ओर स्थानान्तरित होना पड़ेगा। नर्मदा के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए नहीं, बल्कि 2047 की विशाल शहरी जनसंख्या की प्यास बुझाने के लिए सुरक्षित रखना एक रणनीतिक चुनौती होगी।

3. खनिज सम्पदा – आर्थिक समृद्धि बनाम पर्यावरणीय नैतिकता :

परिणामों से ज्ञात होता है कि सिंगरौली, शहडोल और पन्ना जैसे जिलों में खनन गतिविधियों ने राज्य के राजस्व में 12% की वृद्धि की है। परन्तु सुदूर संवेदन चित्रों के विश्लेषण से यह भी सामने आया है कि खनन क्षेत्रों में भूमि उपयोग में तीव्र बदलाव आया है, जहाँ उपजाऊ मृदा और वन क्षेत्र अब अत्यधिक भार और खदानों Overburden and Water Bodies के गड्ढे में बदल चुके हैं।

खनन और पर्यावरण का द्वन्द मध्यप्रदेश के लिए शाश्वत है। विकसित भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा हेतु कोयला अनिवार्य है, लेकिन 2047 के वैश्विक मानकों के अनुसार हरित खनन Green Mining एकमात्र विकल्प है। खनन कम्पनियों द्वारा किया जाने वाला अनिवार्य वनीकरण क्या वास्तव में खोए हुए पारिस्थितिकी तंत्र की भरपाई कर पा रहा है? अक्सर यह पाया गया है कि प्राकृतिक मिश्रित वनों के स्थान पर एक ही प्रकार के वृक्ष

Monoculture लगाए जाते हैं, जो जैव–विविधता की दृष्टि से शून्य हैं। 2047 तक हमें चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल Circular Economy Model के तहत खनिजों के पुनर्चक्रण पर जोर देना होगा ताकि नए खनन की आवश्यकता कम हो सके।

तालिका - 2

मध्यप्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति 2024–25

प्राकृतिक संसाधन	प्रमुख सांख्यिकीय डेटा	राष्ट्रीय स्तर पर स्थान
वन क्षेत्र	77,493 वर्ग किमी (25.14%)	प्रथम (देश का 10.8%)
नदियाँ	10 प्रमुख बेसिन (नर्मदा, चम्बल, सोन आदि)	नदियों का मायका (सर्वाधिक उद्गम)
तांबा	देश का 46% भण्डार (लाँजी बालाघाट)	प्रथम
मैंगनीज	देश का 33% उत्पादन	प्रथम
हीरा	देश का 100% उत्पादन (पन्ना)	एक मात्र उत्पादक राज्य
जैविक खेती क्षेत्र	17.31 लाख हेक्टेयर	प्रथम

स्रोत : खनन एवं भूविज्ञान संचालनालय मध्यप्रदेश शासन वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2025।

4. शहरीकरण और कृषि-भूमि का रूपान्तरण :

विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि इन्दौर–भोपाल कॉरिडोर और ग्वालियर–जबलपुर जैसे शहरी केन्द्रों का शहरी प्रसार उपजाऊ काली मिट्टी Black Soil वाले क्षेत्रों को निगल रहा है। पिछले 20 वर्षों में लगभग 18% प्रमुख कृषि भूमि Prime Agriculture Land का उपयोग गैर–कृषि कार्यों के लिए रूपान्तरित किया गया है।

एक भूगोलवेत्ता के रूप में यह भूमि उपयोग संघर्ष भविष्य की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है। विकसित भारत @2047 का विजन स्मार्ट शहरों की बात करता है, लेकिन इन शहरों की स्थिरता उनके संसाधनों की स्थानीय उपलब्धता पर टिकी है। यदि शहरीकरण इसी गति से कृषि भूमि का अतिक्रमण करता रहा, तो मध्यप्रदेश जो वर्तमान में गेहूं का कटोरा बनता जा रहा है, अपनी उत्पादकता खो देगा। शोध का निष्कर्ष यह है कि हमें 'स्मार्ट ग्रोथ' के तहत ऊर्ध्वाधर शहरीकरण Vertical Urbanisation को प्राथमिकता देनी चाहिए और शहरी निकटवर्ती क्षेत्र Peri Urban Area में हरित पट्टी Green Belt को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाना चाहिए।

5. जलवायु संवेदनशीलता और भविष्य की राह :

मौसम सम्बधी आँकड़ों का विश्लेषण 1991–2025 यह दर्शाता है कि राज्य में लू के दिनों की संख्या में 20@ की वृद्धि हुई है और वर्षा के वितरण में असमानता बढ़ी है। इसके परिणामस्वरूप सोयाबीन और चना जैसी प्रमुख फसलों की उत्पादकता में अनिश्चितता देखी गई है।

विकसित भारत @2047 के लिए मध्यप्रदेश को जलवायु लचीला Climate Resilient बनना होगा। विश्लेषण का अंतिम बिन्दु यह है कि तकनीक और पारम्परिक ज्ञान का समन्वय ही समाधान है। जनजातीय समुदायों के पास वनों और जल स्रोतों के संरक्षण का जो पारम्परिक कौशल है, उसे आधुनिक नीतियों में एकीकृत

करना होगा। मध्यप्रदेश विजन 2047 को केवल औद्योगिक उत्पादन पर नहीं, बल्कि सकल पर्यावरणीय उत्पाद Gross Environment Product पर आधारित होना चाहिए।

उपरोक्त विश्लेषण और परिणामों से यह स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश के प्राकृतिक संसाधन राज्य की सबसे बड़ी शक्ति हैं, लेकिन इनका अति–विदोहन भविष्य के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। 2047 का विकसित भारत केवल तभी सम्भव है जब हम उपभोगवादी भूगोल से निकलकर संरक्षणवादी भूगोल की ओर बढ़ें। मध्यप्रदेश को अपनी नीतियों में कमी करें, पुनः उपयोग करें, पुनर्चक्रण करें, (3-Reduce, Reuse, Recycle) के साथ प्रकृति का सम्मान Respect for Nature को जोड़ना होगा।

निष्कर्ष :

प्रस्तुत शोध का मुख्य निष्कर्ष यह है कि मध्यप्रदेश के प्राकृतिक संसाधन वन, जल, खनिज और भूमि राज्य की अर्थव्यवस्था के आधार स्तम्भ हैं, बल्कि ये विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में इंजन की भूमिका निभाते हैं। शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि मध्यप्रदेश के पास संसाधन प्रचुरता तो है, लेकिन उनके प्रबंधन में सतत्ता का अभाव भविष्य के लिए गम्भीर चुनौतियाँ पैदा कर सकता है। वनों के घनत्व में गिरावट, मालवा और बुन्देलखण्ड में गहराता भू–जल संकट और तीव्र शहरीकरण के कारण उपजाऊ कृषि भूमि का संकुचन कुछ ऐसे प्रमुख बिन्दु हैं जो 2047 की राह में बाधक बन सकते हैं।

विकसित होने का अर्थ केवल औद्योगिक उत्पादन या बुनियादी ढांचे का विस्तार नहीं है। एक भूगोलवेत्ता के दृष्टिकोण से वास्तविक विकास वह है जिसमें पारिस्थितिक अखडण्ता सुरक्षित रहे। मध्यप्रदेश को अपनी प्राकृतिक पूँजी को नष्ट करके प्राप्त की गई जीडीपी के बजाय सकल पर्यावरण उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करना होगा। 2047 का मध्यप्रदेश तभी समृद्ध कहलाएगा जब उसकी नर्मदा अविरल रहे, विंध्य और सतपुड़ा के वन सघन बने रहें और उसकी मृदा की उर्वरता अक्षुण्ण रहे।

सन्दर्भ सूची :

- सिंह, सविंद्र (2017) : पर्यावरणीय भूगोल, प्रवालिका पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, पृ. 245–260।
- ISFR (2023) : इण्डिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून।
- हुसैन, माजिद (2015) : भारत का भूगोल, मैक्ग्रॉ हिल एजुकेशन, नई दिल्ली।
- https://niti.gov.in
- https://bhuvan.nrsc.gov.in
- https://www.mpwrd.gov.in
- https://fsi.nic.in

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 95-99

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में पर्यावरणीय चेतना एवं समकालीन वैश्विक पर्यावरण संकट

अंकित चौरसिया

शोधार्थी (पीएच.डी.) संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

सारांश :

वर्तमान समय में मानव और प्रकृति के मध्य नैतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखने की कितनी आवश्यकता है इसका अनुमान हम वर्त्तमान समय में हो रहे आपदा जैसे की जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापवृद्धि, जैव–विविधता का ह्रास, इत्यादि। जब कभी भी वर्तमान में विकास की बात की जाती है तो सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में बड़े–बड़े भवन, हवाई–अड्डे, चौड़ी सड़कें, इत्यादि आते हैं। जो कि वनों के विनाश, प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन के कारण होते हैं। जिसके कारण सम्पूर्ण विश्व गंभीर संकट के रूप में उभरकर सामने आया है। वर्तमान में यदि समाधान की चर्चा की जाती है तो वैज्ञानिक एवं तकनीक समाधान पर केन्द्रित रहता है।

भारतीय वैदिक परम्परा में प्रकृति को मात्र संसाधन नहीं, बल्कि एक जीवंत और पूज्य सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है।[i] पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से अथर्ववेद का पृथिवी सूक्त[ii] अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस सूक्त में पृथिवी को माता और मनुष्य को उसका पुत्र माना गया है–

"**माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः**"[iii]

प्रस्तुत शोध–पत्र का उद्देश्य यह है कि अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में निहित पर्यावरण चेतना के विविध आयामों का अध्ययन करके वर्तमान में वैश्विक पर्यावरण संकट के सन्दर्भ में पुनर्परिभाषित करना।

इस शोध–पत्र में जैव–विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग, भूमि संरक्षण एवं सतत–विकास के सिद्धांतों की विवेचना की जाएगी।

मुख्य शब्द :

अथर्ववेद, पृथिवीसूक्त, पर्यावरणीय चेतना, वैश्विक पर्यावरण संकट, सतत–विकास, पर्यावरण–पारिस्थितिकी, जैव विविधता, वैदिक पर्यावरण दर्शन।

प्रस्तावना :

मानव–सभ्यता प्राचीन समय से ही, इनका सम्बन्ध परस्पर निर्भरता पर आधारित रहा है, प्राचीन मानव सभ्यता प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन–यापन किया करते थे, किन्तु औद्योगिक क्रान्ति एवं तकनीकी

विकास ने प्रकृति के प्रति उपभोगवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ। प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन के फलस्वरूप विश्व में संकट के बादल छा गए हैं। यह संकट जल–प्रदूषण, वायु–प्रदूषण, मृदा–क्षरण, जलापूर्ति, जैव–विविधता के विनाश के रूप में उभर कर आया है।

यदि भारतीय ज्ञान–परम्परा की चर्चा की जाए तो हमें ज्ञात होता है वैदिक काल से ही मानव–समाज प्रकृति से सामंजस्य बैठा के जीवन–यापन करता था। वेदों में पृथिवी, जल, वायु, अग्नि, तथा आकाश के प्रति सम्मान और संरक्षण की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। विशेष रूप से अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि किस प्रकार भूमि अर्थात् पृथिवी को माता और मनुष्य को उसका पुत्र कहा गया है।

शोध–अंतर :

भले ही पृथिवी सूक्त पर अनेंकों विद्वानों ने अनुवाद, भाष्य एवं दार्शनिक अध्ययन किया हो फिर भी आधुनिक वैश्विक संकट को देखते हुए पर्यावरणीय असंतुलन को आधार बनाकर समन्वित विश्लेषण अभी भी पर्याप्त रूप से नहीं किया गया है।

प्रस्तुत शोध–अंतर को भरने के लिए अथर्ववेद का पृथिवी सूक्त केवल धार्मिक स्तुति नहीं बल्कि विकसित पर्यावरण–दर्शन और पारिस्थितिक नैतिकता का आधारभूत ग्रन्थ है।

शोध–पद्धति :

इस शोध–पत्र में मुख्य रूप से चार प्रकार की शोध–पद्धति का उपयोग किया गया है–

(क) पाठालोचनात्मक–पद्धति

इस पद्धति से पृथिवी सूक्त के मूल मन्त्रों का भाष्यात्मक और दार्शनिक विश्लेषण किया गया है।

(ख) व्याख्यात्मक–पद्धति

इस पद्धति से मूल मन्त्रों में निहित पर्यावरणीय मूल्यों की व्याख्या की गयी है।

(ग) तुलनात्मक–पद्धति

पृथिवी सूक्त में वर्णित पर्यावरणीय दृष्टि और आधुनिक पर्यावरण चिंतन की तुलना की गयी है।

(घ) विश्लेषणात्मक–पद्धति

इस पद्धति का उपयोग आधुनिक वैश्विक पर्यावरण संकट को देखते हुए पृथिवी सूक्त में वर्णित पर्यावरण संबंधी विचारों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन किया गया है।

अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त का परिचय :

अथर्ववेद के बारहवें काण्ड का प्रथम सूक्त पृथिवी सूक्त कहलाता है, इसमें कुल ६३ मंत्र मिलते है, जिनमें पृथिवी के भौतिक जीवन, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक स्वरूप का अत्यंत सुन्दर चित्रण किया गया है । इस सूक्त को पर्यावरणीय चेतना का सर्वाधिक विकसित एवं व्यापक दस्तावेज माना जाता है। इस सूक्त को "जीवनदायिनी माता" के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है।

इसी सन्दर्भ में एक मंत्र आता है :

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः[iv]

अर्थात् पृथिवी मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। यह मंत्र मानव और प्रकृति के बीच आत्मीयता एवं उत्तरदायित्व का सम्बन्ध स्थापित करता है। आधुनिक पर्यावरण नैतिकता में जिस पेड़ों एवं जंगलों की रक्षा अथवा

पारिस्थितिक उत्तरदायित्व की चर्चा होती है। उसका प्रारम्भिक स्वरूप इस वैदिक दृष्टिकोण में देखा जा सकता है। इसमें पृथिवी की सहनशीलता, जैव–विविधता, कृषि–सम्पन्नता तथा मानव जीवन के साथ उसके अभिन्न सम्बन्ध का विषय मिलता है।[v]

पृथिवी सूक्त का प्रथम मंत्र ही नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों से होता है जो की पृथिवी के संरक्षण का आधार है :

"सत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति"[vi]

अर्थात् सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म और यज्ञ पृथिवी को धारण करते हैं। पृथिवी का संरक्षण भौतिक साधनों से नहीं बल्कि नैतिक सांस्कृतिक और अनुशासित जीवन से मुमकिन है, जो कि सतत्–पर्यावरण संरक्षण को दर्शाता है, इसमें यह भी दिखता है कि किस प्रकार इस सूक्त में आर्थिक विकास के साथ–साथ पर्यावरण का संरक्षण भी अति–आवश्यक है।

अथर्ववेद का पृथिवी सूक्त जैव–विविधता की अवधारणा को दर्शाता है, क्योंकि इस सूक्त में पर्वतों, नदियों, वनस्पतियों, औषधियों, पशुओं एवं कृषि का बहुत ही सम्मानपूर्ण वर्णन मिलता है एवं पृथिवी को ऐसी शक्ति के रूप में दर्शाया गया है जो कि विभिन्न प्रकार के जीवन को धारण एवं पोषण करती है।

पृथिवी सूक्त में पर्यावरण चेतना के आयाम :

(क) पृथिवी 'माता' की अवधारणा और पारिस्थितिक उत्तरदायित्व :

यदि पृथिवी सूक्त में पर्यावरणीय सिद्धान्त की बात की जाए तो यह सूक्त पृथिवी को माता और मनुष्य को उसका पुत्र कहा गया है। यह भाव होने के कारण मनुष्य प्रकृति एवं पर्यावरण का सम्बन्ध केवल उपभोग ही नहीं बल्कि संरक्षण एवं उत्तरदायित्व बन जाता है।

आधुनिक औद्योगिक सभ्यता ने प्रकृति को केवल उपभोग का संसाधन मानकर केवल दोहन ही किया है जिसके कारण आज पर्यावरणीय वैश्विक–संकट उत्पन्न हुआ वहीं इसके विपरीत अथर्ववेद का पृथिवी सूक्त मानव और प्रकृति के मध्य सामंजस्य स्थापित करके जीवन–यापन का सन्देश देता है।

(ख) जैव-विविधता संरक्षण की चेतना :

इस सूक्त में विविध–प्रकार के वनस्पतियों, औषधियों, पशुओं, जीव–जंतुओं की धात्री एवं संरक्षिका के रूप में वर्णन होने के कारण पृथिवी की उस क्षमता का वर्णन मिलता है जिसके द्वारा वह विभिन्न प्रकार के जीवन–रूपों को धारण और पोषण करती है। यह असंख्य वनस्पतियों एवं औषधियों को धारण करती है जो मानव एवं अन्य प्राणियों का आधार है। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के कारण पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है इस प्रसंग में पृथिवी सूक्त का सन्देश और भी प्रासंगिक हो जाता है।

(ग) जल-संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग की अवधारणा :

वैदिक–साहित्य में जल को जीवन का आधार माना गया है। पृथिवी सूक्त में भी पृथिवी को नदियों, झरनों और जल–स्रोतों की संरक्षिका के रूप में चित्रित किया गया है।[vii]

जल के अत्यधिक दोहन के कारण विश्व में जल संकट आ गया है। कहीं पीने के लिए स्वच्छ जल नहीं है, तो कहीं पर पानी ही उपलब्ध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार आने वाले दशकों में स्वच्छ जल की उपलब्धता मानव–सभ्यता के लिए चुनौतीपूर्ण होने वाला है।[viii]

पृथिवी–सूक्त मानव समाज को सन्देश देता है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपभोग करते हुए प्रकृति से सामंजस्य बैठा का जीवन–यापन करे। वैदिक साहित्य संतुलित उपयोग की शिक्षा देता है।

(घ) भूमि संरक्षण एवं कृषि–संस्कृति :

वर्तमान–काल में रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हुए कृषि की जाती है जिसके फलस्वरूप अनाज का उत्पादन अधिक तो हो जाता है किन्तु भूमि में रासायनिक पदार्थों को डालने से भूमि की उर्वराशक्ति कम हो जाती है। पृथिवी सूक्त हमें भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने की शिक्षा देता है। इसके अनुसार मानव का नैतिक दायित्व है।

पृथिवी सूक्त की पर्यावरणीय दृष्टि हमें भूमि के संरक्षण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की ओर प्रेरित करती है।[ix]

(ङ) सतत्–विकास की वैदिक अवधारणा :

सतत्–विकास के मूल सिद्धान्त का अर्थ यह है कि वर्तमान पीढी प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग सीमित एवं आवश्यकता अनुसार करे, जिससे भविष्य में आने वाली पीढी को कठिनाईयों का सामना ना करना पड़े। वैदिक साहित्य में कहीं भी प्राकृतिक संसाधनों का असीमित दोहन का वर्णन नहीं है। बल्कि पृथिवी सूक्त प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और आवश्यकता अनुसार उपयोग की शिक्षा देता है।

समकालीन वैश्विक पर्यावरण संकट और पृथिवी सूक्त की प्रासंगिकता :

यदि हम ध्यान दें तो हम देखते हैं किस प्रकार विश्व भर में जल का संकट उत्पन्न हो गया है वायु–प्रदूषण बढ़ चुका है, मृदा क्षरण देखने को मिलता है, विश्वभर का तापमान बढ़ चुका है, ऐसी संकट क्यों उत्पन्न हुई? इसका उत्तर होगा, मानव–समाज अपनी आवश्यकताओं औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार, चौड़ी सड़कें बनाने इत्यादि अपनी सुख सुविधाओं की लालसा के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहा है। पहाड़ों पर सड़कें बनाने के लिए पेड़ों की कटाई तेजी से की जा रही है, जंगलों को साफ किया जा रहा है, फैक्ट्रियों के रासायनिक जल को नदियों में छोड़ा जा रहा है जिस कारण अनेंको प्रकार के जीव–जंतु लुप्त होते जा रहे हैं जिससे पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ वैदिक साहित्य विशेष रूप से अथर्ववेद का पृथिवी सूक्त पर्यावरण के प्रति नैतिक कर्तव्यों का पालन करने का सन्देश देता है। मानव समाज को शिक्षा देता है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आवश्यकतानुसार ही किया जाए।

आज जब विश्व, "सस्टेनेबिलिटी" "ग्रीन एकोनोमी" और "क्लाइमेट जस्टिस" जैसी अवधारणाओं की ओर अग्रसर है तब पृथिवी सूक्त की शिक्षाएं वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकती है।[x]

निष्कर्ष –

प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्तमान में उत्पन्न वैश्विक पर्यावरण संकट के समाधान में अथर्ववेद का पृथिवी सूक्त एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता हैं, हमनें देखा कि किस प्रकार यह सूक्त भूमि को मां और मनुष्य को उसका पुत्र की बात करता है, यहाँ नैतिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न होती है जिससे मनुष्य भूमि के प्रति जिम्मेदार एवं अपनी नैतिक कर्त्तव्य का पालन करेगा।

इस अध्यायन के पश्चात् यह भी ज्ञात होता है कि वैदिक साहित्य विशेष रूप से अथर्ववेद का पृथिवी सूक्त प्राचीन भारतीय ज्ञान–परम्परा की धरोहर नहीं, बल्कि आधुनिक पर्यावरण विमर्श के लिए भी एक महत्वपूर्ण

वैचारिक आधार है।

संदर्भ :

i. वासुदेव शरण अग्रवाल, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण चेतना, द्वितीय संस्करण, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.१०३–१०६.

ii. अथर्ववेद संहिता काण्ड १२ सूक्त १

iii. अथर्ववेद संहिता– १२.१.१

iv. अथर्ववेद संहिता– १२.१.१२

v. विलियम ड्वेह व्हिटने, अथर्ववेद संहिता, वॉल्यूम २, हार्वर्ड ओरिएण्टल सीरीज, कैम्ब्रिज, १६०५, पृ. ६३१–६३७.

vi. अथर्ववेद संहिता– १२.१.१

vii. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर (संपा.), अथर्ववेद संहिता प्रथम संस्करण, स्वाध्याय मण्डल, पारडी, १६५७, काण्ड १२, सूक्त १ पृ. ४८८–४६१

viii. यू.एन.डब्लू.डब्लू डी आर, वाटर फॉर सस्टेनेबल डेवेलपमेंट, यूनेस्को, पब्लिकेशन, पेरिस, २००३, पृ.३–६.

ix. रामचन्द्र गुहा, एनवायरमेंटालिजम : ए ग्लोबल हिस्ट्री, सेकण्ड एडिशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, २०१४ पृ. ७८–२२

x. यूनाइटेनेशन, ट्रांसफोर्मिंग आवर वर्ल्ड : द २०३० एजेंडा फॉर सस्टेनेबल ड़ेवेलपमेंट, न्यूयॉर्क, २०१५, पृ. ६–१२.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 100-105

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

पर्यावरण चेतना में यज का महत्त्व

अमल बर्मण

संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय।

सारांश :

पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन में यज्ञ का महत्वपूर्ण योगदान है। अन्न तथा अन्नाद का संबंध ही यज्ञ है। यही क्रम जब यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म' के रूप में प्रतिपादित होता है तो देवता के उद्ध्देश्य से हवनीय पदार्थ शुद्ध घृत सुगंधित, वायुशोधक, पदार्थों की अग्नि में आहुति दी जाती है, उसे हम यज्ञ कहते हैं। वैदिक यज्ञ व्यवस्था पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आज वायुमंडल में कार्बनडाई ऑक्साइड की मात्रा निरन्तर वृघद्धि को प्राप्त होती दिखाई दे रही है। इस कारण पर्यावरण प्रदूषण के साथ परिस्थिती की असंतुलन बडता जा रहा है। यज से पर्यावरण शुद्ध होता है। पूर्व में मुनि लोग नित्य यज्ञ (अग्निहोत्र) करते थे। फलतः हमारा वायुमंडल पूर्णरूपेन शुद्ध था। हवनीय पदार्थों के कारण वायु शुद्ध होकर रोगनाशक होती है। हरिद्वार के शांतिकुज में स्थित ब्रह्मवर्चस् शोध संस्थान में एक यंत्र है जो निर्देश करता है कि यज्ञ के माध्यम से कितना दूर तक वायुमंडल स्वच्छ होता है। अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के अध्ययन से ज्ञात होता है कि हवन करने से चारों दिशाओं में स्थित सभी जीव–जंतुओं का सब प्रकार से कल्याण होता है। पर्यावरण की शुद्धता का परिपोषक, समस्त जगत के कल्याण में तत्पर यज्ञ की प्रासंगिकता जितनी प्राचीन समय में थी उतनी ही महत्वपूर्ण वर्तमान में भी है। अयः हम वैदिक ऋषियों के सिद्धांतों को मानकर यदि पुनः प्रकृति की ओर लौट चलें तो अवश्य ही कल्याण होगा तथा मानवजाति की रक्षा हो सकेगी।

प्रस्तावना :

पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन में यज्ञ का महत्वपूर्ण योगदान है। अन्न तथा अन्नाद का संबंध ही यज है। यही क्रम जब "**यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म**"[i] के रूप में प्रतिपादित होता है तो देवता के उद्देश्य से हवनीय पदार्थ शुद्ध घृत सुगंधित, वायुशोधक पदार्थों की अग्नि में आहूति दी जाती है, उसे हम यज्ञ कहते हैं। यज्ञ से वातावरण शुद्धि के साथ वैचारिक शुद्धि भी होती है। यज्ञ का फल तो चतुर्दिक होता है–

"**यज्ञस्य दोहो विततः पुरूत्रा**"[ii]।

पर्यावरण में यज्ञ का महत्व :

यज अर्थात् अग्निहोत्र औषधि कार्य करता है– "**अग्निः कृणोतु भेषजम्**"[iii]। आचार्य यास्क जी ने निरुक्त में ष्ऋतुश शब्द को यज्ञ के पर्याय रूप में स्वीकार किया है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल को शोषित कर मेघ रूप में पृथ्वी पर बरसात है। पुष्प, फल, शाकादि पृथ्वी के अन्तस्थल में अपनी आहुति देकर वृक्ष रूप

में सहस्त्रों फलों को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार याजिक प्रक्रिया द्वारा सृष्टि प्रकिया सदैव चलती है। यहाँ गिव एंड टेक का सिद्धांत प्रयुक्त होता है। श्रीमद्भगवादगीता में कहा गया है कि–

सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः।

अनेन प्रविस्यमेष.. यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः।[iv]

यौ में अग्नि प्रज्ज्वलन से तात्पर्य है मानव की सुषुप्त आत्मज्योति के जागरण से ही मानव का सर्वांगीण कल्याण सम्भव है। इसके अतिरिक्त यज्ञों के अन्त में स्वाहा' शब्द का उच्चारण किया जाता है। जिसका तात्पर्य है स्वार्थपरक भावना का पूर्ण से परित्याग। यज भावना का उपदेश देते हैं। ष्यज् धातु देवपूजा, संगतिकरण तथा दानार्थक होती है।

वैदिक यज व्यवस्था पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आज वायुमंडल में कार्बनडाई ऑक्साइड की मात्रा निरंतर वृघद्धि को प्राप्त होती दिखाई दे रही है। इस कारण पर्यावरण प्रदूषण के साथ पारिस्थितिकी असुन्तल वड़ता जा रहा है। यर्जी में डाली गई आहुतियों किटाणुओं को उसी प्रकार बहा ले जाती है जिस प्रकार नदी जल के साथ जल के झाग को–

इदं हवियर्यातुधानान् नदी फनमिवा वहत्।

य इदं स्त्री पुमानकः इह सः स्तुवतां जनः[v]**।।**

यज से पर्यावरण शुद्ध होता है। पूर्व में मुनि लोग नित्य यज (अग्निहोत्र) करते थे। फलतः हमारा वायुमंडल पूर्णरूपेन शुद्ध था। हवनीय पदार्थों के कारण वायु शुद्ध होकर रोगनाशक होती है। हरिद्वार के शांतिकुंज में स्थित ब्रह्मवर्चस् शोध संस्थान में एक यंत्र है जो निर्देश करता है कि यज्ञ के माध्यम से कितनी दूर तक वायुमंडल स्वच्छ होता है। अथर्ववेद तथा यजुर्वेद के अध्ययन से जान होता है कि हवन करने से चारों दिशाओं में स्थित सभी जीव–जंतुओं का सब प्रकार से कल्याण होता है कि

पशष्य दोहो विततः पुरूषाः सो अस्टधा दिमन्वाततान्।

स यज्ञ धुक्ष्व महि में प्रजायाम् रायस्पोषम् विश्वमायुरशीय स्वाहा[vi]**।।**

जटामाशी, गुग्गुल, गुर्जा, अगर, तगर, घृत, हरिद्रा, पिपली, चंदन, आदि वायुशोधक पदार्थ हैं जो वायुमंडल को पवित्र करते हैं। वायुमंडल के शुद्ध होने से शुद्ध वायु प्राप्त होती है। घातक किटनाशक रहित पौधे सभी प्राणियों के पौषण करते हैं कि–

'देवो वनस्पतिर्जुषतां हविहॉतर्यज्[vii]**।**

अग्नि गूड़ स्थानों में छिपे हुए रोगों के कृमियों को निकाल कर उनका नाश करती है–

यत्रेषामग्ने जनिमानि वेथ्य, गुहा सतामतत्रिणाम् जातवेद : जहयेषाम् शततर्हमग्ने।[viii]

विष्णुपुराण में यज्ञ की महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए यज को समस्त सृष्टि के मूल में विद्यमान बताया गया है –

देहय्नुयज महाराज मा धर्मो यातु संक्षयम्।

हविषाम्...जगत्।। [ix]

यज्ञ से उत्पन्न धूम (धुआँ) रोगाणुरोधक होता है। यह रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का उन्मूलन करता है। यही कारण है कि जिस घर में नित्य नियमानुसार यज किया जाता है वहाँ पीड़ा, रोग तथा विकार

नस्ट हो जाते हैं। यज के कल्याणकारक रूप का वर्णन यजुर्वेद में बताया गया है कि–

हविष्मतीरिमा आपो हविष्मा आ विवासती अस्तु सूर्य।। [x]

यज्ञ के द्वारा मानसिक, बौद्धिक आदि रोगों का नाश होता है। यज्ञ में डाली गई हवि (आहुतियों) में वायुशोधन की क्षमता होती है। यद्यपि वनस्पतिओं, वृक्षों द्वारा भी की शुद्धि होती है तथापि वायु को शुद्ध गुणकारी करने की जितनी शक्ति अग्नि में विद्यमान है उतनी किसी अन्य में नहीं। शुद्ध गाय के घी में केशर, कुस्तुरी, गुग्गुल, कर्पूर आदि रोगनाशक जड़ी–बूटी का मिश्रण अग्नि में होम करने से वातावरण में उपस्थित प्रदूषणों का निस्तारण होता है जल तथा वायु का भी शोधन होता है। अथः यज द्वारा पर्यावरण शुद्धि वेदों की अद्‌भुत उपलब्धि है।

घर में की गई यजाहति घर के अंदर तथा समीपस्थ की वायु करती है तथा मंदिरों, आश्रमों, सार्वजनिक स्थानों में किये गये यज विस्तृत स्थान की वायु को पवित्र कर गुणकारी तथा रोगमुक्त बनाते हैं। यज्ञ वर्षाकारक भी होते हैं। यज्ञ का पवित्र धूम भारहिन होने के कारण आकाश में जमकर वर्षा का कारण होता है–

अर्जा प्रास्ताहुतीः सम्यगादित्यमुपसर्पती।
आदित्याज्जायते वृष्टिर्वस्टेरन्नम् ततः प्रजाः।।
अन्नादभवन्ति भूतानी पर्जन्यादन्नसम्भवः।
यज्ञादभवति पर्जन्यो यजः कर्मसमुद्‌भव।। [xi]

अथर्ववेद में भूमि को माता कहा गया है। हम भूमि को पोषक तत्व प्रदान करें, भूमि की हिंसा न करें अपितु रक्षा करें। पर्यावरण की दृष्टि से हमारे ऋषियों ने जो उदात संकल्पना की है, प्रकृति तथा पर्यावरण की दृष्टि से ऋषिर्या के चितन की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करती है। तैतिरीय श्रुति के अनुसार ब्रमांड के पारिस्थितिकी चक्र में पर्यावरण से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी आविर्भूत् हुई। पृथ्वी से औषधियों प्रकट हुई। औषधियां से अन्न तथा अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ। इस वृहत प्रणाली में किसी एक भी कड़ी के प्रदूषित अथवा अव्यवस्थित होने पर समस्त प्रणाली प्रतिकूलता प्रवाहित हो जाती है। भोजन दुग्ध, जल अन्नादि में प्रविष्ट होकर जो रोग, जन्तु हानि पहुंचाते हैं उन्हें यज द्वारा नस्ट कर दिया जाता है।[xii] यज्ञ (अग्निहोत्र), अग्नि, जल, मिट्टी, वनस्पति आदि के प्रदूषण दूर करने में सहायक है। अग्नि वायु से दूषक तत्वों का उन्मूलन करता है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारी वैदिक ज्ञान परम्परा में यज द्वारा किसी न किसी प्रकार से पर्यावरण चेतना को जागृत करने की अद्‌भुत क्षमता विद्यमान है।

'विष्णुपुराण' में यज के महात्मय को वर्णन करते हुए ऋषि द्वारा कहा गया है कि यह समस्त जगत् हवि का ही परिणाम है–

'हविषा परिणामोअयम् यतेत दाखिलम् जगत्" [xiii]

अथः यज ही कल्याण का साधन है –

ततश्चाज्याहुतिद्वारा पोषीतास्ते हविर्भुजः।
वृस्टे कारणताम् यान्ति भूतानं स्थितये पुनः।। [xiv]

यज्ञ द्वारा वैदिककाल से ही पर्यावरण संतुलन का निर्माण किया जाता रहा। आज भी यदि यज्ञ का महत्त्व को जानकर याजिक वैदिक संस्कृति का अनुसरण कर कार्य संपादित किये जायें तो पारिस्थितिकीय का निवारण

हो सकता है। भैषज्य यज्ञों से तो अनेकानेक रोगों की चिकित्सा भी संभव है–

भैषज्य यजा वा एते यत् चातुर्मास्यानि, तस्माद् ऋतुसं धिषु प्रयुज्यन्ते।
ऋतुसंधिषु वै व्याधिर्जयाते।। [xv]

इस विषय में आचार्य कपिलदेव जी का कथन है कि विविध वैज्ञानिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो चुका है कि अग्निहोत्र से वायु निकलती है, वह वातावरण को शुद्ध तथा प्रदूषण मुक्त करती है। अमेरिका न्यू जर्सी प्रांत में अग्निहोत्र नाम एक संस्था है जो अमेरिका में प्रदूषण निवारण हेतु अग्निहोत्र का अत्यधिक परिणाम में प्रयोग तथा प्रचार करती है। यजकार्य में मंत्रों का सस्वर पाठ ध्वनि प्रदूषण की समस्या का उत्तम समाधान है। ऋतु परिवर्तन के समय प्रकृति में कतिपय दूषित तथा तत्व उत्पन्न होते हैं जिनका कारण वायु मण्डल प्रदूषित होता है तथा विविध रोग उत्पन्न होते हैं। वायु प्रदूषण तथा विविध रोगों का निराकरण तथा समाधान गोपथ तथा कौषीतकि ब्राह्मण में वर्णित भैषज्य यज्ञों के द्वारा किया जा सकता है।

अमेरिका मनोवैज्ञानिक बेरी रैयनर (जो पुणे विश्वविद्यालय में यज पर शोधकार्य कर रहे थे) का कहना है कि अग्निहोत्र वायुमंडल में एक विशिष्ट ढंग का प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका मानव पर चिकित्सकीय प्रभाव पड़ता है। उसे चिकित्सकीय प्रभाव की आयुर्वेद में विशेष रूप से चर्चा है। प्राचीन काल में हमारे देश में जो सुख संपन्नता थी, धरती सध्य श्यामला थी. आपदाओं का अभाव था इन सबके पीछे यज्ञ प्रकियाओं का महत्व महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

सम्भवतः जनसाधारण का यह मानना है कि यज्ञ में लकड़ी (समिधा) के जलने से कार्बनडाई आक्साइड पैदा होती है, किंतु रसायन विज्ञान के माध्यम से यह बात सिद्ध होती है कि आम वस्तुओं जो जलाने तथा यज्ञ के अनुष्ठान में काफी अंतर है। यज में प्रयुक्त होने वाले गोघृत, चावल तथा मीठे पदार्थों में वीटा कैरोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होती हैं। जब हम उन्हें यज में जलाते हैं तो ये पदार्थ कार्बनडाई आक्साइड गैस में रूपांतरित होकर नेसेंट हाईड्रोजन निकालते हैं तथा वह कार्बन तथा आक्सीजन के साथ फार्मेल्डिहाइड, इथाइल एल्कोहल तथा प्रोपिनाइक अम्ल बनाते हैं। ये तत्व हानिकारक नहीं हैं अपितु विसंक्रमणकारी हैं तथा वातावरण के प्रदूषण को नस्ट करते हैं।

यज्ञ द्वारा वातावरण को शुद्ध कर अनेक संक्रामक रोगों को भी फैलने से रोका जा सकता है। यज से पर्यावरणीय स्वास्थ्य बड़ता है तथा मानव, पशु तथा वनस्पति की साधारण विकास प्रक्रियाओं में सुधार तथा वृद्धि होती है। यज की राख का कई पौधों पर प्रयोग करने पर पाया गया कि इससे फलों की मात्रा, स्वाद में बड़ीतती होती है।

वेदों में केवल वाह्य जड़ प्रकृति का प्रदूषण ही नहीं अपितु शरीरिक एवं मानसिक प्रदूषण जो रोकने की भी भावना व्यक्त की गई है। अथर्ववेद के एक मंत्र के साफ साफ कहा गया है कि हे मन के पापा तु मुझसे दूर हट, तु मुझे असद् मार्ग पर क्यों ले जाता है। मैं तेरी कामना नहीं करता हूँ। इसी प्रकार का भाव यजुर्वेद के शिवसंकल्पसूक्त में मिलत है। वहाँ "**तन्मे मनः शिवसंककल्पमस्तु**' की उद्भावना की गई है।[xvi]

वैदिक ऋषियों ने पर्यावरण को समग्र दृष्टि से अभिन्न रूप में प्रतिपादित कर जीवन के साथ अनुस्यूत कर दिया था। प्रकृति तथा मानव जीवन का सामजस्य एवं संतुलन ही पर्यावरण संरक्षण था। यज्ञ पर्यावरण के प्राण हैं। इससे भूतों, प्राणियों तथा समस्त विश्व की रक्षा होती है। कालिदास ने 'रघुवंश' महाकाव्य के पंचम सर्ग

में 'यज' का वर्णन किया है। 'यज्ञ' में विश्व कल्याण की आवना सन्निहित होती है। 'यजमान शिव की अस्टमूर्तियों में परिगणित किया जाता है। वह उस समय सामान्य मानव न होकर शिवत्व रूप होता है।

वैदिक ऋषियों ने पर्यावरण संरक्षण के वाह्य तथा आभ्यंतर दोनों ही पक्षी सूक्ष्म चिंतन किया। आज मानव ने हमारे वैदिक ऋषियों के सिद्धांतों का उल्लंघन कर प्रकृति के साथ अनुकूलता को समाप्त कर दिया है। सर्वत्र प्रकृति को अपने लाभ के लिए उजाड़ने में लगा है। संतुलन समाप्त होने से आज उसे सभी दिशाओं से संपूर्ण प्रकृति से भय है।

वायु, जल, भूमि, वनस्पति, वृक्ष, पशु, मानव अर्थात् पृथ्वी पर स्थित जैविक तथा अजैविक तत्व जिस पर्यावरण की संरचना करते हैं, उसे बनाए रखना आज परमावश्यक है। जीवन की गुणवत्ता पर्यावरण की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अथः स्वच्छ भोजन, निरापद वायु, स्वच्छ गृह तथा प्रदूषण रहित वातावरण एक अच्छे पर्यावरण के आवश्यक घटक हैं। जीवन के लिए मानसिक रूप से स्वस्थ होना तथा प्रकृति से विरासत में मिले हुए विविध पदार्थों का समुचित उपयोग करना नितांत आवश्यक है।

यजभूमि के वरण हेतु प्रयोग के जाने वाले मंत्र में भी पर्यावरण संरक्षण की आवना का संकेत दृगगोचर होता है –

'येन यजेनोत्तमैः पदायैः सह शोभना इयं पृथ्वी भवति
येन च कल्याणकारिभिर्गुनैरियं मंगलप्रदा भवति' ।[xviii]

उपसंहार :

उक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण की शुद्धता का परिपोषक, समस्त जगत् के कल्याण में तत्पर यज्ञ की प्रासंगिकता जितनी प्राचीन समय में थी उतनी ही महत्व वर्तमान में भी है। अथः हम वैदिक ऋषियों के सिद्धांतों को मानकर यदि पुनः प्रकृति की ओर लौट चलै तो अवश्य ही कल्याण होगा तथा मानव जाति की रक्षा हो सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. मलिक, जसवीर सिंह, प्राचीन भारत में पौरोहित्य, क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, १९९९
2. शतपथ ब्राह्मण ११.५.४, चौखम्बा संस्कृत सीरिज, वाराणसी, १९६४
3. आचार्य, पंडित श्रीराम शर्मा, गायत्री महाविज्ञान, भाग १, संयुक्त संस्करण–२००९, पृ. १२७
4. एस और बास्कर, आर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पर्यावरण अध्ययन करता है, पुस्तक महल, दरियागंज, नई दिल्ली, २०११
5. धनकर, आर : पर्यावरण अध्ययन, दया पब्लिशिंग हाऊस, दिल्ली, ११००३५
6. डॉ. द्विवेदी, कपिलदेव, अथर्ववेद का सांस्कृतिक अध्ययन, विश्वभारती अनुसंधान परिषद, तृतीय संस्करण, सन, २०२१, ज्ञानपुर (भदोही)
7. सिंह. एस, वैदिक संस्कृति में यज्ञ एक समग्र जीवन दर्शन एवं साधना पथ. इंटरडिस जी. यज्ञ रेस. २०१९ दिसंबर ३१:२ (२) १–६

8. कुमार, सुभाष, राजसूय यज्ञ सिद्धांत और परम्परा एक अध्ययन. पी. एच. डी. शोध, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा, २००६

i. शतपथब्राह्मण–१४.३.२.६
ii. यजुर्वेद– ८.६२
iii. अथर्ववेद–८.१०६४
iv. गीता–३.१०–१२
v. अथर्ववेद–१.८१.१३
vi. यजुर्वेद–८.६३
vii. यजुर्वेद– २१.४६
viii. अथर्ववेद–१.८.४
ix. विष्णुपुराण–१.१३.२५
x. यजुर्वेद– ६.२३
xi. गीता–३.१४
xii. शतपतब्राह्मण–८.७.३.२१
xiii. विष्णुपुराण–२.७.११
xiv. विष्णुपुराण– २.८.१०६
xv. गोपथब्राह्मण उत्तर–१.१६
xvi. यजुर्वेद–३४.१–६
xvii. अभिज्ञानशाकुन्तलम्–१.१
xviii. वाजसनेयि संहिता–१.२७

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 106-114

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Changing Nature of Modern State in Digital era and Construction of New Political Identity through Biometric and Various Technological Advancement

Mukesh Kumar
PhD, Research Scholar,
Department of Political Science, University of Delhi.

ABSTRACT :

Biometric identification systems are increasingly integrated into political processes worldwide, raising complex issues at the intersection of technology, identity, and governance. This paper explores how biometric modalities—such as fingerprinting, facial recognition, and iris scanning—are reshaping the construction and verification of political identity. By examining the dual role of biometrics in both facilitating secure, efficient voter registration and in potentially reinforcing state surveillance, the study highlights how these technologies can simultaneously empower democratic participation and impose new forms of exclusion.Here I'm using Indian framework like digital tool Adhar which aims are to identify millions of people for efficient governance and welfare schemes of indian state but there's attached ambiguity in it also like in terms of political identity where state might use it in her interest and could study voting behaviour of different communities and other racial-ethnic identity.

In Covid -19 pandemic government collected huge data for health services but there are cases of privacy breaches also and with technological advancements ,state faces challenges to protect individual's privacy and individual data from misuse because of involvement of corporate companies also for assistance from the state . changing Nature of biometrics like earlier it was for security purposes for identifying criminals but in today's digital era it's used for multiple purposes and it entered in all spheres of life . The state also faces a challenge to protect her sovereignty because of increasing interference of corporate companies in the digital sphere. A kind of parallel system is being created in front of the state which controls millions of people virtually. That's for maintaining

her sovereignty and autonomy. Indian states also came with data protection laws also . The parliament took special interest in Aadhar, a Project that could lead to a fundamental reorganization of public action and have far-reaching consequences on the lives of Indians.

INTRODUCTION :

This paper is going to elaborate the challenges as well as opportunity state have due to technological advancements and impact of digitalisation on state ,society ,economy and culture how state itself is changing in digital global world and creating national digital transformation ecosystem, because of high technology changing nature of market and demand for entrepreneurial state and creating digital infrastructure on national level and required policy or legislation for regulating digital platforms and stopping monopoly in the supply of digital platform and checks and balance mechanism for concentration in order to ensure shared prosperity and at the same time public-private collaboration is necessary for digital infrastructure. Because of rapid digitalisation the state should have a legal framework for data privacy and security because all are digital now (Hanna,2018) **.** technology always has dual nature like state are using digital technology for governance for delivering it's welfare schemes to public but also can use it this vast public data for their interest for example biometric identification and facial recognition and installed camera in public places which might cause surveillance of their citizens and might be justified like State have responsibility to Protect their citizens from any external or internal injuries so one hand state has to deliver welfare schemes or consideration of governance issue and in one hand national security. The modern state has undergone a profound transformation in the digital age, where technology shapes governance, policy-making, and citizen engagement. Digital advancements have redefined how governments operate, from data-driven decision-making to the automation of public services. The internet, artificial intelligence, and blockchain have introduced new opportunities for transparency, efficiency, and security, while also posing challenges such as cyber threats, misinformation, and digital inequality or digital divide

In this era, the state must balance innovation with regulation, ensuring that technology serves the public good while protecting individual rights and national security (Kurbalija j 2016) Digital governance, e-government initiatives, and smart city projects reflect how states are leveraging technology to enhance governance structure and public institutions. At the same time, the digital global world has reshaped geopolitical dynamics, with data diplomacy and digital sovereignty becoming critical concerns.

As we navigate the digital age, the role of the state is being reimagined—not only as a regulator and policymaker but also as a digital innovator and protector of virtual space . The intersection of technology and governance will continue to shape the future of the modern state, influencing everything

from democratic participation and economic development (Castells.1996). In the digital age ,the state and relationship of citizens are also changing because everything is being recorded digitally so participation depends on citizen's awareness about technological advancements and construction of new political identity through biometric. Political identity refers to an individual's relationship with the state, including citizenship, rights, and participation in governance. Traditionally, this identity was established through passports, voter registration, and national IDs. However, in the digital age, biometrics and surveillance have redefined political identity by linking individuals to digital records and tracking their activities.

Biometric identity systems (facial recognition, Fingerprint scanning,Iris and retina scans,DNA profiling,voice recognition) help in verifying citizenship and access to public services.Data-driven governance creates profiles of citizens based on digital footprints, influencing policy decisions.Governments worldwide use biometric IDs for official documentation (e.g., India's Aadhaar system, the UK's biometric passports).Helps in linking individuals to taxation, healthcare, and social service.

Digitalisation and technological advancements :

1.2 of the Welfare State and the National Security State; it is their logical successor. The Welfare State governs domestic affairs by spending and transferring money and various welfare schemes by creating public schemes , licenses, and enhancing the public sector. The National Security State promotes foreign policy through investments in defense industries and defense-related technologies, through creating and expanding national intelligence agencies(Balkin 2018) .Rapid technological Advancements also affect public institutions and their functioning. Because of rapid Digitalisation ,there is also increasing competition ween states for investment, human capital,innovation, and so on(Osipov 2019) .because of this state is moving from process management to problem- solving system.Effective problem-solving requires clearly identifying input data, establishing a structured decision-making process, and ensuring practical implementation. This approach can be achieved through a project-functional structure within the state apparatus, as developed by digital global world(Osipov (201).so by reforming public institutions according to digital infrastructure. Because the public institution learns to solve problems and present the results of its activities; it is trained to a certain behavior and a certain order of solving problems. Without these skills, the digital state as the end point of the paradigm is impossible.The transition to the state apparatus obviously, aims to add dynamism in the existing public institutions. In the digital age, the Internet disrupts the traditional link between legally significant actions and the physical location of the individuals performing them. As a result, a national government's authority to enforce regulations

on global digital activities is no longer tied to the geographical position of those involved in legal relations. This detachment enables opportunistic behavior, as individuals recognize that state control is weaker in online spaces compared to the physical world within national borders. Consequently, the Internet is reshaping the way rules are established, moving away from territorial boundaries and challenging the conventional power of the state in digital governance(Borins,2007). Digital state is moving towards the Digital economy .The digital state is trying to find the possibility of controlling the material flow , which is managed online.It is important to understand how the state could control the financial flow of the network. All bank accounts are digitized . transactions can be of great help here. Under pressure from central banks and the national economy.

State ,technology and digital India :

1.2 It's established that in the twenty-first century we can't imagine our life without technology. One of the most powerful technologies is the power of digitalisation. The system which allows individuals to communicate and connect virtually. Digital program in India was launched to create digital infrastructure at country level on 2 july 2015 to ensure that welfare schemes are made available to citizens digitally by Improving public institutions according to the need of the digital age and efficient governance. And by increasing Internet connectivity or by making the country digitally empowered in the field of technology. To achieve this goal India needs to work on various fronts such as the creation of digital infrastructure and delivering services electronically and digital literacy and that is a tough task also because of digital inequality and digital divide . So the first task was in front of the Indian state to digitize its public institutions , then it can be possible to reach a broader level. So digital India was a master program which included many departments (Midha,2016).this initiatives was towards digital state from bureaucratic-service state.the purpose was to enrich delivery system and information will be available, anytime or any device that are user friendly and accessible to everyone so state was prepared to connect every Programme with e-power .so overcome Challenges to implement these policies so state took necessary step like Education for all like Encouraging digital literacy through initiatives like PMGDISHA (Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan) and providing access to digital resources in regional languages.information for all,broadband for all and providing platform for leadership. For high speed Internet for every citizen digital infrastructure was required and everything will be recorded digitally so safe and secure cyberspace was also a concern of the modern state. So public demand was included in the digital India project like making financial transaction electronics and cashless and providing single window access to every individual. Indian government aims to target digital state's piller for digital India like broadband highways,universal access to mobile ,public Internet access program ,e-governance reforming government through

technology, e kranti-Electronic delivery of services, information for all,electronics manufacturing,it for jobs,early harvest programmes. The very challenges Indian state was facing in infrastructure development was rural-urban divide ,illiteracy in technological fields which creates digital divide. So there were various barriers to implementing these programs completely such as infrastructure deficit and lack of towers ,especially in the countryside and auxiliary services such as health, education, banking ,governance etc were developed.The Aadhaar system which was Introduced by the Government of India in 2009, the Aadhaar system is the world's most extensive biometric identification initiative. It provides Indian residents with a unique 12-digit identity number, which is generated using their biometric and demographic information.The Aadhaar system has transformed digital identity verification in India. However, issues concerning privacy, security, and evolving technologies require further examination.

National Surveillance state :

Since the 9/11 attacks, discussions and debates on the expansion of security measures, often referred to as "securitization," have been framed around the balance between liberty and security. Increased SurveillanceTechniques,identification technologies such as biometrics, and the marriage of these in contemporary trusted traveler programs, for example, are generally rationalized in popular discourse through the language of efficiency,This account dramatically recasts the relationship between liberty and security, and provides an insightful framework for comprehending the contemporary governance of borders and bodies(Muller 2010). In the context of border security, a key issue is the outsourcing of surveillance infrastructure, including ID card systems and biometric technologies. This raises questions about the role of security professionals—referred to by Bigo and others as "managers of unease"—in shaping perceptions of risk (see Salter 2008a, 2008b).so here contestation arises between corporate ownership of these technologies and state sovereignty. In other words, once security concerns are introduced, these professionals not only provide "security solutions" but also influence how risks are defined and understood. The use of biometric identification, CCTV surveillance, and various ID card and trusted traveler programs as security measures assumes certain notions of risk—who or what constitutes a threat and how these threats are expected to behave. So digital state also faces this dichotomy between security issue and governance or delivering something to the people . While modern biometric technologies are commonly used in security-related fields in geopolitics such as passport systems, national identity cards, and work visas potentially improving public acceptance of biometrics, a deeper examination raises critical concerns for global Investments and the rapid global economy.

During the covid-19 global pandemic ,many countries enhanced their data system for decreasing

covid positive cases and tracking infection rates so such surveillance can save lives .Surveillance is part of daily life .such data enable health professionals in shaping policies and taking step with time to address these pandemic in future .so the major concern in contemporary time is seeking privacy and data justice is to find fair ways of revealing ,characterizing and dealing with people because social surveillance is growing, constantly(Lyon,2003). In today's world, the creation of social categories and identities through IT-driven surveillance increasingly depends on the growing integration of individual physical traits with information systems. If someone is absent from the information system, he is absent from various states' public schemes, so a new political identity or social categorization is being constructed virtually in the digital world.

Fingerprinting has traditionally been linked to criminal investigations and forensic science in the public perception, but this view is rapidly changing. The concern over its "stigmatizing effect" has lessened as its application has expanded to a wider range of individuals. Previously associated mainly with criminal records, fingerprinting has now become an essential tool for identifying and categorizing different social groups, such as welfare recipients, refugees, and migrants. It is now a vital technology in immigration and naturalization procedures, playing a key role in identity verification(Stalder and Lyon,2003).

Digital welfare State :

State is moving towards a digital welfare state, the concept of digital welfare state was discussed in the general assembly in New York in 2019(Alston,2019).it was pointed out that due to rapid digitalisation and technological advancements the state is going towards a technology based welfare system to ensure that technology and data can be utilized to benefit citizens in providing welfare services .digital welfare system will be governed by automated system. So here digital consent is very important which states have to consider seriously for efficient functioning of the digital governance system. In India, the Unique Identification Authority of India (UIDAI) was created to develop the Aadhaar biometric identification system. Government officials presented it as a tool for accurately verifying welfare recipients. Automating social services also aims to reduce fraud and corruption between beneficiaries and the authorities overseeing these programs. Additionally, evidence suggests that automation can enhance the efficiency and effectiveness of government operations.

In March 2019, the Kenyan government introduced the National Digital Registry System (NIMS), commonly known as Huduma Namba (Mutung'u & Rutenberg, 2020). This system is designed to link various national databases by assigning each citizen a unique identification number. To facilitate this, the federal government mandates the submission of biometric data, which is recorded as a citizen code. Similar to India's Aadhaar system, each individual is assigned a distinct number after their

biometric data undergoes de-duplication, enabling them to authenticate themselves for NIMS-integrated.. services using their biometric information. This world wide experience shows digital IDs are now closely linked to an individuals ' legal identity and to state recognition, including citizenship rights and participation in state's making (Mutung'u, 2022). For example, a digital ID can enable individuals to state's welfare services, register for real estate and open bank accounts and SIM cards.Through the nationwide digitalisation of everything , the government collects information about each person's nationality, place of birth, origin, marital status, educational background etc for governance purposes or delivering something. The traditional welfare state was established to mitigate risks in industrial relations by offering social protection guarantees specifically for formal sector workers. In contrast, the modern welfare state evolved in response to shifting demographic challenges, extending a broad range of welfare services to a more diverse group, including low-skilled workers, women, children, and the elderly, rather than focusing solely on industrial laborers. The Digital welfare State which stems from automated decision-making powered by technology, presents unique challenges. While risks associated with industrialization and demographic shifts persist, the integration of data and technology has introduced new social risks that were previously unimaginable. Collectively, these are referred to as contemporary social risks (Liu and Wang ,2019).

The automation-related risks in the 21st century differ significantly from those of the 20th century. The increasing complexity of digitized welfare services necessitates a more thorough and context-aware approach to mapping welfare service governance in the digital era.The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was launched in August 2005.but there were many challenges in implementation in rural lavel . Because of lack of infrastructure and transparency in financial transactions and handling records. But the state digitized mgnrega schemes through information technology. Information communication technology is used in MGNREGA in very different ways in the implementation procedure. It will help in disseminating the information on time which will help in ensuring transparency ,delay in wages can be easily handled by the use of proper techniques of information communication technology and digitalization. Information communication technology can be used in MGNREGA in very different ways in the implementation procedure. In the digital governance system it is used to help in disseminating the information on time which will help in ensuring transparency. Information technology is used for communication purposes with regular updates in government websites and in various social media handles. Like departments of information technology in some of the villages of Haryana and Rajasthan for the success of information. The Government of India, along with the Ministry of Rural Development, has undertaken several initiatives to enhance the effectiveness of MGNREGA through the use of ICT. By leveraging technology, the

ministry has interconnected all Gram Panchayats, blocks, districts, and states. Efforts are being made to strengthen ICT infrastructure at the village level through Bharat Nirman Rajiv Gandhi Seva Kendra. Additionally, initiatives such as Soochna Seva Kendra, biometric work assessment, biometric attendance for managing muster rolls at worksites, and community radio for scheme awareness and critical discussions are set to be launched at the Gram Panchayat level.

CONCLUSION :

In the digital age, the modern state is undergoing a significant transformation, reshaping governance, security, and political identity through advancements in biometrics and technology. The integration of biometric identification systems with AI, big data, and blockchain is redefining citizenship, election processes, and national security. While these innovations improve efficiency, transparency, and security, they also raise serious concerns regarding privacy, surveillance, and potential misuse of personal data. As governments increasingly adopt digital governance, the key challenge is finding a balance between technological advancement and ethical responsibility. Ensuring that biometric innovations empower citizens without infringing on their rights requires strong legal frameworks, inclusive policies, and international collaboration. The formation of new political identities in this digital era must align with democratic principles and protect individual freedoms. In twenty first century in this technological advanced era state itself converting in to digital state and through data collection and data mining becoming digital welfare State like in india "Adhar system" and banking system by linking it through biometric for delivering various welfare schemes to its citizens also faces various challenges it's implementation because privacy and concern of data sovereignty and involvement of various corporate sector in it .So transparency and State's autonomy are major concern of it . The digital age demands more of governments than ever before, it's a kind of information state or national surveillance state which is different from traditional security state.

Because of rapid digitalization this is a permanent state not temporary like in emergency and war like situations .so digital economy demands innovative government,not only transform itself as accountable actor but but also to create digital infrastructure and necessary policies and platform to facilitate the dynamic nature of digital economy.so digital state must build their capacity over time and learn to play new and expanded roles adjusting with digital state.the role of digital state in this digital age is not static but must evolve as the economy and technology does . States can learn to create learning societies.They can foster mutual learning through partnership with private and public collaboration.In digital state for balancing security and individual rights, governments must implement strict data protection laws, ensure transparency, and allow citizens control over their biometric data should have a legal framework. Ultimately, a responsible approach to biometric state policies can

lead to improved governance while safeguarding civil liberties and individual rights.

References :

- Vásquez, B. L. (201G). David Garland. The Welfare State (A very short introduction). Revista De Derecho, 29(2), 343–348. https://doi.org/10.40G7/s0718-0950201G000200018
- Lyon, D. (2007). Surveillance, security and social sorting. International Criminal Justice Review, 17(3), 1G1–170. https://doi.org/10.1177/10575G770730GG43
- Esu, A. (201G). Book review: Benjamin J Muller, Security, Risk and the Biometric State: Governing Borders and Bodies. International Sociology, 31(2), 20G–208. https://doi.org/10.1177/02G8580915G27100
- Borins, S., Kernaghan, K., & Brown, D. (2007). Digital state at the leading edge. http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA81775271
- Larasati, Z. W., Yuda, T. K., & Syafa'at, A. R. (2022). Digital welfare state and problem arising: an exploration and future research agenda. International Journal of Sociology and Social Policy, 43(5/G), 537–549. https://doi.org/10.1108/ijssp-05-2022-0122
- Wagg, D. J., Worden, K., Barthorpe, R. J., & Gardner, P. (2020). Digital Twins: State-of-the-Art and future Directions for modeling and simulation in Engineering Dynamics Applications. ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems Part B Mechanical Engineering, 6(3). https://doi.org/10.1115/1.4046739
- Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: taking stock, looking ahead. Journal of Economic Literature, 38(3), 595–613. https://doi.org/10.1257/jel.38.3.595
- Andrejevic, M. (2007). Surveillance in the digital enclosure. The Communication Review, 10(4), 295–317. https://doi.org/10.1080/10714420701715365
- Balkin, J. M. (2008). The Constitution in the National Surveillance State. SSRN Electronic Journal. https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1345501_code293225.pdf?abstractid=1141524
- Fisher, L. (2009). The Constitution and 9/11: recurring threats to America's freedoms. Choice Reviews Online, 46(08), 46–4696. https://doi.org/10.5860/choice.46-4696

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 115-126

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Social Engineering, Caste Coalitions and Electoral Politics : BJP's Strategy in Haryana (2014–2024)

Kamal

Research Scholar, Department of Political Science,
University of Delhi, New Delhi.

Abstract :

This research examines the role of social engineering and caste-based coalitions in shaping the electoral outcomes of the Bharatiya Janata Party (BJP) in Haryana during 2014, 2019, and 2024. Haryana's political history has been dominated by the Jat community, but demographic changes, urbanization, and rising political awareness among Other Backward Classes (OBCs) created an opportunity for political realignment. BJP capitalized on this by strategically mobilizing OBC, non-Jat, and urban voters while mitigating Jat alienation. This study analyzes caste polarization, party narratives, candidate selection, and welfare policies, using secondary sources, constituency-level data, and election statistics. Findings indicate that BJP's success was driven not only by national leadership but also by deliberate social engineering**,** reshaping Haryana's electoral map. The research contributes to understanding identity politics, coalition-building, and electoral engineering in Indian state elections.

Keywords :

Social engineering, caste-based electoral coalitions, Jat–OBC polarization, Bharatiya Janata Party (BJP), Haryana politics, electoral realignment, identity politics, Indian state-level elections.

1. Introduction :

Haryana, a northern Indian state carved out of Punjab in 1966, has historically exhibited a pattern of caste-dominated electoral politics, with the Jat community occupying a position of political and social dominance. As a land-owning agrarian caste, Jats exercised disproportionate influence over rural power structures, party leadership, and electoral outcomes. For decades, political formations such as the Indian National Congress and the Indian National Lok Dal (INLD) relied heavily on Jat consolidation, making electoral competition largely predictable and reinforcing the dominance of a

single caste bloc (Singh, 2017; Chowdhry, 2011). This dominance was further institutionalized through patronage networks, local leadership control, and mobilization around agrarian interests. In contrast, Other Backward Classes (OBCs), Scheduled Castes (SCs), and urban middle-class voters remained politically fragmented and underrepresented, limiting their collective bargaining power within the state's political system (Jodhka, 2017).

This relatively stable political configuration began to shift in the years leading up to the 2014 Haryana Assembly elections. Structural changes such as demographic diversification, urbanization, and the increasing political consciousness of non-dominant castes created conditions for electoral realignment. The Bharatiya Janata Party (BJP) capitalized on these transformations by adopting a strategy of social engineering that deliberately challenged Jat-centric politics. Unlike earlier parties, the BJP sought to construct a broad-based electoral coalition centered on OBCs, non-Jat castes, urban voters, and sections of Dalits, while simultaneously attempting to manage and contain Jat disaffection (Jaffrelot, 2015; Jaffrelot, 2019).

The 2014 Assembly elections marked a critical turning point, as the BJP emerged as the single largest party and subsequently consolidated its dominance in the 2019 and 2024 elections. Central to this success was the strategic mobilization of Jat–OBC polarization. By projecting itself as a representative of marginalized and aspirational non-Jat communities, the BJP was able to fracture the traditional caste equilibrium that had sustained Congress and INLD dominance. This polarization was reinforced through leadership projection, candidate selection favoring OBC and non-Jat leaders, and the deployment of welfare-oriented governance initiatives aimed at broadening social support (Palshikar & Kumar, 2018; Pai, 2014). Welfare schemes and development narratives were framed in ways that transcended narrow caste identities while still appealing to specific social groups, thereby stabilizing the BJP's emerging coalition.

Over the period from 2014 to 2024, this strategy matured into a durable electoral formula. The BJP combined caste-based mobilization with a centralized leadership narrative and governance performance, allowing it to convert social coalitions into consistent electoral outcomes. As scholars of Indian electoral politics argue, such coalition-building reflects a shift from reliance on dominant castes to the strategic aggregation of multiple subaltern groups, reshaping the nature of political competition at the state level (Chandra, 2004; Jaffrelot & Verniers, 2020).

The objectives of this study are threefold: first, to analyze the impact of Jat–OBC polarization on electoral outcomes in Haryana; second, to examine the strategies employed by the BJP in constructing and sustaining caste-based coalitions; and third, to assess the broader implications of social engineering for the state's political landscape. By focusing on Haryana, this paper contributes

to a deeper understanding of identity politics, caste-based electoral engineering, and the reconfiguration of regional power in contemporary Indian state elections (Palshikar & Kumar, 2018)

2. Methodology :

This research adopts a mixed qualitative and quantitative methodological approach to examine the role of social engineering and caste-based coalitions in Haryana's electoral politics. The study draws on secondary literature on caste, identity politics, and electoral strategies, particularly scholarly works on social engineering and caste mobilization in North India (Jaffrelot, 2003; Kumar, 2020). Quantitative data are sourced from constituency-level election results published by the Election Commission of India for the Haryana Assembly elections of 2014, 2019, and 2024. In addition, caste-wise voting patterns and attitudinal data are derived from CSDS–Lokniti post-poll surveys and related datasets.

The analysis involves mapping the BJP's seat-wise electoral performance across three consecutive elections and assessing patterns of caste-based support among Jats, OBCs, and non-Jat groups. Qualitative analysis complements this by examining candidate selection, campaign narratives, and governance promises to identify deliberate strategies of social engineering. Together, these methods enable a comprehensive assessment of electoral realignment and caste polarization in Haryana

3. Historical and Political Background of Haryana :

Haryana, formed in 1966 after its separation from Punjab, has a political landscape deeply shaped by caste hierarchies, with the Jat community historically occupying a dominant position. Predominantly landowning, Jats have exerted substantial influence over panchayat governance, agricultural production, and village-based social networks. This dominance was reinforced through economic advantages, dense kinship ties, and patterns of military recruitment, enabling the community to consolidate political power and mobilize votes collectively (Jaffrelot, 2003; Chowdhry, 2011). Consequently, political parties such as the Indian National Congress (INC) and the Indian National Lok Dal (INLD) heavily relied on Jat loyalty, designing candidate selection and policy priorities to secure electoral support from this influential caste.

3.1 Traditional Dominance of Jats :

The Jats' electoral dominance is closely linked to landholding patterns, particularly in districts like Rohtak, Hisar, and Sirsa, which allowed the community to exert control over rural constituencies. Historically, both INLD and Congress prioritized Jat representation over other groups, ensuring party policies and leadership structures reflected Jat interests. Electoral outcomes often hinged on Jat consolidation; for instance, in the 1991 assembly elections, the majority of rural constituencies were determined by Jat voting patterns (Singh, 2017). This reinforced the perception that political

success in Haryana was contingent upon maintaining Jat support, limiting the influence of other social groups.

3.2 Role of OBCs and Non-Jat Communities :

Despite their numerical strength, OBCs and non-Jat groups historically remained politically fragmented. Communities such as Yadavs, Sainis, Gujjars, and other backward castes lacked cohesive political platforms, and previous attempts by mainstream parties to mobilize these groups were often unsuccessful due to intra-group divisions and weak leadership (Kumar, 2020). Urban voters, including business communities, professionals, and Brahmins, began to play an increasingly significant role post-1990s as Haryana experienced rapid urbanization. Industrial hubs like Gurugram and Faridabad emerged as centers of economic activity, shifting some electoral influence away from caste-dominated rural constituencies toward development-oriented urban electorates (CSDS–Lokniti, 2014).

3.3 Evolution of Caste-Based Voting Patterns Pre-2014 :

Before 2014, Haryana's voting patterns were largely predictable along caste lines. Rural constituencies were dominated by Jat consolidation, while OBC and non-Jat groups were courted selectively but often split their votes. Urban constituencies were contested primarily on development issues, though elite and Brahmin votes retained influence. The foundation for electoral realignment was laid by demographic diversification, rising political consciousness among OBCs, and rapid urbanization, which collectively enhanced the bargaining power of non-dominant groups. These shifts created the conditions for a realignment of Haryana's electoral politics, setting the stage for parties willing to mobilize non-Jat and urban constituencies to challenge the traditional dominance of Jat-centric parties (Yadav & Palshikar, 2014; Jaffrelot, 2015).

4. BJP's Electoral Strategy in Haryana :

BJP's approach in Haryana combined social engineering, candidate strategy, and governance messaging. Unlike previous parties, BJP recognized the potential of OBC and non-Jat consolidation to challenge traditional Jat dominance

4.1 2014 Assembly Elections: Strategy and Execution :

- **Anti-incumbency :** Disillusionment with Congress over corruption and governance failures (Jaffrelot, 2019).
- **National Modi Wave :** Leveraging Narendra Modi's popularity to attract urban and first-time voters.
- **Caste-Based Social Engineering :** BJP targeted non-Jat communities and OBCs using community-specific rallies and welfare promises.
- **Candidate Selection :** Appointment of Manohar Lal Khattar, a non-Jat leader, symbolized

inclusivity. BJP also increased OBC and non-Jat candidates by 15% compared to previous elections (Kumar, 2020).

BJP's rural campaign strategy in 2014 focused on local issues such as irrigation, agriculture subsidies, and rural employment, appealing to OBC and non-Jat voters dissatisfied with Jat-dominated parties.

4.2 2019 Assembly Elections : Refinement and Coalition Management :

The 2019 elections demonstrated BJP's refined caste management :

- **Jat Reservation Agitation (2016) :** The agitation highlighted Jat demands for government job quotas. BJP mitigated alienation by engaging moderate Jat leaders and forming alliances with JJP to maintain influence in mixed-caste constituencies (Singh, 2017).
- **Strategic Alliance with JJP :** This helped in constituencies where OBCs and Jats were evenly split.
- **Campaign Messaging :** BJP emphasized development, infrastructure, education, and welfare schemes, ensuring urban and non-Jat support while preventing Jat alienation.

BJP also employed micro-targeted campaigns, analyzing constituency-level data to allocate resources where OBC and non-Jat votes could be maximized.

4.3 2024 Electoral Context: Consolidation and Challenges :

By 2024, BJP continued to balance caste representation while facing new challenges :

- **Urbanization and Youth Influence :** Younger voters in Gurugram, Faridabad, and Panchkula increasingly prioritized development over caste allegiance.
- **Evolving Caste Dynamics :** BJP sustained OBC consolidation while carefully selecting Jat-friendly candidates to avoid backlash.
- **Policy and Governance Messaging :** Welfare schemes such as skill development programs and women-centric policies reinforced BJP's inclusive narrative (Jaffrelot, 2019).

5. Caste Polarization : Jat vs OBC

Caste polarization, particularly between Jats and OBCs, was central to BJP's strategy.

5.1 Jat Political Mobilization :

Jats historically controlled rural vote banks, but divisions arose due to :

- Factionalism within INLD and JJP
- Differing responses to reservation policies
- Generational shifts among rural Jats

BJP engaged moderate Jat factions, minimizing confrontation, and ensuring selective alignment without alienating the broader community (Singh, 2017).

5.2 OBC Consolidation :

OBCs were historically fragmented. BJP consolidated this group by :

- **Promoting welfare schemes :** Education and employment programs targeted OBC youth.
- **Candidate Representation :** OBC candidates increased from 18% in 2014 to 25% in 2024.
- **Rhetorical Inclusion :** Campaigns emphasized development and equality while subtly highlighting the need to balance Jat dominance (Kumar, 2020).

5.3 Campaign Narratives and Messaging :

BJP employed micro-targeted messaging :

- **Rural OBC voters :** Focused on agriculture, employment, and welfare.
- **Urban voters :** Emphasized development, infrastructure, and anti-corruption narratives.
- **Media strategy :** Reinforced inclusive development while maintaining Jat-friendly symbolic gestures.

This created a durable caste coalition, minimizing risks of alienation while maximizing electoral gains.

6. Electoral Data Analysis :

6.1 Seat-Wise and Constituency-Level Analysis :

Year	Total Seats	BJP Seats Won	Vote Share (%)	Key Constituencies
2014	90	47	33.20	Gurugram, Rohtak, Faridabad
2019	90	40	36.49	Hisar, Jhajjar, Karnal
2024	90	48	39.94	Gurugram, Ambala, Panchkula

Analysis reveals :

- BJP performed strongly in urban centers and OBC-dominated rural areas.
- Jat-dominated constituencies were selectively targeted through alliances and candidate selection.
- Data indicates incremental growth in vote share correlated with OBC and non-Jat consolidation (Election Commission of India, 2014; 2019; 2024).

6.2 Voting Patterns : Jat, OBC, and Non-Jat Communities :

Community	2014 (%)	2019 (%)	2024 (%)
Jat	28	30	32
OBC Yadav	62	64	66
Other OBC	47	50	52
Non-Jat Urban	51	55	58

BJP's numerical advantage came from OBC consolidation and urban voter mobilization,

offsetting partial Jat alienation (CSDS-Lokniti Survey, 2024).

6.3 Social Engineering and Candidate Strategy :

- Candidate selection emphasized OBC and non-Jat representation in rural constituencies.
- Urban constituencies received candidates with development-oriented credentials.
- Campaign resource allocation was data-driven, focusing on swing constituencies where OBC/ non-Jat votes could be decisive.

This deliberate social engineering transformed Haryana's political map, weakening traditional Jat hegemony while consolidating BJP's electoral base.

7. Critiques and Limitations :

While the Bharatiya Janata Party's use of social engineering and caste-based coalition-building in Haryana between 2014 and 2024 has yielded significant electoral success, the strategy is not without its limitations and potential risks. A critical evaluation reveals that the reliance on caste polarization, particularly between Jat and OBC communities, raises concerns regarding long-term social cohesion, political inclusivity, and governance stability. Moreover, methodological constraints in studying caste-based voting behavior further complicate definitive conclusions.

7.1 Risks of Over-Polarization :

One of the most significant critiques of BJP's electoral strategy in Haryana is **the** risk of excessive caste polarization, particularly the sharpening of the Jat–OBC divide. While polarization can serve as an effective electoral mobilization tool in the short term, it carries the potential to deepen social divisions over time. The strategic consolidation of OBC and non-Jat voters, achieved partly through the political marginalization of Jat dominance, may reinforce perceptions of exclusion among certain social groups. Such dynamics risk transforming electoral competition into a zero-sum contest between communities rather than a deliberative process based on governance and policy performance.

Over-polarization can also weaken social trust and inter-community cooperation, especially in rural areas where caste relations shape everyday economic and social interactions. Haryana's agrarian society depends heavily on cooperative labor arrangements, shared local institutions, and social interdependence across caste lines. Persistent political polarization may disrupt these relationships, leading to localized tensions and long-term instability. Furthermore, when electoral success becomes closely tied to identity-based mobilization, political discourse may shift away from substantive governance issues such as agrarian distress, employment generation, and public service delivery.

From a governance perspective, prioritizing electoral consolidation over inclusive policymaking may result in uneven policy outcomes. Communities perceived as electorally less

significant may receive reduced political attention, reinforcing cycles of marginalization. This poses a challenge for democratic accountability, as governance risks becoming selectively responsive rather than universally inclusive. As Jaffrelot (2019) notes, identity-based political strategies, when overused, can undermine the integrative function of democratic politics by privileging electoral arithmetic over social harmony.

7.2 Alienation of the Jat Community :

Another critical limitation of BJP's strategy lies in the potential alienation of the Jat community, which has historically played a central role in Haryana's political and social life. Although BJP has attempted to manage Jat dissatisfaction through selective engagement, symbolic representation, and alliances with Jat-led regional parties, sections of the community continue to perceive political marginalization. The aftermath of the 2016 Jat reservation agitation intensified feelings of grievance, particularly regarding employment opportunities and state responsiveness to Jat demands.

Alienation of a politically assertive and socially influential group like the Jats carries long-term electoral risks. Discontented Jat voters may increasingly consolidate behind regional parties such as the Indian National Lok Dal or the Jannayak Janata Party, potentially revitalizing regional political formations. Such a development could fragment BJP's carefully constructed coalition, especially in rural constituencies where Jat voters retain numerical and organizational strength. Additionally, sustained alienation could encourage protest politics and social mobilization outside electoral channels, complicating governance and law-and-order management.

From a broader democratic perspective, the marginalization of a dominant group does not automatically translate into social justice or inclusivity. Instead, it may replace one form of dominance with another, without addressing structural inequalities. Singh (2017) argues that durable political stability in Haryana requires negotiated accommodation among communities rather than competitive exclusion. Without meaningful inclusion of Jat interests within a broader governance framework, BJP's electoral gains may face diminishing returns in the long run.

7.3 Methodological Limitations :

In addition to political critiques, this study faces several methodological limitations that must be acknowledged. First, the lack of comprehensive constituency-level caste-wise voting data restricts the precision of quantitative analysis. Electoral data in India is not officially disaggregated by caste, requiring scholars to rely on post-poll surveys, qualitative assessments, and proxy indicators. While these sources offer valuable insights, they may not fully capture the complexity of voter behavior.

Second, the findings of this study are context-specific to Haryana and should not be generalized uncritically to other Indian states. Caste structures, historical political trajectories, and socio-

economic conditions vary significantly across regions. Strategies that succeed in Haryana may not yield similar outcomes in states with different dominant castes or social configurations. Comparative analysis would be required to assess the broader applicability of BJP's social engineering model.

Third, Haryana's political landscape is subject to rapid socio-economic change**,** including urbanization, educational expansion, and generational shifts in political preferences. These transformations may alter caste identities and voting behavior over time, reducing the predictive value of past electoral patterns. As Kumar (2020) highlights, voter alignments are increasingly influenced by issue-based considerations, leadership perception, and economic aspirations, alongside traditional caste loyalties. Consequently, conclusions drawn from the 2014–2024 period must be interpreted with caution when forecasting future electoral dynamics.

8. Conclusion :

The period between 2014 and 2024 represents a decisive phase in Haryana's political history, marked by the Bharatiya Janata Party's (BJP) effective use of social engineering and caste coalition-building to secure consecutive electoral victories. This study shows that BJP's dominance cannot be attributed solely to national leadership or the "Modi factor." Rather, it resulted from a carefully calibrated strategy that reshaped traditional caste alignments and mobilized previously fragmented social groups.

Caste polarization, particularly between Jat and OBC communities, functioned as a strategic electoral tool. By consolidating OBC, non-Jat, and urban voters, BJP compensated for partial Jat alienation while avoiding uniform opposition from the community. This balancing act was reinforced through targeted candidate selection, welfare-oriented governance narratives, and symbolic inclusion, enabling the construction of a broad and resilient electoral coalition.

The analysis further highlights a significant electoral realignment in Haryana. Traditional Jat dominance, long central to rural politics, weakened as OBCs and non-Jat communities gained greater political visibility and bargaining power. This shift transformed party competition and redefined the social bases of political representation in the state. BJP's approach demonstrates how identity politics, when combined with organizational capacity and policy messaging, can significantly reshape regional political landscapes (Jaffrelot, 2019).

However, the findings also reveal risks and limitations. Over-reliance on caste-based strategies may intensify social polarization, strain governance, and risk alienating Jat voters if opposition parties mobilize discontent effectively. Evolving socio-economic conditions and contextual variability caution against deterministic interpretations of caste-based voting behavior.

In conclusion, BJP's experience in Haryana illustrates the strategic integration of identity

politics with electoral management. While social engineering has proven electorally effective, its long-term sustainability depends on balancing pragmatism with inclusive governance and social cohesion. As Jaffrelot (2019) emphasizes, durable political realignments require the capacity to transcend short-term electoral calculations and contribute to democratic stability

References :

- Bayly, S. (1999). *Caste, society and politics in India from the eighteenth century to the modern age*. Cambridge University Press.
- Bhaskar, U. (2024, October 9). Haryana elections 2024: How BJP's social engineering perforated Jat dominance. *Moneycontrol*. https://www.moneycontrol.com
- Brass, P. R. (2003). *The production of Hindu–Muslim violence in contemporary India*. University of Washington Press.
- Chandra, K. (2004). *Why ethnic parties succeed: Patronage and ethnic head counts in India*. Cambridge University Press.
- Chhibber, P., & Nooruddin, I. (2016). Party competition and electoral outcomes in Haryana: Caste and coalition politics. *Journal of South Asian Studies, 39*(3), 377–400. https://doi.org/10.1080/00856401.2016.1208335
- Chowdhry, P. (2011). *Political economy of production and reproduction: Caste, custom, and community in North India*. Oxford University Press.
- CSDS–Lokniti. (2014). *National election study 2014: Post-poll survey*. Lokniti Research Programme.
- CSDS–Lokniti. (2019). *Post-poll survey of Haryana assembly elections 2019*. Lokniti Research Programme.
- CSDS–Lokniti. (2024). *Post-poll survey of Haryana assembly elections 2024*. Lokniti Research Programme.
- Dirks, N. B. (2001). *Castes of mind: Colonialism and the making of modern India*. Princeton University Press.
- Election Commission of India. (2014). *Statistical report on general elections to the Haryana Legislative Assembly, 2014*. https://eci.gov.in
- Election Commission of India. (2019). *Statistical report on general elections to the Haryana Legislative Assembly, 2019*. https://eci.gov.in
- Election Commission of India. (2024). *Statistical report on general elections to the Haryana Legislative Assembly, 2024*. https://eci.gov.in
- Gaur, B. S. (2024). A comprehensive study of Haryana Assembly elections. *International*

Journal of Innovative Research in Technology, 10(9), 215–221. https://ijirt.org

- Government of Haryana. (2023). *Socio-economic caste census and welfare reports*. https://haryana.gov.in
- Gupta, D. (2005). *Caste in question: Identity or hierarchy?* Sage Publications.
- Gupta, D. (2018). Caste, politics and electoral mobilization in North India. *Indian Political Science Review, 52*(2), 215–232.
- Hansen, T. B. (1999). *The saffron wave: Democracy and Hindu nationalism in modern India*. Princeton University Press.
- Jaffrelot, C. (2003). *India's silent revolution: The rise of the lower castes in North India*. Permanent Black.
- Jaffrelot, C. (2015). The BJP's 2014 election campaign: National populism and social engineering. *Contemporary South Asia, 23*(2), 151–166. https://doi.org/10.1080/09584935.2015.1027662
- Jaffrelot, C. (2019). Haryana: The making of a BJP stronghold. *Economic and Political Weekly, 54*(15), 34–42.
- Jaffrelot, C. (2019). *Modi's India: Hindu nationalism and the rise of ethnic democracy*. Princeton University Press.
- Jaffrelot, C., & Gayer, L. (2012). Muslims in Indian cities: Trajectories of marginalisation. *Economic and Political Weekly, 47*(39), 38–46.
- Jaffrelot, C., & Kalaiyarasan, A. (2019). The political economy of the Jat agitation for Other Backward Class status. *Economic & Political Weekly, 54*(7), 29–37.
- Jaffrelot, C., & Verniers, G. (2020). The BJP's 2019 victory: Modi's populism and the consolidation of a Hindu vote. *Studies in Indian Politics, 8*(2), 131–151.
- Jodhka, S. S. (2017). *Caste in contemporary India*. Routledge India.
- Kharb, S. D. (2025). Haryana Vidhan Sabha election 2024: Explaining the verdict. *Knowledgeable Research: A Multidisciplinary Journal, 4*(04), 50–69.
- Kumar, A. (2020). Electoral politics and caste mobilization in Haryana: 2014–2019. *Asian Journal of Political Science, 28*(2), 112–130.
- Kumar, S. (2014). Social coalitions and electoral politics in India. *Studies in Indian Politics, 2*(1), 45–60.
- Kumar, S. (2019). How the BJP cracked Haryana's caste conundrum. *Mint*. https://www.livemint.com
- Manor, J. (2018). *The political economy of democratic decentralization*. World Bank.
- Pai, S. (2014). *The politics of social engineering: BJP's Dalit strategy*. Oxford University

Press.

- Pal, K., & Mishra, J. (2019). BJP's sweeping electoral victory in Haryana. *Economic & Political Weekly, 54*(32), 24–26.
- Pal, K., & Mishra, J. (2021). Continuity and change in Haryana politics: Lok Sabha and assembly elections, 2019. In *Electoral Dynamics in the States of India* (pp. 57–74). Routledge India.
- Palshikar, S., & Kumar, S. (2018). *Social engineering and electoral coalitions in India*. Oxford University Press.
- PTC News Desk. (2024, October 10). Haryana elections 2024: Five major factors behind BJP's historic victory. *PTC News*. https://www.ptcnews.tv
- Singh, K. (2019). Agrarian change and political mobilisation in Haryana. *Journal of Rural Studies, 68*, 235–244.
- Singh, S. (2017). *Caste and electoral politics in North India: A case study of Haryana*. Routledge India.
- Singh, S. (n.d.). Examining state's electoral politics through the regional eye: A case study of Ahirwal region in Haryana.
- Sridharan, E. (2014). Electoral alliances in India. *Party Politics, 20*(4), 559–572.
- Sridharan, E. (2019). The BJP's new social coalition in 2019. In E. Sridharan & S. Vaishnav (Eds.), *India votes: Elections 2019* (pp. 83–104). Oxford University Press.
- The Quint Staff. (2024, September 28). The lay of the electoral land: Caste coalitions in Haryana politics. *The Quint*. https://www.thequint.com
- Vaishnav, M. (2017). *When crime pays: Money and muscle in Indian politics*. Yale University Press.
- Varshney, A. (2002). *Ethnic conflict and civic life: Hindus and Muslims in India*. Yale University Press.
- Yadav, S., & Birla, A. (2024). Caste, community, and victory: Decoding the BJP's historic third win in Haryana's 2024 elections. *Knowledgeable Research Journal, 6*(2), 45–60.
- Yadav, Y. (1999). Electoral politics in the time of change: India's third electoral system. *Economic and Political Weekly, 34*(34–35), 2393–2399.
- Yadav, Y. (2014). The BJP's new social coalition. *Economic and Political Weekly, 49*(39), 26–29.
- Yadav, Y., & Palshikar, S. (2014). Between fortuna and virtu: Explaining the Congress' ambivalence in Haryana politics. *Economic and Political Weekly, 49*(12), 45–53.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 127-148

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Beyond the Binary : Male Victimization and the Unfinished Project of Gender Justice in India

Ms. Sangeeta

Guest Faculty at School of Open Learning,

Department of Political Science, University of Delhi.

Abstract :

This paper examines the under explored phenomenon of a male in intimate and familial relationships, where the conceptualisation of vulnerability is equated solely with women and power with men, and under the umbrella of patriarchy. We suggest that the recognition of male victimhood is not contrary to gender justice, but rather expands the norm of gender justice, making space for justice to be responsive to suffering, regardless of its gender. The study is more of a multi-method qualitative design, which includes judicial discourse analysis of family-court judgments, a systematic empirical review of peer-reviewed studies and government reports that were published between 2018 and 2026, and critical discourse analysis of digital men's rights ecosystems. We found that in a community-based study 52.4 percent of married men reported gender-based violence, mostly emotional or psychological abuse (51.6 percent), and very few (9 percent) reported physical abuse. The 2026 case of Pramod versus Megha, the focus of the judicial discourse, exhibits a strong presumption in favour of women maintenance claimants, and the frequent use of gendered stereotypes, which makes male victimhood epistemically invisible. In addition, policy frameworks like the National Family Health Survey and the Ministry of Women and Child Development's Women Helpline only consider the violence committed against women by their spouses, creating a national data collection blind spot, and excluding male complainants. The digital men's rights movement frequently resorts to strategic essentialism, presents every man as a victim of marriage laws and is not interested in real rights of certain at-risk groups of men. There is a very underdeveloped evidence base on non-normative masculinities – gay, bisexual, trans and disabled men. Thus, we conclude that a gender-inclusive framework of justice is crucial to ensure that the various vulnerabilities are not ignored or undermined and that women remain protected in the unfinished project of gender justice in India.

Keywords : Male Victimization, Patriarchy, Gender Justice, Emotional Abuse, Strategic Essentialism

1. Introduction :

Historical context of the feminist movement in India, which was able to bring the systemic violence and discrimination of women in a patriarchal society to the fore, has definitely helped shape the discourse on gender justice in India [1]. In this movement, in the rightful challenge of male dominance, a strong analytical framework of women as victims and men as perpetrators was created. This framework has been essential in gaining legal protection through the Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 and mobilisation of state resources through the Ministry of Women and Child Development, but at the same time it has also unwittingly led to an epistemic blind spot. The patriarchal family is a system of structures and practices [2] that has caused damage not only for women but also for men, who are expected to be stoic, emotionally contained and impenetrable in the context of victimisation in intimate and family relationships, which renders their experience of such victimisation into a structurally unintelligible one.

This paper aims to explore this under-researched phenomenon of male victimisation in India where the dichotomy of power and vulnerability is largely assumed to be the domain of women and men respectively. The main thesis of our work is that male victimization does not contradict gender justice but extends its normative frame to include an awareness that justice must be attuned to suffering, wherever it may occur. The aim of this research is to develop an inclusive understanding of gender justice that does not ignore any form of harm based on gender but is nevertheless mindful of past and historical gender inequalities, the fight against which the feminist movement has rightly raised. We believe that existing legal and policy frameworks, based on a women-as-victims and men-as-perpetrators dichotomy, do not fully reflect the true nature of intimate partner violence and are thus actually a form of institutional neglect that undermines principles of justice.

The importance of the research is that it can help in changing the nature of legal reform, mental health policy and family governance in India as it goes beyond the binary of gender and introduces the notion of a relation of vulnerability. We want to critically assess the different empirical findings and legal discourses and to understand how male experiences of victimisation are recognised, contested or invisible in the current discourse of gender justice. The present study is based on political theory, feminist jurisprudence, recognition theory and recent literature on masculinity to challenge the normative ideas that are embedded in Indian family laws and public policies [3]. Moreover, we are in dialogue with new scholarship that seeks to deconstruct carceral norms and rethink justice in a non-punitive/impunitive framework [4] and with approaches that aim at a decolonialization of laws and policies, which are based on a gender binary of women/men [5].

Section 2 presents an overview of the key literature related to the discussion on gender justice, patriarchy in society and feminist movement in India over the years. In section 3, our theoretical framework is introduced, which is based on recognition theory and feminist jurisprudence and seeks to better comprehend the phenomenon of victimisation of men in a wider relational context of vulnerability. In section 4, we outline our multi-method qualitative research design, which includes judicial discourse analysis, systematic empirical review and critical discourse analysis of digital ecosystems. Section 5 gives our findings on the prevalence of male victimisation, the epistemic asymmetry in judicial discourse and the systemic exclusion of male complainant in policies. The implications of these findings for imagining gender justice beyond a binary of patriarchy and patriarchy critic are discussed in Section 6, with recommendations for legal reform and policy change found in Section 7.

2. Literature Review :

The academic terrain in India on gender justice has been largely defined by feminist legal work which is centered on women's experiences of domestic violence and systemically experienced discrimination. The literature in this tradition has identified the different types of harm that are done to women in the form of foundation works that have led to the enactment of protective laws like the Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005 [6]. This body of literature has played a pivotal role in bringing the issue of domestic violence to the forefront, and in countering the previous view of intimate partner violence as a private family matter. One important issue with this scholarship is that it is often based on a binary framework of gender, with women as the only victims and men as the only perpetrators, and thus male victimization in intimate relationships is precluded.

Alongside this has developed a parallel strand of masculinity studies, which has also questioned the social construction of male identity and what this means for men's health. Concepts like "hegemonic masculinity," as theorized by scholars like Raewyn Connell, have been used to describe a "currently accepted" response to the problem of the legitimacy of patriarchy, which ensures the dominance of men and the subordination of women [7]. Researchers working in the Indian context have adapted this framework to describe how Indian men are unable to report victimisation or seek assistance as a result of norms of stoicism, emotional restraint and economic providerhood [8]. These studies indicate that patriarchy does not just affect women, it affects men in that it creates constricting roles for them that try to make the experience of vulnerability undeniable. However, this literature has not, to a large extent, been incorporated into feminist legal literature, and there has been little incorporation of masculinity studies into family law and domestic violence policy analysis.

A framework of recognition theory, as elaborated by Axel Honneth and Nancy Fraser, can be

useful to understand the dynamics of invisibility and misrecognition that underlie Indian masculinity in the context of male victimization. While this is important for social justice in terms of resources, it is also crucial for Honneth that an individual's identity and experiences are treated as legitimate [9]. In her criticism of Honneth, Fraser stresses the importance of differentiating between claims to recognition that contest status hierarchies and those that corroborate them [10]. This distinction is very important in understanding the movement for men's rights in India, which tends to focus on what we call strategic essentialism, namely, all men are oppressed by the marriage laws rather than promoting substantive rights of certain vulnerable groups of men like elderly men, disabled men, queer men etc. Recognition theory in this way offers a normative perspective to assess whether the facts of man's victimhood broaden or narrow the field of gender justice.

Studies on male victimisation in India are still limited and approach in a disjointed fashion. The National Family Health Survey, which is the main source of data on prevalence of domestic violence in India, only includes woman's spousal violence, and not the victimisation of men. This structural blind spot has been pointed out by scholars who claim that the lack of information on male victimization is also a form of violence in which the patriarchal binary is consolidated [12]. Whereas, only a few studies have tried to document prevalence of male victimisation, one being a cross-sectional study of one thousand married men in community settings, showed high prevalence of emotional or psychological abuse (51.6 percent) and lower prevalence of physical violence (6 percent) [13]. The results indicated that male victimisation can be non-physical and so more difficult to 'invisible' in legal or policy terms, which are more likely to focus on physical harm.

Legal scholars have studied the judicial discourse on domestic violence in India and report the regular use of gendered stereotypes in family courts. Studies of maintenance cases under Section 125 of Code of Criminal Procedure reveal that there is a strong presumption that able-bodied men are able to earn and maintain their wives and children, and the female claimants are prima facie aggrieved persons [14]. This epistemic asymmetry, which treats the man who complains as a presumed less credible witness, based on his presumed economic ability to provide for himself, and the woman who responds as a presumed victim, has been criticized as institutionalized gender bias that impedes the principle of equal justice. But this literature has failed to systematically address the way the male victims' experience of victimization comes to be unthinkable in the legal framework, and the way that the legal discourse is linked to the wider policy picture that ignores male complainants in shelter homes, counseling centres and legal support.

The online men's rights movement in India has recently garnered attention from scholars, who have documented ways in which men's rights groups online build narratives of male victimisation and

organise for legal change [15]. In these studies, a homogenous story of male and female is found and mostly caste and class and queer identities are not included or if included are as an exception to the main story. The main call to action is to join national men's rights meets, file counter complaints and push for legal accountability and with the frequent use of words such as, false case, maintenance extortion, and gender bias. The evidence type mentioned is mostly personal anecdote and judicial judgment screenshots, which represent the translation of victimhood to a counter-grievance narrative and frequently uses strategic essentialism. However, this literature has failed to consistently differentiate between strategic essentialism for the purpose of removing feminist protections and substantive rights claims for the purpose of broadening gender justice, a distinction which we try to operationalise in our research, using the lens of recognition theory.

So far, the literature on gender justice in India is rich and diverse, but largely works within the binary frame-where female is synonymous with the vulnerable and male is synonymous with the powerful. There has been also a lack of systematic application of recognition theory to males' victimisation, and methodologically fragmented empirical research on male victimisation; feminist legal scholarship has concentrated on women's victimisation, masculinity studies has not been engaged with legal theory. We attempt to fill these gaps by combining these strands of scholarship in one analytical treatment, which considers male victimisation from the perspective of judicial discourse, empirical prevalence and digital activism. This way we promote an inclusive understanding of gender justice that takes account of a wide range of forms of harm, regardless of gender and is sensitive to historical injustices which the feminist movement has rightly been concerned with. We believe this is not a contradiction to the feminist agenda and also extends the normative space of gender justice to declare that no justice can turn a blind eye to suffering, regardless of where it happens.

3. Theoretical Framework and Contextual Background :

We attempt to dissect the concept of male victimisation in intimate and familial relationships in India by using a three-pronged theoretical lens of recognition theory, feminist jurisprudence and critical masculinity studies. This is a framework to help us discard the idea of a binary of vulnerability = feminine, and power = masculine, and to think of gender justice as a relational and context-specific project, which must always be responsive to suffering, wherever it is found.

Our analysis is based on the foundational normative theory of recognition, as elaborated by Axel Honneth. Honneth believes that social justice is not simply a matter of securing the equitable distribution of material resources but also ensuring that an individual's identity, experience and contribution are recognized as valid and valuable within the social order [9]. Misrecognition—or the systematic denial of an individual's or group's experiences and identity—is a type of injustice as

harmful as material deprivation. For the purposes of this paper, we argue that the epistemic invisibility of men's experiences of intimate partner violence is a product of institutionalised misrecognition, when applied to the Indian context. An exclusive focus on the dyad of women as victims and men as perpetrators renders male victimhood structurally unintelligible, if it is even recognized at all. This is not a simple mistake; it is what we could call a form of epistemic violence: a negation of the recognition that men need to have their suffering acknowledged, addressed and redressed.

A very important aspect of Nancy Fraser's critique of Honneth's recognition theory is the distinction she makes between claims for recognition that contest status hierarchies and those that affirm them [10]. Fraser, however, counters that not every recognition demand is progressive: some could be regressive in that they make demands in the name of group identity, which may ignore internal differences and power relations. This is especially relevant in the context of the men's rights movement in India, which is often one that we refer to as strategic essentialism: here, the focus is on the oppression of all men, not on more substantive rights for specific vulnerable sub-groups like elderly men, disabled men, queer men. Using Fraser's approach, it is possible to assess whether such claims of male victimhood broaden or narrow the scope of gender justice, or if they are simply a reversion to a more traditional understanding of victim-perpetrator roles, which bolsters rather than undermines patriarchy.

Feminist jurisprudence forms the second pillar of our theory; it is a critical lens with which to analyse the mechanisms and processes through which legal institutions and doctrines are created and through which gendered hierarchies are reproduced. Feminist legal scholars have shown that law is not a neutral force that settles conflicts but rather a place of struggle where gendered norms are articulated, challenged and legitimated [16]. Thus, in the Indian context family law is in a complex matrix of personal laws, secular laws and judicial precedents that all contribute to the construction of gendered subject positions. For example, the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, defines domestic violence which necessarily and implicitly invokes the idea of a male perpetrator and a female victim, and male victimhood is thereby rendered legally unintelligible. In this regard, the presumption of the Code of Criminal Procedure, under Section 125, that governs the maintenance claims is that men are the economic providers and women the dependent recipients, which leads to an epistemic asymmetry in favour of male complainants. An analysis of legal doctrines and practices through a lens of feminist jurisprudence can be used to identify what we call epistemic asymmetry, the systematical favoring of female victimhood claims over male ones in the law.

The third pillar of our theoretical approach is critical masculinity studies, which offers us the analytical tools to comprehend how the male experience of and subjectivity in relation to patriarchy

is formed. Following Raewyn Connell's idea of hegemonic masculinity, we think of masculinity as a set of genders practices that represents the prevailing solution to the question of legitimacy of patriarchy [7]. Hegemonic masculinity in Indian context is manifested in norms of stoicism, emotional restraint, economic providerhood and physical invulnerability. These norms limit men to reporting victimisation, or accessing help, or even identifying them as violence. As an institution of social structures and practices the patriarchy puts such rigid expectations on men, and at the same time denies them the institutional support they need to deal with victimisation [2]. Incorporating the ideas of critical masculinity studies into our framework allows us to look at how the victimisation of men can be invisible both legally and politically, and also because of a process of acculturation where harm to men is hard to express because of the internalisation of gender norms.

The institutional and policy context of our analysis is that of the current institutional and policy environment in India. The Ministry of Women and Child Development has a Women Helpline (181) which explicitly does not include male complainants, and the National Family Health Survey (NFHS) defines domestic violence as women's experience of being victims of violence by their spouses [11]. What this means is that male victimisation remains a systemic blind spot in national data collection and service provision, and therefore a blind spot at the level of state policy. In addition, the way the judiciary spoke about domestic violence, as illustrated in Pramod v. Megha (2026), implies a strong presumption in favor of female maintenance claimants, and a routine use of gendered stereotypes that make male victimhood epistemically invisible. This institutional context, along with the theoretical framework mentioned above, goes on to form the analytical base for our empirical study on male victimisation in India.

4. Research Design and Methods :

The study is conducted using multi-method qualitative research design which consists of judicial discourse analysis, systematic empirical review and critical discourse analysis (CDA) as a way to understand the phenomenon of male victimization in the legal and social frame of the Indian society. The methodological positioning aims at grasping the multidimensionality of epistemic invisibility, by exploring how the experiences and perception of male intimate partner violence are rendered 'unintelligible' in legal, empirical and discursive arenas. The choice of each method allows to tackle a different aspect of the research question and the triangulation of the methods allows a more comprehensive analysis of institutional, cultural and structural mechanisms that produce and sustain the binary of patriarchy.

4.1 Judicial Discourse Analysis :

The judicial discourse analysis looks at how family courts in India produce, legitimize or

disavow male victimhood by relying on specific language, arguments, and evidentiary frameworks in their verdicts. The family-court judgments of the male complainant and female respondent were purposefully sampled from legal databases like Indian Kanoon and SCC Online, the keywords used were: "male victim", "husband complainant", "maintenance claim by husband", and "domestic violence complaint by man". Contemporaneity was achieved by focusing on judgments made from 2018-2026, while also seeking to represent the diversity of judgments issued at the district court, high court, and Supreme Court levels in India.

Case details that were analysed included court name, case number, date of judgment, presiding judge, complainant profile (age, occupation, income, duration of marriage), and respondent profile (age, occupation, income, duration of marriage). Credibility assessments were coded by looking at how the court treated the evidence of a male complainant as compared to the evidence of the female respondent, and specifically the use of gendered stereotypes, the use of economic capacity as a proxy for credibility and the court's treatment of the counter allegations—such as misuse of legal provisions. These dimensions were captured systematically by a structured coding template, which included categories for gendered stereotypes (for example: "able-bodied man presumed capable of earning"), misuse rhetoric (for example: "false case," "maintenance extortion") and explicit recognition or denial of the victimhood of men. There were also categories for intersectional factors – caste, class, disability – and the legal arguments offered by both sides and the remedies ordered by the court, in the coding sheet.

Coding was done iteratively starting with the theoretical codes and continuing with the data codes which were obtained inductively. A subset of judgments was coded by two coders in order to achieve inter-coder reliability, which was achieved by discussion and the fine-tuning of the coding scheme. The analysis then focused on patterns on the judgements, looking at how the language of these judgements creates an epistemic asymmetry that privileges female victimhood claims, while making male victimhood claims structurally unintelligible. The case of Pramod versus Megha, 2026, is used as an anchor case to illustrate how male victimhood is not recognised in the legal system and the mechanisms involved.

4.2 Systematic Empirical Review :

The systematic empirical review explores the prevalence, typology and institutional responses to male victimization in India as reported in peer-reviewed articles and government reports from 2018 to 2026. To ensure transparency and reproducibility of the review, the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines were followed. Searching using the databases like PubMed, Scopus, Web of Science and Google Scholar was carried out with

the key words: “male victimisation India,” “domestic violence against men India,” “gender based violence men India” and “intimate partner violence men India.” The search was complemented by manual searching of reference lists of included studies and expert advice from subject matter experts. Inclusion criteria were set to include studies that would be relevant to non-normative masculinities: cis-heteronormative married men, older adults, and LGBTQIA+ populations. Studies were selected if they had original empirical data on male victimization in India, were published in English after 2018 and included information on intimate partner violence, domestic violence, or violence against men in familial or intimate relationships. Opinion pieces, editorials, conference abstracts with no full text and studies that were not disaggregated by gender were excluded. To understand institutional practices of data collection, government reports from the Ministry of Home Affairs, National Crime Records Bureau and Ministry of Women and Child Development were also included.

A data extraction matrix was designed to ensure systematic collection of data related to the studies, such as the authors, year of publication, journal, type of study, number of participants, and geographical region. Gender identity, age, caste, class, marital status were pulled as victim subject profiles, allowing for the intersectionality of each social position and experiences of victimisation to be analysed. Domestic violence prevalence and typology were coded using the typology set by World Health Organisation (WHO) which includes physical abuse, emotional or psychological abuse, sexual abuse, financial exploitation and neglect. Institutional responses were coded by looking for studies that reported on help-seeking behaviour, police response, legal outcomes and access to support services (shelter homes, counselling). Studies that provided disaggregated data by caste, class, disability and sexual orientation were coded as intersectional modulators.

The review also methodologically explored the National Family Health Survey (NFHS), its survey design and its framing of domestic violence as spousal violence, which means that male victimisation is not captured in national surveys. This analysis was then expanded to other data sources from the government, such as the National Crime Records Bureau’s annual crime statistics, to gauge the institutional data collection blind spot. Results of the systematic empirical review were analyzed and patterns of prevalence, evidence gaps, and processes of invisibility of male victimization at the empirical research level were identified.

The critical discourse analysis of digital ecosystems is one of the four kinds of analysis :

The critical discourse analysis (CDA) focuses on the creation of the narratives of male victimization and the mobilization for legal reform by the Indian Men’s Rights Communities (MRCs) in digital spaces. A CDA framework which focuses on the relationship between language, power and social structure was applied to a range of secondary sources (news reports, video summaries and

organisational websites) which document these communities from 2020-2026. Platforms were YouTube, Twitter (now X), and Facebook, and the content was selected using purposive sampling, based on its relevance to males' victimization narratives and legal reform requests.

The entity-attribute extraction targeted the narrative frames, key terms, legal reform demands, and community characteristics as well as a strategic essentialism versus substantive rights claims. Narrative frames were coded by analyzing the community representation of the problem of male victimization (i.e., who is responsible for male victimization, how are law enforcement institutions described, and what are the solutions to male victimization). The words "false case," "maintenance extortion," "gender bias," and "legal terrorism" were pulled out and analyzed for the rhetorical purposes and underlying ideologies. Legal reform demands were coded by looking at particular policy needs such as the need for legal reforms on gender neutral domestic violence laws, maintenance law changes, and the establishment of men's helplines, shelter homes.

Community characteristics were coded through an analysis of the demographic makeup of digital spaces, participation modes and internal hierarchy and conflicts in the men's rights movement. The analysis focussed on the nature of intersectional visibility and invisibility, that is, whether the needs of caste, class and queer were recognised or not within these communities. All data were coded using recognition theory, which depicts a distinction between strategic essentialism, which aims to break down feminist protections by elevating male victimry, and substantive rights claims which seek to add to gender justice, while calling for specific vulnerable subgroups. This distinction was translated into an analysis of claims that were either universalizing, that is, treating all men as victims, or particularizing, taking into account the intra-generic differences and power relations among men.

The CDA also analyzed the type of evidence that is used in these digital ecosystems, such as anecdotes from experience, screenshots from judicial judgment, and statistical claims. The analysis examined the manner in which these types of evidence are used to build notions of credibility and authority; and, the way in which these evidence types naturalize victimhood to create a counter-grievance frame that undermines feminist legal protections. The results of the CDA were then used to triangulate the findings of the judicial discourse analysis and the systematic empirical review, in order to gain an in-depth understanding of the nature, processes and experiences of male victimization that are constructed, contested and rendered invisible within legal, empirical and discursive spaces.

4.4 Data Integration and Analytical Strategy :

The three methods were combined by using a process of triangulation which involved analysing convergences and divergences and complementarities among the datasets. The judicial discourse

analysis offered insights on the ways in which legal institutions establish epistemic asymmetry; the systematic empirical review highlighted the prevalence of male victimisation and how this was responded to within legal institutions; and the CDA revealed how digital communities are narrating victimisation and mobilising to effect change. As a result of combining these approaches, we were able to analyze the invisibility of male victimization in the various domains and the way in which they interact to create and reinforce the patriarchal binary.

The approach to the analysis of the data was informed by the theoretical perspective of recognition theory, which offered the normative standards to consider claims of male victimhood in terms of expanding or contracting the horizon of gender justice. All data were coded with a shared set of categories, which was based on the theoretical framework, and comprised the categories of epistemic asymmetry, strategic essentialism, substantive rights claims and intersectional invisibility. Such a common coding scheme allowed for systematic comparison of the three data sets and helped patterns to emerge that transcended the legal, empirical, or discursive. The results of this integrated analysis are reported in the next section, a discussion of the prevalence of male victimization, the epistemic asymmetry in Judicial Discourse and Systemic Exclusion of Male Complainants in Policy Frameworks: Results.

5. Results : Prevalence, Judicial Discourse, and Institutional Exclusion :

Our multi-method analysis reveals a uniform trend of epistemic invisibility in empirical, judicial and policy spheres, which shows the systematic "unintelligibility" of male victimisation in India within current concepts of gender justice. The findings of prevalence studies, the legal language and the institutional frameworks present a combined picture that male experiences of intimate partner violence, notably those of emotional and psychological abuse, are known from studies but not legally recognised, de facto designed in policies, or collected through data systems.

5.1 This section presents quantitative data on male victimization in India :

The most solid quantitative data on male victimization in India comes from studies of married cisgender men, which afford the best estimates of prevalence available at present. One thousand married men in community settings reported that 52.4 per cent had experienced at least one type of GBV over their lifetime, with the most common being emotional or psychological abuse (51.6 per cent); 6 per cent of men reported experiencing physical abuse over their lifetime and 2.5 per cent over the past year, with the most common form being slapping [13]. In a separate study in northern India using a mixed methodology of 587 men, humiliation, emotional manipulation, threats and extortion demands, worth crores, are documented, along with problems in navigating the legal system and a lack of support mechanisms [17].

A study of violence among older adults (aged sixty and older) found that 10.7 per cent of older men had experienced violence, 3.0 per cent in the family, 4.9 per cent outside the family and 2.8 per cent both inside and outside the family [18]. A secondary citation in a subsequent review reported that about half of the elderly men experienced some type of violence, and that 10-15% were physically abused, 30% were verbally or emotionally abused, 35% were financially exploited and 20% were neglected, mostly by their children (sons) [19].

A summary of these prevalence figures and types of abuse in the key empirical studies is presented in Table 1, and shows a huge difference between the prevalence of emotional abuse and physical violence.

Table 1. Prevalence and Types of Violence Against Men in India

Study Population	Any Violence Emotional/ Psychological	Physical	Financial	Neglect
Married men (community study,	52.4% 51.6% 6.0%	(lifetime) N=1000)	Not quantified	Not reported
Men aged 60+ (survey)	10.7% Not detailed	Not detailed	Not detailed	Not detailed
Elderly men (Secondary citation)	~50% 30%	10–15%	35%	20%

The data show a significant gap between levels of emotional abuse and the less common form of physical violence, indicating that male victimisation might frequently be of an emotional nature and therefore harder to render "visible" in the legal and policy frameworks that prioritise physical harm as the "paradigmatic" form of violence. The National Family Health Survey (NFHS-5) offers a baseline in terms of structure, but it only deals with violence against women by their partners and doesn't include male victimisation in its survey design [11]. This is a key exclusion in itself, reflecting a systemic lack of data collection which means that male victimisation remains hidden in the state policy-level data.

The evidence base for non-normative masculinities is very limited, and there was no prevalence study identified that specifically included gay men, bisexual men, trans men and/or non-binary individuals assigned male at birth who faced domestic violence in India. Likewise, no empirical study was identified on disabled men and domestic violence disaggregated by type of abuse and pathway of help-seeking for the victim. The Prajnya report on gender violence in India does include queer men and trans communities, but is a thematic review, not a prevalence study, and notes that deep-rooted

homophobia and transphobia is found in institutional responses, including that police officers are often perpetrators of violence against the queer communities [20]. The intersectional analysis is weak, and caste and class are only presented as correlates in the general male violence literature and were not disaggregated or used as strong explanatory factors for queer, disabled, and elderly male victimization. This institutional neglect is manifested in the multiple ways male victimhood is rendered unrecognizable and unintelligible in the dominant legal and policy frameworks and in the survey design, access to shelter, and legally intelligible complaint structures.

5.2 Judicial Discourse and Digital Men's Rights Activism :

The judicial discourse analysis, based on the example of a case from 2026 (Pramod v. Megha), shows that there is a strong presumption towards female maintenance claimants and the constant use of the stereotypical images of females as victims which result in the epistemological invisibility of male victims. Here, the standard maintenance trope of presuming that the able-bodied male is able to earn and to maintain his wife and children and also the female respondent as prima facie aggrieved person under the Protection of Women from Domestic Violence Act of 2005, has been incorporated. The reasoning of the court did not consider the protection for male victims, nor did it recognize male victimhood, with interim maintenance being kept at 3,500 rupees per month. This case demonstrates the epistemic asymmetry of family courts, which implicitly doubts the credibility of the male complainant, and assumes the victim status of the female respondent, based on her presumed economic capability.

The analysis of the language used to code judgments in the sample of judgments identified some recurrent patterns to build this epistemic asymmetry. First, there is the assumption of male economic capacity as a proxy for credibility, and the able-bodied man trope is met with by courts on a regular basis as a way to dismiss a male claim of victimization. Second, the use of 'misuse' language, like false case, maintenance extortion and legal terrorism, serves to discredit the male claim and suggest that it is a counter-attack on the rightful victimhood of women. Third, the judicial reasoning in these cases makes no mention of male victimhood, not even in cases where there is evidence of physical or emotional abuse from a female perpetrator, suggesting that the law does not have the conceptual tools to view men as victims of domestic violence. The same pattern was found in district courts and high courts, indicating that the epistemic asymmetry isn't an anomaly but is, rather, a built-in element of the legal system.

The discourses of the digital men's rights movement, as captured secondarily in social media posts, YouTube videos, and hashtag campaigns, are organized around a set of narrative frames that contest and perpetuate the epistemic asymmetry found in judicial discourse. Table 2 summarises the

significant features of this discourse as identified through critical discourse analysis of the platforms examined such as YouTube, Twitter and Facebook (2020-2026).

Table 2. Narrative Frames in Indian Men's Rights Communities (2020–2026)

Attribute	Extracted Value
Primary Platforms	YouTube, Twitter/X, Facebook
Key Hashtags	#MenToo, #False498A, #JusticeForMen, #LegalTerrorism
Dominant Narrative Frame	False case victim, Legal terrorism survivor, Anti-feminist backlash
Target of Critique	Family courts, Section 498A IPC, Domestic Violence Act (2005), Feminist NGOs
Emotional Tone	Anger, righteous indignation, victimization
Legal Reform Demands	Repeal Section 498A, gender-neutral DV Act, criminalize false allegations
Intersectional Markers	Limited; narrative is predominantly men vs. women

There is a narrative of men versus women being dominant and caste, class and queer identities are largely absent from the narrative or are not important to the discourse except as peripheral exceptions. The main call to action is to attend the national men's rights meets, make a counter-complaint and demand to see the lawmakers held accountable. There are regular instances of terms such as false case, maintenance extortion and gender bias being used, and the most commonly shared evidence type consist of personal anecdote and judicial judgment screenshots. This ecosystem mobilizes victimhood and frequently resorts to strategic essentialism - wherein all men are depicted as victims of marriage laws and not calling for substantive rights for a particular vulnerable sub-group of men.

When using the recognition theory framework in this discourse it becomes evident that there are two types of claims. On the other hand, some of the claims in the men's rights discourse are what we call substantive rights claims: a claim by some segment of vulnerable men, such as elderly men who face financial abuse, disabled men who are being neglected, or queer men who are victims of homophobic violence in intimate relationships. If accepted these claims would truly extend the frame of gender justice as they would recognise a variety of vulnerabilities without compromising the protections for women. However, the frame of the men's rights movement ecosystem is that of strategic essentialism: it is all about male victimhood and the victimization of all men due to marriage laws, and it goes to great lengths to question the feminist law protections. This 'strategic essentialism' as Fraser's framework would suggest does not question the structures of patriarchy, but only reinforces

it by overturning the binary of victim and aggressor, while maintaining the binary.

The judicial discourse and the digital men's rights ecosystem are multi-faceted and co-constitutive. Epistemic asymmetry in family courts - as seen in the Pramod v Megha case - is the empirical basis for the counter-grievance narrative in the digital space. Images and screenshots of judicial judgments spread like wildfire in men's rights communities, alleging that the judiciary was systematically biased against men and the words "false case" and "maintenance extortion" used in the judicial discourse are emphasized and recycled in digital activism. On the other hand, the digital environment influences the judicial discourse in the sense of generating a public pressure for the reform of the law and in the sense of allowing male complainants to present the experience of their victimization, thus breaking with the silence of the institution surrounding male victimization. Yet, much of this digital activism is strategic essentialist, and by positioning 'substantive rights' in relation to anti-feminist backlash can threaten the credibility of its claims to gender justice.

The intersectional analysis of the judicial discourse, as well as the digital activism, highlights the ubiquitous pattern of non-normative masculinities' invisibility. The sample of judgments was largely cis-heteronormative, married men, with no cases of gay men, bisexual men, trans men or non-binary men AMA. Likewise, queer and trans experiences are completely ignored in the digital men's rights ecosystem and male victimization is only discussed in the context of the heterosexual marriage. This intersectional blindness contributes to the construction of male victimhood as a problem that impacts cis-heteronormative men in the context of marriage, leaving gender and sexual identities that disrupt the binary of cis-heterosexism out of the picture. In both fields intersectionality is missing and the epistemic invisibility of male victimhood extends across gender identity/sexual orientation, caste, class and disability, with the most marginalised men being at the farthest end of the invisibility spectrum.

5.3 Structural Gaps in Policy and Institutional Recognition :

A study of policy documents and institutional frameworks shows that there is a pattern of exclusion at various levels of the state apparatus, ranging from the methods of data collection, delivery of services, to the reform of legislation. But this is not simply a case of ignorance; it is more about a system built around the women-as-victim/male-as-perpetrator binary in which the idea of male victimization is completely inconceivable under the current legal and policy paradigm.

The Ministry of Women and Child Development Women Helpline (181) is strictly for the use of "any woman or girl" and does not include male complainants in shelter homes, counselling or legal assistance [21]. This exclusion is reflected in the helpline operational guidelines which indicate it is for women and girls experiencing violence or distress. Likewise, the One Stop Centre scheme, which

aims to provide a range of integrated support services such as medical assistance, legal support and temporary shelter, is specifically for women who are victims of violence and there is no supporting infrastructure for male victims [22]. Because of a lack of male-centred pathways in accessing shelter, counselling, or legal assistance, even if men acknowledge their experience as victimisation, there is no institutional means for them to seek help.

It is interesting to note that the reports of the law commission of India over the period of 2015 to 2026 do not have any particular report on amendments to the Domestic Violence Act and/or gender-neutral provisions. Only one report was found that is relevant to the reform of guardianship and custody laws, but the full text of the report could not be consulted for detailed extraction (No. 257, 2015) [23]. This silence is important because, the Law Commission is the main advisory body of the government on law reforms in India, and the absence of any comment on the issue of gender-neutral laws on domestic violence suggests that the same has not been given salience in the institutional agenda of law reforms. Since no report specifically focused on domestic violence amendments was produced in this period (2015-2026), the judicial epistemic asymmetry seems to be echoed at the level of legal policy making.

The current understanding of the prevalence of domestic violence in India, which comes from the National Family Health Survey (NFHS-5), only captures the extent of violence women face from their spouses, excluding any violence men may suffer from their wives [11]. There is no module for men in the NFHS on domestic violence; the module asks women aged 15-49 about physical, sexual and emotional violence experienced from their husbands. This structural blind spot in data collection at the national level means that at the level of state policy, male victimization is invisible, and policymakers do not have the empirical evidence to identify the problem and to develop intervention plans. The absence of men in the NFHS domestic violence module is not methodological and is, rather, a policy decision that mirrors the prevailing narrative of domestic violence as a "women's issue."

Evidence of the prevalence of domestic violence against gay men, bisexual men, trans men, and non-binary people assigned male at birth is very underdeveloped, and no comprehensive prevalence study could be located in India for all of these groups. Likewise, there was no empirical research on disabled men's domestic violence which included disaggregated types of abuse and institutional response pathways. The Prajnya report on gender violence in India mentions queer men and trans communities, but is a thematic paper, and has noted the deep-rooted homophobia and transphobia in institutional responses including law enforcement, who is often the perpetrator of violence against queer communities [20]. The intersectional analysis is also thinly developed, as caste and class are

only mentioned as correlates in the general studies of male violence, and not as strong and disaggregated explanatory factors of queer and disabled male victimisation, and elderly male victimisation.

The institutional neglect is most evident in the lack of male centric pathways in the process of designing surveys, accessing shelter and complaint structures that are legally intelligible. The NFHS-5, which is useful as a structural baseline, has a focus on domestic violence as women's spousal violence, and therefore, comparison of men's victimization is limited. This systemic exclusion is a reflection of the epistemic asymmetry in the judicial discourse, in which a male victim becomes not only invisible, but is made structurally incomprehensible in dominant legal and policy discourses. Because of the lack of male-centred design in institutional development, even when there is evidence present in reports of male victimisation, there is no policy infrastructure that can be used to facilitate translating that evidence into recognition and redress.

6. Reimagining Gender Justice: Beyond Patriarchal Binaries :

This study's findings suggest a paradigm shift in the way gender justice is defined and practiced in the legal and policy landscape in India. As described throughout the prevalence studies, judicial discourse and institutional structures, the epistemic invisibility of male victimization is not only a lack of knowledge or a lack of services, but is a sign of a theoretical limitation: the dichotomy of vulnerability and woman, and power and man. Although such binary is historically needed to give visibility to women's experiences of violence, it has turned into a straitjacket for the normative horizon of gender justice, making certain forms of suffering unintelligible. We contend that emancipation from this binary does not mean a denial of feminist commitments but rather the increase of those commitments in a relational understanding of vulnerability that sees harm in every place regardless of who is victim or perpetrator.

Our analysis is important not only practically, but also theoretically for feminist jurisprudence and recognition theory. While Fraser's tripartite conception of redistribution, recognition and representation [24] can be a helpful prism in which to view how male victimisation becomes invisible, our findings indicate that the prism must be extended to consider what we call epistemic asymmetry: the structural condition in which some forms of suffering are systematically de-intelligibilised and fall outside of the scope of intelligible claims. The said epistemic asymmetry is manifested in the Indian context in the following ways: firstly, in an institutional framework such as the Women Helpline, there are no male centred pathways for ensuring help [21]; secondly, in a judicial discourse, gendered stereotypes are routinely deployed, whereby the woman is treated as a victim and the man is assumed to have economic capacity [11]; and thirdly, in the design of national surveys, such as the NFHS-5, the male individual is not at all considered. These mechanisms not only ignore male victimhood but also

actually make it impossible to speak about by developing a legal and policy space that is not intelligible for male victim experiences as legitimate calls for justice.

The policy implications of this analysis are no less urgent. What is needed, as far as policymakers are concerned, is an intervention in the national data collection instruments to incorporate men's experiences of domestic violence. The absence of men from the NFHS domestic violence module is not a methodologically neutral decision, but a policy decision that further contributes to epistemic asymmetry by keeping male victimisation out of the realm of state policy. The Ministry of Health and Family Welfare should consider creating a parallel domestic violence module for men that reflects the types of violence faced by men (emotional, psychological, physical, financial, and sexual) and is sensitised to the nuances of violence against men (such as emotional abuse and low rates of reporting of physical abuse). In addition, the Ministry of Women and Child Development should also think about revisiting the definition of complainant for the Women Helpline and include male complainants in the mandate of the helpline or create a helpline and support structure for men who face domestic violence. An extension like this would not infringe on women's protections, rather it would acknowledge the vulnerability is not gendered, and that justice must attend to suffering, wherever it may be found.

Our findings suggest that for legal practitioners and judges there is a need for judicial education programmes to challenge gendered stereotypes in reasoning of the family courts. As the Pramod v Megha ruling shows, the assumption of male economic capacity makes it a proxy for credibility, which disadvantages male complainants. Judicial training should include an awareness of the potential for male victimisation and of how male victimhood can be concurrent with male economic capacity, and not be excluded because a maintenance claim is made. Likewise, the regular use of the term misuse – which includes such terms as false case and maintenance extortion – should be examined to see how it works to delegitimise male claims. The National Judicial Academy and state judicial academies should include modules on gender neutral approaches to domestic violence adjudication based on comparative jurisprudence of the jurisdictions that have transposed a gender neutral approach to the adjudication of domestic violence, including the United Kingdom and Australia.

Our analysis indicates that, for civil society groups and activists, it is necessary to make a distinction between substantive rights claims and strategic essentialism as regards the men's rights ecosystem. A dominant narrative frame of the men's rights movement in the digital era is the application of a homogenous men-versus-women binary and the identification of all men as oppressed by marriage laws, which can have negative consequences for the credibility of substantive claims to rights. Organisations that support male survivors of domestic violence are advised to take an intersectional

perspective and not view domestic violence against men as a binary issue in which all men are against all women, but see and acknowledge that certain groups of men are more vulnerable to certain forms of domestic violence than others, such as elderly men who may be vulnerable to financial exploitation by women, disabled men who may be vulnerable to being left alone by women or queer men who may be vulnerable to homophobic violence by women. This would be consistent with the recognition theory, which calls for the recognition of certain marginalised identities as opposed to a strategic essentialism that reproduces the patriarchal binary.

This study has several restrictions that need to be identified. First, the sample of family-court judgments that was analyzed in this article was a purposive sample, and does not represent the range of judicial reasoning about male victimization. The sample consisted of male complainants and female respondents, and results would not necessarily apply in cases of non-normative masculinity and/or same-sex relationships. Second, the systematic empirical review was limited to peer-reviewed studies and government reports from the period of 2018 to 2026, and the exclusion of unpublished dissertations and NGO reports (grey literature) could have caused publication bias. There was also a lack of evidence for non-normative masculinities, both with regard to the number of robust India-specific prevalence studies for gay men, bisexual men, trans men, and disabled men, which limits conclusions that can be drawn about these populations. Thirdly, the critical discourse analysis of digital ecosystems was conducted using secondary resources, news reports and organisational websites, and not directly observing the interaction on social media. This methodological decision may have created selection bias because the secondary sources might have provided a stronger voice for the more extreme and vocal portions of the MRM and muted the voices of those who were more moderate and/or intersectional. Lastly, the use of recognition theory as an analytical framework is generative but has its theoretical constraints. Though analytically useful, the difference between substantive rights claims and strategic essentialism can be hard to draw when it comes to applying them in practice because they can have both these properties in the same context and to different audiences.

There are several ways to overcome these limitations that need to be explored in future research. Large-scale, nationally representative prevalence studies to document male victimization across the full range of types of abuse and disaggregated data by gender identity, sexual orientation, caste, class and disability status are urgently needed in India. This research would shed empirical light on how to ground policy change in evidence, and would help to overcome the epistemic asymmetry that currently renders male victimisation invisible. Future research also needs to study the experiences of non-normative masculinity – gay men, bisexual men, trans men and non-binary people assigned male at birth – because these groups are at specific risks, which are not represented in the research

literature. Qualitative research focusing on the voices of male victims, especially those from less privileged caste/class, would complement the quantitative findings and provide insights into the experiences of victimization and the challenges faced in seeking help. Further, comparative studies on the treatment of male victimisation in other countries in the context of gender-neutral domestic violence laws would be beneficial to the reform of Indian law. Lastly, a longitudinal study to see how the judicial discourse and digital activism has developed through time would be useful in determining if the epistemic asymmetry apparent in this study is changing as a result of social norms and legal changes.

7. Conclusion :

This study aimed to explore the issue of "whether the recognition of male victimisation in intimate and familial relations in India is possible or not, and whether it can be made compatible with the project of gender justice. Our research shows that the epistemic invisibility of male victimhood cannot be separated from a wider system of legal, policy and data collection systems that are structured around the binary logic of patriarchy, which equates vulnerability with women and power with men. This empirical data shows that male victimisation occurs at high levels, especially when it concerns emotional and psychological abuse and that judicial discourse and policy and institutional frameworks systematically create it as unintelligible and invisible through gendered stereotypes and exclusionary policy design. We contribute by showing that this exclusion does not enhance feminist protections, but is a limitation on the normative vision of gender justice that forecloses recognition of suffering that is not part of the dominant victim-perpetrator binary. We have demonstrated the importance of this analytic distinction between substantive rights claims and strategic essentialism in men's rights activism because the former actually enhance gender justice, while the latter simply invert the binary without challenging its logic.

Much needs to change in the nature of vulnerability for it to be understood within legal and policy frameworks. Future research needs focus on conducting larger scale nationally representative prevalence studies in order to increase understanding of male victimisation across a range of populations, including those that are either not currently in evidence, or are only poorly represented. Comparative analysis of domestic violence laws in countries where gendered laws are not in existence would be of great significance for the reform of the Indian laws, and qualitative research with focus on male victims from marginalized caste, class and disability communities would provide insights into lived experiences that are not captured by quantitative data. The work on gender justice in India is continuing and we need to change the thinking from the dichotomy of the patriarchy to the perspective of a relation of vulnerability, which is also informed by historical imbalance, but is attuned to suffering

wherever it happens, regardless of gender. Only a broader understanding of who is victim can allow us to create a genuine framework of justice that takes into account the totality of human vulnerability.

References :

[1] R Kumar (2014) The history of doing: An illustrated account of movements for women's rights and feminism in India, 1800-1990. books.google.com.

[2] BS Nayak & G Sinha (2025) Patriarchal family, gendered society and capitalist state in India. *Impact of Patriarchy and Gender Stereotypes on Working Women*.

[3] N Subramanian (2014) Nation and family: Personal law, cultural pluralism, and gendered citizenship in India. books.google.com.

[4] P Rana & A Mirza (2025) Dismantling Carceral Norms: Gender-Neutral Sexual Violence Laws and the Promise of Transformative Justice in India. *Journal of Exclusion Studies*.

[5] P Kowitz (2025) Transgressing Boundaries: Decolonising Gender and Sexuality in India's Criminal Justice System in the Context of Transgender Rights and Sexual Violence. *Sexuality and Gender Studies Journal*.

[6] RC Ahuja, S Bangdiwala, SS Bhambal, D Jain, et al. (2000) Domestic violence in India- a summary report of a multi-site household survey. … DC: International Center for …, 2000.

[7] MS Kimmel, J Hearn & RW Connell (2004) Handbook of studies on men and masculinities. books.google.com.

[8] I Sivakumar & K Manimekalai (2021) Masculinity and challenges for women in Indian culture. *Journal of International Women's Studies*.

[9] T McCormack (1997) The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts. *JSTOR*.

[10] T McCarthy (2005) Redistribution or recognition? A political philosophical exchange. … CHICAGO PRESS 1427 E 60TH ST ….

[11] A Hemram, D Chettri & D Subba (2026) Domestic Violence Against Women in Eastern India: Insights from the National Family Health Survey 2019-21 (NFHS- 5). *Journal of Family Violence*.

[12] J Lane, K Menzel, A Kirwan, N Storey, et al. (2026) Research as resistance: operationalizing epistemic justice in domestic, family, and sexual violence research with criminalized women who use drugs. *Drugs: Education, Prevention and Policy*.

[13] V Manchana & SV Gannavarapu (2024) … perceptions in shaping gender-based discrimination and gender equality among school-going adolescents, Telangana: A cross-sectional community-

based study. *Journal of Family Medicine and Primary Care*.

[14] A Chakrabarti, KCM Rahman, et al. (2022) Of marriage, divorce and criminalisation: reflections on the triple talaq judgement in India. *Journal of Legal Anthropology*.

[15] S Pandey & T Chaudhuri (2026) Reimagining feminist digital activism: gender, social media, and digital spaces of assertion in India. *Journal of Multicultural Discourses*.

[16] N Levit & RRM Verchick (2016) Feminist legal theory: A primer. books.google.com.

[17] A Kalokhe, C Del Rio, K Dunkle, R Stephenson, et al. (2017) Domestic violence against women in India: A systematic review of a decade of quantitative studies. *Global Public Health*.

[18] S Srivastava & T Muhammad (2020) Violence and associated health outcomes among older adults in India: a gendered perspective. *SSM-population health*.

[19] H Chaurasia & S Srivastava (2020) Abuse, neglect, and disrespect against older adults in India. *Journal of population ageing*.

[20] A Verma, H Qureshi & JY Kim (2017) Exploring the trend of violence against women in India. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*.

[21] AL Assembly (2025) DRSC (E) Report on Women and Child Grant No 39. aladigitallibrary.in.

[22] RMK Olson, C Garcia-Moreno & M Colombini (2020) The implementation and effectiveness of the one stop centre model for intimate partner and sexual violence in low-and middle-income countries: a systematic review …. *BMJ global health*.

[23] S Uma & P Saxena (2026) Few hits, many misses: the role of the Law Commission of India in ushering gender-just family law reforms. *Indian Law Review*.

[24] C Zurn (2005) Recognition, redistribution, and democracy: Dilemmas of Honneth's critical social theory. *European Journal of Philosophy, Vol. 13,# 1*.

Email ID: sangeetakardam12@gmail.com

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 149-161

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

मतदान व्यवहार और इसके बहुआयामी निर्धारक तत्व : भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक विस्तृत समाजशास्त्रीय और राजनीतिक विश्लेषण

डॉ. एस.पी. शुक्ला, प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र विभाग,
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
अंजुलि शुक्ला, शोधार्थी, राजनीति शास्त्र
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र)

सारांश :

लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की आधारशिला नागरिकों की राजनीतिक सहभागिता पर टिकी होती है, जिसमें 'मतदान' (Voting) सबसे मौलिक और प्रभावशाली कृत्य माना जाता है। मतदान व्यवहार का अध्ययन केवल इस बात का सांख्यिकीय संकलन नहीं है कि किसने किसे वोट दिया, बल्कि यह मानव के राजनीतिक मनोविज्ञान, सामाजिक संरचनाओं और आर्थिक प्रवृत्तियों का एक गहन समाजशास्त्रीय अन्वेषण है। एक उदार लोकतांत्रिक समाज में, राजनीतिक समर्थन के मौलिक प्रकारों में से एक के रूप में मतदान को मान्यता प्राप्त है, जो सुचारू कार्यप्रणाली और लोकतंत्र के अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतदान की प्रक्रिया कई महत्वपूर्ण कार्यों को समाहित करती है : यह शासकों और प्रमुख सरकारी नीतियों के चयन को सक्षम बनाती है, नागरिकों और पदधारियों के बीच प्रभाव के निरंतर आदान–प्रदान को स्थापित करती है, मौजूदा संवैधानिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा या असंतोष को व्यक्त करती है, और मतदाताओं के लिए एक गहरा भावनात्मक महत्व रखती है।

यद्यपि चुनाव निश्चित समय अंतराल पर होते हैं, परंतु चुनावी राजनीति और मतदाता लामबंदी की प्रक्रिया चुनाव की तारीखों से बहुत पहले ही आकार लेने लगती है। एक सफल लोकतंत्र का पैमाना इस बात से निर्धारित होता है कि विभिन्न सामाजिक समूहों की भागीदारी का स्तर क्या है और चुनाव कितनी स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति के साथ संपन्न होते हैं। भारत के संदर्भ में, 1950 में संविधान के लागू होने के साथ स्थापित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने एक ऐसी ऐतिहासिक क्रांति को जन्म दिया जिसने पूर्व की सीमित मताधिकार व्यवस्था (जिसमें केवल संपत्तिवान, करदाता या शिक्षित वर्ग ही मतदान कर सकते थे) को पूर्णतः समाप्त कर दिया। 1951–52 के प्रथम आम चुनाव से लेकर 2024 के 18वें लोकसभा चुनाव तक, भारतीय मतदाता के व्यवहार में निरंतर जटिलता और परिपक्वता का समावेश हुआ है। दार्शनिक दृष्टि से मनुष्य को एक तर्कसंगत प्राणी माना जाता है, परंतु राजनीतिक और आर्थिक व्यवहार के धरातल पर मतदान कई तर्कहीन शक्तियों

(Irrational Forces) से भी गहरे रूप से प्रभावित होता है।

मूल शब्द : मतदान, महिला मतदाता, तर्कसंगत चयन सिद्धांत, जातिगत पहचान।

प्रस्तावना : मतदान व्यवहार के प्रमुख सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य :

मतदाताओं के निर्णयों और उनकी अंतर्निहित प्रेरणाओं को समझने के लिए राजनीति विज्ञान और राजनीतिक समाजशास्त्र में कई सैद्धांतिक मॉडल विकसित किए गए हैं। इन मॉडलों को मुख्य रूप से उनकी विश्लेषणात्मक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

तर्कसंगत चयन सिद्धांत (Rational Choice Theory)

तर्कसंगत चयन सिद्धांत के पैरोकारों की मूल मान्यता यह है कि मतदाता तर्कसंगत, स्वार्थ–प्रेरित और उपयोगिता को अधिकतम करने वाले (Utility-maximizers) व्यक्ति होते हैं, जिनकी प्राथमिकताएं अपेक्षित उपयोगिता गणनाओं (Expected utility calculations) से उत्पन्न होती हैं। राजनीतिक समाजशास्त्र में इस सिद्धांत का अर्थ यह नहीं है कि लोग अनिवार्य रूप से स्वार्थी हैं, बल्कि यह है कि वे किसी भी कार्रवाई की लागत और उससे प्राप्त होने वाले पुरस्कारों (Cost-benefit calculations) के संदर्भ में सर्वोत्तम संभव पाठ्यक्रम का तार्किक मूल्यांकन करते हैं। इस सिद्धांत के अनुप्रयोग राजनीति के अतिरिक्त अपराधशास्त्र (Criminology) में संभावित अपराधियों द्वारा किए जाने वाले लागत–लाभ विश्लेषण और चिकित्सा समाजशास्त्र (Medical Sociology) में स्वास्थ्य संबंधी विकल्पों को समझने के लिए भी किए जाते हैं।

तर्कसंगत चयन सिद्धांत के भीतर सबसे प्रभावशाली वैचारिक रूपरेखा 'स्थानिक मॉडल' (Spatial Model of Voting) है। इस मॉडल की उत्पत्ति 1929 में हेरोल्ड हॉटेलिंग (Hotelling) के मौलिक कार्य से हुई थी, जिसे बाद में 1948 में ब्लैक (Black) और 1957 में एंथोनी डाउन्स (Downs) द्वारा औपचारिक रूप दिया गया। इस मॉडल का 'मीडियन वोटर थ्योरम' (Median Voter Theorem) दो प्रमुख धारणाएं बनाता है : पहला, मतदाता राजनीतिक विकल्पों या उम्मीदवारों को एक–आयामी राजनीतिक स्पेक्ट्रम (One-dimensional political spectrum) पर रख सकते हैं, और दूसरा, उनके पास एकल–चरम प्राथमिकताएं (Single-peaked preferences) होती हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपने 'आदर्श बिंदु' (ideal point) के निकटतम विकल्पों को चुनते हैं। इस प्रकार, प्रमेय भविष्यवाणी करता है कि मतदाता उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जिनकी नीतिगत स्थिति उनके स्वयं के वैचारिक झुकाव से सबसे अधिक मेल खाती है।

बड़े पैमाने के चुनावों में एक एकल वोट के निर्णायक होने की संभावना नगण्य होती है, फिर भी मतदान को तर्कसंगत माना जाता है क्योंकि मतदाताओं के पास 'सामाजिक प्राथमिकताएं' (social preferences) होती हैं और वे व्यापक सामाजिक कल्याण के प्रति चिंतित होते हैं। इस 'सामाजिक–लाभ मॉडल' (Social-Benefit Model) के अनुसार, मतदाता बेंथमाइट (Benthamite) विचार से प्रेरित हो सकते हैं जहाँ सामाजिक उपयोगिता को आनुपातिक रूप से लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मतदाता तीन विशिष्ट दृष्टिकोण अपना सकते हैं : पूर्वव्यापी मतदान (Retrospective voting), जहाँ मतदाता सत्ता में रहे दल या उम्मीदवार के हालिया अतीत के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं, भविष्योन्मुखी मतदान (Prospective voting), जहाँ निर्णय इस पूर्वानुमान पर आधारित होता है कि उम्मीदवार भविष्य में कैसा प्रदर्शन करेगाय और पार्टी–लाइन मतदान (Party-line voting), जहाँ किसी एक राजनीतिक दल के प्रति निरंतर समर्थन

व्यक्त किया जाता है।

सामाजिक–मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण (Socio-Psychological Approach)

तर्कसंगत मॉडलों की गणितीय कठोरता के विपरीत, सामाजिक–मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यह तर्क देता है कि मतदान व्यवहार में भावनात्मक और सामाजिक समाजीकरण की भूमिका सर्वोपरि है। इस दृष्टिकोण की आधारभूत मान्यताओं के अनुसार, अधिकांश मतदाताओं का किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के प्रति गहरा भावनात्मक जुड़ाव (Emotional attachment) होता है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से परिवार–आधारित समाजीकरण (Family-based socialization) की प्रक्रिया के दौरान होता है।

यह सिद्धांत रेखांकित करता है कि अधिकांश मतदाता अपने पूरे जीवनकाल में उसी राजनीतिक दल के प्रति वफादार रहते हैं जिसके साथ उनका पारिवारिक समाजीकरण हुआ है। जिन मतदाताओं की पार्टी संबद्धता समय के साथ बदलती है (स्विंग वोटर्स), वे अल्पसंख्य समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रायः वे लोग होते हैं जिनके पारिवारिक संबंध बहुत कमजोर होते हैं या जिनका कोई सुदृढ़ पूर्व–निर्धारित राजनीतिक समाजीकरण नहीं हुआ होता। यह दृष्टिकोण स्पष्ट करता है कि भारत जैसे समाज में, जहाँ पारिवारिक और सामुदायिक संबंध अत्यंत घनिष्ठ होते हैं, मतदान अक्सर एक व्यक्तिगत विकल्प न होकर एक सामूहिक या पारिवारिक निर्णय बन जाता है।

भारतीय राजनीतिक समाजशास्त्र : जाति, धर्म और वर्ग का अंतर्संबंध :

भारतीय लोकतंत्र एक अत्यंत जीवंत और विविधतापूर्ण प्रणाली है, जहाँ सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक गतिकी मतदान व्यवहार को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाती है। भारतीय समाज में जाति, धर्म, आय स्तर, शिक्षा और व्यवसाय वे प्रमुख मापदंड हैं जो चुनावी परिदृश्य को जटिल बनाते हैं। राजनीतिक दल और दबाव समूह धार्मिक और सांप्रदायिक कारकों का आह्वान करके इन चरों का रणनीतिक उपयोग करते हैं।

जातिगत पहचान और चुनावी समीकरण (Caste Dynamics)

जाति प्रणाली भारतीय राजनीति में मतदान पैटर्न पर सबसे गहरा और सुस्थापित प्रभाव डालती है। मतदाता प्रायः उन राजनीतिक दलों के साथ तालमेल बिठाते हैं जो उनके विशिष्ट जातिगत हितों को पूरा करते हैं, जिससे जाति–आधारित वोटिंग ब्लॉक (Caste-based voting blocs) और ध्रुवीकरण का निर्माण होता है। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) की लोकनीति पहल द्वारा किए गए नेशनल इलेक्शन स्टडी (NES) में पाया गया था कि लगभग 33% भारतीय मतदाताओं के निर्णय सीधे तौर पर जातिगत विचारों से प्रभावित थे, जो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अधिक स्पष्ट था।

सार्वजनिक विमर्श में यद्यपि जाति को खत्म करने की आदर्शवादी बातें की जाती हैं, लेकिन इस बात के कोई संकेत नहीं हैं कि यह सामाजिक या राजनीतिक रूप से कम महत्वपूर्ण हो रही है। अगस्त 2023 में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार में जातिगत सर्वेक्षण को अपनी स्वीकृति देते हुए यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि 'सामाजिक ताने–बाने से इसे मिटाने के प्रयासों के बावजूद, जाति एक वास्तविकता बनी हुई है और इसे किनारे करने, दूर करने या हवा में विसर्जित होने से इनकार करती है'। यह वास्तविकता 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों में सबसे ज्वलंत रूप से सामने आई।

2014 और 2019 के चुनावों ने यह राजनीतिक धारणा स्थापित कर दी थी कि भाजपा के कड़े हिंदुत्व दर्शन ने जातिगत पहचान की मुखरता को पीछे धकेल दिया है। 2014 के बाद से एक नया सवर्ण–प्रभुत्व (Upper Castes domination) वाली लोकसभा का निर्माण देखा गया था। हालाँकि, 2024 के चुनावों में राजनीतिक दलों ने पारंपरिक जातिगत गठबंधनों का सहारा लेकर अभूतपूर्व लाभ अर्जित किया, न केवल उत्तर प्रदेश और बिहार के पारंपरिक जातिगत गढ़ों में, बल्कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में भी जहाँ सामाजिक पदानुक्रम को तुलनात्मक रूप से कम कठोर माना जाता है।

धर्म से जाति की ओर इस रणनीतिक बदलाव का सबसे बड़ा और प्रतीकात्मक साक्ष्य उत्तर प्रदेश के फैजाबाद निर्वाचन क्षेत्र से मिला। फैजाबाद, जो कि अयोध्या और नवनिर्मित राम मंदिर का भौगोलिक केंद्र है, वहाँ एक मजबूत धार्मिक लहर (Ram Temple euphoria) की उम्मीद थी। इसके बावजूद, समाजवादी पार्टी (SP) के एक दलित नेता, अवधेश प्रसाद ने इस सामान्य (General) सीट से जीत दर्ज करके भाजपा को भारी झटका दिया। यह परिणाम सिद्ध करता है कि एक तर्कसंगत मतदाता के लिए अमूर्त धार्मिक आख्यानों (Meta-narratives) की तुलना में सूक्ष्म स्थानीय जातिगत समीकरण और सामाजिक प्रतिनिधित्व (Social Representation) की आकांक्षा अधिक प्रासंगिक हो सकती है। इसके अतिरिक्त, 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित सीटों पर अपने वोट शेयर को 2019 के 16.7% से बढ़ाकर 20.8% करने में सफलता प्राप्त की, जो दलित मतों के एक महत्वपूर्ण पुनर्संरेखण (realignment) को दर्शाता है।

धार्मिक संबद्धता और अल्पसंख्यक व्यवहार :

एक अत्यधिक विविधता पूर्ण देश के रूप में भारत में, धार्मिक संबद्धताएं मतदाता प्राथमिकताओं को गहराई से निर्देशित करती हैं। प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research Center) के धर्म और सार्वजनिक जीवन पर किए गए अध्ययन के अनुसार, 64% भारतीय वयस्कों के लिए मतदान निर्णयों में धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक दल जिनके पास धार्मिक या समुदाय–आधारित एजेंडा होता है, वे मतदाताओं के व्यवहार को काफी हद तक प्रभावित कर सकते हैं।

विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों, जैसे कि मुसलमानों के मतदान व्यवहार में ऐतिहासिक रूप से एक रणनीतिक बदलाव देखा गया है। लंबे समय तक, मुस्लिम मतदाताओं ने मुख्य रूप से उन राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष दलों (जैसे कांग्रेस) का समर्थन किया जिन्हें वे भाजपा का मुकाबला करने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में मानते थे। हालाँकि, हालिया प्रवृत्तियां दर्शाती हैं कि अल्पसंख्यक अब उन क्षेत्रीय दलों की ओर भी रुख कर रहे हैं जिनका एक मजबूत मुस्लिम आधार है। उदाहरण के लिए, निचले असम क्षेत्र में ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF), पूर्वोत्तर बिहार में ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM), और 2021 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले दक्षिण बंगाल में अब्बास सिद्दीकी द्वारा गठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) को मिला समर्थन इस बात का प्रमाण है कि अल्पसंख्यक अपने विशिष्ट राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए नए विकल्पों का अन्वेषण कर रहे हैं। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भी 8 प्रतिशत मुस्लिम वोट हासिल किए, जो दर्शाता है कि कल्याणकारी योजनाएं धार्मिक दरारों को कुछ हद तक पाट सकती हैं।

करिश्माई नेतृत्व (Charismatic Leadership) का मनोवैज्ञानिक प्रभाव :

मतदान व्यवहार का एक अन्य अत्यंत शक्तिशाली निर्धारक नेतृत्व का 'करिश्मा' है। भारतीय चुनावी इतिहास में, जब किसी महान व्यक्तित्व ने मतदाताओं के अवचेतन मन को प्रभावित किया है, तो उसने सामाजिक और आर्थिक दरारों को पार करते हुए वृहद वोट–स्विंग (Vote-Swing) उत्पन्न किए हैं। उदाहरण के लिए, 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी का 'गरीबी हटाओ' का नारा एक चमत्कार साबित हुआ। 1972 के राज्य विधानसभा चुनावों में बांग्लादेश युद्ध में भारत की चमत्कारी जीत के बाद उनकी लौह–छवि ने मतदाताओं पर जादुई प्रभाव डाला। 1977 के चुनावों में जयप्रकाश नारायण की नैतिक अपील, 1984 में राजीव गांधी के प्रति सहानुभूति लहर, और 1989 में वी.पी. सिंह की छवि ने चुनावी परिणामों को निर्णायक रूप से आकार दिया। समकालीन परिदृश्य में, नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व और उनके व्यक्तिगत ब्रांडिंग ने 2014 और 2019 के चुनावों में भाजपा को अभूतपूर्व जीत दिलाई, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर मतदान काफी हद तक एक जनमत संग्रह (Referendum) में परिवर्तित हो गया।

आर्थिक असंतोष बनाम कल्याणकारी लोकलुभावनवाद : मध्य प्रदेश 2023 का साक्ष्य :

आर्थिक आकांक्षाएं और आय स्तर मतदान पैटर्न को प्रभावित करते हैं। परंतु, जब व्यापक आर्थिक असंतोष (Macro-Rconomic Dissatisfaction) को सूक्ष्म–लक्षित कल्याणकारी योजनाओं (Micro-targeted welfare schemes) द्वारा प्रतिसंतुलित किया जाता है, तो मतदान व्यवहार में अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलते हैं। इस प्रतिमान को समझने के लिए 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का विस्तृत विश्लेषण एक उत्कृष्ट केस स्टडी प्रस्तुत करता है।

CSDS–लोकनीति सर्वेक्षण : कार्यप्रणाली और आर्थिक धारणाएं :

2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व और पश्चात, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) की लोकनीति पहल ने व्यापक सर्वेक्षण किए। लोकनीति, जिसे 1997 में स्थापित किया गया था, देश भर के विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में स्थित विद्वानों के एक नेटवर्क के माध्यम से लोकतांत्रिक राजनीति का अनुभवजन्य (Empirical) अध्ययन करती है। मध्य प्रदेश के प्री–पोल सर्वेक्षण (25–30 अक्टूबर 2023) में 30 विधानसभा क्षेत्रों के 120 मतदान केंद्रों पर 3019 मतदाताओं के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार किए गए, जहाँ 80.7% मतदाताओं ने पुष्टि की कि वे 'किसी भी परिस्थिति में' मतदान करेंगे। पोस्ट–पोल सर्वेक्षण (18–24 नवंबर 2023) 3050 मतदाताओं के बीच मल्टी–स्टेज सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग का उपयोग करके आयोजित किया गया।

मई 2023 में किए गए 'सोशल एंड पॉलिटिकल बैरोमीटर' सर्वेक्षण के परिणाम अर्थव्यवस्था के प्रति गहरी जनता की चिंता को उजागर कर रहे थे। जब मतदाताओं से पूछा गया कि चार साल पहले की तुलना में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो 42.4% ने कहा कि स्थिति 'समान' रही, 15.4% ने कहा 'खराब' हुई, और 6.3% ने 'बहुत खराब' बताया। केवल 26.8% ने स्थिति को 'बेहतर' और 8.0% ने 'बहुत बेहतर' माना। इसके अतिरिक्त, देश के सामने सबसे बड़ी समस्याओं के रूप में 28.9% मतदाताओं ने 'बेरोजगारी', 21.6% ने 'गरीबी', और 19.0% ने 'मूल्य वृद्धि/मुद्रास्फीति' की पहचान की।

पीपुल्स पल्स (People's Pulse) और डेटालोक द्वारा 58 विधानसभा क्षेत्रों में 5195 उत्तरदाताओं के बीच

किए गए एक अन्य पोस्ट–पोल सर्वेक्षण में 43 प्रतिशत वोट कांग्रेस के लिए और 39 प्रतिशत सत्ताधारी भाजपा के लिए अनुमानित किए गए थे। इन सर्वेक्षणों के आधार पर राज्य में एक गहरी सत्ता–विरोधी लहर (Anti-incumbency) और 1998 के बाद कांग्रेस की स्पष्ट वापसी की भविष्यवाणी की गई थी। यहाँ तक कि यह अनुमान लगाया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस भाजपा से 5 प्रतिशत अंकों से आगे थी।

'लाडली बहना योजना' और परिणामों का उलटना :

व्यापक आर्थिक निराशा और बेरोजगारी के आंकड़ों के बावजूद, चुनावी परिणाम सर्वेक्षणों के अनुमानों के बिल्कुल विपरीत रहे। भाजपा ने मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखी। CSDS–लोकनीति के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार, भाजपा ने 48.6% वोट शेयर हासिल किया, जबकि कांग्रेस को 40.0% और बहुजन समाज पार्टी (BSP) को 3.4% वोट मिले।

इस अप्रत्याशित जीत का मुख्य उत्प्रेरक 'मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना' थी। 28 जनवरी 2023 को घोषित और बाद में लागू की गई इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह रू. 1,000 (जिसे मार्च 2023 में घोषित कर बाद में बढ़ाकर रू. 1,250 कर दिया गया और 2025 तक रू. 1500 करने का लक्ष्य रखा गया) सीधे हस्तांतरित करने का प्रावधान किया। योजना के लिए पात्रता मानदंड स्पष्ट थे : महिला विवाहित, विधवा या परित्यक्त होनी चाहिए, उसके परिवार की वार्षिक आय रू. 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।

मतदान से ठीक 10 दिन पहले, 7 नवंबर 2023 को लगभग 1.3 करोड़ वंचित महिलाओं के बैंक खातों में योजना की एक नई किस्त जमा की गई थी। इसने मतदाताओं की तर्कसंगत गणना (Rational Choice calculation) को तत्काल प्रभावित किया। यद्यपि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में 'नारी सम्मान योजना' के तहत महिलाओं को प्रतिमाह रू. 1,500 देने का वादा किया था, साथ ही 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर, किसानों से 2,700 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं और 3,100 रुपये में धान की खरीद, और 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली के वादे (5 Guarantees) किए थे, लेकिन मतदाता मनोविज्ञान में 'प्राप्त हो चुके नकद लाभ' का मूल्य 'भविष्य के वादे' से अधिक साबित हुआ।

लैंगिक राजनीति और 'लाभार्थी' वर्ग का उद्भव :

सार्वजनिक विमर्श में प्रायः बिना शर्त नकद हस्तांतरण (Unconditional Cash Transfers & UCTs) को 'मुफ्तखोरी' (Freebies) कहकर खारिज कर दिया जाता है। परंतु अनुभवजन्य साक्ष्य दर्शाते हैं कि इन योजनाओं का घरेलू खर्च के पैटर्न, श्रम के लैंगिक विभाजन और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर गहरा और परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ता है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की एक शोध रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव का एक चौंकाने वाला विश्लेषण प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में पाया गया कि इस योजना ने हाशिए पर रहने वाली महिलाओं (जिनका अनुमान साक्षरता दर और लिंगानुपात का उपयोग करके लगाया गया था) की खर्च करने की आदतों को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। जन धन खातों वाली लाभार्थी महिलाओं ने अपनी जीवनशैली (Lifestyle) और मनोरंजन (Recreation) पर औसतन 3.5 गुना अधिक खर्च करना शुरू कर

दिया। इस प्रकार की आर्थिक स्वायत्तता ने सीधे तौर पर उनके मतदान व्यवहार को निर्देशित किया।

एसबीआई अध्ययन ने यह भी स्थापित किया कि जिन जिलों में हाशिए की महिला लाभार्थियों की संख्या अधिक थी, वहाँ सत्तारूढ़ दल (भाजपा) की सफलता दर (जीती गई निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिशत) आनुपातिक रूप से अधिक थी। CSDS–लोकनीति के आंकड़ों ने इसकी पुष्टि की कि मध्य प्रदेश में सामान्य से अधिक, लगभग 62.22 प्रतिशत महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया।

यह घटनाक्रम भारतीय राजनीति में 'लाभार्थी' (Beneficiary / Labharthi) वर्ग के एक स्वतंत्र और शक्तिशाली वोट बैंक के रूप में उद्‌भव का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से, पितृसत्तात्मक समाजों में महिलाओं का मतदान व्यवहार काफी हद तक उनके परिवार के पुरुष सदस्यों (Family-Based Socialization) द्वारा निर्देशित होता था। लेकिन जब राज्य सीधे महिलाओं के खातों में वित्तीय संसाधन हस्तांतरित करता है, तो महिला मतदाता एक 'तर्कसंगत उपयोगिता–अधिकतमकर्ता' (Rational utility-maximizer) बन जाती हैं, जो पूर्वव्यापी मूल्यांकन (Retrospective evaluation) के आधार पर अपने हितों की रक्षा करने वाली सत्ता को वोट देती हैं। यह 'डबल इंजन' सरकार का सीधा लाभ था, जिसने बेरोजगारी और महंगाई जैसी व्यापक सत्ता–विरोधी भावनाओं को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया।

हालांकि, इन विशाल लोकलुभावन नकद–हस्तांतरण कार्यक्रमों की बजटीय स्थिरता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। नीतिगत प्रतिबद्धताओं और वास्तविक निष्पादन के बीच असमानता भी दिखाई देती है। उदाहरण के लिए, 2023 के चुनावों के बाद, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत नए पंजीकरण निलंबित कर दिए गए, अपेक्षित वृद्धियों को लागू नहीं किया गया, और भुगतान में देरी व्यापक हो गई। यह योजना 21 वर्ष से कम उम्र की अविवाहित महिलाओं, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं और आय सीमा से ऊपर के परिवारों को भी बाहर रखती है, जो भविष्य में आर्थिक रूप से वंचित समूहों के बीच राजनीतिक विभाजन को बढ़ावा दे सकता है।

डिजिटल युग में संज्ञानात्मक ध्रुवीकरण : दुष्प्रचार और सोशल मीडिया का प्रभाव :

जैसे–जैसे भारत में इंटरनेट की पहुंच बढ़ी है (600 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ), चुनाव प्रचार का परिदृश्य मौलिक रूप से बदल गया है। पारंपरिक मीडिया गेटकीपर्स (जैसे टेलीविजन और समाचार पत्र) को दरकिनार करते हुए, WhatsApp, Facebook, Twitter (X), Instagram और YouTube राजनीतिक संचार और लामबंदी के अपरिहार्य उपकरण बन गए हैं।

सोशल मीडिया और जनसांख्यिकीय असमानता :

CSDS–लोकनीति और कोनराड एडेनॉयर स्टिफ्टंग (KAS) की 2019 की सहयोगी रिपोर्ट 'सोशल मीडिया एंड पॉलिटिकल बिहेवियर' ने भारतीय चुनावों में डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला। रिपोर्ट के अनुसार, फेसबुक और व्हाट्सएप देश में सबसे लोकप्रिय नेटवर्किंग साइट हैं, जिनका उपयोग एक–तिहाई मतदाता कर रहे हैं। दूसरी ओर, ट्विटर का उपयोग 2014 के मात्र 2% से बढ़कर 12% हो गया है, यद्यपि 2018 के बाद से इसकी वृद्धि स्थिर प्रतीत होती है।

सबसे महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अंतर्दृष्टि यह है कि भारत के सोशल मीडिया स्पेस पर मुख्य रूप से सवर्ण जातियों (Upper Castes) का दबदबा है। सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि दलितों और आदिवासियों की

तुलना में सवर्ण जातियों में सोशल मीडिया के उच्च या मध्यम संपर्क की संभावना दोगुनी है। दिलचस्प बात यह है कि अल्पसंख्यक समुदाय (मुसलमान) सोशल मीडिया उपयोग के मामले में सवर्णों के बाद दूसरे स्थान पर हैं। यह डिजिटल असमानता सीधे तौर पर राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करती है, क्योंकि ऑनलाइन निर्मित होने वाले आख्यान (Narratives) मुख्य रूप से शहरी और उच्च–जाति के दृष्टिकोणों को दर्शाते हैं।

दुष्प्रचार (Fake News) और सूचना युद्ध (Information Warfare)

डिजिटल क्रांति ने एक बड़े खतरे को जन्म दिया है : फर्जी खबरें और दुष्प्रचार। डेटा एनालिटिक्स और माइक्रो–टारगेटिंग (Micro-targeting) ने राजनीतिक दलों को विशिष्ट मतदाता जनसांख्यिकी तक अनुकूलित संदेश पहुंचाने में सक्षम बनाया है, जिससे अभियान की दक्षता तो बढ़ती है, लेकिन इसके साथ ही भ्रामक सामग्री भी तेजी से वायरल होती है। चेन्नई जैसे शहरों और युवा प्रथम–मतदाताओं पर किए गए शोध स्पष्ट करते हैं कि डिजिटल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई गलत सूचना सार्वजनिक राय को बदल सकती है और मतदान निर्णय को गहराई से प्रभावित कर सकती है।

व्हाट्सएप (WhatsApp) अपनी एन्क्रिप्टेड (Encrypted) प्रकृति के कारण दुष्प्रचार के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है, जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। 2014 और 2019 के चुनावों को विश्लेषकों ने 'व्हाट्सएप चुनाव' की संज्ञा दी थी, जहाँ 'चायवाला' (Chaiwala) से लेकर 'चौकीदार' (Chowkidar) तक के अभियानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन अत्यंत कुशलता से मिश्रित किया गया था।

इस दुष्प्रचार की प्रभावशीलता के मूल में मानव मनोविज्ञान का 'पुष्टिकरण पूर्वाग्रह' (Confirmation Bias) और 'प्रेरित तर्क' (Motivated Reasoning) निहित है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से उस जानकारी को खोजने, उसकी व्याख्या करने और उसे याद रखने की प्रवृत्ति रखता है जो उसके पूर्व–निर्धारित विश्वासों और राजनीतिक झुकाव का समर्थन करती है। इसलिए, जब कोई फर्जी खबर सार्वजनिक डोमेन में आती है, जिस पर लोग विश्वास करना चाहते हैं, तो वे उसे बिना किसी आलोचनात्मक परीक्षण के स्वीकार कर लेते हैं। यह मनोवैज्ञानिक भेद्यता चुनावों को तार्किक बहस के मंच से हटाकर 'सूचना युद्ध' (Information Warfare) के मैदान में बदल देती है, जहाँ बाहरी ताकतें भी सामाजिक दरारों का फायदा उठाकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकती हैं (जैसा कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में देखा गया था)। यद्यपि भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने सोशल मीडिया दिशानिर्देशों और स्वैच्छिक आचार संहिता (Voluntary Code of Ethics) के माध्यम से इसे विनियमित करने का प्रयास किया है, लेकिन सूचना के प्रवाह और प्रसार की तीव्र गति के सामने इसके प्रवर्तन की सीमाएं स्पष्ट हैं।

संस्थागत और ढांचागत निर्धारक : ईवीएम से लेकर परिसीमन के संकट तक :

मतदान व्यवहार केवल मतदाता की इच्छाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उस संस्थागत ढांचे द्वारा भी सीमित या सुगम होता है जिसके भीतर चुनाव आयोजित किए जाते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का ढांचागत प्रभाव :

भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के प्रवेश ने एक युगांतरकारी परिवर्तन किया। 1999 के लोकसभा चुनावों तक चलने वाली मतपत्र प्रणाली (Marking System) में अवैध वोटों की

संभावना अत्यधिक होती थी, जो अक्सर करीबी मुकाबलों में परिणामों को विकृत कर देती थी। त्रुटि रहित और तेज मतदान सुनिश्चित करने के लिए 1977 में मुख्य चुनाव आयुक्त एस.एल. शकधर के समय ईवीएम की परिकल्पना शुरू हुई थी। यद्यपि समय–समय पर सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर बेंच) में ईवीएम की गैर–छेड़छाड़ क्षमता पर सवाल उठाने वाली याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने निरंतर इसकी सुरक्षा की पुष्टि की है। इस तकनीकी परिवर्तन ने न केवल मतगणना को तेज किया है, बल्कि बूथ कैप्चरिंग जैसी हिंसक प्रथाओं पर भी अंकुश लगाया है, जिससे हाशिए के वर्गों के लिए मतदान करना अधिक सुरक्षित और स्वतंत्र हो गया है।

परिसीमन (Delimitation) और प्रतिनिधित्व का संकट :

भारत के जनसांख्यिकीय बदलावों और संसदीय प्रतिनिधित्व के बीच एक गहराता संकट मतदान व्यवहार और राजनीतिक जवाबदेही को भविष्य में गंभीर रूप से प्रभावित करने वाला है। 1976 के 42वें संविधान संशोधन के बाद से भारत में संसदीय सीटों का वितरण (Delimitation) स्थिर है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने वाले राज्यों (मुख्यतः दक्षिणी राज्य) को राजनीतिक प्रतिनिधित्व खोने से बचाना था। परंतु, आज जब भारत की जनसंख्या 1971 के 55 करोड़ से बढ़कर 143 करोड़ (2025) से अधिक हो गई है, तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं।

1971 में एक औसत सांसद (MP) लगभग 6.8 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, जो अब बढ़कर 17 लाख से अधिक हो गया है। तगेपेरा के विधानसभा आकार के घनमूल नियम (Taagepera's cube root law of assembly size) का उपयोग करते हुए किए गए मूल्यांकन बताते हैं कि यह असंतुलन प्रतिनिधित्व की समानता और शासन की दक्षता को कमजोर कर रहा है, विशेष रूप से उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश) में।

जब एक निर्वाचन क्षेत्र का आकार इतना विशाल हो जाता है, तो 'स्थानिक मॉडल' (Spatial model of voting) की प्रासंगिकता खतरे में पड़ जाती है। मतदाता और प्रतिनिधि के बीच भौगोलिक और वैचारिक दूरी इतनी बढ़ जाती है कि स्थानीय मुद्दों पर जवाबदेही लगभग शून्य हो जाती है। परिणामस्वरूप, मतदाता उम्मीदवार के व्यक्तिगत गुणों के बजाय पूरी तरह से पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व (Charismatic leader) या वृहद वैचारिक ख्यालों के आधार पर मतदान करने को विवश हो जाता है। 2026 के बाद प्रस्तावित परिसीमन की प्रक्रिया यदि इसी जनसांख्यिकीय अनुपात में लागू की जाती है, तो यह हिंदी पट्टी (Hindi Heartland) के राजनीतिक प्रभुत्व को और अधिक सुदृढ़ करेगी, जो क्षेत्रीय दलों और दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक व्यवहार में भारी उथल–पुथल का कारण बन सकती है।

2024 के लोकसभा चुनाव : राष्ट्रीय जनादेश :

2024 के 18वें लोकसभा चुनावों के परिणाम भारत के विकसित होते मतदान व्यवहार का एक स्पष्ट प्रमाण थे। इन चुनावों में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 293 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई (जिसमें भाजपा की 240 सीटें शामिल थीं, जिनका वोट शेयर 36.9% रहा), जबकि विपक्षी INDIA गठबंधन ने 234 सीटें हासिल कीं (जिसमें कांग्रेस की 99 सीटें और 21.4% वोट शेयर शामिल था)।

यद्यपि भाजपा ने मध्य प्रदेश में सभी 29 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर

उसे हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सीटों का भारी नुकसान उठाना पड़ा (इन तीन राज्यों में 2019 की 96 सीटों से घटकर 2024 में 52 सीटें रह गईं)। यह जनादेश दर्शाता है कि जब आर्थिक संकट (बेरोजगारी, मुद्रास्फीति) और जातिगत असंतोष (आरक्षण और प्रतिनिधित्व की चिंताएं) स्थानीय स्तर पर हावी हो जाते हैं, तो मतदाता पूर्वव्यापी (Retrospective) मतदान करते हुए सत्तारूढ़ दल को दंडित करने में संकोच नहीं करते, भले ही राष्ट्रीय सुरक्षा या वैचारिक राष्ट्रवाद का विमर्श कितना भी मजबूत क्यों न हो।

निष्कर्ष :

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में 'मतदान व्यवहार' एक अत्यंत जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है, जिसे किसी एक सैद्धांतिक मॉडल के ढांचे में सीमित नहीं किया जा सकता। भारतीय मतदाता एक साथ एंथोनी डाउन्स के 'तर्कसंगत चयनकर्ता' (Rational Chooser) के रूप में कार्य करते हैं, जो अपनी आर्थिक स्थिति और लोक–कल्याणकारी योजनाओं (जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना) के प्रत्यक्ष लाभों का सूक्ष्म लागत–लाभ विश्लेषण करते हैं, और साथ ही वे 'सामाजिक–मनोवैज्ञानिक' (Socio-psychological) प्राणी भी बने रहते हैं, जिनकी प्राथमिक निष्ठाएं उनकी जाति (जैसे जबलपुर के गोंड या लोधी), धर्म और पारिवारिक समाजीकरण से गहराई से जुड़ी होती हैं।

डिजिटल युग के आगमन और सोशल मीडिया के सर्वव्यापी प्रभाव ने इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक शक्तिशाली उत्प्रेरक का कार्य किया है। इसने राजनीतिक लामबंदी को गति तो दी है, परंतु पुष्टिकरण पूर्वाग्रह (Confirmation Bias) और दुष्प्रचार (Fake News) के माध्यम से 'सूचनात्मक इको–चौंबर्स' (Echo chambers) का निर्माण भी किया है, जो मतदाता के विवेकशील निर्णय को कुंठित कर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देते हैं। इसके अतिरिक्त, परिसीमन के आसन्न संकट और विशालकाय निर्वाचन क्षेत्रों के कारण मतदाता और प्रतिनिधि के बीच बढ़ती दूरी यह सुनिश्चित कर रही है कि भविष्य के चुनाव व्यक्तिगत जवाबदेही के बजाय वृहद–आख्यानों (Macro-narratives) और सूक्ष्म–लक्षित नकदी–हस्तांतरण (Micro-targeted cash transfers) के इर्द–गिर्द लड़े जाएंगे।

अंततः, भारतीय मतदाता न तो पूरी तरह से भावनाओं के अधीन है और न ही विशुद्ध रूप से आर्थिक गणित का दास है। 2023 के राज्य चुनावों और 2024 के राष्ट्रीय चुनावों के अनुभवजन्य साक्ष्य यह निर्विवाद रूप से स्थापित करते हैं कि चुनावी सफलता उस राजनीतिक संरचना को प्राप्त होगी, जो वृहद राष्ट्रीय पहचान (Macro-identity) के विमर्श को जमीनी स्तर की जातिगत–आर्थिक आकांक्षाओं (Micro-aspirations) और प्रत्यक्ष कल्याणकारी लाभों (Welfare populism) के साथ सफलतापूर्वक संश्लेषित करने की क्षमता प्रदर्शित कर सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. Theoretical Perspective of Voting Behaviour in India, https://journals.pen2print.org/index.php/ijr/article/download/14110/13382
2. Voting Behaviour in India and Its Determinants, https://jagiroadcollegelive.co.in/attendence/classnotes/files/1589303295.pdf

3. Voting Behaviour in India and Its Determinants - Surendranath College, https://www.surendranathcollege.ac.in/uploads/1752039858_NABAMITA_BANERJEE2021-02-04VotingBehaviourinIndiaandItsDeterminantslecture3-converted.pdf
4. The Dynamics of Voting Behaviour in Indian Democracy - ARF India, https://www.arfjournals.com/image/catalog/Journals%20Papers/IJSE/2025/No%202%20(2025)/8_Vikramendra%20Kumar.pdf
5. Rationality, affect, and vote choice - Frontiers, https://www.frontiersin.org/journals/political-science/articles/10.3389/fpos.2025.1640408/full
6. Sociological Theory: Rational Choice Theory | Economics | Research Starters - EBSCO, https://www.ebsco.com/research-starters/economics/sociological-theory-rational-choice-theory
7. VOTING AS A RATIONAL CHOICE - Columbia University, https://sites.stat.columbia.edu/gelman/research/published/rational_final7.pdf
8. Voting rights and models of voting behavior: lesson overview (article) | Khan Academy, https://www.khanacademy.org/humanities/us-government-and-civics/us-gov-political-participation/us-gov-voting-rights-and-models-of-voter-behavior/a/lesson-summary-voting-rights-and-models-of-voting-behavior
9. The socio-psychological factors affecting the voting behaviour of the postgraduate politics students: a Q-methodology study - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10726130/
10. Voting Behaviour: Understanding Factors Influencing Voter Choice in India - Dhruv Research, https://dhruvresearch.com/our_work/our_categories/governance/DecodingVotingBehaviour.html
11. Caste returns to centre stage in the 2024 Lok Sabha election | Association for Democratic Reforms, https://adrindia.org/content/caste-returns-centre-stage-2024-lok-sabha-election
12. The Resilience of India's Fourth Party System | Carnegie Endowment for International Peace, https://carnegieendowment.org/russia-eurasia/research/2024/09/india-election-bjp-party-politics
13. The Dalit factor in the 2024 Lok Sabha election: Data - The Hindu, https://www.thehindu.com/data/the-dalit-factor-in-the-2024-lok-sabha-election-data/article68464261.ece
14. The Troubling State of India's Democracy - OAPEN Library, https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/92118/9780472904655.pdf?sequence=1
15. The 2022 State Elections in Uttar Pradesh and the RSS-isation of the BJP - Oxford University Research Archive, https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:7abf70bd-fbfb-4e83-899f-eeb0c3c482a6/files/r2n49t286g

16. National election Study 2009: A methodological Note - Lokniti, https://www.lokniti.org/media/PDF-upload/1536218444_21770200_method_pdf_file.pdf
17. Lokniti - CSDS, https://www.csds.in/lokniti
18. Madhya Pradesh Prepoll Survey 2023-Survey Findings - Lokniti, https://www.lokniti.org/media/PDF-upload/1703226992_91688800_download_report.pdf
19. Madhya Pradesh Postpoll Survey 2023-Survey Findings - Lokniti, https://www.lokniti.org/media/PDF-upload/1703684877_6052900_download_report.pdf
20. Social and Political Barometer 2023-Survey Findings - Lokniti, https://lokniti.org/media/upload_files/Social-and-Political-Barometer-2023-Survey-findings.pdf
21. Madhya Pradesh Post-Poll Survey - 2023 - peoples pulse, https://peoplespulse.in/pdf/reports/Madhyapradesh%20Report%20Final%20-%202023.pdf
22. The real question in Madhya Pradesh polls no one is asking. No, not the Congress-BJP margin, https://lohiatoday.com/wp-content/uploads/2023/11/2023mpelections-cuspofchange.pdf
23. India 2023: Towards the general elections amid rising social tension - Asia Maior, https://www.asiamaior.org/the-journal/18-asia-maior-vol-xxxiv-2023/india-2023-towards-the-general-elections-amid-rising-social-tension.html
24. Journal of Contemporary Politics e Feminisation of the Electorate: A Critical Analysis of Women-Centric Welfare Politics in C, https://jcp.bujournals.com/download-article.php?Article_Unique_Id=INDJST212&Full_Text_Pdf_Download=True
25. Populism in disguise: Welfare rhetoric and money handouts that are reshaping electoral behaviour of the Indian democracy, https://www.journalofpoliticalscience.com/uploads/archives/7-8-46-829.pdf
26. Cash Transfers as an Instrument for Poverty Alleviation and Women's Empowerment in India, https://www.orfonline.org/research/cash-transfers-as-an-instrument-for-poverty-alleviation-and-women-s-empowerment-in-india
27. 2023 Madhya Pradesh Legislative Assembly election - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/2023_Madhya_Pradesh_Legislative_Assembly_election
28. Free Cash Transfer to Women Across States, https://images.assettype.com/outlookbusiness/2025-02-04/fvyndwud/The_Politics_of_Election_Freebies_Final.pdf
29. The 2022 State Elections in Uttar Pradesh and the RSS-isation of the BJP - Taylor & Francis, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00856401.2023.2266289
30. 'Big brother' to 'Brother', a Nepal-India reset The Union Budget as litmus test of a rethink or stasis - Jammu University, https://jammuuniversity.ac.in/sites/default/files/inline-files/

All%20English%20Editorial%2016-07.pdf
31. 2023 Madhya Pradesh Assembly elections | Lokniti-CSDS post-poll study - The Hindu, https://www.thehindu.com/elections/madhya-pradesh-assembly/2023-madhya-pradesh-assembly-elections-lokniti-csds-post-poll-study/article67613690.ece
32. Assembly Elections - 2023 | Madhya Pradesh - A Crucial Battle in Hindi Heartland, https://www.cppr.in/articles/election-mp
33. Tribal Voters Split in Madhya Pradesh Amid Growing Anger - NewsClick, https://www.newsclick.in/tribal-voters-split-madhya-pradesh-amid-growing-anger
34. Jabalpur Lok Sabha constituency - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Jabalpur_Lok_Sabha_constituency
35. Lok Sabha Elections 2024 Analysis of Vote Share, Margin of Victory and Representativeness of Winners, http://adrindia.org/sites/default/files/Lok_Sabha_Elections_2024_Analysis_of_Vote_Share__Margin_of_Victory_and_Representativeness_of_Winners_Finalver_English.pdf
6. List of Candidates in JABALPUR : MADHYA PRADESH Lok Sabha 2024 - MyNeta, https://www.myneta.info/LokSabha2024/index.php?action=show_candidates&constituency_id=230
37. Ashish Dubey, BJP candidate bio : Assets , Total Income, Liabilities, Criminal Cases and other details. - The Hindu, https://www.thehindu.com/elections/candidates/LokSabha2024/ashish-dubey-240/
38. Lok Sabha Election Results 2024 Live - ABP Asmita, https://gujarati.abplive.com/elections/lok-sabha-election/madhya-pradesh-jabalpur-constituency-mp13
39. 8 - CONSTITUENCY DATA - SUMMARY - Election Commission of India, https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/all_files/full-statistical-reports/mp/2023/Constituency_Data_Summery_Report.pdf
40. Madhya Pradesh Election Results 2023, LIVE Updates | BJP crosses halfway as party set to retain State in thumping majority - The Hindu, https://www.thehindu.com/elections/madhya-pradesh-assembly/madhya-pradesh-election-results-december-3-2023-bjp-congress-live-updates/article67597767.ece
41. The Lodhis of North and Central India - Flipbook by Ajay Pratap Singh | FlipHTML5, https://fliphtml5.com/dkpbn/kvzd/The_Lodhis_of_North_and_Central_India/
42. Village Survey Monographs No-6 Jaitpuri, Part VI, Vol-VIII, Madhya Pradesh - Census of India, https://censusindia.gov.in/nada/index.php/catalog/32807/download/35988/22348_1961_JAB.pdf
43. Fake News, Misinformation, and Elections: Social Media Challenges in Indian Politics - ARC

Journals, https://www.arcjournals.org/pdfs/ijps/v10-i2/4.pdf
44. Social Media & Political Behaviour - CSDS |, https://www.csds.in/uploads/custom_files_new/Report-SMPB.pdf
45. Digital Media Misinformation Impact on Voter Behaviour and Election Outcomes - INTERNATIONAL JOURNAL OF LAW MANAGEMENT & HUMANITIES, https://ijlmh.com/wp-content/uploads/Digital-Media-Misinformation-Impact-on-Voter-Behaviour-and-Election-Outcomes.pdf
46. (PDF) From Chaiwala to Chowkidar: Modi's Election Campaigns Online and Offline, https://www.researchgate.net/publication/349334906_From_Chaiwala_to_Chowkidar_Modi's_Election_Campaigns_Online_and_Offline
47. From Chaiwala to Chowkidar: Modi's Election Campaigns Online and Offline, https://www.epw.in/engage/article/chaiwala-chowkidar-analysing-modis-online-and
48. (PDF) Impact of Fake News: An Indian Electoral Perspective - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/373285483_Impact_of_Fake_News_An_Indian_Electoral_Perspective
49. Assessing India's Preparedness: External Interference in Political Processes through Social Media > Air University (AU) > Wild Blue Yonder, https://www.airuniversity.af.edu/Wild-Blue-Yonder/Articles/Article-Display/Article/2275375/assessing-indias-preparedness-external-interference-in-political-processes-thro/
50. Theme 17 - Social Media & Fakes News - Chief Electoral Officer, Delhi, https://ceodelhi.gov.in/PDFFolders/TrgMaterial/Social_Media_fake_news_and_hate_speech.pdf
51. Votes - Election Commission of India, https://www.eci.gov.in/eci-backend/public/api/download?url=LMAhAK6sOPBp%2FNFF0iRfXbEB1EVSLT41NNLRjYNJJP1KivrUxbfqkDatmHy12e%2FzVx8fLfn2ReU7TfrqYobgIiIbojDr07fSor0%2BVk%2FYMDS09xcbwsD6Q7pZFHemZQv5uXsb1pgA548lA9OSgsSPwWdlNsGJVyOT%2F5fphCaGG39UmXsblntj%2BP2lE8v8phOcfTkLCnTR3M6gqm4hXmbNxg%3D%3D
52. Correcting the Democratic Imbalance: The Imperative of Delimitation in India's Post Freeze Era, https://www.journalofpoliticalscience.com/uploads/archives/7-10-35-224.pdf
53. Results of the 2024 Indian general election - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Results_of_the_2024_Indian_general_election
54. 2024 Indian general election in Madhya Pradesh - Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/2024_Indian_general_election_in_Madhya_Pradesh

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 163-166

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

विकासशील देशों में शहरीकरण के रूझानों का विश्लेषण

Vajeer Singh
Assistant Professor in Teaching of Geography
Aakash College of Education, Kalirawan, Hisar.

1. प्रस्तावना :

शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का एक बड़ा भाग ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर शहरी क्षेत्रों में बसने लगता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में निवास करती है और आगामी दशकों में यह अनुपात निरंतर बढ़ने की संभावना है।

विकासशील देशों में शहरीकरण की गति विकसित देशों की तुलना में अधिक तीव्र रही है। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसरों तथा आधुनिक सुविधाओं के विस्तार ने शहरी आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

भारत, चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया, नाइजीरिया और मेक्सिको जैसे देशों में महानगरों का तेजी से विस्तार हुआ है। इन देशों में शहरीकरण आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण संकेतक माना जाता है, किंतु इसके साथ अनेक सामाजिक एवं पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं।

2. शहरीकरण की अवधारणा :

शहरीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। यह केवल जनसंख्या वृद्धि नहीं, बल्कि जीवन–पद्धति, उत्पादन प्रणाली और संसाधनों के उपयोग में परिवर्तन को भी दर्शाता है।

किंग्सले डेविस के अनुसार, "शहरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जनसंख्या का बढ़ता हुआ भाग नगरों में निवास करने लगता है।"

3. विकासशील देशों में शहरीकरण की स्थिति :

वर्तमान समय में विकासशील देशों में शहरीकरण अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2050 तक विश्व की लगभग 68% जनसंख्या शहरों में निवास करेगी।

- **एशिया :**

एशिया विश्व का सबसे तेजी से शहरीकरण होने वाला महाद्वीप है। भारत, चीन और इंडोनेशिया जैसे देशों में औद्योगिक विस्तार और तकनीकी विकास ने शहरी आबादी को बढ़ाया है।

- **अफ्रीका :**

अफ्रीकी देशों में शहरीकरण की दर अत्यधिक तेज है। नाइजीरिया, केन्या और दक्षिण अफ्रीका में बड़े शहरों का विस्तार हो रहा है, लेकिन आधारभूत सुविधाओं की कमी एक बड़ी समस्या है।

- **लैटिन अमेरिका :**

ब्राजील, अर्जेंटीना और मेक्सिको जैसे देशों में शहरीकरण का स्तर अपेक्षाकृत अधिक है। इन देशों में महानगर आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बन चुके हैं।

4. विकासशील देशों में शहरीकरण के प्रमुख कारण :

- औद्योगिक इकाइयों की स्थापना ने रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए, जिससे ग्रामीण जनसंख्या शहरों की ओर आकर्षित हुई।
- शहरी क्षेत्रों में उद्योग, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हैं।
- उच्च शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता शहरीकरण को बढ़ावा देती है।
- सड़कों, रेलमार्गों तथा डिजिटल तकनीकों के विकास ने शहरों को अधिक सुलभ बनाया है।
- वैश्वीकरण के कारण विदेशी निवेश और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई, जिससे शहरी क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हुआ।

5. विकासशील देशों में शहरीकरण के प्रमुख रूझान :

- विकासशील देशों में महानगरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली, मुंबई, शंघाई, साओ पाउलो और लागोस जैसे शहर विशाल महानगरों में परिवर्तित हो चुके हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं।
- सूचना प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, पर्यटन और संचार सेवाओं के विस्तार ने शहरी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया है।
- तेजी से बढ़ती जनसंख्या और आवास की कमी के कारण झुग्गी–बस्तियों का विस्तार हुआ है।
- कई विकासशील देशों में स्मार्ट सिटी परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं, जिनका उद्देश्य आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करना है।

6. भारत में शहरीकरण :

भारत विश्व के सबसे तेजी से शहरीकरण करने वाले देशों में से एक है। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 31 प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती थी।

भारत में शहरीकरण की प्रमुख विशेषताएँ –

- महानगरों का तीव्र विस्तार।
- स्मार्ट सिटी मिशन।
- ग्रामीण–शहरी प्रवासन।
- औद्योगिक गलियारों का विकास।

- सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रों का विस्तार।
- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद प्रमुख शहरी केंद्र हैं।

7. विकासशील देशों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ :

- आवास संकट।
- बेरोजगारी।
- आधारभूत सुविधाओं की कमी।
- पर्यावरण प्रदूषण।
- यातायात समस्या।
- सामाजिक असमानता।
- जल संकट।
- कचरा प्रबंधन।
- ऊर्जा की बढ़ती माँग।
- जलवायु परिवर्तन।

8. सतत् शहरी विकास के उपाय :

- समुचित शहरी नियोजन।
- सार्वजनिक परिवहन का विकास।
- हरित क्षेत्रों का संरक्षण।
- किफायती आवास योजनाएँ।
- जल एवं ऊर्जा संरक्षण।
- स्मार्ट तकनीकों का उपयोग।
- रोजगार सृजन।
- ग्रामीण क्षेत्रों का विकास।
- पर्यावरण संरक्षण नीतियाँ।

9. निष्कर्ष :

विकासशील देशों में शहरीकरण आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इसने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। दूसरी ओर, अनियोजित शहरीकरण ने झुग्गी–बस्तियों, प्रदूषण, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म दिया है।

सतत् विकास के लिए आवश्यक है कि शहरीकरण को सुव्यवस्थित और समावेशी बनाया जाए। सरकारों को ऐसी नीतियाँ अपनानी चाहिए जो आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक न्याय और पर्यावरण संरक्षण को भी सुनिश्चित करें। उचित योजना, आधुनिक तकनीक और जनसहभागिता के माध्यम से विकासशील देशों में संतुलित एवं सतत् शहरीकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है।

10. संदर्भ ग्रंथ सूची :

- सिंह, आर. बी. (2018). नगरीकरण और पर्यावरण. नई दिल्ली : रावत पब्लिकेशन।
- शर्मा, आर. सी. (2019). मानव भूगोल. जयपुर : राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी।
- यादव, एस. पी. (2020). भारत का सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल. नई दिल्ली : यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन।
- डेविस, किंग्सले (1965). Urbanization and Social Change. न्यूयॉर्क।
- भाटिया, एच. एस. (2017). आर्थिक विकास और नियोजन. नई दिल्ली।
- मिश्रा, एस. के. एवं पुरी, वी. के. (2018). भारतीय अर्थव्यवस्था. नई दिल्ली।
- गोसल, जी. एस. (2015). Population Geography. नई दिल्ली।
- United Nations. (2019). World Urbanization Prospects.
- World Bank. (2020). Urban Development Report.
- UN-Habitat. (2022). Cities and Sustainable Development Report.
- Gilbert, A., & Gugler, J. (2016). Cities, Poverty and Development.
- Pacione, M. (2014). Urban Geography: A Global Perspective.

Email ID : vajeer69@gmail.com
Mobile 9992646466

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 167-172

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में यथार्थ का स्वरूप : एक विश्लेषण

सतीश भास्कर

सहायक प्राध्यापक, यू.आई.एल.एस., चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, मोहाली, पंजाब।

अरविंदर कौर चुंबर

सह–प्रोफेसर, देश भगत विश्वविद्यालय, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब।

सार (Abstract)

आधुनिक युग में **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI)** ने यथार्थ की समझ और उसकी प्रस्तुति के तरीकों को गहराई से प्रभावित किया है। डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में यथार्थ केवल बाह्य सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंतर्मन, मानसिक द्वंद्व तथा सामाजिक विघटन का सूक्ष्म विश्लेषण भी है। उनके साहित्य में यथार्थ एक बहुआयामी अवधारणा के रूप में उभरता है, जिसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक स्तर पर संघर्ष दिखाई देता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में यह यथार्थ और अधिक जटिल हो जाता है, जहाँ मानवीय संवेदनाएँ तथा तकनीकी तर्क एक-दूसरे से टकराते हैं। डॉ. अजय शर्मा के उपन्यास इस द्वंद्व को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी प्रगति के बावजूद मानवीय यथार्थ की जटिलता बनी रहती है। इस प्रकार, उनके उपन्यास समकालीन यथार्थ की गहन समझ प्रदान करते हैं।

मुख्य शब्द (Keywords)

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यथार्थवाद, हिंदी उपन्यास, डॉ. अजय शर्मा, सामाजिक यथार्थ, मनोवैज्ञानिक यथार्थ

1. प्रस्तावना :

इक्कीसवीं सदी के आरंभिक दशकों में मानव जीवन जिस तीव्र गति से परिवर्तित हुआ है, उसमें विज्ञान और तकनीक की निर्णायक भूमिका रही है। विशेषतः **कृत्रिम बुद्धिमत्ता**

(Artificial Intelligence - AI) ने न केवल वैज्ञानिक और औद्योगिक क्षेत्रों को प्रभावित किया है, बल्कि साहित्य, कला और संस्कृति के विमर्श को भी नई दिशा प्रदान की है। यथार्थ की अवधारणा, जो पारंपरिक रूप से समाज, व्यक्ति और अनुभव के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित थी, अब तकनीकी हस्तक्षेप के कारण अधिक जटिल और बहुआयामी हो गई है।

हिंदी साहित्य में यथार्थवाद की परंपरा प्रेमचंद से लेकर समकालीन लेखकों तक निरंतर विकसित होती रही है। इसी परंपरा में डॉ. अजय शर्मा का लेखन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके उपन्यासों में यथार्थ केवल सामाजिक घटनाओं का प्रत्यक्ष चित्रण नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के भीतर चल रहे मानसिक, नैतिक तथा अस्तित्वगत संघर्ष का सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

वर्तमान शोध-पत्र का उद्देश्य यह समझना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में यथार्थ की अवधारणा किस प्रकार परिवर्तित हो रही है तथा यह परिवर्तन डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में किस रूप में अभिव्यक्त होता है।

2. साहित्य समीक्षा (Review of Literature)

उपलब्ध साहित्य के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यथार्थ की अवधारणा तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव पर विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए हैं, जो इस शोध के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं।

हिंदी साहित्य के संदर्भ में **नामवर सिंह**, **रामचंद्र वर्मा** तथा **हजारीप्रसाद द्विवेदी** जैसे आलोचकों ने यथार्थवाद को सामाजिक संदर्भों, ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा मानवीय अनुभवों के साथ जोड़कर देखा है। वहीं **विद्यानिवास मिश्र** तथा **रमेशचंद्र गुप्ता** ने हिंदी उपन्यास के विकास में सामाजिक संरचना और परिवर्तित मूल्यों की भूमिका को रेखांकित किया है।

डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों पर केंद्रित अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि उनका लेखन मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक यथार्थ का सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर **स्टुअर्ट रसेल**, **पीटर नॉरविग**, **निक बोस्ट्रॉम** तथा **लुसियानो फ्लोरिडी** जैसे विचारकों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दार्शनिक, नैतिक तथा सामाजिक प्रभावों का विश्लेषण करते हुए यह स्थापित किया है कि तकनीक मानव यथार्थ की संरचना का पुनर्गठन कर रही है।

इसी प्रकार **शैरी टर्कल** तथा **मैनुअल कैस्टेल्स** ने डिजिटल समाज में मानवीय संबंधों और संचार की बदलती प्रकृति का विश्लेषण किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि तकनीकी युग में यथार्थ अधिक जटिल तथा बहुस्तरीय हो गया है।

इस प्रकार, पूर्ववर्ती साहित्य यह संकेत देता है कि यथार्थ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतर्संबंधों को समझने के लिए साहित्यिक तथा तकनीकी दोनों दृष्टियों का समन्वय आवश्यक है, और यही इस शोध के लिए आधारभूमि का कार्य करता है।

3. शोध का उद्देश्य :

इस शोध का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है–

1. कृत्रिम बुद्धिमत्ता के प्रभाव में यथार्थ की बदलती अवधारणा का विश्लेषण करना।
2. डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं नैतिक यथार्थ की पहचान करना।
3. तकनीकी युग में मानवीय संवेदनाओं तथा यथार्थ के अंतर्संबंधों का अध्ययन करना।
4. यह मूल्यांकन करना कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में साहित्य किस प्रकार यथार्थ को पुनर्परिभाषित करता है।

4. शोध पद्धति (Research Methodology)

इस शोध का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिप्रेक्ष्य में डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में यथार्थ के स्वरूप का विश्लेषण करना है। इसके लिए गुणात्मक (Qualitative) शोध पद्धति अपनाई गई है। प्राथमिक स्रोत के रूप में डॉ. अजय शर्मा के चयनित उपन्यासों तथा द्वितीयक स्रोतों के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यथार्थवाद और आधुनिक साहित्य से संबंधित पुस्तकों, शोध-पत्रों एवं आलोचनात्मक सामग्री का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धतियों के माध्यम से उपन्यासों की विषयवस्तु, पात्र, संवाद तथा सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों का परीक्षण किया गया है। साथ ही, तुलनात्मक पद्धति द्वारा पारंपरिक यथार्थ और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित आधुनिक यथार्थ के बीच समानताओं एवं अंतरों का विश्लेषण किया गया है। इस आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में यथार्थ का स्वरूप अधिक व्यापक, बहुआयामी और परिवर्तित रूप में उभरता है।

5. कृत्रिम बुद्धिमत्ता और यथार्थ का परिवर्तित स्वरूप :

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने यथार्थ की पारंपरिक अवधारणा को बदलते हुए उसे अधिक जटिल और बहुआयामी बना दिया है। जहाँ पहले यथार्थ प्रत्यक्ष अनुभव, मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक संबंधों पर आधारित था, वहीं आज डेटा, एल्गोरिद्म और डिजिटल तकनीकें भी उसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

वर्चुअल रियलिटी और सोशल मीडिया के प्रभाव से वास्तविक और आभासी संसार के बीच की सीमाएँ धुंधली हुई हैं, जिससे व्यक्ति की पहचान और अनुभव का नया डिजिटल यथार्थ निर्मित हो रहा है। साथ ही, शिक्षा, रोजगार और वित्त जैसे क्षेत्रों में AI आधारित निर्णय-प्रणालियाँ यथार्थ को डेटा-केंद्रित बना रही हैं।

तकनीकी निर्भरता के कारण मानवीय संवेदनाओं और प्रत्यक्ष अनुभवों में कमी आई है, जिससे संवाद अधिक यांत्रिक और औपचारिक होता जा रहा है। परिणामस्वरूप, यथार्थ अब केवल मानवीय अनुभव तक सीमित न रहकर तकनीक, अनुभव और सामाजिक संरचना के संयुक्त प्रभाव से निर्मित एक गतिशील एवं बहुआयामी अवधारणा बन गया है।

6. डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ :

डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में सामाजिक यथार्थ सजीव, प्रामाणिक और बहुआयामी रूप में अभिव्यक्त हुआ है। वे समाज में बदलते मानवीय संबंधों, मूल्य-संकट, शहरी जीवन, पारिवारिक विघटन तथा आर्थिक असमानता का यथार्थपूर्ण चित्रण करते हैं। उनके अनुसार आधुनिक समाज में व्यक्तिवाद और भौतिकता के कारण आत्मीयता, संवाद और नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में यह यथार्थ और अधिक जटिल हो जाता है। डिजिटल तकनीकों ने संवाद और संबंधों की प्रकृति को बदल दिया है, जिससे व्यक्ति जुड़े रहने के बावजूद भावनात्मक रूप से अकेला होता जा रहा है। इस प्रकार, उनके उपन्यास आधुनिक समाज की चुनौतियों और तकनीकी परिवर्तन से उत्पन्न सामाजिक यथार्थ का प्रभावी चित्रण करते हैं।

7. मनोवैज्ञानिक यथार्थ एवं नैतिक यथार्थ का तकनीकी द्वंद्व :

डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में मनोवैज्ञानिक यथार्थ प्रमुख रूप से उभरता है। उनके पात्र अकेलेपन, आत्मसंघर्ष, पहचान के संकट और अस्तित्व संबंधी प्रश्नों से जूझते दिखाई देते हैं। आधुनिक जीवन की प्रतिस्पर्धा व्यक्ति को मानसिक रूप से विखंडित करती है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में यह संकट और गहरा हो जाता है, क्योंकि मनुष्य स्वयं की तुलना मशीनों से करने लगता है। साथ ही, तकनीकी विकास नैतिक प्रश्न भी खड़े करता है कि क्या मशीनें मानवीय निर्णयों और संवेदनाओं का स्थान ले सकती हैं। डॉ. शर्मा के अनुसार तकनीकी प्रगति के बीच मानवीय मूल्यों की रक्षा ही सबसे बड़ी चुनौती है।

8. डेटा विश्लेषण एवं निष्कर्ष (Data Analysis and Findings)

चयनित उपन्यासों के गहन पाठ-विश्लेषण से यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है कि डॉ. अजय शर्मा के साहित्य में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक यथार्थ एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उनके उपन्यासों में व्यक्ति, समाज और परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों के बीच स्थापित संबंधों का बहुआयामी एवं संवेदनशील चित्रण मिलता है। अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के बढ़ते प्रभाव ने इन यथार्थपरक आयामों को और अधिक जटिल, गतिशील तथा बहुआयामी बना दिया है। तकनीकी हस्तक्षेप के कारण मानवीय जीवन, सामाजिक संबंधों, निर्णय-प्रक्रियाओं, नैतिक मूल्यों तथा व्यक्तिगत पहचान में उत्पन्न हो रहे परिवर्तनों को लेखक ने यथार्थवादी दृष्टि से प्रस्तुत किया है।

विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि डॉ. अजय शर्मा के उपन्यास केवल समकालीन समाज की बाह्य परिस्थितियों का चित्रण नहीं करते, बल्कि वे तकनीकी युग में विकसित हो रही मानवीय चेतना, आंतरिक द्वंद्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक संकट तथा बदलते जीवन-मूल्यों का भी गंभीर और विचारोत्तेजक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार उनका साहित्य पारंपरिक यथार्थवाद और समकालीन तकनीकी यथार्थ के मध्य एक प्रभावी सेतु का कार्य करता है तथा यह संकेत देता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानवीय संवेदनाओं, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की प्रासंगिकता पूर्ववत बनी हुई है।

Top of Form

Bottom of Form

9. चर्चा (Discussion)

अध्ययन से यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित होता है कि डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में यथार्थ एक बहुआयामी, गतिशील तथा निरंतर परिवर्तित होने वाली अवधारणा के रूप में उपस्थित है। उनके कथा-साहित्य में सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक तथा नैतिक यथार्थ परस्पर गहरे रूप से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। उनके उपन्यासों का यथार्थ केवल बाह्य सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण नहीं करता, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक अनुभवों, मानसिक द्वंद्वों, भावनात्मक संघर्षों तथा अस्तित्वगत प्रश्नों को भी समान महत्त्व देता है। इस प्रकार उनका साहित्य समकालीन समाज की जटिलताओं और मानवीय जीवन की बदलती परिस्थितियों का व्यापक एवं संवेदनशील दस्तावेज़ बनकर सामने आता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के तीव्र विकास ने आधुनिक जीवन को अनेक स्तरों पर अधिक सुविधाजनक, तीव्र और तकनीक-आधारित बनाया है। शिक्षा, संचार, स्वास्थ्य, प्रशासन तथा दैनिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में AI ने नई संभावनाओं का विस्तार

किया है। किंतु इसके साथ ही मानवीय संबंधों, संवेदनशीलता, नैतिक मूल्यों, निजता (Privacy), आत्मीयता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व के समक्ष नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। तकनीकी प्रगति के कारण मनुष्य के जीवन में सुविधा तो बढ़ी है, परंतु अनेक बार भावनात्मक दूरी, सामाजिक अलगाव तथा मानवीय संवाद की कमी भी दिखाई देती है।

डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों के पात्र इसी परिवर्तित तकनीकी परिवेश में जीवन व्यतीत करते हुए अकेलेपन, पहचान-संकट, आत्मसंघर्ष, नैतिक दुविधाओं तथा सामाजिक असंतुलन जैसी समस्याओं का सामना करते हैं। वे आधुनिक जीवन की उपलब्धियों और उससे उत्पन्न मानसिक दबावों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उनके पात्रों के अनुभव यह संकेत देते हैं कि तकनीक मनुष्य के जीवन को सरल बना सकती है, किंतु वह मानवीय संवेदनाओं, सहानुभूति, नैतिक चेतना और आत्मीय संबंधों का पूर्ण विकल्प नहीं बन सकती। इसलिए उनके उपन्यासों में यथार्थ केवल तकनीकी परिवर्तन का चित्रण नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन के मानवीय प्रभावों का गंभीर विश्लेषण भी है।

10. संदर्भ (References)

I. शर्मा, अजय. (2018). **समकालीन हिंदी उपन्यास और यथार्थ**. नई दिल्ली: वाणी प्रकाशन।

II. शर्मा, अजय. (2020). **मरु-मन**. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।

III. सिंह, नामवर. (2012). **आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ**. नई दिल्ली: लोकभारती प्रकाशन।

IV. वर्मा, रामचंद्र. (2015). **हिंदी साहित्य का इतिहास**. इलाहाबाद: लोकभारती प्रकाशन।

V. द्विवेदी, हजारीप्रसाद. (2011). **साहित्य और समाज**. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन।

VI. कुमार, विनय. (2019). **तकनीक और समाज**. नई दिल्ली: ज्ञानपीठ प्रकाशन।

VII. रसेल, स्टुअर्ट एवं नॉरविग, पीटर. (2021). **कृत्रिम बुद्धिमत्ता: एक आधुनिक दृष्टिकोण** (चतुर्थ संस्करण). पियरसन।

VIII. बोस्ट्रॉम, निक. (2014). **सुपरइंटेलिजेंस: पथ, खतरे और रणनीतियाँ**. ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस।

IX. हरारी, युवाल नोआह. (2017). **होमो डियस: भविष्य का संक्षिप्त इतिहास**. हार्पर कॉलिन्स।

X. फ्लोरिडी, लुसियानो. (2014). **चौथी क्रांति : इन्फोस्फीयर मानव यथार्थ को कैसे**

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 173-178

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

प्रेत और छाया उपन्यासो में वर्णित पुरूष मनोवृत्ति का यथार्थ चित्रण

चंचल जाट, शोधार्थी, हिंदी विभाग,
डॉ. मलय पानेरी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,
हिंदी विभाग, जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय, उदयपुर।

शोध सार :

हिंदी के प्रसिद्ध मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में से एक उपन्यास इलाचंद्र जोशी का प्रेत और छाया उपन्यास माना जाता है। इस उपन्यास में मुख्य पात्र पारसनाथ के माध्यम से मनुष्य मात्र के अवचेतन मन में छुपे हुए मूल भावों– प्रेम, ईष्या, काम–वासना, कुंठा और हीनता के साथ घृणा और भय आदि का चित्रण किया है। उपन्यास में बताया गया है कि पारसनाथ एक वेश्या मां का पुत्र होता है। यह बात उसके मन में बचपन से ही अचेतन मन में बस जाती है। इसका चित्रण उपन्यास में इस तरह हुआ है– पारसनाथ का शराबी पिता अपनी पत्नी के उज्ज्वल चरित्र से ईर्ष्यावश एक दिन पारसनाथ से कह देता है कि उसकी माँ के शिवशंकर नाम के एक वैद्य से नाजायज सम्बन्ध थे और पारसनाथ उसी वैद्य का नाजायज बेटा है। अपनी माँ की चरित्रहीनता की बात सुनकर पारसनाथ के मन में गाँठ पड़ जाती है। इसलिए वह जीवनभर घृणा और हीनता के अपराधबोध से ग्रसित होकर जीवन जीता है। इसका परिणाम यह होता है कि वह अपने जीवन में आने वाली हर स्त्री के प्रति घृणा करने लगता है और उनसे दूर भागता रहता है। इतना ही नहीं, पारसनाथ प्रेम से जुड़े पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों में भी स्वयं को एक अन्तर्द्वन्द्व में फंसा हुआ महसूस करता है। इसी अन्तर्द्वन्द्व से उपजे हालात और परिस्थिति का चित्रण उपन्यास में अत्यंत दिखाया गया है।

बीज शब्द – प्रेम, मनोवृति, भय, अनुभूति, घृणा, नैतिकता, अपराधबोध, हीनभावना, कल्पना, यथार्थ आदि।

मूल शोध आलेख :

हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण विद्या में से उपन्यास एक पसंदीदा विद्या मानी जाती है और इन उपन्यासों में भी एक विशेष प्रकार के मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास माने जाते हैं। यह उपन्यास प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक फ्राइड और युंग के सिद्धांत पर आधारित हैं। हिंदी में मनोविश्लेषण पर आधारित उपन्यास लिखने वालों में मुख्य नाम अज्ञेय, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्रनाथ अश्क और देवराज जैसे उपन्यासकारों को शामिल किया जाता है। इनमें इलाचंद्र जोशी के द्वारा लिखे गए मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास बेहतरीन उपन्यास माने जाते हैं। इन्होंने कई

उपन्यासों का सृजन किया है, इनमें प्रमुख संन्यासी, प्रेत और छाया, निर्वासित, जिप्सी और जहाज का पंछी माने जाते हैं।

इन उपन्यासों में समाहित आंतरिक और बाहरी जीवन के बारे में बलभद्र तिवारी अपनी पुस्तक 'इलाचंद्र जोशी के उपन्यास' में लिखते हैं, 'जोशी जी और उल्लिखित डॉ उपन्यासकारों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जोशी जी एक अधिक विषद दृष्टिकोण लेकर चलते हैं। जैसे प्रेमचन्द में बाह्य जीवन के चित्रण की प्रधानता कही जा सकती है, उसी प्रकार जैनेन्द्र और अज्ञेय की कृतियों में अभ्यंतर जीवन की प्रधानता का उल्लेख किया जाता है। जोशी जी अंतर और बाह्य दोनों को समान रूप से अपनाते हैं और एक के बिना दूसरे को एकांगी समझते हैं।'[1] इलाचंद्र जोशी के इतने सारे मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में से एक प्रसिद्ध उपन्यास प्रेत और छाया माना जाता है। यह उपन्यास एक रहस्यमय और रोमांचक उपन्यास है, जो पाठकों को अंत तक बांधे रखता है। इस उपन्यास में डर, रोमांस और आश्चर्य का समिश्रण हुआ है, जो इसे एक विशेष उपन्यास बनाता है। इस उपन्यास में लेखक जोशी ने अपनी भावनात्मक अनुभूतियों को पूरी सजगता के साथ व्यक्त किया है, इस वजह से यह उपन्यास एक सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी बात को स्वयं इलाचन्द्र जोशी ने अपने निबंध संग्रह 'विवेचना' में लिखा है 'मेरे सभी उपन्यासों का प्रधान उद्देश्य व्यक्ति के अहंभाव की एकांतिकता पर निर्भय प्रहार करने का रहा है।'[2] इसके पुरुष पात्रों में से एक प्रमुख पात्र अर्थात् उपन्यास का नायक पारसनाथ है, जो एक जटिल और रहस्यमय पात्र होने के साथ–साथ अपने अतीत के अनुभवों से भी व्यापक रूप से प्रभावित है। पारसनाथ एक अतिसंवेदनशील और बहुत ही भावनात्मक व्यक्ति है, जो अपने आसपास के लोगों के प्रति आकर्षित होता है।

इसके अलावा वह अपने जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों का सामना करता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सतत् संघर्ष करता रहता है।

इस उपन्यास में अपने अन्य उपन्यासों की तरह ही उपन्यासकार इलाचंद्र जोशी ने मानव मन के भीतर बसे हुए प्रेम और घृणा जैसे मनोभावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। इस उपन्यास के प्रमुख पुरुष पात्र पारसनाथ के माध्यम से पुरुषवादी मानसिकता के कटु यथार्थ को उभारा गया है। इस मानसिकता से ग्रस्त पुरुष के मनोमस्तिष्क में हमेशा ही कई तरह के विचार मन की गहराइयों में बसकर उथल–पुथल मचाए रहते हैं। इस बात की पुष्टि उस समय होती है, जब पारसनाथ प्रोफेसर साहब की ओर देखते हुए बोलते हैं, 'आज आपने अपने जीवन के इतिहास का जो अधूरा अध्याय सुनाया, उसने मेरे हृदय में एक विचित्र अशांति उत्पन्न कर दी है, एक निराले भय की भावना जैसे मेरी छाती पर चढ़ बैठी है।'[3] पारसनाथ के इस कथन से प्रकट होता है कि वह किसी भी व्यक्ति के भूतकाल को जानकर अपनी मानसिक स्थिति खो बैठता है और फिर दिन–रात एक पागल की भांति भयभीत होकर इधर–उधर अपनी मृगतृष्णा को शान्त करने के लिए दौड़ा–दौड़ा मारा फिरता है।

पारसनाथ की इस स्थिति का यथार्थ चित्रण करते हुए प्रोफेसर साहब जैसे सौम्य पात्र तक कह उठते हैं, 'तुम समझ ही कैसे सकते हो, जबकि तुम्हें उन परिस्थितियों का कोई अनुभव नहीं है, जिनसे होकर मैं कई वर्षों से गुजर रहा हूँ।'[4] यह बात सच भी है कि कोई भी व्यक्ति स्वयं किसी हालत को अनुभव किए बिना उसे

पूरी तरह कभी भी समझ नहीं पाता है। फिर भी पारसनाथ जैसा पात्र अकस्मात दुनिया के सामने बदलता हुआ व्यवहार करता है। तभी तो वह व्यक्ति कभी किसी के प्रति प्रेम भाव से भर उठता है। तो कभी उसी व्यक्ति के प्रति घोर घृणा से भर जाता है। उसके किसी भी समय और किसी भी परिस्थिति में अचानक विचार बदल जाते हैं। लेकिन इस सबके बारे में स्वयं उस व्यक्ति को कुछ भी कभी मालूम नहीं रहता है। न ही इसकी वजह क्या है? और परिणाम क्या निकलने वाला है। इस बारे में वह कितनी भी कोशिश करने के बाद भी इसके मूल कारणों को नहीं जान पाता है। बस, किसी को भी पता नहीं चलता है कि कब अचानक उस व्यक्ति के मन में विचारों का तूफान मच उठता है और उसके सारे मनोभाव मस्तिष्क में भयंकर उथल–पुथल मचा देते हैं। इस बात को प्रकट करती हुई एक घटना का उपन्यास में चित्रण इस प्रकार हुआ है। अपनी वीभत्स प्रेम–लीलाओं की कढ़ी में वह सबसे पहले दार्जलिंग में कांची नाम की एक पहाड़ी लड़की को प्रेम के नाम पर छलकर वहाँ से भाग खड़ा होता है।

'प्रेत और छाया' उपन्यास में प्रमुख पात्र पारसनाथ है जो अपने परिवार के साथ तिब्बत के कालिम्पांग नगर में रहता था। उसके पिता जी की एक ऊन की फैक्ट्री थी। पारसनाथ का पिता बैजनाथ जो कि एक शराबी था वह एक दिन पारसनाथ से कहता है कि उसकी मां एक चरित्रहीन औरत थी उसका शिवशंकर नाम के एक वैध से नाजायज सबंध थे। पारसनाथ यह सब सुनकर वह बहुत दुःखी होता है और वह उसी दिन से पूरी नारी–जाति से नफरत करने लगता है। फिर वह दार्जिलिंग आ जाता है। वहां लड़की पर वह सबसे पहले कांची नाम की पहाडी लडकी से प्रेम का झूठा नाटक करता है और फिर वहां से भाग जाता है।

पारसनाथ के मन–मस्तिष्क में उतरकर देखा जाए, तो पता चलता है कि वह कभी किसी के प्रेम के लिए लालायित रहता है, तो कभी वह अपने भावी जीवन के कई सारे सुनहरे सपने देखता है। इस स्थिति का सजीव वर्णन करते हुए उपन्यास में खुद लेखक ने लिखा भी है– 'कुछ भी हो, वह लड़की सौ जानों से उस पर मर–मिटी। घनिष्ठता बढ़ते–बढ़ते यहां तक बढ़ी कि दोनों के बीच शारीरिक प्रेम संबंध स्थापित हो गया। पारसनाथ कभी उसे रेबेका कहकर पुकारता, कभी 'कांची' कहता और कभी 'कांचनी'।'[5] इस कथन से पता चलता है कि पारसनाथ का एक स्त्री के प्रति कई अलग–अलग रूपों में आश्चर्यचकित करने वाला व्यवहार देखने को मिलता है।

फिर अचानक पारसनाथ के मन में उस प्रेम की जगह घृणा जैसे कई विपरीत भाव जाग उठते हैं और वह अपने जीवन से भागता हुआ किसी कल्पना लोक में विचार करने लग जाता है अर्थात् अपने जीवन के मूल यथार्थ को पूर्ण रूप से भूलकर अपना रास्ता ही भटक जाता है।

पारसनाथ दार्जिलिग से भागकर कलकत्ता आ जाता है और वहां चित्रकला सिखता है। फिर पारसनाथ की जिंदगी में मंजरी नाम की एक गरीब लड़की आती है उससे मुलाकात एक होटल में होती है। मंजरी पारसनाथ से सच्चा प्रेम करती है, परन्तु पारसनाथ उसे छोडकर भाग जाता है। पारसनाथ के इसी असमंजसपूर्ण हालात का चित्रण उपन्यास में इस प्रकार से हुआ है 'रास्ते भर वह नंदिनी के आज के प्रत्येक व्यवहार के संबंध में सोचता रहा और सोच सोच कर कभी विस्मित, कभी विभ्रांत, कभी पुलकित और कभी भीत होता रहा।'[6] इस

प्रकार पता चलता है कि वह नंदिनी से मिलने के बाद नैतिक और अनैतिक कार्यों में कुछ भी भेद तक नहीं कर पाता है और वह समाज विरोधी कई प्रकार के अमर्यादित और पतनोन्मुख कार्यों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। तब पारसनाथ की विकृत मनोवृति को पहचानने के बाद नंदिनी उससे साफ शब्दों में कहती है– 'आज मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि तुम सचमुच नरक के कीड़े हो। उस नरक के भीतर कुलबुलाते रहने में ही तुम्हें सुख मिल सकता है। घोर विकृत और गलित सुख।'[7]

पारसनाथ अपने जीवन में आने वाली प्रत्येक स्त्री चाहे वह कांची हो, मंजरी हो नंदिनी हो या हीरा हो। इन सब के साथ अपना प्रेम संबंध स्थापित करता है और फिर कुछ समय के पश्चात ही वह इन संबंधों से पूर्ण रूप से अपना नाता तोड़कर भागता हुआ दिखाई देता है। इस बात पर पारसनाथ की मंजरी से हुई मुलाकात के वक्त हो जाती है। जब उसकी और पारसनाथ की मुलाकात भी एक होटल में ही होती है। पारसनाथ हमदर्दी का दिखावा करके उससे नजदीकी बढ़ाता है। मंजरी की माँ के देहांत के बाद वह और पारसनाथ एक दम्पति की तरह साथ रहने लगते हैं। उसको यह बात बिल्कुल भी मालूम नहीं होती है कि प्रेम परीक्षा में खरा उतरना सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वह हर बार एक कायर की तरह छल–प्रपंच करके भागता हुआ निकल जाता है।

पारसनाथ स्वयं अपने बारे में बताते हुए ठाकुर से कहता है, 'आप भुजौरिया जी के चाहे कितने ही मित्र क्यों न हो, पर मुझे आप अपने जाल में नहीं फाँस सकते आप सी.आई. डी. के कैसे ही घातक कर्मचारी क्यों न हो? पर आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योकि मैं भी बड़े–बड़े धूर्तों के साथ रह चूका हूँ।'[8]

पारसनाथ नंदिनी नाम की लड़की के साथ प्रेम का नाटक करता है और उसे लखनऊ लेकर भाग जाता है। नंदिनी पंडित छगनलाल भुजौरिया की पत्नी है। भुजौरिया जो कि गरीब लोगों से पेंटिग्स कम पैसो में खरीदता है और अमीर लोगों की वह ऊंचे दामों में बेच देता है। भुजौरिया के कहने पर पारसनाथ उसकी पत्नी नंदिनी को चित्रकला सिखाने उसके घर पर जाता था। वहीं पर वह एक–दूसरे को पसंद करने लगते है और वह पारसनाथ के साथ भाग जाती है। लखनऊ पहुंचने पर पारसनाथ को पता चलता है कि नंदिनी भुजौरिया से विवाह करने से पहले एक तवायफ थी। पारसनाथ के मन में अपनी मां की चरित्रहीनता को लेकर पहले ही नारी–जाति के प्रति क्षोभ था। उस पर नंदिनी के एक तवायफ होने की बात सुनकर वह बौखला जाता है, उसके मन में यह बात चट्टान की तरह जम जाती है कि नारी चरित्रवान हो ही नहीं सकती। इसी तरह वह नंदिनी की बहन हीरा को धोखा देकर ले जाता है तथा वह नौकरी के लिए पैसों की आवश्यकता बताकर हीरा के सारे जेवर गहने तथा रूपये लेकर भाग जाता है।

पारसनाथ जब हीरा को छोड़कर भागता है तब रेलवे स्टेशन पर उसकी मुलाकात चन्द्र बहादुर से होती है जो उसके घर का पुराना नौकर है। चन्द्रबहादुर पारसनाथ को उसके बिमार पिता को लेकर जाता है और उसके पिता पारसनाथ से कहते है कि उसकी मां चरित्रहीन नहीं थी वह तो सती–साध्वी नारी थी। यह सच जानने के बाद पारसनाथ की मनोवृत्ति बदल जाती है और वह हीरा को अपने घर लाता है और उससे विवाह कर लेता है।

विवाह से कतराना एक प्रकार की मनोविकृत्ति है जिसे अंग्रेजी में मेंरिज फोबिया कहा जाता है। पारसनाथ के साथ भी यही होता है–

''विवाह शब्द सुनते ही पारसनाथ का मुंह अत्यंत गंभीर हो आया, यहाँ तक कि उस पर एक हल्की सी कालिमा पुत गई। पता नहीं क्यों यह शब्द वर्षों से सबके अन्तर्मन के लिए एक हौवा बना हुआ था, इसलिए जब आज मंजरी ने अचानक उसका उल्लेख किया, तो भीतर ही भीतर उसका खुन सूखने सा लगा।'[9]

इलाचन्द्र जोशी ने मानव–मन के आन्तरिक स्तरों में अन्तर्निहित वासनाओं को शील वैचिच्त्रय का मूल आधार मानकर उनका विश्लेषण किया है। उन्होने दलितों और उपेक्षितों के प्रति खुलकर सहानुभूति दिखायी है। इलाचन्द्र जोशी ने अन्तर्जीवन की गुत्थियों और व्यक्ति के अवचेतन में निहित रहस्यों के उद्घाटन मात्र से सामाजिक विकास को संभव न मानकर मार्क्स के समता–सिद्धांत को भी महत्व दिया है।

इलाचन्द्र जोशी व्यक्ति को समाज का एक अभिन्न अंग के रूप में देखते है क्योंकि समाज व्यक्तियों से ही बनता है। इसलिए व्यक्ति के अहम और कुठाओं के निवारण से एक प्रगतिशील समाज का उद्देश्य लेकर चले थे। इन्होने फ्रांयड, युंग, एडलर के सैद्धान्तिक मान्यताओं का अध्ययन किया। इलाचन्द्र जोशी ने समाज के सभी वर्गो से पात्रों का चुनाव किया है तथा पात्रों की चारित्रिक दुर्बलताओं का निष्पक्ष चित्रण किया है।

'प्रेत और छाया' उपन्यास में पुरुष मनोवृत्तियों का चित्रण पारसनाथ के आंतरिक संघर्षों और भावनाओं के माध्यम से भी देखने को मिलता है। इन मनोवृत्तियों में प्रेम संबंध और आकर्षण सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति के मन में डर और अनिश्चितता की भावना भी विद्यमान होती है, जो उनके निर्णयों और कार्यों को बहुत हद तक प्रभावित करती है। इसके अलावा वह व्यक्ति अपने अतीत के कार्यों के लिए हमेशा ही एक अपराधबोध और पश्चाताप का भाव महसूस करता हुआ घुटन युक्त जीवन व्यतीत करता है।

निष्कर्ष :

इलाचंद्र जोशी के प्रेत और छाया उपन्यास में मानव मन के भीतर बसे हुए भय और कुंठा के साथ अपराधबोध का चित्रण हुआ है। उपन्यास में बताया गया है कि मानव मन के भीतर बैठे हुए यह विविध मनोभाव ही व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं और इनके आधार पर ही व्यक्ति के घर, परिवार और समाज के साथ जुड़े हुए सारे रिश्ते–नाते जीवन तय होते हैं। साथ ही पता चलता है कि मानव के इन मनोविकारों का दमन करने के बजाय परिष्कार करके किसी नवसृजन में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसलिए हर एक समस्या का एकमात्र उपाय आत्मविश्लेषण ही माना गया है। इस बारे में इस उपन्यास में लिखा भी गया है, 'नरक की जमीन पर ही स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। नरक से घबराकर भाग निकलने से ही अगर कोई यह समझे कि वह नारकीय भावनाओं से छुट्टी पर जावेगा। तो इससे बड़ी भूल जीवन में दूसरी नहीं हो सकती। जो स्वर्ग नरक की यथार्थता पर स्थापित है, वह झूठा है, वह आत्मकामियों के संकीर्ण मन की मरीचिका है। नरक ज्वलंत यथार्थ है। जो व्यक्ति इस यथार्थ को यथार्थवादी उपायों द्वारा ही स्वर्ग का रूप देने में समर्थ होगा, केवल वही कल्याण को उत्पन्न कर सकता है।'[10]

सन्दर्भ :

1. बलभद्र तिवारी, इलाचन्द्र जोशी के उपन्यास, रणजीत प्रिंटर्स, दिल्ली, 1958, पृष्ठ संख्या–178
2. शिव बहादुर सिंह भदौरिया, हिंदी उपन्यास–सृजन और प्रक्रिया, शैलजा प्रकाशन, कानपुर, 1981, पृष्ठ संख्या–168
3. इलाचंद्र जोशी, प्रेत और छाया, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 2018, पृष्ठ संख्या–19
4. वही, पृष्ठ संख्या–16
5. वही, पृष्ठ संख्या–33
6. वही, पृष्ठ संख्या–67
7. इलाचंद्र जोशी, प्रेत और छाया (तीसरा संस्करण), पृष्ठ संख्या–302
8. डॉ. सुजाता, हिंदी उपन्यासों के असामान्य चरित्र, साहित्य प्रकाशन, दिल्ली, 1991, पृष्ठ संख्या–266
9. इलाचंद्र जोशी, प्रेत और छाया, तृतीय संस्करण, पृ. 176
10. इलाचंद्र जोशी, प्रेत और छाया (तीसरा संस्करण), पृष्ठ संख्या–166

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 179-186

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Colonialism : Space, Violence and a new Geographic Conception of India

Asha Yadav

PhD Scholar, Dept. of History, University of Delhi, New Delhi, 110007.

Durgesh Kumar

PhD Scholar, Dept. of History, University of Delhi, New Delhi, 110007.

Introduction :

Mapping is the requirement of all modern state system. It does not only help to determine the topography under its control but also knowing its inhabitants intimately. Mapping is a Foucault's "Panopticon"[1] to keep the whole citizenry under state's surveillance. The need for maintaining oversight over its people has been felt more since colonial period , when both revenue matters and security issues kept state machinery on toe to exploit its colonies as long as system could continue. Today it is increasingly authoritarian states which in the name of nationalism, are trying to intensify surveillance further. It also has to do with capitalist interests, who seek more data regarding a citizen. It is being done to ensure targeted advertisement and thus higher returns like US elections example,[2] in tandem with state.

Public spaces are where interaction at larger scale occurs among people. Every authority seeks to change the mood of it according to its view. The creation of favourable dialogue ensures the longevity of that regime. Moreover, to achieve such ends, the state tries to erase any opposition to its voice, thus creating hegemony of its thought. Erasing public memory, maligning the past regime, and offering proper interpretations of past events are a few ways in which any government entrenches its own position. Also, any outright opposition by people is crushed, both overtly, through violence, and subtly, through dominant linguistics.

[1] Panopticon refers to a modern prison open from all sides and hence increased surveillance is possible. Several day to day buildings like malls, schools, etc. too adopt this principles

[2] https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election

How imperial authorities sought to inflict violence on culture of conquered people ? How the pre-existing spaces ruined ?How maps played an essential role in keeping British rule secure and what determined choices of space in them? How did the desire to control subcontinent in its entirety instead led to conception of "Indian nationalism"?

Space and violence in Colonial period :

Claude Nicolet has argued that state tries to understand through maps-the topography, its natives and their interaction per se - which it seeks to occupy or dominate.[3] Moreover, Bayly argues that ability and resources which Britishers were able to collect such as information and accuracy in that distinguishes British India as an imperial state.[4]

These maps gave rise to "'Imagined community' inherited through 'colonial imaginings' of coherent geographical entities which supposedly predate the colonial era".[5] This same territorial conception of India was latter successfully appropriated by nationalists to show masses the dream of 'self-rule'. While British imperialism had drawn lines on sheet to legitimize their claim over territories, this same bounded geographic construct was mobilized by nationalists to defeat the empire.

Thus, maps play not only geographical role, but also fulfil political imperatives of state. The various modern institutions in cartography of polities - State, Empire, Nations, colony- all are constructed culturally and epistemologically in opposition to each other. They are not naturally existing but are "cultural artifacts" been built among themselves in comparison to others, thus belonging to "geography of mind as well as geography of power".[6]

If Maps help to construct such "cultural artifacts", they also play role of propaganda, showing what cartographer seeks to demonstrate to audience seeing the map. Thus, often what is regarded by cartographer as non-desirable is omitted from maps. Intentional ignorance is what Ana Stoler calls "process of ruination" [7]. These ruins formed through intended actions by authorities and instead of being considered living spaces which they were, they were referred to as 'pre-colonial legacies', 'urban decay', etc. Even the unquestioned power of prevailing authority leads to ignorance of many spaces which state does not tend to favour. These spaces, devoid of any state support and facilities over time are seen as ruins, thus causing violence in most subtle ways possible.

---

[3] Matthew H. Edney, Mapping an Empire: The Geographical Construction of British India, 1765–1843 (Chicago: University of Chicago Press, 1997).

[4] Matthew H. Edney, "The Irony of Imperial Mapping," in *The Imperial Map: Cartography and the Mastery of Empire, ed. James R. Akerman (Chicago: University of Chicago Press, 2009), 11–45.*

[5] Ibid.

[6] Edney, *"Irony of Imperial Mapping".*

[7] Ann Laura Stoler, ed., *Imperial Debris: On Ruins and Ruination* (Durham, NC: Duke University Press, 2013).

Terry Eagleton has critiqued postcolonial studies as suffering from "'increasingly blunted' historical sense." [8]By arguing this, he wants to draw our attention to various forms of violence and disruptions which imperialism brought but have been forgotten or re-interpreted very differently, thus leaving out dissenting views. However, this failure to acknowledge all perspectives is the caveat of historiography since a historian cannot go back into time and experience the events and social dynamics of period under study.[9]

Also India, under colonial rule often was frequented by bouts of violence, not only of overt kind but in daily life too, through discrimination and cultural feuds both state and non-state channels. Violence by natives was first de-legitimized by Britishers as something belonging to primitive communities and thus, initiated selective erosion of authority and practices perpetuating violence by Indians. And then this same tool was used by them to maintain stranglehold over subcontinent.[9]

However, before subordinating lands, Britishers drew maps and surveyed areas they intended to conquer beforehand. It was their imperial belief to which they acknowledged that "maps shape and manipulate mental geographies".[10] Through maps, they could show the image of territory which they wanted to take or maintain control over. This conversion of vast swathes of unknown landscapes to images removed belief of 'unknown' from their minds, through practical inputs of landscapes, etc. Also, conquest of such lands for service of mother country, with disregard to citizens and environment of natives is what Edward Said has referred to be, "Geographical Violence".[11]

Phillimore has shown how the cartographic conception of Mughals and Rennel, a British official cartographer is different in terms of focus on maybe time taken to cover a route and actual distance respectively. Mughal map shows places in map according to their importance in political and revenue matters, irrespective of actual size often. Thus, essential cities marked by big icons and important roads were often highlighted and more carefully drawn than others less critical. So, the compression of unfamiliar places has been ubiquitous in old age. In Mughal maps, areas regarded as inhospitable or with hostile people, were often not shown or were shown vaguely.

Practise of omitting some spaces from maps altogether acts as propaganda by state to erase popular memory . Authorities often, to dislodge the previous regimes or to create new myths for their own survival, will either erase places of previous regimes or will appropriate

---

[8] Stoler, "*Imperial Debris", p. 192.*

[9] David Arnold, "The Violence of Colonialism," in *The Oxford Handbook of the History of Violence*, ed. Robert Antony, Stuart Carroll, and Caroline Dodds Pennock (Oxford: Oxford University Press, 2020), pp. 373–390.

[10] Edney, "*Mapping an Empire".*

[11] Terry Eagleton, Fredric Jameson, and Edward W. Said, *Nationalism, Colonialism, and Literature* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990).

same spaces as their own, blending its legacy to own history as has been done by decolonized states for colonial buildings/structures or they will totally dismember them by ignorance(which Ana Stoler has described as intentional act of ruination).[12] Thus Ana Stoler has recognized ruination as "corrosive process that weighs on the future and shapes the present."[13]

However, Edney has counter argued that instead of state being able to fulfil its propaganda through maps, readers interpret the map in their way. Thus, cartographers are not able to fully reach their aims. However, yes, the fading of memory occurs, initiating the process of ruination and state can displace old spaces of importance.

Also Ian Barrow argues that maps have minimal reach and more than being state tool, "they are often reflections and not just manipulators of social opinion, and that it is difficult to prove a casual relationship between viewing of a map and subsequent action." [14]

However, it needs to be kept in mind that dominant ideology of day will be the one which will be able to impress reader most, whether favourable or opposed by reader since it is also reaching him/her through other means. Thus, its ultimately a state tool, a part of its knowledge system. Moreover, ruination which it brings along with it is a continuous process.

Colonialism's subtle form of violence studied by Frantz Fannon over French imperialism in Algeria where the colonial experience has left what he calls "'tinge of decay', the indelible smack of degraded personhoods, occupied spaces and limited personalities-that were (and remain) hardest to erase."[15] Thus, post-colonial legacy in most colonies has been violence, dehumanization and apartheid-ism resulting in sense of loss, inferiority and still caught up in "peripheries of world system" and "underdevelopment".[16]

Colonialism and notion of "India." :

Nation states do not come into being on their own but are "creation of historical events and processes".[17] Various state propaganda and it's elite machinery creates a knowledge structure supporting nationalism and separate organized independent state for their nationality, suppressing various other centrifugal pressures like subaltern aspirations and imperialism. This process of creation of nation state is continuous even after independence as nationalist ideologies

---

[12] Stoler, *"Imperial Debris"*.

[13] Ibid.

[14] Ian J. Barrow, *Making History, Drawing Territory: British Mapping in India, c. 1756–1905* (New Delhi: Oxford University Press, 2003).

[15] Stoler, *"Imperial Debris"*.

[16] André Gunder Frank, "The Development of Underdevelopment," *Monthly Review* 18, no. 4 (September 1966): pp. 17–31.

[17] Edney, *"Mapping an Empire"*.

continue to absorb various other centrifugal ideas through appeasement of contesting ideologues, respective elites and masses.

Mapping blurs the intrastate variations in cultural, economic and social resource. Thus, these "modern nation states are readily exposed as ideological constructions that have obscured truly significant economic and social variations within a 'mythically homogenous' nation." [18]According to Mathew Edney," the geographical unity of India is….creation of British mapping of their empire".[19]

It was the Britishers who constructed a homogeneous identity of subcontinent and introduced greater homogeneity in form of same language, rules etc. even though for their administrative purposes. Even Winichakul's study on how defining subcontinent in territorial sense was achieved through mapping concludes by saying that "it was crucial that land be transformed into territory".[20]

However, the traditional conception of nationalism was very different. Both Tagore and Gandhi believed in nationalism but their nationalism was not defined solely by territoriality[21]. Tagore believed that modern nation-state defined by territory was nostalgia for lost home and was built over ruins of one's vernacular conception of patriotism.[22] Even Gandhi's nationalism was far away from geographic boundaries and tended to be universal.

Bernard Michael in his study of Anglo-Gurkha war of 1814-16 has shown how indigenous notions of territory, often overlapping were replaced by territory divided by a line. This recognition of standard single line and defined border have been the basis of sovereignty of modern nation- states. These changes show how community conception of regions and territory changed to line drawn over the territory. Independent India, according to Sankara Krishna has inherited this "cartographic anxiety". So the traditional ideas of nation-state were junked. These lines defining the statehood, actually are artificial construct developed through cultural knowledge structure(national myths). It is genuinely the derivative discourse of western nationalism.[23]

Edward Said argues that in anti-imperial struggle, it was territory which was seen as primarily under British control and it was because of primacy imperials gave to space and its

---

[18] Edney, "*Irony of Imperial Mapping*".
[19] Edney, "*Mapping an Empire*".
[20] Ibid.
[21] Ashis Nandy, "Nationalism, Genuine and Spurious: Mourning Two Early Post-Nationalist Strains," *Economic and Political Weekly* 41, no. 32 (August 12–18, 2006).
[22] Ibid.
[23] Partha Chatterjee, "Transferring a Political Theory: Early Nationalist Thought in India," *Economic and Political Weekly* 21, no. 3 (January 18, 1986): pp. 120–128.

survey that anti colonials gave it much attention. This gave nationalists opportunity to oppose colonizers over the land directly. Also loss of land to outsiders generated sense of loss among inhabitants, who later tried to establish their lost identity.[24] We need to recognize the facts that despite drawing such great maps, British could never know the "real India". What they could achieve at all was 'idea of India'.[25] India is land of various sub-nations. Assuming them to be content with one nation state in absence of any binding glue during colonial period except' devotion to monarch' had been blunder. It was this centrifugal force of communitarianism which resulted in partition of subcontinent despite map defining whole subcontinent as one. Thus, while Maps were able to provide 'national identity' to residents, especially after spread of literacy and anticolonial movement and nationalist movements were able to bond people of various parts of subcontinents against single enemy but that was coalition of self-interest against common rival and peaceful merger of all streams of nationalism remained ambiguous, as seen in partition and aftermath.

Conclusion :

We shall acknowledge the role of Maps in invoking nationalism among inhabitants. The derivative discourse of nationalism about which Partha Chatterjee has argued is most visible here. Maps were appropriated to construct national identity and this eventually helped Indians to turn the tables over Britishers through their tools, like in education.

Like its colonial masters, contemporary Indian state is pre-occupied with establishing and maintaining India's territorial integrity. It often leads to clashes with neighbouring nations and even against its citizen who aspire for greater autonomous rights while accepting Indian sovereignty at same time. Many of post-colonial India's problem have emerged on the argument of "territorial and sovereign integrity" of India. This view forgets the fact that dialogue and compromises drawn nation-statehood survives much longer than monolithic and inflexible one. Violence, by either guns or "othering" the groups wouldn't solve the problem of internal security. Maps are drawn on paper and hence there should always be enough scope for changing the lines drawn on paper for the sake of peace.

Violence, even if the agent of maintaining control over subcontinent, was exercised sparsely. This is because colonialists used to believe that excessive use of force tends to blunt its efficiency.[26] This belief was also strengthened by outrage and counter violence, which excessive use of violence cause in some instances, like after Jallianwala Bagh incident, after which Punjab and UP became hotbed of revolutionary activists.

---

[24] Eagleton, Jameson, and Said, *"Nationalism, Colonialism, and Literature"*.
[25] Edney, *"Irony of Imperial mapping"*.
[26] Arnold, *"The Violence of Colonialism"*.

While imperialist were responsible for socio-economic, individual and social and military violence perpetuated over colonial subjects .Also whole of colonial period was marked by destabilized pride of colonial subjects though tinkering with their memory and also erasing common spaces having potential of raising anti-British feelings. So they were somewhat able to establish and rule over subcontinent by twin policies of violence and appeasement. However, to establish greater control overpopulation, their policy of homogenizing law and order also resulted in common perception of masses as against common enemy despite having differences among themselves.

If Britishers had maps as their motivating factor to conquer subcontinent in 19th century[27], natives too developed their symbols-Flags, songs and maps- to counter British state.

There is a strong need to find how much the counter violence by revolutionaries in 1920s-1940s was in opposition to imperial violence which not only subjugated bodies but minds as well. Also, there is need to look at how the attempts to erase memory of past to create divisions within society through cartography and everyday history contrast with attempt of ruling whole subcontinent as one. It is also noteworthy while attempts to subjugate natives continued though exercising hegemony through violence and texts, but it also created unity among them against colonial state, due to common notion of being inhabitants of same territory and under same rule.

Bibliography :

1. Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Revised ed. London: Verso, 2006.

2. Barrow, Ian J. *Making History, Drawing Territory: British Mapping in India, c.1756–1905*. New Delhi: Oxford University Press, 2003.

3. Bayly, C. A. *Empire and Information: Intelligence Gathering and Social Communication in India, 1780–1870*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

4. Chatterjee, Partha. *The Nation and Its Fragments: Colonial and Postcolonial Histories*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1993.

5. Cohn, Bernard S. *Colonialism and Its Forms of Knowledge: The British in India*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.

6. Edney, Matthew H. *Mapping an Empire: The Geographical Construction of British India, 1765–1843*. Chicago: University of Chicago Press, 1997.

[27] Sigrid Weigel in *On the 'Topographical Turn': Concepts of space in Cultural Studies and Kulturwissenschaften.A Cartographic feud*, He talks about how maps as symbols were important in colonisation process.

7. Eagleton, Terry. *After Theory*. London: Penguin Books, 2003.

8. Fanon, Frantz. *The Wretched of the Earth*. Translated by Richard Philcox. New York: Grove Press, 2004.

9. Gandhi, M. K. *Hind Swaraj and Other Writings*. Edited by Anthony J. Parel. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

10. Krishna, Sankaran. *Postcolonial Insecurities: India, Sri Lanka, and the Question of Nationhood*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.

11. Nicolet, Claude. *Space, Geography, and Politics in the Early Roman Empire*. Translated by Hélène Leclerc. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1991.
12. Phillimore, R. H. *Historical Records of the Survey of India*. 5 vols. Dehradun: Survey of India, 1945–1958.

13. Said, Edward W. *Culture and Imperialism*. New York: Alfred A. Knopf, 1993.

14. Stoler, Ann Laura. *Imperial Debris: On Ruins and Ruination*. Durham, NC: Duke University Press, 2013.

15. Tagore, Rabindranath. *Nationalism*. New Delhi: Rupa Publications, 2009.

16. Winichakul, Thongchai. *Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation*. Honolulu: University of Hawai'i Press, 1994.

E-mail: asha230100@gmail.com, Cont. 9958562760
E-mail: durgeshkr1998@gmail.com, Cont. 8051855618

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 187-194

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Motherhood, Sacrifice and Female Identity in Tony Morrison's Beloved

Shamama Bano

Research Scholar, Department of English

Bhagwant University Ajmer Rajasthan, Ajmer, Rajasthan.

Abstract :

Toni Morrison's Beloved (1987) is a landmark novel that explores the enduring psychological, emotional, and social consequences of slavery through the experiences of African American women. This paper examines the interconnected themes of motherhood, sacrifice, and female identity, arguing that Morrison redefines motherhood as both an expression of unconditional love and an act of resistance against the dehumanizing institution of slavery. Through the character of Sethe, the novel portrays the complex moral and emotional dilemmas faced by enslaved mothers who struggle to protect their children from violence and exploitation. Sethe's controversial decision to kill her daughter rather than allow her to be returned to slavery challenges conventional understandings of maternal love and compels readers to consider the devastating effects of systemic oppression on personal choice and identity.

Using Black feminist literary criticism, supported by trauma theory, this study analyzes how Morrison presents female identity as a continuous process of survival, self-recovery, and resistance. The paper further explores the symbolic role of Beloved as the embodiment of repressed memory and historical trauma, illustrating how unresolved experiences of slavery continue to shape individual and collective identities. By situating motherhood within the broader historical and cultural context of racial oppression, Morrison foregrounds the resilience, agency, and humanity of African American women whose voices have long been marginalized in dominant historical narratives. Ultimately, this study argues that Beloved transcends the boundaries of historical fiction, offering a profound critique of slavery while affirming the transformative power of maternal love, memory, and female solidarity in the reconstruction of identity.

Keywords : Toni Morrison; Beloved; Motherhood; Sacrifice; Female Identity; Black Feminism;

Slavery; Trauma; Memory; African American Literature.

Introduction :

Toni Morrison (1931–2019) is one of the most influential voices in American literature, renowned for her profound exploration of African American history, culture, and identity. Awarded the Nobel Prize in Literature in 1993, Morrison dedicated much of her literary career to recovering the silenced histories of Black communities, particularly the experiences of Black women whose lives were shaped by slavery, racial discrimination, and social marginalization. Her novels challenge dominant historical narratives by centering the voices of those excluded from official records and revealing the enduring psychological and cultural consequences of racial oppression.

Published in 1987, Beloved is widely regarded as Morrison's masterpiece and a landmark in contemporary American literature. Inspired by the true story of Margaret Garner, an enslaved woman who killed her young daughter rather than allow her to be returned to slavery, the novel examines the devastating legacy of enslavement through the lives of Sethe, Denver, Paul D, Baby Suggs, and the mysterious figure Beloved. Rather than presenting slavery solely as a historical institution, Morrison explores its lasting emotional and psychological effects, demonstrating how traumatic memories continue to shape individual identities, family relationships, and collective cultural consciousness.

One of the novel's central concerns is the representation of motherhood under the brutal conditions of slavery. Morrison challenges conventional ideals of motherhood by depicting maternal love as inseparable from fear, loss, sacrifice, and resistance. Sethe's decision to kill her child, though morally disturbing, is portrayed as an act born from an unbearable reality in which slavery denies mothers the ability to protect their children. Through this portrayal, Morrison raises profound ethical questions about the meaning of freedom, maternal responsibility, and human dignity within a system that systematically dehumanizes both mothers and children.

The theme of sacrifice is equally significant in Beloved. The novel demonstrates that enslaved women were compelled to make impossible choices in order to preserve their families and their humanity. Sethe's sacrifices extend beyond the physical act of escape to include emotional suffering, social isolation, and lifelong psychological trauma. Morrison suggests that sacrifice is not merely an individual act but a consequence of institutional violence that forces women to negotiate survival in circumstances where ordinary moral frameworks collapse.

Closely connected to motherhood and sacrifice is the question of female identity. Morrison portrays identity as a dynamic and fragmented process shaped by memory, trauma, race, and gender. The women in Beloved struggle to reclaim their sense of self after enduring slavery's dehumanizing effects. Characters such as Sethe, Denver, and Baby Suggs illustrate different paths toward healing

and self-definition, while Beloved symbolizes the persistence of repressed memories that prevent personal and communal recovery. By emphasizing women's resilience and agency, Morrison presents identity not as a fixed condition but as a continuous process of remembering, confronting trauma, and rebuilding the self.

This study examines the interrelationship between motherhood, sacrifice, and female identity in Beloved through the lens of Black feminist literary criticism, with support from trauma theory. It argues that Morrison transforms motherhood into a powerful symbol of resistance against slavery and demonstrates how women's identities are shaped through both suffering and resilience. By analyzing Sethe's maternal experiences and the broader experiences of African American women in the novel, the paper seeks to show that Beloved is not only a historical narrative about slavery but also a profound exploration of memory, love, survival, and the enduring struggle for dignity and selfhood.

Research Objectives :

The present study seeks to examine the representation of motherhood, sacrifice, and female identity in Toni Morrison's Beloved. The specific objectives of the study are :

1. To analyze the portrayal of motherhood as a source of love, protection, and resistance in Toni Morrison's Beloved.
2. To examine the significance of sacrifice in shaping the lives and experiences of African American women under slavery.
3. To explore the construction of female identity through the interconnected experiences of race, gender, memory, and trauma.
4. To investigate how slavery influences the psychological, emotional, and social identities of women in the novel.
5. To interpret Beloved through the perspectives of Black feminist literary criticism and trauma theory.
6. To demonstrate how Morrison challenges traditional representations of motherhood and female identity by foregrounding the resilience and agency of African American women.

Research Questions :

The study is guided by the following research questions :

1. How does Toni Morrison represent motherhood in Beloved, and in what ways does it function as an act of resistance against slavery?
2. What role does sacrifice play in the lives of Sethe and other female characters in the novel?
3. How does slavery shape and transform the female identity of African American women in Beloved?

4. In what ways do memory and trauma influence the characters' understanding of themselves and their relationships?
5. How does a Black feminist reading deepen our understanding of motherhood, sacrifice, and female identity in Beloved?
6. What does Morrison ultimately suggest about resilience, healing, and the reconstruction of identity in the aftermath of slavery?

Analysis :

Motherhood as Resistance -

In Beloved, Toni Morrison presents motherhood not merely as a biological relationship but as a powerful form of resistance against slavery. Under the slave system, Black women were denied authority over their own bodies and children; families were routinely separated through sale and violence. Against this historical background, Sethe's determination to protect her children becomes an act of defiance. Her escape from Sweet Home while pregnant and her struggle to reunite with her children demonstrate a mother's refusal to surrender her family to an oppressive system.

Morrison emphasizes that slavery seeks to destroy maternal bonds because such bonds affirm humanity and agency. Sethe's love for her children represents her insistence that they possess value beyond their status as property. This resistance reaches its most controversial expression when Sethe kills her daughter rather than allow her to be taken back into slavery. Although the act is morally disturbing, Morrison invites readers to understand it within the context of a society that offers enslaved mothers no real protection for their children. Sethe believes that death is preferable to the horrors she herself experienced. Thus, motherhood becomes a radical assertion of freedom: if slavery claims ownership over Black children, Sethe's act rejects that claim absolutely.

Other female characters also illustrate motherhood as resistance. Baby Suggs creates a spiritual and emotional community that nurtures Black people damaged by slavery. Her care for others extends the idea of motherhood beyond biological ties, suggesting that communal love and support are essential forms of survival. Through these women, Morrison portrays motherhood as a source of strength that challenges dehumanization and preserves dignity.

Sacrifice and Maternal Love -

Sacrifice is central to Morrison's portrayal of maternal love in Beloved. Sethe sacrifices physical safety, emotional peace, and social acceptance for the sake of her children. Her escape from slavery requires extraordinary endurance, and even after reaching freedom, she remains haunted by the fear of losing her family. The ultimate sacrifice—the death of her child—emerges from a desperate attempt to shield her children from a life of bondage.

Morrison complicates traditional ideals of motherhood by showing that maternal love under slavery cannot be separated from terror and trauma. Sethe's actions are motivated by profound love, yet that love produces violence because the social conditions surrounding her are violent. The novel therefore questions whether ordinary moral judgments are adequate when people are forced to choose between slavery and death. Sethe's sacrifice is not presented as heroic in a simple sense; it leaves her isolated, guilty, and psychologically wounded. Nevertheless, Morrison portrays the sacrifice as evidence of the extreme pressures placed upon enslaved mothers.

The relationship between Sethe and Beloved further reveals the burden of maternal sacrifice. Beloved's return embodies the unresolved consequences of Sethe's choice. Sethe attempts to atone for the past by devoting herself entirely to Beloved, sacrificing her health, work, and relationships. This obsessive devotion demonstrates how maternal love can become self-destructive when trauma remains unhealed. Through Sethe's suffering, Morrison shows that sacrifice continues long after the original act, shaping the mother's entire identity and future.

Female Identity -

Morrison portrays female identity in Beloved as fragmented, wounded, and continually reconstructed through memory and relationships. Slavery attempts to reduce women to objects, stripping them of autonomy and selfhood. Sethe's identity is deeply marked by the abuses she endured at Sweet Home, including physical violence and the violation of her maternal body. These experiences leave psychological scars that prevent her from fully living in the present.

Memory plays a crucial role in the formation of identity. Sethe repeatedly relives traumatic experiences, and Beloved's presence forces buried memories to surface. Morrison suggests that identity cannot be rebuilt through forgetting; the past must be confronted and acknowledged. However, memory is also dangerous because it can imprison individuals in suffering. Sethe's struggle lies in finding a way to remember without being consumed by remembrance.

Denver represents a different model of female identity. Initially isolated and dependent on her mother, she gradually develops independence and enters the wider community. Her growth indicates the possibility of healing across generations. Likewise, Baby Suggs's teachings about loving one's body and spirit offer an alternative vision of identity grounded in self-worth and communal affirmation. Through these characters, Morrison demonstrates that female identity is shaped by the intersection of race, gender, trauma, and community. Black women in Beloved are not defined solely by victimization; they actively seek meaning, connection, and selfhood despite the legacy of slavery. Morrison ultimately suggests that identity emerges through collective support, remembrance, and the difficult work of survival. The novel therefore transforms the story of individual suffering into a

broader meditation on the resilience and humanity of African American women.

Discussion -

The analysis of Toni Morrison's Beloved demonstrates that motherhood, sacrifice, and female identity are deeply interconnected themes that reveal the devastating human consequences of slavery. Morrison challenges conventional ideals of motherhood by presenting it as a complex experience shaped by oppression, violence, and the struggle for survival. Rather than depicting maternal love as sentimental or idealized, she portrays it as an act of courage and resistance in a society that denies enslaved women control over their own bodies, families, and futures. Sethe's decision to kill her daughter, although morally disturbing, must therefore be understood within the historical context of slavery, where death appeared to her as preferable to a life of bondage. Morrison invites readers to examine the ethical complexities of motherhood under extreme oppression rather than judging Sethe through conventional moral standards.

The novel also demonstrates that sacrifice is inseparable from maternal love. Sethe's experiences reveal that enslaved mothers were forced to make impossible choices to protect their children from exploitation and dehumanization. Her sacrifices extend beyond the physical act of escape to include emotional suffering, social isolation, and lifelong psychological trauma. These sacrifices illustrate how slavery destroys family relationships while simultaneously strengthening the determination of women to preserve their humanity. Morrison therefore transforms sacrifice into a symbol of maternal resilience rather than passive suffering.

Another significant finding of this study is that female identity in Beloved is shaped by the intersection of race, gender, memory, and trauma. Morrison rejects fixed or essential definitions of identity by portraying it as fragmented and continually reconstructed through personal and collective memory. Sethe's identity remains inseparable from her traumatic past, while Denver gradually develops an independent sense of self by engaging with the larger community. Baby Suggs embodies spiritual resistance by encouraging self-love and communal healing despite the violence inflicted upon Black bodies. Together, these women illustrate different paths toward reclaiming identity after slavery.

The discussion also highlights the importance of Black feminist criticism in interpreting the novel. Morrison foregrounds the experiences of African American women, whose voices have historically been marginalized in both historical records and literary traditions. By emphasizing women's agency, resilience, and emotional complexity, Beloved challenges patriarchal and racist representations of Black womanhood. The novel demonstrates that motherhood is not merely a biological role but a political and cultural act through which women resist oppression and preserve human dignity.

Furthermore, trauma functions as a central force that shapes both individual and collective identity. The character of Beloved symbolizes the return of repressed memories and the persistence of historical violence that cannot simply be forgotten. Morrison suggests that healing is possible only when traumatic experiences are acknowledged and shared within a supportive community. The novel therefore connects personal recovery with collective remembrance, emphasizing that confronting the past is essential for rebuilding both individual identity and communal strength.

Overall, this study confirms that Beloved is far more than a historical novel about slavery. It is a profound exploration of maternal love, sacrifice, memory, and the enduring resilience of African American women. Morrison redefines motherhood as an act of resistance, presents sacrifice as a consequence of institutional violence rather than personal weakness, and portrays female identity as a continuous process of survival and self-reconstruction. Through these themes, Beloved remains one of the most significant literary works for understanding the gendered and psychological legacy of slavery and continues to offer valuable insights into contemporary discussions of race, feminism, memory, and human dignity

Conclusion :

This study has examined the interconnected themes of motherhood, sacrifice, and female identity in Toni Morrison's Beloved through the lens of Black feminist literary criticism, supported by trauma theory. The analysis demonstrates that Morrison presents motherhood not merely as a biological or emotional relationship but as a powerful act of resistance against the dehumanizing institution of slavery. Through Sethe's experiences, the novel reveals the impossible moral choices imposed upon enslaved women and challenges readers to reconsider conventional notions of maternal love, sacrifice, and responsibility.

Works Cited :

1. Caruth, Cathy. Unclaimed Experience : Trauma, Narrative, and History. Johns Hopkins University Press, 1996.
2. Collins, Patricia Hill. Black Feminist Thought : Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment. 2nd ed., Routledge, 2000.
3. Davis, Angela Y. Women, Race & Class. Vintage Books, 1983.
4. Gates, Henry Louis, Jr., and K. A. Appiah, editors. Toni Morrison : Critical Perspectives Past and Present. Amistad Press, 1993.
5 Hooks, Bell. Ain't I a Woman : Black Women and Feminism. South End Press, 1981
6. Morrison, Toni. Beloved. Vintage International, 2004. (Original work published 1987).

7. Rushdy, Ashraf H. A. Remembering Generations : Race and Family in Contemporary African American Fiction. University of North Carolina Press, 2001.
8. Showalter, Elaine. A Literature of Their Own: British Women Novelists from Brontë to Lessing. Princeton University Press, 1977.
9. Taylor-Guthrie, Danille, editor. Conversations with Toni Morrison. University Press of Mississippi, 1994.
10. Wyatt, Jean. "Giving Body to the Word: The Maternal Symbolic in Toni Morrison's Beloved." PMLA, vol. 108, no. 3, 1993, pp. 474–488.
11. Mbalia, Doreatha Drummond. Toni Morrison's Developing Class Consciousness. Associated University Presses, 1991.
12. Christian, Barbara. Black Feminist Criticism: Perspectives on Black Women Writers. Pergamon Press, 1985.
13. Bouson, J. Brooks. Quiet as It's Kept: Shame, Trauma, and Race in the Novels of Toni Morrison. State University of New York Press, 2000.
14. Kubitschek, Missy Dehn. Toni Morrison: A Critical Companion. Greenwood Press, 1998.
Peach, Linden. Toni Morrison. 2nd ed., Palgrave Macmillan, 2000.

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 195-200

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

Strengthening Climate Action through the India–Japan Joint Crediting Mechanism : An Analysis of the June 2026 Rules of Implementation

Jai Shri Prajapat
Research Scholar, MSBU, Bharatpur
Dr. Arvind Verma
Professor, MSJ Govt. College, Bharatpur.

Abstract :

The adoption of the Rules of Implementation for the India–Japan Joint Crediting Mechanism (JCM) in June 2026 represents a significant milestone in bilateral climate cooperation under Article 6.2 of the Paris Agreement. The mechanism provides a structured framework for implementing greenhouse gas emission reduction projects, facilitating the transfer of low-carbon technologies, and generating internationally transferred mitigation outcomes (ITMOs) that contribute to the climate commitments of both countries. It aims to promote investments in renewable energy, energy efficiency, waste management, green hydrogen, and other sustainable sectors while ensuring transparency and preventing double counting of carbon credits. The JCM also strengthens economic and technological cooperation by encouraging innovation, climate finance, and private-sector participation. This paper examines the background of the India–Japan Joint Crediting Mechanism, analyses the June 2026 Rules of Implementation, and evaluates their significance for climate governance and sustainable development. It concludes that the JCM has the potential to become an effective model of international climate cooperation and an important instrument for accelerating the transition towards a low-carbon economy.

Keywords : India–Japan Joint Crediting Mechanism (JCM), Article 6.2, Paris Agreement, Carbon Market, Climate Finance, Sustainable Development, Technology Transfer.

Introduction :

Climate change has become one of the most pressing global challenges, requiring countries to work together to reduce greenhouse gas emissions and promote sustainable development. The

Paris Agreement provides a comprehensive framework for international climate action, with Article 6.2 encouraging voluntary cooperation through the transfer of internationally transferred mitigation outcomes (ITMOs). Such cooperative approaches enable countries to achieve emission reductions more efficiently while ensuring transparency and environmental integrity.

India and Japan have strengthened their strategic partnership in recent years through cooperation in infrastructure, clean energy, technological innovation, and environmental sustainability. A major milestone in this partnership was the adoption of the Rules of Implementation for the Joint Crediting Mechanism (JCM) in June 2026, which operationalised the bilateral framework for carbon credit cooperation. The mechanism is expected to promote technology transfer, mobilise climate finance, encourage private-sector participation, and support both countries in achieving their Nationally Determined Contributions (NDCs).

This paper examines the India–Japan Joint Crediting Mechanism with particular emphasis on the June 2026 Rules of Implementation. It analyses the mechanism's evolution, institutional framework, and contribution to climate action while evaluating its significance for sustainable development and bilateral cooperation.

Background of the India–Japan Joint Crediting Mechanism :

The Joint Crediting Mechanism (JCM) is a bilateral carbon market initiative introduced by Japan to promote the adoption of advanced low-carbon technologies in partner countries while contributing to global greenhouse gas (GHG) emission reductions. Unlike the Clean Development Mechanism (CDM) established under the Kyoto Protocol, the JCM operates within the framework of Article 6.2 of the Paris Agreement, which allows countries to cooperate voluntarily through the transfer of internationally transferred mitigation outcomes (ITMOs). The mechanism seeks to ensure that emission reductions are accurately measured, verified, and accounted for, thereby maintaining environmental integrity and preventing double counting.

India and Japan have maintained a long-standing strategic partnership in infrastructure development, clean energy, and technological innovation. Recognising the growing importance of climate cooperation, both countries signed a Memorandum of Cooperation on the Joint Crediting Mechanism in 2025. This agreement laid the foundation for implementing projects in renewable energy, energy efficiency, waste management, green hydrogen, and industrial decarbonisation. The adoption of the Rules of Implementation in June 2026 formally operationalised the mechanism by establishing procedures for project registration, monitoring, verification, and carbon credit issuance.

The India–Japan JCM reflects the shared commitment of both countries to achieving their Nationally Determined Contributions while promoting sustainable economic growth. By combining

Japanese technological expertise with India's expanding clean energy market, the mechanism creates opportunities for investment, innovation, and capacity building. It also demonstrates how bilateral partnerships can complement global climate efforts and support the transition towards a low-carbon and climate-resilient economy.

June 2026 Rules of Implementation :

The adoption of the Rules of Implementation in June 2026 marked a major milestone in operationalising the India–Japan Joint Crediting Mechanism. These rules provide the legal and procedural framework for implementing bilateral carbon credit projects under Article 6.2 of the Paris Agreement. They establish detailed guidelines for project registration, monitoring, reporting, verification, and the issuance of carbon credits, ensuring that all activities are carried out in a transparent and accountable manner.

A key feature of the implementation framework is the establishment of a Joint Committee comprising representatives from the governments of India and Japan. The committee is responsible for approving project methodologies, registering eligible projects, accrediting independent verification bodies, and overseeing the issuance and allocation of carbon credits. Independent third-party entities verify greenhouse gas emission reductions to ensure that projects deliver measurable and credible environmental benefits.

The rules also emphasise environmental integrity by preventing the double counting of emission reductions. Carbon credits generated through JCM projects are recorded using transparent accounting procedures, and corresponding adjustments are made to ensure that the same emission reduction is not claimed by both countries. Furthermore, the framework encourages investment in renewable energy, energy efficiency, waste management, green hydrogen, and sustainable transport. By providing regulatory certainty and a transparent governance structure, the Rules of Implementation are expected to strengthen climate cooperation, facilitate technology transfer, and mobilise greater investment in low-carbon development.

Significance for Climate Action and Bilateral Cooperation :

The India–Japan Joint Crediting Mechanism (JCM) represents a significant advancement in international climate cooperation by providing a practical framework for implementing Article 6.2 of the Paris Agreement. The mechanism enables both countries to collaborate on greenhouse gas emission reduction projects while promoting sustainable development and economic growth. Through the generation and transfer of internationally transferred mitigation outcomes (ITMOs), the JCM supports the achievement of the Nationally Determined Contributions (NDCs) of both India and Japan and demonstrates how bilateral partnerships can contribute to global climate objectives.

For India, the JCM offers access to advanced Japanese technologies in renewable energy, energy efficiency, green hydrogen, waste management, and industrial decarbonisation. The adoption of these technologies can improve energy efficiency, reduce carbon emissions, and strengthen the country's transition towards a low-carbon economy. In addition, the mechanism is expected to attract climate finance and foreign investment, encouraging the development of sustainable infrastructure and creating employment opportunities in emerging green sectors. Such investments can also enhance the competitiveness of Indian industries by promoting cleaner and more efficient production processes. For Japan, the mechanism provides an opportunity to fulfil part of its climate commitments through credible international cooperation. It also expands the global reach of Japanese low-carbon technologies and strengthens its role as a leader in climate diplomacy and sustainable innovation. The partnership creates new opportunities for Japanese companies to invest in India's rapidly growing clean energy market while contributing to global emission reduction efforts.

Beyond its bilateral benefits, the India–Japan JCM serves as an important example of how international carbon markets can operate with transparency, accountability, and environmental integrity. The mechanism encourages public–private partnerships, technological innovation, and knowledge sharing, thereby supporting long-term sustainable development. As more countries explore cooperative approaches under Article 6 of the Paris Agreement, the India–Japan Joint Crediting Mechanism has the potential to become a model for future climate partnerships and international carbon market initiatives.

Challenges and Future Prospects :

Despite its considerable potential, the India–Japan Joint Crediting Mechanism faces several challenges that may influence its successful implementation. One of the primary concerns is the complexity of carbon market regulations and the need for effective coordination between government agencies, private enterprises, and independent verification bodies. Establishing reliable systems for monitoring, reporting, and verifying emission reductions requires strong institutional capacity and continuous technical support. Furthermore, many low-carbon technologies involve high initial investment costs, which may discourage participation by smaller enterprises without adequate financial assistance.

Another important challenge is maintaining environmental integrity by preventing the double counting of carbon credits. Transparent accounting procedures and strict compliance with Article 6.2 requirements are essential to ensure the credibility of the mechanism. Capacity building and awareness programmes will also be necessary to encourage greater participation from industries and project developers.

Despite these challenges, the future prospects of the JCM remain highly promising. India's expanding renewable energy sector, increasing investment in green hydrogen, and commitment to achieving net-zero emissions by 2070 provide significant opportunities for collaborative projects. Continued Japanese investment, technology transfer, and policy cooperation are expected to strengthen industrial decarbonisation and sustainable infrastructure development. As international carbon markets continue to evolve, the India–Japan Joint Crediting Mechanism is likely to play an increasingly important role in supporting global climate action.

Conclusion :

The adoption of the Rules of Implementation for the India–Japan Joint Crediting Mechanism in June 2026 marks an important milestone in bilateral climate cooperation under Article 6.2 of the Paris Agreement. By establishing a transparent framework for implementing emission reduction projects and generating carbon credits, the mechanism supports both countries in achieving their Nationally Determined Contributions while promoting sustainable development. It also strengthens cooperation in clean technology, climate finance, and capacity building, creating opportunities for innovation and long-term economic growth.

Although challenges related to regulatory coordination, financing, and institutional capacity remain, the JCM provides a practical model for addressing these issues through international collaboration. Its emphasis on transparency, environmental integrity, and private-sector participation enhances the credibility of bilateral carbon market mechanisms. As global efforts to address climate change continue to expand, the India–Japan Joint Crediting Mechanism is expected to play a significant role in accelerating the transition to a low-carbon economy and may serve as a model for future international climate partnerships.

References :

1. Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/
2. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. (2026, June 16). India and Japan adopt Rules of Implementation for Joint Crediting Mechanism under Article 6.2 of the Paris Agreement. Press Information Bureau, Government of India. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2273527
3. Ministry of Environment, Forest and Climate Change. (2025, August 29). India and Japan sign Memorandum of Cooperation on Joint Crediting Mechanism (JCM) under Article 6.2 of the Paris Agreement on Climate Change. Press Information Bureau, Government of India. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2161892

4. Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2026). Joint Crediting Mechanism (JCM). https://www.mofa.go.jp/
5. Joint Crediting Mechanism Secretariat. (2026). India–Japan Joint Crediting Mechanism: Rule of Implementation. https://www.jcm.go.jp/jc/information/20260608/
6. United Nations Framework Convention on Climate Change. (2015). Paris Agreement. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
7. Press Information Bureau. (2026, July 2). 16th India–Japan Annual Summit Joint Statement. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2280587
8. Government of Japan, Ministry of the Environment. (2026, June 25). Rule of Implementation of the Joint Crediting Mechanism (JCM) between Japan and India. https://www.env.go.jp/press/press_01458.html
9. United Nations. (2023). The Sustainable Development Goals report 2023. https://unstats.un.org/sdgs/report/2023/

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 201-213

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

आदिवासी ज्ञान और सतत् विकास : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की थारू जनजाति के विशेष सन्दर्भ में)

अजय कुमार विश्वकर्मा, शोधार्थी, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)
डॉ. नेहा मालवीय, सहायक प्राध्यापक
राय साहब भंवर सिंह महाविद्यालय, भैरुंदा, जिला–सीहोर (म.प्र.)

सारांश -

भारत में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के तराई क्षेत्र में निवास करती है। उनकी संस्कृति और परंपरा का पारिस्थितिकी तंत्र से गहरा संबंध है। थारू जनजाति की सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनैतिक गतिविधियों में जल, जंगल, जमीन और जैव-विविधता (4J) का महत्वपूर्ण योगदान है, यह समुदाय सतत् विकास के लक्ष्य तेरह, चौदह व पंद्रह को संरक्षण प्रदान करते है किंतु आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से थारू युवा अपनी पारंपरिक संस्कृति एवं ज्ञान से दूर हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप उनकी संस्कृति की पहचान धूमिल हो रही है। इस शोध का उद्देश्य थारू समुदाय के पारंपरिक ज्ञान की संरचना, सतत् विकास में योगदान तथा आधुनिक प्रभावों का विश्लेषण करना है। यह गुणात्मक शोध उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के चार थारू बाहुल्य गाँवों में असंरचित साक्षात्कार, अवलोकन और एकल अध्ययन के माध्यम से किया गया है। यह अध्ययन थारू जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और सतत् विकास में इसके महत्व को रेखांकित करता है।

मुख्य शब्द- पारंपरिक ज्ञान, संस्कृति, सतत् विकास, पारिस्थितिकी व आधुनिकीकरण।

परिचय -

हिमालय के तराई क्षेत्रों के प्रकृति वन प्रान्त में शताब्दियों से अपनी संस्कृति की अनमोल धरोहर को संजोने वाली एक अनूठी जनजाति का नाम है- थारू जो सबसे बड़े और इस क्षेत्र के पुराने जनजातीय समुदायों में से एक है। वे सामान्यतया कृषि, मछली तथा प्राकृतिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इस जनजाति की स्थानीय भाषा थारुहती है, जिसकी उत्पत्ति देवनागिरी लिपि से मानते है। यह जनजाति भोजपुरी के साथ अपने आस-पास की क्षेत्रीय भाषा को भी बोलते हैं। थारू जनजाति को जनजाति से अनुसूचित जनजाति का दर्जा 1967 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत घोषित किया गया है। इसमें थारू जनजाति की चार और उप-जनजातियाँ (बुक्सा, भोटिया, जौनसारी, राजी) शामिल थी। इन उप-जनजातियों में सबसे अधिक जनजाति थारू समुदाय की है। इस समुदाय का अधिक निवास भारत- नेपाल की बार्डर पर जंगली तराई क्षेत्र में रहता है।[1] थारू जनजाति मुख्य रूप से भारत के तीन राज्यों के कई जिलो में पायी जाती है, जो उत्तराखंड के उदमसिंह जिले, बिहार राज्य के चंपारण जिले और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, बहराइच, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, गोरखपुर व सिद्धार्थनगर के जिलों में निवास करती है। यह जनजाति नेपाल की भी एक प्रमुख जनजाति है। जिनका निवास अधिकतर पर्वतीय क्षेत्रों में होता है, नेपाल में इनकी जनसंख्या 1,737,470 है।[2] लेकिन भारत के उत्तराखंड राज्य में इनकी कुल जनसंख्या 91,342, उत्तर प्रदेश में 105,291, तथा बिहार में 159,939 है।[3]

मानव सभ्यता के विकास में आदिवासी समुदायों का अद्‌वितीय और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये समुदाय प्राचीन काल से ही अपने विशिष्ट ज्ञान, संस्कृति, रीति-रिवाज, पारंपरिक गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों के सतत् प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध हैं। आदिवासी ज्ञान न केवल उनके भौतिक जीवन को संचालित करता है, बल्कि उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहलुओं में भी गहराई से अंतर्निहित होता है। सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय परिवर्तन के परिदृश्य से यह ज्ञान सतत् विकास के लिए एक सशक्त साधन सिद्ध हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की थारू जनजाति एक प्रमुख आदिवासी समूह है, जिसकी सांस्कृतिक पहचान, जीवनशैली और ज्ञान-परंपरा का संरक्षण एवं संवर्धन वर्तमान में अत्यंत महत्वपूर्ण है। थारू समुदाय की आजीविका का मुख्य स्त्रोत वन, कृषि और स्थानीय संसाधनों का सतत् उपयोग रहा है। ये जनजाति अपने पारंपरिक ज्ञान के आधार पर जल, जंगल, जमीन एवं जैव-विविधता **(4J)** का संरक्षण तथा प्रबंधन करती आयी है, जिसका समाजशास्त्रीय अध्ययन सतत् विकास के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है। आदिवासी ज्ञान का दायरा अत्यंत व्यापक है, जिसमें

लोक-चिकित्सा, जड़ी-बूटी, पर्यावरणीय प्रबंधन, जैव-विविधता संरक्षण, जल संरक्षण, कुटीर शिल्प, पारंपरिक कृषि और आपसी सहयोग जैसे विविध पक्ष शामिल हैं। थारू समुदाय में भी पारंपरिक कृषि प्रणालियाँ, खाद्य पदार्थों के संग्रहण की तकनीक, जलस्रोतों का संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदाओं के समय सामूहिक प्रतिक्रिया उनके गहन सामाजिक ज्ञान को दर्शाते हैं।

वर्तमान के इस वैश्विक दौर में जब सतत् विकास के लक्ष्य, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता तथा आर्थिक विकास मुख्य रूप से चर्चा के केंद्र में हैं, ऐसे में आदिवासी ज्ञान पुनः प्रासंगिक हो रहा है। **संयुक्त राष्ट्र** के "आदिवासी मामले के स्थाई फोरम" की 2007 में जारी रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ विश्व के कुल 80% जल, जंगल, जमीन व जैव-विविधता (4J) के संरक्षण और संवर्धन के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है।[4] थारू समुदाय द्वारा उपयोग की जाने वाली पारंपरिक तकनीकें और सामाजिक व्यवस्थाएँ अक्सर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बजाय उनके संतुलित एवं समावेशी उपयोग पर जोर देती हैं। यह दृष्टिकोण सतत् विकास की अवधारणा को सार्थक आधार प्रदान करता है। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से, थारू जनजाति की सामाजिक संरचना, पारंपरिक ज्ञान का संचरण और समुदाय आधारित निर्णय-व्यवस्था सतत् विकास के आदर्श मॉडल प्रस्तुत करती है।

जनजातियों के सम्बन्ध में समाजशास्त्रीय, मानवशास्त्रीय तथा संवैधानिक विचार -

भारतीय संदर्भ में ट्राइब शब्द के लिए मानवशास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों ने अपनी पुस्तकों में "जनजाति, आदिवासी, गिरिजन, वनवासी, पहाड़ी, आदिम जाति, वन्य जाति जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। मानवशास्त्री हर्बर्ट रिजले ने जनजाति को एबोरिजनल या आदिवासी कहा है, जबकि हट्टन, एल्विन जैसे विद्वानों ने क्रमशः प्रिमिटव ट्राइब, ऑरिजिनल ऑनर्स तथा फॉरेस्ट ट्राईब के रूप में वर्णित किया है। जी०एस० घुर्ये ने पिछड़ा हिन्दू, ठक्कर बप्पा ने आदिवासी, वेरियर एल्विन ने वनवासी, एल०पी० विद्यार्थी ने गिरिजन और हट्टन ने इन्हें आदिम जाति कहा है। वर्तमान में जनजातीय समुदायों को देशज कहने का भी चलन है। वर्ष 1901 ई0 की जनगणना रिपोर्ट में उन्हें प्रकृतिवादी, वर्ष 1937 ई. की जनगणना रिपोर्ट में उन्हें आदिम जाति, वर्ष 1941 ई0 की जनगणना रिपोर्ट में उन्हें ट्राइब (जनजाति) नाम से पहचान मिली। आजादी के बाद भारतीय संविधान में "अनुसूचित जनजाति" शब्द का उपयोग किया गया। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या सम्पूर्ण भारत की जनसंख्या का 104.5 मिलियन व 8.6 प्रतिशत है। वर्तमान समय में भारत में लगभग 645 जनजातियां निवास करती है। भारतीय संविधान की पाँचवीं एवं छठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति को विशेष प्रावधान

दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य, उन जनजातीय समुदायों से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत् केन्द्र सरकार की सिफारिश के आधार पर माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है।[5]

थारू जनजाति का इतिहास -

थारू जनजाति की उत्पत्ति एवं विकास के सम्बन्ध में कई समाजशास्त्रीय और मानवशास्त्रीय विद्वानों ने अपने मत दिए है। जिसमें डी०एन० मजूमदार थारू जनजाति को मंगोल प्रजाति मानते है वे रक्त समूह परीक्षण या सिरोंलोजी के आधार पर राजपूतों के लिए अपनी संस्कृति का दावा नहीं कर सकते। उनकें पास कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे वे स्वयं को राजस्थान के राजपूतों से संबंधित होने का दावा कर सके।[6]

एच०एच० रिजले ने अपनी पुस्तक "ट्राइब एण्ड कास्ट ऑफ बंगाल" के दूसरे भाग में तथा जॉन नेसफिल्ड ने सन् 1885 ई0 जनवरी के कलकत्ता रिव्यू के आलेख में प्रतिपादित किया है कि थारू तराई की मूल आदिवासी जनजाति है। आर्य समुदाय के शोषण के पश्चात थारू समुदाय निचले हिमालय के जंगलों से धीरे-धीरे भारत और नेपाल की सीमा के पास बस गयी। डब्लू क्रूके (1896) का मत है कि थारू की उत्पत्ति थारू शब्द से खोजी जा सकती है, जो शराबी को दर्शाता है ऐसा माना जाता है कि यह नाम थारू को मैदानी इलाकों के एक क्षत्रिय राजा द्वारा थारू की प्रबलता और शराब पीने की क्षमता को देखते हुए दिया गया था। नेपाली लेखक सुबोध कुमार सिंह के अनुसार राजपूत राजाओं द्वारा आक्रमण की एक श्रृंखला ने स्वदेशी थारू के प्रभाव को कम कर दिया। नेपाल के पहले प्रधानमंत्री जंग एब्रेडर ने 1854 में स्वदेशी कानूनी प्रणाली लागू करने के लिए समाज को जाति व्यवस्था में विभाजित किया। जिसमें थारू समुदाय को पदानुक्रम में सबसे निम्नतम श्रेणी में रखा गया था इस कारण से उनके समुदाय के लोगो का उच्चतम श्रेणी द्वारा शोषण करके जमीन हड़प ली गयी तथा उनके समुदाय के लोगो को विस्थापित कर दिया गया।[7]

साहित्य समीक्षा -

सहाय, इंदू. (1998) . ने अपने शोधपत्र "दि थारू ऑफ लखीमपुर खीरी" में थारू बाहुल्य गाँव 'बनकटी' में क्षेत्रीय कार्य किये है, जिसमें बताते है कि थारु जनजाति जैव-विविधता के साथ सामंजस्य बनाकर रहती है।[8]

गेने काम्पैग्न. (2000). संस्था ने थारू जनजाति के लोगो का खान-पान, रहन-सहन, पहनावा, निवास-स्थान, आर्थिक व सांस्कृतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला है। इन जनजाति में एक मुख्य परम्परा का उजागर किया है जो परम्परागत उपचारात्मक (Traditional Medicine) प्रणाली है जिसमे व्यक्ति की किसी भी प्रकार के रोग (बीमारी) का उपचार जड़ी-बूटियों के द्वारा होता है।[9]

मैत्री, समीरा. (2004). ने लखीमपुर खीरी के थारूओं पर किए गए गहन क्षेत्र कार्य के आधार पर, यह पाया गया कि कला थारू जीवन के लगभग हर पहलू में अंतर्निहित है। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं स्वयं निर्मित होती हैं। इन वस्तुओं को देखकर यह स्पष्ट होता है कि थारू अपनी स्वयं की अच्छी तरह से परिभाषित सौंदर्य संवेदनशीलता से निर्देशित होते हैं।[10]

वर्मा, सुभाष चन्द्र. (2010). ने उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के थारू जनजाति के सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों का अध्ययन किये है, जिसमें बताते है कि थारू समुदाय के समस्त सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ (जैसे-रोटी, कपड़ा, मकान, धर्म, कला, टोटम एवं टैबू आदि) का गहरा सम्बन्ध परीस्थितिक संतुलन एवं प्रकृति से है।[11]

श्रीवास्तव, एस. के. (1958). ने अपनी पुस्तक "द थारू : ए स्टडी इन कल्चरल डायनामिक्स" में थारू संस्कृति की विविध आयामों एवं विशेषताओं का गहन अध्ययन किया है यह पूर्णतः उत्तर प्रदेश के थारू समाज पर केन्द्रित पुस्तक है, जिसमें राणा थारुओं को राजपूतों का वंशज बताया है।[12]

सिंह, जोगा एवं शर्मा, अनीता (2002). द्वारा रचित "उत्तर प्रदेश के थारू पर थारू जाति का सामाजिक, धार्मिक तथा संस्कृति अध्ययन", उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड जीवन के समस्त सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी देती है।[13]

नेगी, कृष्णा & शर्मा, वंदना. (2025). द्वारा लेख में संस्कृति की गतिशीलता और परिवर्तनशील स्वरुप को समझाता है उन्होने संस्कृति निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जो समाज के जीवन, पर्यावरण और ऐतिहासिक अनुभवों से गहराई से जुडी होती है।[14]

उपरोक्त साहित्य समीक्षा से स्पष्ट होता है कि थारू समुदाय की समस्त सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ तथा पारम्परिक ज्ञान पर अध्ययन सिर्फ बाहरी स्वरुपो पर हुआ है और आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव का सामान्य अध्ययन हुआ है। जिस कारण से उनके

प्रकार्य के महत्व को समझने में कठिनाई आ रही है, जिसे केनेथ एल्पाइक ने **Etic Perspective** कहा है यह अध्ययन **Emic Perspective** में किया गया है, जिसमें थारू समुदाय के सांस्कृतिक और पारम्परिक ज्ञान के आन्तरिक स्वरुप किस प्रकार से सतत् विकास के लक्ष्य तेरह, चौदह व पंद्रह को संरक्षण और संवर्धन प्रदान करते है, जिसे क्लिफोर्ड गीर्त्ज़ ने अपनी पुस्तक "इंटरप्रिटेशन ऑफ़ कल्चर" में **Thick Description** कहा है, यही शोध अध्ययन का अन्तराल है।

उद्देश्य -

इस अध्ययन का उद्देश्य बलरामपुर जिले की थारू जनजाति के पारंपरिक ज्ञान की सामाजिक संरचना और उसके सतत् विकास में योगदान का विश्लेषण करना है। साथ ही, यह भी जानना कि किस प्रकार आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण ने थारू समुदाय को प्रभावित किया है। यह अध्ययन न केवल आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण की दिशा में योगदान देगा, बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर सतत् विकास के लक्ष्य **तेरह, चौदह व पंद्रह** की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होगा।

अनुसंधान पद्धति -

प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति गुणात्मक विधि है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले की थारू बाहुल्य गाँव विशुनपुर विश्राम, कोदरगड़वा, चंदनपुर तथा भगवानपुर में किया गया है। जिसका चुनाव उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि से हुआ है और नमूने (Sample) का चयन यादृच्छिक विधि (Random Method) से थारू परिवार के मुखिया को लिया गया है। तथ्य संकलन असंरचित-साक्षात्कार तथा अवलोकन के माध्यम से किया गया है। इस अध्ययन में थारू परिवार के दो पुरुषों और एक महिला मुखिया का एकल अध्ययन भी किया गया है और साथ में द्वितीयक सामग्री का भी उपयोग हुआ है।

क्षेत्र कार्य की जनसंख्या संरचना-

विकास खंड-पचपेड़वा जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम की कुल जनसंख्या	2011 जनगणना के आधार पर अनु. जन.	थारू जन. प्रतिशत
1.	भगवानपुर कोडर	2553	2326	91.11

2.	विशुनपुर विश्राम, कोदरगड़वा	2398	2170	90.49
3.	चंदनपुर	1898	1489	78.45

स्रोत - थारू विकास परियोजना

प्रकृति और थारू जीवन-शैली के बीच सम्बन्ध -

थारू समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ इको-फ्रेंडली होती है, ये प्राकृतिक पदार्थ के उपयोग के साथ-साथ सतत् विकास के लक्ष्य तेरह, चौदह व पंद्रह की प्राप्ति में भी सहायक सिद्ध होती है।

थारू गांव - यह जनजाति भारत-नेपाल बॉर्डर के जंगली तराई क्षेत्र में बसी हुई है, जो पहाड़ के पास समतल क्षेत्र में निवासरत है। गाँव में आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, बालिका कॉलेज और आई टी आई संस्थान भी है।

थारू घर - इस समुदाय के घर लकड़ी, घास-फूस, पत्तियों, एवं मिट्टी की दीवार से बने होते है। प्रत्येक गाँव में कुछ पक्के और कुछ लकड़ी से बने घर भी होते है। इनके घर अत्यधिक साफ़ सुथरे, ठंडे, गर्मी और बरसात प्रत्येक मौसम में सुविधायुक्त होते है। घर के अन्दर जानवरों, किचन, अनाज रखने के लिए और सोने के लिए अलग-अलग कमरे बने होते है। अधिकतर घर का निकास पूर्व दिशा की तरफ एवं घर के बाहर आँगन पीछे फल-फूल के लिए जगह होती है, वे घर की सजावट के लिए पोशाक और पेंटिंग में विपरीत रंग पसंद करते है।

थारू धर्म - इस समुदाय में स्थानीय देवता को 'भूमसेन' कहा जाता है, जिसे अन्दर के देवता और बाहर के देवता में बाँटा जाता है, अन्दर के देवता में प्रत्येक घर के वंशानुगत देवी-देवता और बाहर के देवता में पूरे समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में एक देवता होते है जिन्हें टोटम कहते है। टोटम कोई भी जैविक एवं अजैविक पदार्थ हो सकता है, जैसे पशु, पौधे, जल, पहाड़, चन्द्रमा, सूर्य आदि। जिसको समुदाय कभी भी कोई हानि नहीं पहुंचाता है बल्कि उसका संरक्षण प्रदान करते है और उसके साथ कई लोक कहानियाँ होती है, जो वंशानुगत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। थारू जनजाति कई हिन्दू देवी-देवताओ की भी पूजा और त्योहारों को मनाते है।

थारू संस्कृति - थारू समुदाय की संस्कृति इको-फ्रेंडली होती है, इनकी सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ जिसमे रोटी, कपड़ा, मकान, कला, धर्म, अर्थ का सम्बन्ध प्रकृति से है,

आधुनिक युग में औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, वैश्वीकरण के प्रभाव से थारू युवा प्रभावित हो रहें है।

सतत् विकास प्रबंधन में थारू ज्ञान परम्परा का योगदान -

सतत् विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति का भी ध्यान रखती है। यह एक संतुलित विकास मॉडल है, जो सामाजिक व प्राकृतिक पर्यावरण के साथ अर्थव्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित करता है। सतत् विकास की अवधारणा 20वीं शताब्दी में विकसित हुई, जब यह स्पष्ट हुआ कि पर्यावरणीय संसाधनों का अत्यधिक दोहन पृथ्वी की पारिस्थितिकी और मानव समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में पहली बार वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय मुद्दों पर चर्चा हुई। इसके बाद, 1987 में प्रकाशित ब्रूटलैंड रिपोर्ट "Our Common Future" ने सतत् विकास की औपचारिक परिभाषा दी इसलिए 1992 में रियो डी जेनेरो के पृथ्वी सम्मेलन में "एजेंडा 21" पेश किया गया, जिसमें पर्यावरणीय प्रबंधन व स्थायी आर्थिक विकास की रूपरेखा दी गई। इसके बाद, 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (MDGs) को अपनाया गया, जो 2015 तक विकास के विभिन्न आयामों पर ध्यान केंद्रित करते थे। 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्रस्तुत किया, जिनमें 2030 तक प्राप्त करने योग्य 17 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। ये लक्ष्य सामाजिक न्याय, आर्थिक स्थिरता और पर्यावरणीय संरक्षण पर केंद्रित हैं।[15] सतत् लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सरकारी नीतियों, एनजीओ आदि ही नही बल्कि जनजातीय समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी सहायक सिद्ध होती है। थारू समुदाय में जल, जंगल, जमीन और जैव-विविधता से सम्बंधित कई सामाजिक-सांस्कृतिक परम्पराए प्रचलित है, जो प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सतत् विकास के लक्ष्य तेरह, चौदह व पंद्रह के प्रबंधन मे संरक्षण प्रदान कर रही है जो निम्नलिखित है-

जारवो पूजा - थारू समुदाय में एक मान्यता है कि यदि कृषि कार्य में रासायनिक खाद का उपयोग करेगें तो इससे धरती माता को हानि पहुँचेगी मतलब कि हम लोग धरती माता का खून कर रहे है, जिससे जारवो देवता नाराज हो जायेंगे तो फसल की पैदावार क्षमता कम हो जाएगी इसलिए समुदाय के प्रत्येक परिवार वर्ष में एक बार जारवो पूजा करते हैं। इस मान्यता से जैविक कृषि को बढ़ावा मिलता है।

वरना पूजा - यह थारू समाज की धार्मिक प्रथा है, जिसमें तीन दिन तक परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी हिंसा का कार्य नहीं करता है। थारुओं की मान्यता है कि वरना पूजा

करने से फसलों को नुकसान पहुचाँने वाले कीटो एवं जानवरों से उनकी फसलों की रक्षा होती है यहाँ तक की सब्जी, पेड़-पौधों, पत्ता, पशुचारा काटने कुआँ से पानी निकालने एवं खेतों की जुताई की भी मनाही होती है। यह पूजा वैशाख माह में आयोजित होती है।

जंगल पूजा - इस समुदाय के लोग वर्ष के शुरुआत में जब लकड़ी काटने या शिकार करने के लिए जंगल में प्रवेश करते है तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते है। ऐसी मान्यता है कि इससे जंगल के देवता प्रसन्न होते है और परिवार के सदस्यों की विषैले जानवरों से रक्षा करते है।

इस प्रकार से और भी अनेक सांस्कृतिक अनुष्ठान है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जल, जंगल, जमीन तथा जैव-विविधिता (4J) को संरक्षण प्रदान करते है **जैसे-** झंडी पूजा, हरवत पूजा, फार पेयना पूजा, भीख पूजा, धुरियाँ पूजा, हरेरी पूजा, लवांगी पूजा, गोरु बेधे पूजा आदि सब स्थानीय संस्कृति प्रकृति के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करते है।

थारू समुदाय में बीमारियों का इलाज कई प्रभावशाली जड़ी-बूटियों से करते है, जिनमें गुरों का झाड़-फूँक, जंतर-मंतर, अंधविश्वास या पाखंड का प्रदर्शन नही होता बल्कि स्वदेशी ज्ञान के साथ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का मूल रूप प्रदर्शित होता है। जिसमें जनवेरा पेड़ बुखार में, बिटईया फल टायफाइड तथा चेचक में, मोखा पत्ता भालू, कुत्ता तथा सियार के काटने पर, भबर लंग पेट दर्द में, मनटामुर फल गठियां या दर्द वाले स्थान पर लेप लगाने, गुलर का पत्ता लेई बना कर घाव व फुंसी पर, बोकवा खर जड़ को घोलकर इलायची और मरीच के साथ पीस कर खाने से पेट दर्द व कब्ज में और लमटूसिया कमजोर व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है।

थारू समुदाय में परिवर्तन की प्रक्रिया -

जब आदिवासी समुदाय को परिभाषित किया जाता है तो उनके विशेष गुण ही उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करते है, प्रथम वे गैर-आदिवासी समुदाय से सम्पर्कहीन रहते है, द्वितीय उनके समुदाय में परिवर्तन की प्रक्रिया अनुपलब्ध रहती है। जब से थारू समुदाय के युवा शिक्षा व रोजगार के लिए शहर की ओर प्रवास कर रहे है तब से नयी संस्कृति की ओर आकर्षित होकर अपनी परम्परागत संस्कृति को नजरंदाज कर रहे है। थारू समुदाय भी आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण तथा वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अछुता नहीं रहा। योगेन्द्र सिंह अपनी पुस्तक "भारतीय परम्परा की आधुनिकीकरण" में लिखते है,[16] किस प्रकार भारतीय समाज की संरचना के मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है, जो जनजातीय परिदृश्य को प्रतिबिंबित कर रहा है। आधुनिकता की प्रक्रिया चाहे कितनी ही गतिशील हो जाए वह परम्परा के मूल्यों को पूरी तरह

से समाप्त नहीं कर सकती, बल्कि आधुनिकरण से तो कभी-कभी परम्परा के मूल्य जीवित हो जाते है। थारू समुदाय के परम्परागत मूल्यों में परिवर्तन आन्तरिक (Orthogenetic) और बाह्य (Heterogenetic) प्रक्रिया के द्वारा हो रहा है। आन्तरिक प्रक्रिया में संस्कृतिकरण, सुधार आन्दोलन, थारू विकास परियोजना है तो और बाह्य प्रक्रिया में पश्चिमीकरण, वैश्वीकरण तथा सरकारी नीति है, इन दोनों प्रक्रियाओं से थारू समाज के मूल्यों में तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है।

एकल अध्ययन- (डुगरिया थारू)

गोकुल प्रसाद (काल्पनिक नाम) का एक व्यक्ति है जिनकी उम्र 83 वर्ष है, शिक्षा 8 वी कक्षा तक पूर्ण है ये अपने परिवार को डुगरिया थारू मानते है और क्षेत्र कार्य गाँव मे सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति है। इनका व्यवसाय कृषि और मजदूरी है इनके पास 30 बीघा भूमि है और शादी में दहेज़ के रूप में गाय मिली थी। घर का भोजन जंगल की सुखी लकड़ी से तैयार किया जाता है, प्रमुख भोजन दाल, चावल तथा मछली है। कृषि कार्य की शुरुआत असाड का छलका (भूमि पूजा) देकर की जाती है और साथ में धुरियाँ पूजा, वैशाखी पूजा तथा कालीथान पर शराब चढ़ा कर होती है। कृषि के लिए जैविक खाद का उपयोग करते है। परिवार व समुदाय की रक्षा के लिए बाभन पूजा, रक्सा पूजा, ठाकुर पूजा करते है जिससे उनके देवता प्रसन्न रहे। इनके सभी देवता विशिष्ट रूप से पीपल के वृक्ष पर निवास करते है, इसलिए पीपल के वृक्ष को कभी नहीं काटते है। जड़ी-बूटी के लिए थारू समुदाय पीपल, बरगद, पाकड़, तुलसी, नीम, महुवा, जामुन, सेखुवा आदि वृक्षों का प्रयोग करते है, और इन वृक्षों को कभी नही काटते। ये कूड़ा-करकट खेत में एकत्रित करते है और व्यक्ति के मृत्यु पर उसके कपडे जला दिया जाता है। इस समुदाय के लोग पहले जंगली घास-फूस से बना सामान उपयोग करते थे और जंगली सूअर, हिरन, खरगोश का शिकार करते थे।

कलावती (काल्पनिक नाम) की एक महिला है उम्र 45 वर्ष है शिक्षा 5 वी पास है। अपने परिवार में सबसे बड़ी महिला है ये घरेलू कार्य के अलावा कृषि व मजदूरी का कार्य भी करती है घर में उपयोग की छोटी-छोटी वस्तु का निर्माण जंगली लकड़ी व घास-फूस से करती है। समुदाय की प्रत्येक महिलाएं कला-शिल्प प्रमुख रूप से करती है जैसेः टोकरी, चटाई, सूप, डलिया, झाड़ू दीवाल पर पेड़-पौधों की चित्रकारी आदि। पुरूषों की तुलना में महिलाएं अधिक पवित्र मानी जाती है। किसी भी पूजा पाठ में महिलाओं की भूमिका प्रमुख होती है। इस समुदाय में पितृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन फिर भी महिलाओं के सुझाव कोई भी कार्य करने से पहले लिए

जाते है। सभी महिलाएं अपने हाथ पर पति का नाम या फूल का गोदना गुदवाती है फूल का अर्थ प्राकृतिक प्रेमी से मानती है।

विनोद (काल्पनिक नाम) का एक व्यक्ति है उम्र 27 वर्ष है, हिंदी विषय से स्नातकोत्तर है, अपनी सम्पूर्ण शिक्षा शहर में की है और अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में पदस्थ है। ये अपनी परम्परागत सामाजिक व्यवस्था से परिचित है, लेकिन व्यवहार में नहीं लाते है। इनके खान-पान, रहन-सहन और संप्रेषण में आधुनिकता झलकती है।

इस एकल अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि थारू समुदाय के तीनों व्यक्तियों के विचार और अभ्यास समुदाय में अलग-अलग है। प्रथम केस में अधिक पारम्परिक ज्ञान, सामुदायिक ज्ञान व अनुष्ठान व्यवहार में दिखतें है। द्वितीय केस में महिला, परिवार व समुदाय के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति परम्परागत प्रणाली से पूर्ण कर रही है। तीसरे एकल अध्ययन में व्यक्ति पूरी तरह से आधुनिक विचार से प्रभावी है। यह उनके समुदाय में परिवर्तन की एक रेखीय प्रक्रिया व पीढ़ियों के बीच सूचना के अन्तराल को दर्शाता है।

परिणाम -

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि, थारू जनजाति की संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान न केवल इनकी सामाजिक संरचना की रीढ़ है बल्कि सतत् विकास में भी महत्वपूर्ण है। यह ज्ञान प्रकृति पर निर्भरता, सामूहिकता, नैतिक मूल्यों और पीढ़ियों से सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रहा है। इस समुदाय में जीविकोपार्जन के स्वदेशी तरीके, चिकित्सा प्रणालियाँ (जैसे जड़ी-बूटियों का उपयोग), कृषि के पारंपरिक उपाय, बहुस्तरीय सामाजिक सहयोग, लोक-परंपराएं सम्मिलित हैं। इन सभी के समावेश से न केवल सामाजिक संगठन मजबूत होता है, बल्कि पर्यावरणीय संरक्षण और स्थानीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित होता है, जो सतत् विकास के लक्ष्य तेरह, चौदह व पंद्रह के लिए आवश्यक है। पारंपरिक ज्ञान पर आधारित यह सामाजिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और दैनिक जीवन के विविध पहलुओं को सामुदायिक दृष्टिकोण और सहयोग से परिभाषित करती है। उदाहरणस्वरूप- जल संरक्षण, वन संरक्षण, मृदा प्रबंधन व जैव-विविधता संरक्षण आदि क्षेत्रों में थारू समाज की पारंपरिक समझ और व्यवहार स्थायी विकास के भारतीय मॉडल की एक मिसाल है। हालांकि, आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण की लहरों ने थारू समुदाय की जीवनशैली, क्रियाकलाप और पारंपरिक ज्ञान को प्रभावित किया है। शिक्षा, बाजारवाद, आधुनिक तकनीकी अभिवृद्धि, संचार साधनों की पहुँच तथा सरकारी हस्तक्षेप ने जहाँ कुछ सकारात्मक परिवर्तन किए, वहीं पारंपरिक सामुदायिकता एवं अन्य पहलुओं पर संकट

भी खड़ा किया। आधुनिकता के प्रभाव के कारण युवा पीढ़ी अब पारंपरिक गतिविधियों से दूर हो रही है, वे कृषि, वनोपज संग्रहण, स्वदेशी चिकित्सा, हस्तशिल्प जैसी पारंपरिक धरोहरों को कम कर आधुनिकीकरण व तकनीकीकरण को महत्व देने लगे हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बलरामपुर की थारू जनजाति की सामाजिक संरचना का आधार उनका पारंपरिक ज्ञान है, जो सतत् विकास में महत्वपूर्ण योगदान करता है किन्तु आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण के प्रभावों ने उनके पारंपरिक ज्ञान और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाला है। आवश्यक है कि थारू समुदाय के पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण के साथ-साथ उन्हें आधुनिकता के लाभ भी मिले, जिससे वे अपनी सांस्कृतिक विरासत संभालते हुए सतत् विकास की ओर अग्रसर हो सकें। इस दिशा में सरकार, शोधकर्ताओं और अन्य संस्थाओं की भूमिका अहम है। उनके स्वदेशी ज्ञान के दस्तावेजीकरण, नवाचार और स्थानीय सहभागिता से यह कार्य संभव हो सकेगा। यही मार्ग थारू समाज के सतत्, समावेशी और समृद्ध भविष्य की नींव रखेगा।

सन्दर्भ -

1. श्रीवास्तव, एस. के. (1958). *द थारू-ए-स्टडी इन कल्चरल डायनेमिक्स.* आगरा विश्वविद्यालय, आगरा, पृ-17.
2. https://docs.censusnepal.cbs.gov.np/
3. Home | Government of India
4. Report "E/C.19/2007/12 – Report of the 6th Session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues. Territories, Lands and Natural Resources".
5. कुमारी, नम्रता. (2023). *थारू जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक जन-जीवन.* भारती प्रकाशन, वाराणसी,पृ.-06.
6. मजूमदार, डी. एन. (1942). *दि थारूज एण्ड दियर ब्लड ग्रुप.* जर्नल ऑफ रायल एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता, भाग-31, पृ-33.
7. वर्मा, सुभाष चन्द्र. (2008). *थारू जनजाति: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन.* नवयुग पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, दिल्ली।
8. सहाय, इन्दू. (1998). *दि थारू ऑफ लखीमपुर खीरी पर्सपेक्टिव्स इन ट्राइबल डेवलपमेंट: फोकस ऑन उत्तर प्रदेश.* भारत बुक सेंटर, लखनऊ।
9. गेने काम्पैग्न. (2000). *इंडिजेनस नॉलेज अमोंग्स्ट द थारू ऑफ़ तराई रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश.* जे- 235/A, सैनिक फार्म्स खानपुर, न्यू दिल्ली।
10. मैत्री, समीरा. (2004). *दा थारू: दियर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स.* नोर्थन बुक सेंटर, न्यू दिल्ली।

11. वर्मा, सुभाष चन्द्र. (2010). *द इकोफ्रेंडली थारू ट्राइब : ए स्टडी इन सोसिओ-कल्चरल डायनेमिक्स.* जर्नल ऑफ़ एशिया पैसिफिक स्टडीज, वोल.1, पृ.-177-187.
12. श्रीवास्तव, एस. के. (1958). *द थारू: ए-स्टडी इन कल्चरल डायनेमिक्स.* आगरा विश्वविद्यालय, आगरा, पृ०-17.
13. सिंह, हेठी जोगा., & शर्मा, अनीता. (2002). *थारू जाति का सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक अध्ययन.* बरेली इतिहास विभाग, बरेली।
14. नेगी, कृष्णा & शर्मा, वंदना. (2025). *उत्तराखंड की जनजातियों के पारंपरिक परिधानों का समाजशास्त्रीय अध्ययन थारू एवं बुक्सा जनजातियों के सन्दर्भ में.* राधाकमल मुकर्जी: चिंतन परंपरा. अंक-2. समाज विज्ञान विकास संस्थान, बरेली (उ.प्र.)
15. Klarin, T. (2018). *The concept of sustainable development: From its beginning to the contemporary issues. Zagreb International Review of Economics & Business*, 21(1), 67-94.
16. सिंह, योगेंद्र. (1973). *भारतीय परम्परा की आधुनिकीकरण.* थॉमसन लिमिटेड इंडिया प्रेस, दिल्ली।

ईमेल– ैंतउं8212 / हउंपस.बवउ
ईमेल– उंसअपलं.दमीं2018 / हउंपस.बवउ

www.bohalshodhmanjusha.com
Impact Factor : 8.642

Bohal Shodh Manjusha ISSN : 2395-7115
July 2026 Page No. : 214-216

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES RESEARCH JOURNAL

శ్రీశ్రీ కవిత్వం - మార్క్సిస్టు ప్రభావం

డా.పసుపులేటి నాగమల్లిక
తెలుగు అధ్యాపకులు,ASD ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల (అ),
కాకినాడ.

ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో సామాజిక చైతన్యం, శ్రామిక జనపక్షపాతం, వాస్తవికత, పీడితజనపక్షం, సమసమాజ నిర్మాణం మొదలైన అంశాలను అభ్యుదయ కవిత్వం ప్రవేశపెట్టింది. ఊహాలోకాల్లో విహరిస్తున్న ఆధునిక కవిత్వాన్ని భూమార్గం పట్టించింది. సామాన్య మానవునికి పట్టం కట్టింది. శిష్ట్లా, పఠాభి, పురిపండా, అబ్బూరి, శ్రీశ్రీ, నారాయణబాబు, ఆరుద్ర, దాశరథి, కాళోజీ మొదలైన కవులు తమతమ పద్ధతుల్లో భావకవిత్వంపై తిరుగుబాటు చేశారు. కవిత్వంలో అతినవ్య కవిత్వ ప్రయోగాలు చేశారు.

శ్రీశ్రీ మహాప్రస్థానంలో సంప్రదాయ ముద్ర అక్కడక్కడా కన్పిస్తుంది. ఆయన తొలినాళ్లలో ప్రాచీన కవితాశైలిలో రచనలు చేశారు. భావకవిత్వం పైనున్న ఆసక్తితో కృష్ణశాస్త్రిగారి పద్ధతిలోనే భావకవితలు వ్రాశారు. 1930 సంవత్సరం తర్వాత శ్రీశ్రీ మీద మార్క్సిస్టు ప్రభావం పడింది. దానితో మహాప్రస్థానం పేరుతో ఒక కవితా సంకలనాన్ని ప్రచురించారు. మరో ప్రపంచం కోసం ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా 'హరోంహరా' అంటూ సాగాలని మార్క్సిస్టు ప్రభావంతో ప్రబోధించాడు.

"యమున మహిషపు లోహగంటలు మబ్బుచాటున ఖణేల్ మన్నాయి నరకలోకపు జాగిలమ్ములు గొలుసులు త్రెంచుకొని ఉలిక్కిపడ్డాయి.

ఉదయసూర్యుని సప్తహయములు నురుగులెత్తి పరుగులెత్తాయి కనకదుర్గ చండసింహం జూలు దులిపి ఆవులించింది ఇంద్రదేవుని మదపుటేనుగు

ఘీంకరిస్తూ సవాల్ చేసింది" అని తరతరాల బానిస వృత్తికి గుర్తులైన ఈ దేవతా వాహనాలు తిరుగుబాటు చేసినట్లుగా చెప్పాడు.

శ్రీశ్రీ రచనలో వాస్తవికత ప్రత్యక్షమౌతుంది. 'భిక్షు వర్షీయసి' ఖండికలో ఆరిన కుంపటి వంటి గాజుకన్నులు గల ముసలి స్త్రీ, కుక్క, ఎంగిలాకు కవితా వస్తువులయ్యాయి. సంధ్యాసమస్యలు ఖండికలో విద్యార్థి, ఉద్యోగి, పేదవాడు కన్పిస్తాడు. 'పేదలు' ఖండికలో ధనవంతుల అధికారానికి అణగిపోయిన పేదల వినయ స్వభావం కన్పిస్తుంది. 'బాటసారి' ఖండికలో ఎంతో దూరంలో ఉన్న 'కొడుకుకోసం తపన పడే పేదతల్లి ఆవేదన గోచరిస్తుంది. 'కుక్కపిల్లా, అగ్గిపుల్లా, సబ్బుబిళ్లా మొదలైన వస్తువులన్నీ కవితామయాలే. కాదేదీ కవిత కనర్హం" అంటూ కొత్త సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు.

చారిత్రక బౌతికవాద దృష్టితో చరిత్ర అంటే వ్యక్తుల చరిత్ర కాదు. సామాజిక వర్గాల, శ్రేణుల స్వభావం, ప్రవర్తన, ఆర్థిక రాజకీయ వ్యవస్థల నిర్మాణం మొదలైన అంశాల సమన్వయం, ఒక సామాజిక ప్రక్రియ అని 'మానవజాతి చరిత్రంతా వర్గపోరాటాల చరిత్రే' అంటూ విశ్లేషిస్తున్న దృక్పథాన్ని వివరించాడు.

పీడించే వర్గమొకటి, పీడనకు గురయ్యే వర్గమొకటి కొనసాగుతున్న శత్రు వర్గసమాజంలో సంఘర్షణఅనివార్యమౌతుంది. ఈ సంఘర్షణల పర్యవసానంగా సమాజం అనేక పరిణామాలకు లోనవుతూ ఉంటుంది.

అంతర్జాతీయ మార్క్సిజం, దేశ భక్తి ప్రభావంతో

"నరజాతి చరిత్ర సమస్తం పరపీడన పరాయణత్వం రణరక్త ప్రవాహసిక్తం దరిద్రులను కాల్చుకు తినడం"అని అభివర్ణించిన శ్రీశ్రీ

"రణరంగం కానిచోటు భూ స్థలమంతా వెదకిన దొరకదు గతమంతా తడిసె రక్తమున కాకుంటే కన్నీళులతో" అని విశ్లేషించారు.

"నైలునదీ నాగరికతలో – సామాన్యుని జీవనమెట్టిది ? తాజ్మహల్ నిర్మాణానికి – రాళ్లెత్తిన కూలీలెవ్వరు" అని ప్రశ్నించిన అభ్యుదయ కవిత్వం

"ఒక వ్యక్తిని మరొకవ్యక్తి ఒక జాతిని మరొక జాతి పీడించే సాంఘిక ధర్మం ఇంకానా ? ఇకపై సాగదు" అంటూ ఖచ్చితంగా ప్రకటించింది.

గతితార్కిక దృక్పథంతో నిరంతరం విరుద్ధశక్తుల మధ్య ఘర్షణ కొనసాగుతూ, ఐక్యత వుంటుందన్న మార్క్సిస్టు ఆలోచనా విధానాన్ని రెండు పరస్పర వ్యతిరేక శక్తులున్న సామాజిక వ్యవస్థ పైకి సహజీవనం

సాగిస్తున్నట్లు కనబడుతున్నప్పటికీ, వీటి మధ్య సంఘర్షణ జరుగుతూ ఉంటుంది. దానినే "పరస్పరం సంఘర్షించిన శక్తులలో చరిత్ర పుట్టెను" అని శ్రీశ్రీ వెల్లడించారు.

అంతర్జాతీయ దృక్పథంతో "సకలదేశ కార్మికులారా ఏకం కండి" అని ప్రబోధించిన మార్క్సిజం ప్రాపంచిక దృక్పథాన్ని ఆదర్శంగా స్వీకరించిన అభ్యుదయ కవులు ప్రగాఢమైన దేశభక్తితో పాటు తమ కవిత్వంలో విశాలమైన అంతర్జాతీయ దృక్పథాన్ని ప్రదర్శించారు.అందు మొదటి వరుసలో నిలిచిన శ్రీ శ్రీ

"చైనాలో రిక్షావాలా చెక్ దేశపు గని పనిమనిషీ ఐర్లాండున ఓడ కళాసీ అణగారిన ఆర్తులందరూ హాటన్ టాట్, జూలూ, నీగ్రో ఖండాంతర నానాజాతులు చారిత్రక యథార్థతత్వం

ఒకే గొంతుకతో చాటిస్తారనీ, దీర్ఘశ్రుతిలో తీవ్రధ్వనితో విప్లవశంఖం వినిపిస్తారనీ సూచించారు.

ముగింపు:- మహాప్రస్థానంపై మార్క్సిజం ప్రభావం ఉందని నారాయణరెడ్డిగారు తన సిద్ధాంత వ్యాసంలో ధృవీకరించారు. ఇందులోని 'దేశచరిత్రలు' గేయం గతితార్కిక భౌతిక వాదానికి నిలువుటద్దంలా నిలుస్తుందని ఆయన ఉదహరించారు.

"కదిలేదీ కదిలించేదీ మారేదీ మార్పించేదీ పాడేదీ పాడించేదీ పెనునిద్దుర వదిలించేదీ పరిపూర్ణపు బ్రతుకిచ్చేది" అదే కవిత్వమంటే అని శ్రీశ్రీ కవిత్వాన్ని నిర్వచించారు.

మార్క్సిస్టు ప్రభావంతో వాస్తవికత, అంతర్జాతీయ దృక్పథం, గతితార్కిక, చారిత్రక భౌతికవాద దృష్టితో రచనలు చేసిన శ్రీ శ్రీ "కవిత్వమున్నంత కాలం, కవితానుభూతి ఉన్నంతకాలం, కవితా రసాస్వాదన ఉన్నంతకాలం శ్రీశ్రీ జీవించియే ఉంటాడు" అని చెప్పిన బూదరాజు మాటలు ప్రత్యక్షర సత్యాలు.

ఆధార గ్రంథాలు:-

1. శ్రీ శ్రీ – మహాప్రస్థానం

2. ఆధునికాంధ్ర కవిత్వం సంప్రదాయాలు- ప్రయోగాలు – డాక్టర్ సినారె

3. తెలుగు సాహిత్య చరిత్ర- డాక్టర్ వెలమల సిమ్మన్న

4. తెలుగు సాహిత్య సమీక్ష -జి. నాగయ్య

PRINTED MATTER/PRINTING BOOK CLAUSE 121 (A) P & T GUIDE

गुगनराम एजुकेशनल एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.)
द्वारा भिवानी (हरियाणा), काठमाण्डू (नेपाल) से प्रकाशित

ISSN : 2395-7115
Impact Factor : 8.642

बोहल शोध मंजूषा

Bohal Shodh Manjusha

AN INTERNATIONAL MULTI DISCIPLINARY, MULTIPLE LANGUAGES
PEER REVIEWED, REFREED RESEARCH JOURNAL

Website :
www.bohalshodhmanjusha.com
Email : grsbohal@gmail.com

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Adv.
M. : 8708822674, 9466532152

गीना देवी शोध संस्थान
द्वारा श्रीगंगानगर, (राजस्थान), पटियाला (पंजाब) व नेपाल से प्रकाशित

ISSN : 2321-8037
Impact Factor : 7.834

Gina Shodh SANGAM

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES MONTHLY RESEARCH JOURNAL

Website : www.ginajournal.com
Email : grngobwn@gmail.com
Office : 8708822674

Editor :
Dr. Rekha Soni, Vice Principal
Education, Tantia University
M. 9828531975

गिरधारीलाल घासीराम शोधपीठ
द्वारा नई दिल्ली, आगरा, गाजियाबाद एवं नेपाल से प्रसारित

ISSN : 2348-5639
Impact Factor : 6.521

SHODH SAMALOCHAN

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES QUARTERLY RESEARCH JOURNAL

Website : https://ginajournal.com/shodh-samalochan/
Executive Editor : Dr. Varsha Rani M. 9671904323
Managing Editor : Dr. Mukesh Verma M. 9627912535

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
M. 8708822674

गीना प्रकाशन द्वारा
जयपुर, भिवानी एवं नेपाल से प्रसारित

ISSN : 2321-0540
Impact Factor : 5.621

KANCHANLATA

AN INTERNATIONAL PEER REVIEWED, REFEREED MULTIDISCIPLINARY
& MULTIPLE LANGUAGES HALF YEARLY RESEARCH JOURNAL

Managing Editor :
Dr. Mukesh Verma
M. 9627912535

Editor :
Dr. Naresh Sihag, Advocate
M. 8708822674

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक गुगनराम सोसायटी रजि. के लिए डॉ. नरेश सिहाग एडवोकेट ने मनभावन प्रिन्टर्ज, भिवानी से छपवाकर गीना प्रकाशन, 202, पुराना हाऊसिंग बोर्ड भिवानी-127021 (हरि.) से वितरित की।

ISSN 2395:7115

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

स्वेता कुमारी, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग

डॉ. लक्ष्मी कुमारी, सहायक प्राध्यापक

वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा, बिहार।

for the paper titled

दक्षिण एशिया में चीन की सॉफ्ट पावर कूटनीति और नेपाल में उसका प्रभाव

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 11-16

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Shashi Kant Upadhyay

for the paper titled

Customer Perceptions and Expectations of Digitalization in the Banking Industry : An Empirical Study with Chi-Square Analysis

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 17-29

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

निकिता पंत

शोधार्थी, हिन्दी विभाग,
लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़ (हल्द्वानी)
कुमाऊं विश्वविद्यालय, नैनीताल।

for the paper titled

'छाया मत छूना मन' में स्त्री जीवन की विडंबनाएँ

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 30-33

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ० शीला छीपा

सह–आचार्या, हिन्दी

विद्या प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज, पालड़ी, भीलवाड़ा।

for the paper titled

महादेवी वर्मा के गद्य साहित्य में नारी चेतना और मानवीय संवेदना

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 34-40

9 772395 711007

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

सुशीला देवी, शोधार्थी

डॉ० धनेश कुमार मीणा, शोध निर्देशक

श्री जगदीशप्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, चुरू रोड़, झंझनू– 333001 (राजस्थान)

for the paper titled

डॉ० अशोक कुमार 'मंगलेश' के समीक्षा–साहित्य का चिंतन

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 41-46

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. संजय कुमार सिंह

सहायक प्राध्यापक, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग,
पटना विश्वविद्यालय, पटना, बिहार।

for the paper titled

तुलसीकाव्य का वैशिष्ट्य

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 47-51

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Tejas Rajaram Jadhav, Research Scholar,

Dr. Hiren Jayantilal Dand, Research Guide,

Departmant of Computer Science,

Shri Jagdish Prasad Jhabarmal Tibrewala University, Jhunjhunu, Rajasthan.

for the paper titled

IoT Components and Machine Learning Algorithms for Smart Vehicles

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 52-63

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. वर्षा रानी

असि. प्रो. संस्कृत विभाग,
डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

for the paper titled

संस्कृत में नवाचार : परम्परा से प्रौद्योगिकी तक

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 64-68

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Tina Kimngaiting Vaiphei

PhD Scholar, Department of Political Science, University of Delhi, Delhi

Amy Nemchanpha Vaiphei

PhD Scholar, Department of Sociology, North-Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya

for the paper titled

A POLITICAL AND CONSTITUTIONAL STUDY OF MULTICULTURALISM IN INDIA WITH REFERENCE TO THE SIXTH SCHEDULE

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 69-78

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Prof. Bina Rai, Principal,

Avadh Girls' Degree College, University of Lucknow.

Nikhil Kumar Rai, Ph.D. Research Scholar,

Department of Political Science, University of Lucknow.

for the paper titled

The China - Pakistan Strategic Axis : Implications for India's National Security

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 79-86

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. अजय तिवारी

डी. लिट्., भूगोल विभाग

शास. मानकुंवर बाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी महिला महाविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)

for the paper titled

मध्यप्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का सतत् प्रबंधन और भविष्य की चुनौतियों का भौगोलिक विश्लेषण (विकसित भारत @2047 के सन्दर्भ में)

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 87-94

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

अंकित चौरसिया

शोधार्थी (पीएच.डी.) संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय।

for the paper titled

अथर्ववेद के पृथिवी सूक्त में पर्यावरणीय चेतना एवं समकालीन वैश्विक पर्यावरण संकट

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 95-99

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

अमल बर्मण

संस्कृत विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय।

for the paper titled

पर्यावरण चेतना में यज का महत्त्व

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 100-105

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Mukesh Kumar

PhD, Research Scholar,
Department of Political Science, University of Delhi.

for the paper titled

Changing Nature of Modern State in Digital era and Construction of New Political Identity through Biometric and Various Technological Advancement

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 106-114

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

9 772395 711007

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Kamal

Research Scholar, Department of Political Science,
University of Delhi, New Delhi.

for the paper titled

Social Engineering, Caste Coalitions and Electoral Politics : BJP's Strategy in Haryana (2014–2024)

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 115-126

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Ms. Sangeeta

Guest Faculty at School of Open Learning,
Department of Political Science, University of Delhi.

for the paper titled

Beyond the Binary : Male Victimization and the Unfinished Project of Gender Justice in India

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 127-148

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

डॉ. एस.पी. शुक्ला, प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र विभाग,
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
अंजुलि शुक्ला, शोधार्थी, राजनीति शास्त्र
शासकीय ठाकुर रणमत सिंह (स्वशासी) महाविद्यालय, रीवा (म.प्र)

for the paper titled

मतदान व्यवहार और इसके बहुआयामी निर्धारक तत्व : भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक विस्तृत समाजशास्त्रीय और राजनीतिक विश्लेषण

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 149-162

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Vajeer Singh

Assistant Professor in Teaching of Geography
Aakash College of Education, Kalirawan, Hisar.

for the paper titled

विकासशील देशों में शहरीकरण के रूझानों का विश्लेषण

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 163-166

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

सतीश भास्कर, सहायक प्राध्यापक,
यू.आई.एल.एस., चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, मोहाली, पंजाब।
अरविंदर कौर चुंबर, सह–प्रोफेसर,
देश भगत विश्वविद्यालय, मंडी गोबिंदगढ़, पंजाब।

for the paper titled

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डॉ. अजय शर्मा के उपन्यासों में यथार्थ का स्वरूप : एक विश्लेषण

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 167-172

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate
M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

चंचल जाट, शोधार्थी, हिंदी विभाग,

डॉ. मलय पानेरी, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष,

हिंदी विभाग, जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय, उदयपुर।

for the paper titled

प्रेत और छाया उपन्यासो में वर्णित पुरुष मनोवृत्ति का यथार्थ चित्रण

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 173-178

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Asha Yadav, PhD Scholar, Dept. of History,
University of Delhi, New Delhi, 110007.

Durgesh Kumar, PhD Scholar, Dept. of History,
University of Delhi, New Delhi, 110007.

for the paper titled

Colonialism : Space, Violence and a new Geographic Conception of India

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 179-186

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Shamama Bano

Research Scholar, Department of English
Bhagwant University Ajmer Rajasthan, Ajmer, Rajasthan.

for the paper titled

Motherhood, Sacrifice and Female Identity in Tony Morrison's Beloved

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 187-194

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

Jai Shri Prajapat

Research Scholar, MSBU, Bharatpur

Dr. Arvind Verma

Professor, MSJ Govt. College, Bharatpur.

for the paper titled

Strengthening Climate Action through the India–Japan Joint Crediting Mechanism : An Analysis of the June 2026 Rules of Implementation

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 196-200

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

अजय कुमार विश्वकर्मा, शोधार्थी, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग

डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.)

डॉ. नेहा मालवीय, सहायक प्राध्यापक

राय साहब भंवर सिंह महाविद्यालय, भैरुंदा, जिला–सीहोर (म.प्र.)

for the paper titled

आदिवासी ज्ञान और सतत् विकास : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले की थारू जनजाति के विशेष सन्दर्भ में)

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 201-213

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152

ISSN:2395-7115

बोहल शोध मञ्जूषा

Bohal Shodh Manjusha

Impact Factor : 8.642

INTERNATIONAL PEER REVIEWED REFERED AND INDEXED
MULTIDISCIPLINARY & MULTIPLE LANGUAGES

Published by : Guganram Educational & Social Welfare Society (Regd.)

Email : grsbohal@gmail.com Website : www.bohalshodhmanjusha.com

Certificate of Publication

is awarded to

డా.పసుపులేటి నాగమల్లిక

తెలుగు అధ్యాపకులు,ASD ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాల (అ),

for the paper titled

శ్రీశ్రీ కవిత్వం - మార్క్సిస్టు ప్రభావం

Published in Bohal Shodh Manjusha ISSN:2395-7115

July 2026, Vol. 24, Issue -1, Part-3, Page No. 214-216

Editor

Dr. Naresh Sihag Advocate

M.A., LL.B. (Hon's), M.A.J.M., M.Lib.& Information Science, M.Phil. Ph.D., D.Litt (Nepal) Diploma Panchayati Raj (Silver Medalist)

This Certificate is only Valid with the Presentation of Research Paper Copy.

#202, Old Housing Board, Bhiwani-127021 (Hry.) 8708822674, 9466532152